

(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

पृ.शी. : गिरणी कामगारांच्या दीर्घकालीन समस्या सोडविण्यात शासनास आलेले अपयश

मु.शी.: गिरणी कामगारांच्या दीर्घकालीन समस्या सोडविण्यात शासनास आलेले अपयश या विषयावर सर्वश्री. पांडुरंग फुळकर, मधुकर सरपोतदार, नितीन गडकरी, दिवाकर रावते, विनोद तावडे, डॉ.दीपक सावंत, सर्वश्री अरविंद सावंत, प्रकाश शेंडगे, डॉ.नीलम गोहे, वि.प.स. यांचा प्रस्ताव.

(चर्चा पुढे सुरु.....

श्री. जैनुदीन जव्हेरी (वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक प्राधिकारी संस्था) : सभापति महोदय, नियम 260 के अन्तर्गत हम मुंबई शहर में बंद हुई गिरणियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. इसकी जमीन का लाभ कामगारों को न मिलते हुए, बडे उद्योगपति जिन्होंने गिरणियों को बंद करने का षडयंत्र रचा, उनको इस जमीन का लाभ मिल रहा है. इस जमीन का लाभ गिरणी कामगारों के भविष्य के लिए और उनके बच्चों के लिए नहीं मिला है. यह प्रकरण सिर्फ जमीन का ही नहीं है, महाराष्ट्र में नागपुर, पुलगांव, वर्धा जैसे अनेक ऐसे शहर हैं, जहां पर गिरणी और जो दूसरे उद्योग थे और जहां पर रॉ-मेटीरियल सस्ता मिलता था, वे अच्छे ढंग से चलते थे, उनको बंद कर दिया गया. मिल मालिकों ने सरकार से कई फायदे लिए थे, उन्होंने सब्सिडी ली, उन्होंने सरकार से जमीन लीज पर ली. सरकार का इस बारे में कायदा है और जहां तक मुझे मालूम है कि उद्योगपतियों या किसी और को जब लीज पर जमीन दी जाती है तो लीज के एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि जब उसका परपज चेंज होगा तो लीज रद्द हो जाएगी. वह लीज अपने आप समाप्त हो जाएगी और इसके लिए सरकार को किसी के साथ झगड़ा फसाद करने की जरूरत नहीं है. हमने यह देखा है कि जो गरीब उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं उनको लीज पर दी हुई जमीन सरकार वापस ले लेती है और फिर उस जमीन की लीज वह बडे उद्योगपतियों को बाँट देती है.

सभापति महोदय, गिरणी बंद करना उद्योगपतियों का षडयंत्र है. गिरणी की जमीन का परपज चेंज करके वे दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं. परपज चेंज करने के

. . . A 2

... श्री. जव्हेरी

लिए जो कायदा है, उसके अनुसार परपज चेंज करने के लिए स्थानीय नगर परिषद, ग्राम पंचायत या महानगरपालिका से एन.ओ.सी. लेनी चाहिए। इसके लिए नगर परिषद या महानगरपालिका के सभागृह में ठराव आना चाहिए और परपज चेंज करना सही या नहीं, इस बारे में चर्चा होकर उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। अगर वहां पर उद्योगपति के फेवर में डिसीजन होता है तो सी.ई.ओ. को कलक्टर और सरकार के पास शिकायत करने का अधिकार है और वह बता सकता है कि यह 200 एकड़ जमीन पेपर मिल के लिए थी, यह जमीन कोल माइन्स के लिए थी और इसका ठराव नियमानुसार नहीं हुआ है, इसलिए इस ठराव को रद्द किया जाए। बड़े उद्योगपतियों के बारे में हमेशा यह देखा गया है कि डायरेक्ट ऊपर से आदेश लादे जाते हैं। जो जमीन लीज पर दी गई है, उसका परपज चेंज करने के लिए स्थानीय नगर परिषद, ग्राम पंचायत या महानगरपालिका के स्तर पर निर्णय होना चाहिए, लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए कलक्टर के ऊपर प्रेशर आता है, उसको ऊपर से आदेश दिए जाते हैं।

... भाषण जारी (B 1)

.... श्री. जहेरी

सभापति महोदय, जिस तरह से मुंबई में गिरणी कामगारों का प्रश्न है, उसी तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रश्न हैं। नागपुर में एम्प्रेस मिल का प्रश्न था, उस जमीन पर उद्योग के लिए रिजर्वेशन था। लेकिन वहां की जमीन बेची गई, उसका करोड़ों रुपए में आँक्षण किया गया। कामगारों का प्रोवीडेंट फंड, बोनस, एरियर्स इत्यादि का पूरा पैसा नहीं दिया गया। यहां तक कि सरकार का बकाया टॅक्स भी नहीं दिया गया। सरकार का कायदा है कि अगर कोई मिल लिक्वीडेशन में चली जाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मिल को जो पैसा प्राप्त होता है, उसमें से वह बँक का लेन-देन पूरा करने के बाद जो पैसा बचता है, उसमें से मजदूरों का प्रोवीडेंट फंड, एरियर्स इत्यादि दिया जाता है। हमने यह देखा है कि जो इन्डस्ट्री लिक्वीडेशन में चली जाती है और जब उसकी जमीन बेचते हैं तो दूसरे नाम से वही जमीन ले ली जाती है और मजदूरों का पैसा नहीं दिया जाता है। अगर कोई छोटा व्यक्ति अपना धन्धा बंद करता है तो बँक उससे पूरे गांव की एन.ओ.सी. मांगती है। लेकिन जब बिरला और अंबानी अपनी इन्डस्ट्री बंद करते हैं तो उनको एन.ओ.सी मिल जाती है। वे एक इन्डस्ट्री बंद करते हैं और दूसरी इन्डस्ट्री शुरू करते हैं। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। ये लोग सरकार का करोड़ों रुपए का टॅक्स छुबोते हैं, मजदूरों का पैसा नहीं देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार का कायदा है कि 60 साल तक मजदूर अपनी यूनियन नहीं बना सकते। अभी एक नया धन्धा शुरू हुआ है कि सरकार से सारी सुविधाएं लेकर 500 करोड़ रुपए में एक इन्डस्ट्री शुरू की जाती है और इन्डस्ट्री चालू होने के बाद में वह इन्डस्ट्री 1500 करोड़ रुपए में बिक जाती है। कंपनी का नाम चेंज हो जाता है और सरकार को टॅक्स का पैसा नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, सरकार ने काश्तकारों का कर्जा माफ किया है और उनको 60 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। इस बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन गरीब किसानों के लिए यह एक अच्छा कदम है। यह सरकार गरीबों का दुख दूर करने के लिए कोशिश करती है।

सभापति महोदय, इस सभागृह में मुंबई के गिरणी कामगारों के बारे में चर्चा करते करते हमारे माननीय सदस्य दिल्ली तक चले गए। उन्होंने बताया कि 1986 में जमीन बेचने का विचार हुआ और यह खबर एक समाचार पत्र में आई थी। माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे नेता

.... B 2

.... श्री. जहेरी

स्वर्गीय राजीव गांधी ने श्री. शरद पवार से यह बात कही, लेकिन इस बात का अधिकृत पुरावा नहीं है। हमारे नेता राजीव गांधी ने गरीबों के हित के लिए बहुत से काम किए, गरीबों के बारे में उनके विचार पूरी दुनिया को मालूम हैं। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी का नाम लेना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गरीबों के हित के लिए कार्य करने की परम्परा रही है। हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में ऐसा निर्णय लिया जो कि कोई अन्य नेता नहीं ले सकता। उन्होंने राजे-महाराजाओं के हजारों साल के प्रिविपर्स बंद कर दिये और उनकी जमीन जायदाद वापस ले ली। इस निर्णय के बाद यहां तक मुसीबत आई कि कहीं सरकार न चली जाए, लेकिन वे अपने निर्णय पर कायम रहीं। ऐसा निर्णय लेने वाली हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मजदूरों के हक में निर्णय लिए। उन्होंने जब यह देखा कि कोल माइन्स में मजदूरों को बराबर हक नहीं मिल रहा तो उन्होंने कोल माइन्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसा निर्णय कांग्रेस के शासन काल में हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिये। वे उद्योगपतियों से या अन्य किसी से नहीं डरे। 8-9 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा है और जितने भी अच्छे निर्णय लिए गए, वे सभी निर्णय कांग्रेस पार्टी की विचार-सरणी में कांग्रेसी शासन में लिए गए हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी।

.... भाषण जारी, नंतर तालेवार (सी-1)

SGJ/एसबीटी/ MMP/ पूर्वी श्री शर्मा

10:10

श्री जैनुद्दीन जव्हेरी

कई बार यह कहा जाता है कि आपात्कालीन स्थिति में सरकार ने गलितयाँ की थी. कई बातें कही जाती हैं. लेकिन मैं यह भी कहूँगा कि आपात्कालीन स्थिति में कई बातें अच्छी भी हुई हैं. कार्य करते समय कभी कभी गलितयाँ हो जाती हैं. सरकार से भी गलितयाँ हुई होगी लेकिन बुरे समय में सरकार की हिम्मत बढ़ानी चाहिए. अगर बुरे समय में हम सरकार की हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार को काम करने के लिए हिम्मत नहीं मिलेगी. जो अच्छा हुआ वह हमारा और बुरा हुआ वह तुम्हारा, यह नीति नहीं अपनानी चाहिए. जब मजदूरों के हित में लड़ने की बात होती है तो हम सब एक होकर सरकार को साथ देना चाहिए. ऐसे विषयों में हम सब एक होते हैं और एक होना भी चाहिए. हम करे सो कायदा, हम बोले वह अच्छा, हमारे साथ जो है वे अच्छे और जो हमारे साथ नहीं है वे बुरे, यह नीति बदलनी चाहिए. जब तक यह नीति नहीं बदलेगी तब तक कार्य करने में दिक्कत आएगी.

सभापति महोदय, मेरी सरकार से विनती है कि जो उद्योगपति सरकारी सुविधाओं का फायदा लेते हैं, जैसे जो उद्योगपति सेल्स टैक्स में छूट लेते हैं, सरकारी जमीन लीज़ पर लेते हैं, भविष्य निर्वाह निधि में छूट प्राप्त करते हैं, ऐसे उद्योगपतियों को बाध्य करना चाहिए कि वे कामगारों के हितों की रक्षा करें. जो उद्योगपति सरकारी सुविधाएं लेते हैं लेकिन मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करते उन्हें ब्लेक लीस्ट में डाल कर उन्हें सरकारी सुविधा देना बंद कर दिया जाए. ऐसे उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की परमीशन नहीं देनी चाहिए. सरकार कानून में इस प्रकार का प्रावधान करें तो सब उद्योगपति सुधर जाएंगे. लेकिन होता क्या है, कई बार हम यह देखते हैं कि कार्रवाई के तौर पर नागपुर की फेक्टरी बंद कर दी जाती है तो उद्योगपति किसी दूसरे नाम से चंद्रपुर में फेक्टरी खोल देते हैं. कंपनी के एक-दो अधिकारी बदल दिए जाते हैं बाकी सब अधिकारी वे ही रहते हैं. ऐसा न हो इसलिए इस बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए.

सभापति महोदय, मुंबई में गिरणी कामगारों को घर देने का प्रश्न है, वह उनको दिया जाना चाहिए. हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका खुद का घर हो. कंपनी बंद हो जाने के कारण कामगारों की नौकरी चली गई है, पूरा परिवार सड़क पर आ गया है. जिस प्रकार से सरकार अपने कर्मचारियों को हर प्रकार की सुविधा देती है, जैसे पेंशन देती है और अन्य सुविधा देती है, उसी प्रकार से कामगारों को भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए और कामगारों को भी

...2

(सभापतीस्थानी माननीय तालिका सभापती श्रीमती उषा दराडे)

श्री जैनुदीन जव्हेरी

सुविधा देनी चाहिए. कामगारों को घर मिलना चाहिए, मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, एक हजार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए. महाराष्ट्र में जहां जहां उद्योग है वहां के कामगारों को घर मिलना चाहिए और जो भी कामगारों की समस्या है, प्रश्न है, वे हल करें. मुझे उम्मीद है कि लोकशाही आघाडी की सरकार कामगारों के हितों की रक्षा करेगी और उनके सारे प्रश्न हल करेगी. इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.

इसके बाद श्री तावडे का भाषण

....3

श्री. विनोद तावडे (विधानसभेने निवडलेले) माननीय सभापती महोदय, मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांमुळे गिरणी कामगारांवर कशा प्रकारचे संकट कोसळलेले आहे यासंदर्भात काल पासून अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपले विचार व्यक्त केलेले. या चर्चेमध्ये ज्या मुद्यांच्या उल्लेख झालेला नाही असेच मुद्दे मी या ठिकाणी उपस्थित करणार आहे. मी जे काही मुद्दे मांडणार आहे त्यावर माननीय मुख्यमंत्रीमहोदयांनी भाष्य करावे अशी माझी इच्छा आहे. काल या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. अरुणभाई गुजराथी यांनी या चर्चेच्या अनुषंगाने विचार मांडलेले आहेत. त्यांनी जमीन विक्रीच्या संदर्भात महानगरपालिकेने परवानगी दिली होती अशा प्रकारचे काही विचार मांडले होते. आम्ही सुध्दा महानगरपालिकेत होतो. गिरण्यांच्या जमिनीच्या विक्रीच्या संदर्भात डीसी रुल करण्यात आला त्यामध्ये जर 600 एकर जमीन असेल तर त्यातील 200 एकर जमीन गिरणी मालकाला, 200 एकर जमीन म्हाडाला आणि 200 एकर जमीन महानगरपालिकेला असे ठरले होते परंतु पुन्हा या डीसी रुलमध्ये सुधारणा करण्यात आली व त्यानुसार 30 एकर जमीन महानगरपालिकेला, 22 एकर जमीन म्हाडाला आणि 545 एकर जमीन मिल मालकाला देण्याचे ठरले. त्यानुसार गिरणी मालकांना जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी मिळाली. मिळच्या जमिनी विकल्यानंतर गिरणी कामगारांच्या मुलांना किंवा त्यांना रोजगार देऊ असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.

यानंतर श्री. गायकवाड....

श्री.विनोद तावडे ...

रोजगाराच्या संदर्भात सांगावयाचे म्हणजे गिरणी कामगारांच्या मुलांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरले होते तसेच प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी मिटकॉनवर टाकण्यात आली होती परंतु त्यांना या प्रशिक्षणाचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे त्यांनी प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरु केलेले नाही. शासन जर खरोखर प्रामाणिक असेल तर मिटकॉनला पैसे तातडीने दिले असते व पैसे दिल्यानंतर प्रशिक्षण देण्याचे काम त्यांनी देखील सुरु केले असते. तेव्हा त्यांना पैसे केव्हा देण्यात येणार आहे आणि प्रशिक्षण देण्याचे काम ते केव्हा सुरु करणार आहेत याचे उत्तर मिळाले तर सरकार किती प्रामाणिक आहे हे आम्हाला समजेल. त्याचप्रमाणे 2007 साली कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते त्याची अंमलबजावणी केव्हा होईल याची माहिती आम्हाला माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तरातून मिळावी अशी अपेक्षा आहे.

सभापती महोदया, यानंतर मी दुसरा मुद्दा या ठिकाणी मांडणार आहे. गिरणी कामगारांना द्यावयाच्या घराच्या संदर्भात अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भाषणतून मुद्दे मांडलेले आहेत. तीन महिन्या पूर्वी माननीयमंत्री महोदयांनी घोडपदेव येथे भूमिपूजन केले होते. परंतु गेल्या तीन महिन्यात त्या ठिकाणी कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यावेळी जी काही भाषणे करण्यात आली होती त्यासंबंधीची चर्चा गिरणी कामगारांमध्ये बरीच होत आहे. परंतु अजूनही त्या कामाची प्रगती झालेली नाही तेव्हा या कामगारांना तेथे बांधण्यात येणारी घरे केव्हा मिळणार आहेत ? घरे बांधण्याच्या संदर्भात काही टाईम बाऊन्ड कार्यक्रम तयार करण्यात आला तर या ठिकाणी पोटतिडकीने जो विषय मांडण्यात आला आहे. त्या विषयाच्या उत्तरातून काही तरी हाताशी लागले आहे असे गिरणी कामगारांना वाटेल.

सभापती महोदया, गिरणी कामगारांना घरे बांधून द्यावयाची आहेत त्याबाबतीत आणखी एक मुद्दा मला मांडावयाचा आहे. आज रियल इस्टेटचे भाव वाढलेले आहेत त्याचप्रमाणे एफ.एस.आय. देखील वाढवून दिला जात आहे. धारावी येथे झोपडपट्टीत राहणा-यांना 400 चौरस फुटाची घरे बांधून देण्यात येणार असल्याचे घोषणा करण्यात आली आहे. असे असतांना गिरणी कामगारांना 225 चौरस फुटाची घरे का देण्यात येत आहे ? त्यांना देखील 400 चौरस फुटाची घरे बांधून दिली पाहिजेत. ज्यांनी अनधिकृतपणे जागा घेतल्या व त्या जागावर झोपडया उभ्या केल्या त्यांना घरे देत असतांना 400 चौरस फुटाची घरे दिली जातात मग जे अधिकृतपणे राहतात, ज्यांनी मुंबई

2..

नगरी उभी केली होती ज्यांनी येथे धाम गाळ्ला होता त्यांना 400 चौरस फुटाची घरे का दिली जात नाहीत ? त्यांना देखील 400 चौरस फुटाची घरे देण्यात येतील असे माननीय मुख्यमंत्रांनी सांगितले तर या विषयामध्ये सरकारला खरोखर तळमळ आहे असे सर्वाना वाटेल.

सभापती महोदया, या प्रस्तावावर बोलत असतांना दोन तीन सन्माननीय सदस्यांनी एका मुद्यासंबंधीचा उल्लेख केला होता. शहरातील गिरण्याच्या जमिनीच्या बदल्यात म्हाडाला उपनगरात जागा देण्यात येणार आहे. सिम्पलेक्स मिल मुंबई शहरामध्ये आहे आणि त्याच्या आर्किटेक्टने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे गोरेगाव व्हिलेजमध्ये जागा देण्यात येईल अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. त्याचप्रमाणे या जागेच्या बाबतीत आमची हरकत नाही असे म्हाडाच्या अधिका-यांनी म्हटलेले आहे तेव्हा अशा प्रकारचे ना हरकत पत्र म्हाडाच्या अधिका-यांनी कशाच्या आधारावर दिले आहे ? त्यांनी जर चुकीचे पत्र दिले असेल तर म्हाडाच्या संबंधित अधिका-याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे काय ? म्हाडाचे अधिकारी मनमानी करीत आहेत आणि त्यांची संबंधित व्यक्तीबरोबर साठगाठ आहे त्यामुळे प्रत्येक स्केअर फुटाचा हिशोब करून अशा प्रकारे त्यांना ना हरकत पत्र देण्याचे काम केले जात आहे. सिम्पलेक्स मिलच्या जमिनीच्या प्रकरणामध्ये शासनाने लक्ष घालावे अशी मी या चर्चेच्या निमित्ताने शासनाला विनंती करीत आहे.

या संबंधी ज्या म्हाडाच्या अधिका-यानी आमचा काही आक्षेप नाही असे श्री.जे.एम.पारेख यांना कळविले आहे त्या अधिका-याविरुद्ध सरकार कारवाई करणार आहे किंवा नाही सरकारने जर याप्रकरणात संबंधित अधिकाच्याविरुद्ध कारवाई केली तर खालच्या पातळीवर जी काही ॲडजेस्टमेंट केली जात आहे तिला आळा बसेल. गिरणी कामगाराच्या संदर्भात आणखी काही मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत. ज्या कामगारांची कायदेशीर देणी अजूनही मिळालेली नाहीत त्यांना ती कधी मिळणार आहेत ? काही प्रकरणामध्ये कोर्टात लिटीगेशन सुरु आहे त्यामुळे या गिरणी कामगारांना दरमहा एक हजार रुपये निर्वाह वेतन देण्याची गरज आहे.

नतर श्री.सुंबरे

श्री. विनोद तावडे

हा निर्वाह भत्ता दिला गेला पाहिजे.

दुसरा मुद्दा असा आहे की, जे गिरणी कामगार बेकार आहत त्यांच्या कुटुंबियांना कामगार विमा योजनेप्रमाणे वैद्यकीय मदत चालू ठेवली गेली पाहिजे. आज आरोग्य रक्षणाच्या दृष्टीने अशा बेकार गिरणी कामगारांच्या कुटुंबियांसमोर ज्या समस्या उभ्या राहतात त्यांच्याशी सामना करण्यासाठी त्यांना अशी काही मदत मिळाली तर त्यांची सरकार काळजी घेत आहे असे त्यांनाही वाटू लागेल. असे जे कामगार बेकार झालेले आहेत त्यांचा आर्थिक अपमृत्यू झालेला आहे असे समजून त्यांना प्रॉफिडंड फंडातून पेन्शन देण्याचा आग्रह आपण केंद्राकडे धरला पाहिजे. कारण शेवटी या बाबतीत एनटीसी म्हणजेच केंद्राचा वस्त्रोद्योग विभाग देखील तितकाच जबाबदार आहे. म्हणूनच एक खास बाब म्हणून अशा कामगारांना फॅमिली पेन्शन देण्याचा विचार करणे आज महत्त्वाचे आहे.

सभापती महोदय, बेकार कामगारांच्या मुलांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळाले पाहिजे. नाही तरी आज आपण या बेकार झालेल्या गिरणी कामगारांना नोकरी देत नाही, नोकरीची हमी देत नाही, दुसरा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वा नोकरीसाठी उपयुक्त असे प्रशिक्षण देत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना अशा प्रकारे आधार देण्याची आवश्यकता आहे. मी आपल्याला आठवण करून देऊ इच्छितो की, जेव्हा युती सरकार या राज्यात सत्तेवर होते तेव्हा इंजिनिअरींग कॉलेजमधील एक सीट ही काशिमरमधील विद्यार्थ्यांसाठी आपण आरक्षित ठेवली होती. अशाच प्रकारे गिरणी कामगारांच्या मुलांसाठी आपण इंजिनिअरींग, आर्किटेक्चर इत्यादी कॉलेजांमध्ये बेकार गिरणी कामगारांचा मुलगा वा मुलगी यांच्यासाठी काही सीटस् आरक्षित ठेवाव्यात अशी एक सूचना मी या निमित्ताने करतो. या संदर्भात मिटकॉनला पैसे देऊन ते अशा मुलांना प्रशिक्षण देतील तेव्हा देतील पण या मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने इंजिनिअरींग, मेडिकल, आर्किटेक्चरींग कॉलेजमध्ये काही जागा आपण आरक्षित ठेवल्या तर या मुलांचे त्याही दृष्टीने शिक्षण होऊ शकते. तसेच हे जे बेकार गिरणी कामगार आहेत त्यांची नोंद बीपीएल खाली करून, ते जेव्हा गिरणी कामगार होते तेव्हा ते बीपीएल खाली येत नव्हते पण गिरण्या बंद झाल्याने ते आज बेकार झालेले आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांची नोंद बीपीएल खाली करून घेऊन त्यांना बीपीएल खालील सवलतीचा

..... इ 2 ...

श्री. तावडे

फायदा घावा, आज त्यांची ही महत्त्वाची गरज आहे हे आपण लक्षात घ्यावे. अशा प्रकारच्या उपाय योजना आपण आज करणार असू तर या विधी मंडळामध्ये जी या गिरणी कामगारांबदल चर्चा चालू आहे, त्यांच्याबाबत जी चिंता व्यक्त आपण सारे व्यक्त करीत आहोत तेव्हा त्यांना न्याय खरोखरी घावयाचा असेल तर या मी नेमक्या सुचविलेल्या 5-6 गोष्टी आहेत त्याबाबत आपल्या उत्तराच्या भाषणात काही उल्लेख आला तर या गिरणी कामगारांना न्याय मिळेल असे होईल आणि तेच आज महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. एवढे बोलून मी भाषण संपवितो. धन्यवाद.

..... इ 3 ...

श्री. विलासराव देशमुख (मुख्यमंत्री) : सभापती महोदय, या सदनामध्ये मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची चर्चा माननीय विरोधी पक्षनेता श्री.पांडुरंग फुंडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली आहे. या चर्चेत अनेक सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला आणि गिरणी कामगारांच्या संबंधातील आपल्या तीव्र भावना अत्यंत पोटतिडकीने येथे मांडल्या आहेत. सभापती मोदय, मुंबईतील या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या प्रश्नाच्या इतिहासामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही. परंतु या मुंबईचे वैभव असलेल्या गिरणगाव आणि मुंबईतील गिरण्या यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील दुष्काळी भागातील सगळी मंडळी मुंबईत येऊन पिढ्यान् पिढ्या काम करीत होती. ...

(यानंतर श्री. सरफरे एफ 1 ..

श्री. विलासराव देशमुख...

त्यावेळी वेगवेगळ्या गिरण्यांमध्ये सव्वा दोन लाख गिरणी कामगार काम करीत होते. परंतु मधल्या काळात एक फार मोठा संप झाला, हा संप अनेक दिवस चालला. त्या संपानंतर गिरण्या बंद पडल्या. तेव्हापासून खन्या अर्थाने या वस्त्रोद्योगामध्ये एक प्रकारची मंदीची लाट आली. त्यानंतर अनेक गोष्टींमुळे या गिरण्या दुर्देवाने बंद पडल्या. अनेक कामगारांचे पगार थकले, त्यांचे जीवन उद्धवस्त झाले. गिरणी मालकांनी याबाबत अतिशय उदासीनतेची भूमिका घेतली. आम्ही त्यांचे पैसे देऊ शकत नाही अशाप्रकारची भूमिका त्यांनी घेतली. मला वाटते की, त्यावेळी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आणि इतर अनेकांनी या संदर्भात प्रयत्न केले. त्या गिरण्या पुन्हा सुरु व्हाव्यात म्हणून गिरण्यांच्या आधुनिकीकरणाला परवानगी देण्याचा प्रयत्न झाला. आधुनिकीकरणासाठी गिरणी मालकांकडे पैसे नाहीत म्हणून गिरणी मालकांच्या ताब्यातील काही जमीन विकून आणि त्यामधून पैसे उभे करून पुन्हा नवीन पद्धतीने गिरण्या सुरु करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्याबाबतीत फारशी प्रगती झालेली नाही. आणि म्हणून नियमामध्ये दुरुस्ती करून त्यामध्ये एक फॉर्म्युला असा मान्य केला की, गिरण्यांच्या जमिनीपैकी एक तृतियांश जमीन गिरणी मालकाने ठेवावी, एक तृतियांश जमीन म्हाडाला द्यावी आणि एक तृतियांश जमीन बी.एम.सी. ला द्यावी. हा फॉर्म्युला ठरविल्यानंतर सुधा कुणीही फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. शेवटी जमीन मालकांची अशी भूमिका राहिली की, आपली जमीन ही आपल्याच ताब्यात राहिली पाहिजे आणि बी.एम.सी. व म्हाडाला कमीत कमी जमीन गेली पाहिजे. अशाप्रकारची सतत त्यांची भूमिका राहिली. त्यामुळे राज्य सरकारने डी.सी. रुलच्या सेक्षन 58 प्रमाणे वेळोवेळी प्रयत्न करूनही त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अशाप्रकारचा प्रयोग एक-दोन वेळा करण्यात आला. यामध्ये प्रश्न असा आहे की, जी इमारत पाडली जाईल त्याठिकाणी उद्योग असेल, त्यामुळे ती इमारत पाडल्यानंतर एक तृतियांश, एक तृतियांश पर्यंत इमारत तशीच ठेवून तिच्या आतमध्ये बांधकाम करण्यात आले. कारण तसे करण्यास नियमाची आडकाठी येत नाही. त्यामुळे त्यांनी बाहेरचे स्ट्रक्चर तसेच ठेवून आतमध्ये इमारत बांधण्यास सुरुवात केली. आणि म्हणून प्लॅन डेव्हलपमेंटची अपेक्षा त्यामधून पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे टेकस्टाईल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सन 2001 मध्ये समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीने विविध कामगारांच्या संघटनांबोरोबर अनेक वेळा चर्चा केली, गिरणीच्या मूळ मालकांबोरोबर चर्चा केली. आणि म्हणून या फॉर्म्युल्यामध्ये बदल केल्याशिवाय गिरणी कामगारांची

DGS/ KGS/ MMP/

श्री. विलासराव देशमुख...

देणी देता येणार नाहीत. अनेक गिरणी कामगारांनी आंदोलन, उपोषण अशा सर्वच मार्गाचा अवलंब केला तरीही त्यामधून मार्ग निघत नव्हता. अनेक कामगारांनी आत्महत्या केल्या. इतकी वाईट अवरथा झाल्यानंतर त्यामधून मार्ग काढला पाहिजे. शेवटी पैश्याची जबाबदारी आहे, कामगारांनी घेतलेल्या स्वेच्छा निवृत्तीमुळे त्यांची न्याय देणी त्यांना दिली पाहिजेत. म्हणून त्यामधून मार्ग काढण्याचा समितीने विचार केला व त्या फॉर्म्युल्यामध्ये बदल केला. त्या गिरणी कामगारांना पहिल्यांदा देणी दिली पाहिजेत. जमीन विकल्यानंतर आलेले पैसे त्यांच्या जॉईट अकाऊंटमध्ये जमा केले पाहिजेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. त्यामध्ये नगर विकास विभागाचे सचिव आणि इतर प्रतिनिधींना घेण्यात आले. आणि जमिनीची विक्री केल्यानंतर जमा होणाऱ्या पैश्यामधून गिरणी कामगारांची देणी पहिल्यांना दिली पाहिजेत. ती दिल्यानंतर त्यांना इतर कामांसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे आतापर्यंत 32 गिरण्यांना मुंबई महानगरपालिकेने इतर कामे सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोदयोग महामंडळाच्या जवळपास 25 गिरण्या आणि इतर खाजगी गिरण्या आहेत.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

अशा पद्धतीने ही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आपण जवळपास त्यातून 900 कोटी रुपयांची देणी देऊ शकलो आहोत. त्यांना व्ही.आर.एस.देखील दिली. एवढे च नाही तर आपण असाही प्रयत्न केला की, केवळ कामगारांना व्ही.आर.एस.देऊन प्रश्न सुटणार नाही. साधारणपणे दहा गिरण्यांच्या कम्पाऊंड मध्ये चाळी आहेत आणि त्या चाळीमध्ये गिरणीतील काही कामगार अनेक वर्षांपासून रहात होते. त्यामुळे तुम्हाला त्यांना चाळीतून बाहेर काढता येणार नाही. किमान येथील चाळीमध्ये रहाणाऱ्या लोकांना संरक्षण दिले पाहिजे. त्यामुळे या कामगारांसाठी घरे बांधून द्यावीत, तरच आम्ही तुम्हाला पुढच्या गोष्टीसाठी परवानगी देऊ अशी संबंधितांना अट घालण्यात आली. अशा प्रकारे गिरण्यांच्या जागेमध्ये ज्या चाळी आहेत, तेथील रहाणाऱ्या लोकांची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु बाकीचे कामगार मिलच्या कम्पाऊंडच्या बाहेर रहात होते. मिलच्या कम्पाऊंड मध्ये कामगारांना रहाण्यासाठी ज्या चाळी बांधण्यात आल्या होत्या, त्याठिकाणी साधारणपणे 1000-1200 कामगार रहात होते. त्यापेक्षा जास्त कामगार बाहेर दुसऱ्या ठिकाणी रहात होते. जे कामगार मिलच्या कम्पाऊंड मधील चाळीमध्ये रहात होते, त्यांची घरे ही 60 ते 100 फूट इतकी होती. आज आम्ही झोपडपट्टीवासियांना 225 स्व.फू.इतके घरे देत आहोत. मग या कामगारांनाही तेवढी घरे का देऊ नयेत ? असा विचार केला आणि त्याप्रमाणे निर्णय घेऊन तो कम्पलसरी करण्यात आला. ही बाब त्यांनी मान्य केली. आमच्या ताब्यामध्ये ज्या जमिनी आल्या, तेथे म्हाडाच्यावतीने घरे बांधणार आहोत. त्यातील 50 टक्के घरे ही कामगारांसाठी दिली जातील. याठिकाणी सर्वच कामगारांसाठी व्यवस्था होईल की नाही, हे आजच्या घडीला सांगणे कठीण आहे. याबाबतीत आमचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी जादा एफ.एस.आय.देण्याचा प्रसंग आला तरी तो देण्याची आमची तयारी आहे. एकत्र आमच्याकडे जागा कमी आहे आणि मग पुढे अशीही मागणी होईल की, या कामगारांना 400 स्व.फू., 500 स्व.फू. किंवा 700 स्व.फू. घरे का देऊ नयेत ? अशा प्रकारे अनेक मागण्या येऊ शकतात. ही मागणी चुकीची आहे असे मी मानणार नाही. यामध्ये तेथील स्थानिक परिस्थिती, जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेता यामध्ये जास्तीतजास्त कामगारांना सामावून घ्यावयाचे असेल तर आजच्या घडीला तरी आम्हाला तो विचार करणे शक्य नाही. आज सुध्दा आम्ही सगळ्या कामगारांना मिळालेल्या जागेमध्ये जादा एफ.एस.आय.देऊनही घरे उपलब्ध करून देऊ शकतो की नाही ? हा प्रश्न आहे. परंतु आमचा प्रयत्न राहील की, शेवटी जी घरे

. . . . जी-2

श्री.विलासराव देशमुख

उपलब्ध होतील, ती कोणाला द्यावयाची, याबाबतीत कामगार संघटनांनी निर्णय द्यावा. आणि या गोष्टीला कामगार संघटनेच्या बैठकीमध्ये त्यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे कोणतीही घरे द्यावयाची असतील तर त्यासाठी त्यांच्याकडून मान्यता घेतली जाईल आणि जसजशा जागा उपलब्ध होतील, त्याप्रमाणे कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत निश्चितपणे विचार करता येईल.

सभापती महोदय, दुसरी गोष्ट म्हणजे या कामगारांच्या घरातील एखाद्या व्यक्तिला किंवा जे कामगार बेकार झाले आहेत, त्यांना नोकरी देणे आणि हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे. परंतु आता या मुलांना ट्रेनिंग द्यावे लागेल. कारण तेथे आता गिरण्या नाहीत, तेथे मॉल्स् उभे राहिले आहेत, आय.टी.कंपन्या आलेल्या आहेत आणि अनेक एन्टरटेनमेंटच्या गोष्टी आलेल्या आहेत. नवीन उद्योग आलेले आहेत. पण जोपर्यंत या मुलांना ट्रेनिंग देणार नाही तोपर्यंत त्यांना काम मिळण्यामध्ये अडचणी येतील. म्हणून या मुलांसाठी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतीत जागा ताब्यात घेतली आहे, त्याचा प्लॅन तयार केला असून लवकरच या कामाला सुरुवात करीत आहोत. कारण जर या मुलांना ट्रेनिंग दिले नाही तर या मुलांना नोकरी मिळणार नाही. सध्या नोकरी मिळणे हे सोपे काम नाही. परंतु या मुलांना ट्रेनिंग देऊन नोकरीमध्ये सामावृत्त घेण्याच्या दृष्टीने आमच्या धोरणानुसार प्रयत्न रहाणार आहे. त्यानुसार आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत देण्याच्या बाबतीत निश्चितपणे प्रयत्न करीत आहोत. ही गोष्ट खरी आहे की, त्याठिकाणी एवढे मोठमोठे मॉल्स् निर्माण होणार असतील आणि एवढया मोठया प्रमाणात संपत्ती जनरेट होणार असेल तर आपण सुधा गिरणी कामगारांच्या प्रती काही देणे लागतो अशी भावना गिरणी मालकांनी ठेवली पाहिजे. म्हणून त्यासाठी वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठका घेण्यात येत आहेत. तसेच कोर्टमध्ये काही प्रकरणे सुरु आहेत. तसेच कोर्टने याबाबतीत काही आदेशही दिलले आहेत. त्याप्रमाणे मुख्य सचिवांनी संबंधितांच्या वेगवेगळ्या बैठका घेऊन त्यातून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु यामध्ये प्रामुख्याने कामगारांची देणी हा महत्वाचा विषय आहे. याबाबतीत सांगावयाचे तर साधारण पणे जवळपास 932 कोटी रुपयांची देणी दिलेली आहेत आणि आता फक्त 19 कोटी रुपयांची देणी शिल्लक आहेत. यामध्ये सुधा प्रामुख्याने मफतलाल मिलकडून पैसे यावयाचे आहेत.

यानंतर कृ.गायकवाड

DVG/ MMP/ KGS/ प्रथम श्रीमती रणदिवे..

10:35

श्री. विलासराव देशमुख ...

उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित असल्यामुळे, 19 कोटी रुपयांची देणी शासनाने देणे शिल्लक आहेत. उर्वरित सर्व कामगारांची देणी शासनाने दिलेली आहेत. इतर काही मिल देखील वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोर्टात गेलेल्या आहेत. गिरणीच्या जमिनी ज्या वेळी शासन घेते त्यासंदर्भात काही मंडळी कोर्टात गेलेली आहेत. कोर्टाने काही प्रकरणांना स्थगिती दिलेली आहे. या प्रकरणांचा फॉलोअप व पाठपुरावा करण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. हे ही या ठिकाणी सांगणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. या विषयावर सभागृहात चर्चा झाली. त्यावेळी काही सन्माननीय सदस्यांनी असे म्हटले आहे की, अजूनही काही कामगारांना कायदेशीर देणी देण्यात आलेली नाहीत. त्यांना किमान हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता मिळाला पाहिजे अशी मागणी राज्य शासनाकडे कामगारांच्या संघटनेने केलेली आहे. येथे करण्यात आलेली ही मागणी देखील तपासून पहाण्यात येईल. देणी न मिळाल्यामुळे, कामगारांची उपासमार होत असेल तर ही देणी त्यांना मिळेपर्यंत कामगारांची उपासमार होऊ नये याकरिता काही सूचना केलेली आहे. या सूचनांचा देखील राज्य शासन निश्चित विचार करणार आहे. तसेच या प्रश्नातून मार्ग निघण्यामध्ये कोणतीही अडचण नाही असे मला स्वतःला वाटत आहे. त्यामुळे या प्रश्नातून निश्चितपणे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करणार आहे.

सभापती महोदय, गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर चर्चा होत असताना काही सन्माननीय सदस्यांनी बीपीएल कार्डबाबत काही सूचना केली होती. त्या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, बीपीएल कार्ड देताना कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागते ती यादी कशी ठरविली जाते याची आपल्याला कल्पना असेल. कामगारांना बीपीएल कार्ड देण्याच्या संदर्भात काही तांत्रिक स्वरूपाच्या अडचणी आहेत. बच्याचशा कामगारांना पिवळी कार्ड देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. साधारण हजार ते बाराशे लोकांना रेशनचे पिवळे कार्ड देण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त इतर वेगळ्या मार्गाने गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचा देखील शासन प्रयत्न करणार आहे.

सभापती महोदय, या ठिकाणी कामगारांना घरे देण्याच्या संदर्भात एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या घरांची किंमत कोण ठरविणार, कशी ठरविणार, इतरांना घरे मोफत का

..2..

श्री. विलासराव देशमुख ...

दिली जाणार नाहीत असे अनेक प्रश्न त्या वेळी उपस्थित करण्यात आले होते. त्या संदर्भात मी सांगू इच्छितो की, कोणताही नफा न घेता म्हाडा कामगारांकरिता घरे बांधणार आहे. घर बांधण्याची जेवढी कॉस्ट असेल, तेवढी कॉस्ट केवळ कामगारांकडून वसूल केली जाणार आहे. अशा प्रकारची भूमिका शासनाने घेतलेली आहे. त्या दृष्टीने शासन प्रयत्न करणार आहे. कामगारांची सर्व लेजिटिमेट देणी शासनाने दिलेली आहेत. राज्य शासनाने कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय एक विशेष बाब म्हणून घेतलेला आहे. या कामगारांचे संपूर्ण आयुष्य मुंबईत गेलेले आहे. त्यांच्या जागेवर घरे बांधायची आणि ती इतरांना विकायची हे बरोबर नाही. आज मुंबईतील मोडकळीसा आलेल्या इमारती सतत कोसळत आहेत. त्यामुळे तेथील लोकांना ट्रान्झीट कॅपमध्ये दूर अंतरावर स्थलांतर करावे लागते. परंतु या लोकांची काम करण्याची जागा मुंबईमध्ये असल्याने त्यांना तेथे राहणे गैरसोयीचे होते. यामुळे ज्या जागेवर नवीन इमारती बांधण्यात येणार आहेत तेथील 50 टक्के घरे ट्रान्झीट कॅपला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित 50 टक्के जमीन उपलब्ध होणार आहे त्यामध्ये नियमाप्रमाणे कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. या घरांची किंमत 6 लाख रुपये इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. कामगारांना ही घरे घेणे शक्य व्हावे याकरिता 2 लाख रुपयांची सबसिडी देखील शासनाकडून देण्यात येणार आहे. तसेच जेएनएनयुआरएम योजनेमध्ये ही तरतूद बसवून जास्तीत जास्त मदत देण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे.

सभापती महोदय, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या घरांच्या मेंटेनन्सचा देखील प्रश्न येथे उपस्थित करण्यात आला होता. या बाबत मी एवढेच सांगू इच्छितो की, कामगारांच्या घरातील व्यक्तींना नोकच्या मिळवून देण्याकरिता त्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता शासन प्रयत्न करीत आहे. कामगारांना तुमची व आमची अशी दोघांची देखील सहानुभूति आहे. राज्य शासनाने गिरणी कामगारांना इतर कामगारांपेक्षा वेगळे मानले आहे. या मुंबईमध्ये अनेक कारखाने बंद पडत आहेत, महाराष्ट्रामध्ये देखील अनेक कारखाने बंद पडत आहेत. परंतु मुंबईतील गिरणी कामगारांची शासनाने अधिक काळजी घेतली, अधिक संरक्षण दिले. कारण गिरणी कामगार हा

3..

श्री. विलासराव देशमुख ...

विषय मुंबईच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गिरणी कामगार मुंबईच्या विकासाशी निगडीत आहे. मुंबईचा विकास होण्यामागे गिरणी कागमार मूळ घटक असल्यामुळे त्यांना वेगळ्या पद्धतीने नियम लावलेले आहेत. कायद्यातील 58 वे कलम हे टेक्सटाईल मिल संदर्भात आहे. मुंबईतील टेक्सटाईल मिल वगळता इतर मिलला शासनाने एवढे संरक्षण दिलेले नाही.

यानंतर श्री. बरवड..

श्री. विलासराव देशमुख

या ठिकाणी एखादी इंजिनिअरिंग फॅक्टरी बंद पडली किंवा इतर कोणती फॅक्टरी बंद पडली तर त्यांना हे संरक्षण नाही. परंतु गिरणी कामगारांबद्दलचा विषय हा आपणा सर्वांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय राहिल्यामुळे यामध्ये आपण हा वेगळा विचार केलेला आहे. कारण हल्ली आपण पाहतो की, एखादी फॅक्टरी बंद पडल्यानंतर त्यांना एकदा व्हीआरएस दिली की, कामगार संघटनेपासून कोणीही फारशी जबाबदारी स्वीकारत नाही अशी परिस्थिती साधारणपणे औटोगिक धोरणात किंवा कामगारांबाबतच्या धोरणात आहे. परंतु आपण जेव्हा प्रामुख्याने गिरणी कामगारांचा विचार करतो तेव्हा तो विषय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्या बाजूला सुध्दा कामगार पुढारी बसलेले आहेत. व्ही.आर.एस. देताना रक्कम किती असावी, कमी असावी की जास्त असावी याची चर्चा होऊ शकते परंतु एकदा व्ही.आर.एस. दिल्यानंतर ती जबाबदारी कामगार संघटनेकडे राहात नाही तसेच मिलकडे किंवा सरकारकडे राहात नाही. स्थूल मानाने हे जे काम आहे त्या कामाच्या बाबतीत सरकारने आपली जबाबदारी झटकलेली नाही. यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळे निर्णय घेतलेले आहेत. त्यांच्या घराचा प्रश्न असेल, त्यांच्या नोकरीच्या संदर्भातील प्रश्न असेल, त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रश्न असेल त्याबाबत आपण विचार केलेला आहे. मध्ये एक प्रकरण निर्माण झाले की, म्युझियमची काय गरज आहे ? एवढ्या मोठ्या जमिनीत म्युझियम कोणासाठी करावयाचे ? म्युझियमची कल्यना आमची नाही. या सर्व गिरण्या ज्या ठिकाणी उभ्या आहेत त्या ठिकाणी चिमण्या आहेत आणि ते हेरिटेजमध्ये आहे म्हणून त्यासंदर्भात काही लोक कोर्टात गेले की, हे असेच जतन केले पाहिजे. सगळ्याच मिल्स जतन करावयाच्या म्हटल्या तर कोणत्याच मिलमध्ये काहीही होऊ शकणार नाही. त्यामध्ये असा एक विचार करण्यात आला की, नव्या पिढीला तसेच जे लोक मुंबई बघण्यासाठी येतात त्यांना किमान मुंबईमध्ये अशा प्रकारच्या गिरण्या, टेक्स्टाईल मिल्स चालावयाच्या हे कळण्यासाठी अशी एखादी गिरणी म्युझियम म्हणून जतन करता येईल आणि त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी ठेवता येतील. अशा प्रकारे त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केलेला आहे. अशा पद्धतीने किमान एखादी मिल जतन करून ठेवली आणि त्या ठिकाणी व्यवस्थित प्लॅनिंग केले तर येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना अशा पद्धतीची गिरणी या शहरामध्ये होती, या शहरामध्ये कापड

RDB/ MMP/ KGS/

श्री. विलासराव देशमुख

उद्योग चालावयाचा हे भावी पिढीला कळावे म्हणून हेरिटेजमधून काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केलेला आहे.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की, त्यांना वैद्यकीय मदत मिळाली पाहिजे, त्यांना निर्वाहभत्ता मिळाला पाहिजे. सन्माननीय सदस्यांनी बीपीएलच्या यादीबाबत सांगितले. कदाचित त्या यादीमध्ये सर्वांना घेणे शक्य होणार नाही परंतु आमचा प्रयत्न आहे की, घराच्या संदर्भात जेवढे शक्य आहे तेवढी जास्तीत जास्त घरे बांधून त्यांना अकोमोडेट करु. इतर ठिकाणी ज्या यु.एल.सी.च्या अतिरिक्त जमिनी मुंबई शहरामध्ये उपलब्ध झालेल्या आहेत त्या ठिकाणी सुध्दा घरे बांधून गिरणी कामगारांना त्या ठिकाणी प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार विचार करील. कारण शेवटी ते मुंबई बेटाच्या बाहेर जाऊ नये ही तुमची आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. त्यांना त्या ठिकाणी अकोमोडेट करता येईल. यु.एल.सी.च्या ज्या जमिनी मुंबईमध्ये मिळालेल्या आहेत त्या ठिकाणी घरे बांधता आली तर निश्चितपणे त्याचा विचार करु. या ठिकाणी गिरण्याच्या ज्या चाळी आहेत त्या ठिकाणी ठराविक एफ.एस.आय. देऊन घरे बांधण्याच्या संदर्भात सूचना करण्यात आली. ती सूचना तपासून घेण्यात येईल. त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी जर 4 एफ.एस.आय. दिला तर किमान त्या चाळीमध्ये सुध्दा आणखी जादा घरे उपलब्ध होऊ शकतील अशी एक सूचना एकाने माझ्यासमोर मांडलेली आहे. त्या मिलमध्ये जेवढे लोक काम करीत होते त्यातील समजा चाळीत राहणारे 200 लोक असतील आणि आणखी जादा 200 घरे निर्माण झाली तर त्या ठिकाणी प्राधान्याने त्या मिलमध्ये काम करणाऱ्याला अकोमोडेट करता येईल. हाही एक पर्याय आहे. आमचा हेतू गिरणी कामगारांना मदत करण्याचा आहे. या पर्यायांचा अभ्यास करीत आहोत. गिरणी कामगारांसाठी चाळीच्या पुनर्निमितीसाठी 4 एफ.एस.आय. द्यावा लागता तर तो देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, हे मी सदनाला सांगू इच्छितो. या ठिकाणी असाही विषय मांडण्यात आला की, श्री. पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दुरुस्ती करून या जमिनी विकण्याच्या संदर्भात परवानगी दिली तसेच श्री. राजीव गांधी यांनी परवानगी दिली असा शोध कालच्या चर्चेमध्ये या सदनामध्ये लावलेला आहे. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, खरे म्हणजे हे बोलण्याची गरज नाही.

यानंतर श्री. खंदारे

श्री.विलासराव देशमुख.....

कारण कामगार हा विषय आपण सर्वांनी राजकारणाच्या वर ठेवला पाहिजे. त्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत अशी दोन्ही बाजूची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे आरोप व प्रत्यारोप करून हा प्रश्न सुटणार नाही. ठीक आहे, आमचे काही निर्णय चुकीचे होते. परंतु 5 वर्षे विरोधी पक्षाला सुध्दा सत्तेमध्ये बसण्याची संधी मिळाली होती. कामगारांसंबंधी आज विविध प्रश्न मांडणा-यांनी त्या 5 वर्षांमध्ये कोणते प्रश्न सोडविले ? त्याबदल मला राजकीय भाषण करावयाचे नाही. पण जेव्हा अशा व्यक्तीचे नाव घेऊन सदनामध्ये चर्चा होते त्यावेळी नाईलाजास्तव बोलावे लागते. 1995-99 या कालावधीत मराठी माणसांचे आणि मराठी माणसांसाठीच निर्माण झालेले राज्य होते. त्या काळात कोणत्या योजना राबविल्या होत्या, किती मिल मालकांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या, किती कामगारांसाठी घरे बांधली, त्या काळात किती लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला ? अशा पध्दतीची चर्चा या सदनामध्ये होऊ नये. कारण राजकीय भाषण आपल्यालाच करता येते आणि आम्हाला करता येत नाही अशातील भाग नाही. त्यावेळी भूखंड विक्रीसाठी काढले असे बोलले गेले आहे. त्या कामगारांच्या पगाराची व्यवस्था कशी करावयाची आणि कामगारांची बाकीची व्यवस्था करण्यासाठी, मिल सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने प्रयत्न केले. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली प्रयत्न केले. परंतु एखाद्याने कारखाना सुरु ठेवलाच पाहिजे असा आपल्याकडे कायदा नाही. अशा डायरेक्शन्स सरकारला देता येत नाहीत. खाजगी धंदा करणे परवडत नसल्यामुळे अनेक कारखाने बंद पडतात. कारखाना बंद करण्यासाठी परवानगी लागत नाही. ती परवानगी सरकारने दिली नव्हती. क्लोजरला परवानगी लागते. पण सरकारने क्लोजरला कधीही परवानगी दिली नाही. परवानगी केव्हा दिली जाते, जेव्हा त्या कारखान्याने कामगारांची सर्व देणी दिलेली असेल तेव्हा परवानगी दिली जाते. पण तुम्ही कारखाना चालविलाच पाहिजे असा कायदा ना राज्याचा आहे ना केंद्र सरकारचा आहे. जेव्हा कारखाना बंद पडतो तेव्हा कामगार बेकार होतो, कामगार रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही. त्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी 1991 मध्ये एक फार्मूला काढला होता. या फार्मूल्याला 10 वर्षे कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही. जेव्हा प्रतिसाद मिळत नव्हता तेव्हा परिवर्तन

2....

श्री.विलासराव देशमुख.....

करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. एक परिवर्तन केल्यामुळे किमान त्याच्यातून कामगारांची देणी देण्यात सरकारला यश आले आहे. त्याच्या पुढील पाऊल असे होते की, त्यांना घर उपलब्ध करून दिले पाहिजे, नोकरीसाठी मदत केली पाहिजे, कामगारांच्या मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मदत केली पाहिजे. अशा अनेक बाबींसंबंधी राज्य सरकारने पावले उचललेली आहेत. त्याशिवाय असेही म्हटले आहे की, जो व्यवसाय उपलब्ध होईल त्यातील 75 टक्के जागा कामगारांच्या मुलांसाठी उपलब्ध करून ठेवल्या पाहिजेत, अशाप्रकारचे आदेश शासनाच्यावतीने मालकांना दिलेले आहेत. एवढया साठीच असे म्हटले आहे की, बंद पडलेल्या गिरणीच्या जागेवर जो व्यवसाय सुरु होईल त्याठिकाणी त्यांना नोकरी मिळण्यासाठी प्रशिक्षण दिले पाहिजे. या सर्व बाबींचे समन्वय कोण करणार, त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहणारी यंत्रणा अस्तित्वात पाहिजे. सरकारचे धोरण नेहमीच चांगले असते. परंतु प्रत्यक्षात त्या धोरणाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी यंत्रणेची गरज आहे. यापूर्वी कामगारांची देणी देण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली आहे. पुढील काम अधिक महत्वाचे आहे. हे काम योग्य पद्धतीने होते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असण्याची गरज आहे, हे मी मानतो. सध्या जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेला हे अधिकार देता येतात काय आणि ते देता येत नसेल तर स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करता येते किंवा नाही ते पाहू आणि ती तातडीने निर्माण करू. मग कोणालाही आपले म्हणणे मांडावयाचे असेल तर ते त्या यंत्रणेसमोर मांडावे आणि त्यांच्यामार्फत प्रश्न सोडवून घ्यावेत. मग घरांचा प्रश्न असेल, जागेचा प्रश्न असेल ते त्यांच्यासमोर मांडावेत. आज अशी परिस्थिती आहे की त्यांना कोठे जाता येत नाही.

नंतर श्री.शिगम

(श्री. विलासराव देशमुख)

कारण एकदा व्हीआरएस दिली की आमची जबाबदारी संपली असे मालक समजतात. काही संघटना ह्या आपापल्यापरीने प्रयत्नशील असतात. परंतु शेवटी त्यांच्याही मर्यादा असतात. म्हणून याबाबतीत एक यंत्रणा निर्माण करु की जी यंत्रणा हे सर्व पाहील. याबाबतीत सर्वे करावा लागेल. मुले किती आहेत, त्यांचे शिक्षण किती झालेले आहे, कोणत्या प्रकारचे ट्रेनिंग त्यांना देऊ शकतो हे सर्व काम यंत्रणा निर्माण केल्या शिवाय होणार नाही. कोणी एक व्यक्ती हे काम करु शकणार नाही. म्हणून एक यंत्रणा आम्ही निर्माण करु. ती यंत्रणा या उद्धवरत झालेल्या गिरणी कामगारांच्या घरामध्ये जाऊन घरामध्ये कोण कोण आहे, किती शिक्षण घेतलेले आहे याबाबतची माहिती घेईल. तसेच त्याठिकाणी कोणते उद्योग आहेत वा कोणते उद्योग उभे राहणार आहे याची देखील नोंद घेतली जाईल. एक गोष्ट मात्र नक्की की गिरणी कामगाराच्या घरातील एखाद्या व्यक्तीला तरी नोकरी मिळाली पाहिजे या दृष्टीने राज्य सरकार कठिबध्द आहे. जेवढे म्हणून प्रयत्न आम्हाला करता येतील तेवढे ते आम्ही निश्चितपणे करणार आहोत आणि त्याबद्दल कुणीही शंका घेण्याचे कारण नाही. सभापती महोदय, मी एवढेच सांगेन की, कोणतीही गिरणी बंद पडावी हा सरकारचा हेतू नाही. त्यावेळी एक अशी परिस्थिती निर्माण झाली, प्रचंड आंदोलने झाली, अवास्तव मागण्या मांडल्या गेल्या आणि त्याचा फटका गिरणी कामगाराला बसला. त्यावेळी अनेक बैठका झाल्याचे मला आठवते. सभापती महोदय, वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपण देखील होता. त्याकाळी केन्द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांबरोबरही बैठका झाल्या. काही बैठकांना हजर राहाण्याची संधी मला देखील मिळाली. हे सर्व प्रयत्न झाल्यानंतर सुधा त्यामध्ये फारसे यश आले नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना कसे उभे करता येईल, त्यांना कशी मदत करता येईल हे आपण पाहिले पाहिजे. मदत देण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारचे दुमत नाही. परंतु मदत देत असताना ज्या काही मर्यादा आहेत त्या आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. कारण फार अपेक्षा उंचावून ठेवणे हे चुकीचे आहे. पण आपण जेवढे करु शकतो ते केले पाहिजे. 400 चौ.फुटाचे घर नको , 700 चौ.फुटाचे द्या, त्यांना रोजगार भत्ता द्या अशा प्रकारच्या फार अपेक्षा आपण उंचवायला लागलो तर तेही इष्ट ठरणार नाही. एखाद्या खाजगी फॅक्टरी मधून एखाद्या कर्मचा-याला जेव्हा व्हीआरएस दिली जाते त्यामध्ये त्याला फारसे संरक्षण आज तरी

..2..

(श्री. विलासराव देशमुख...)

मिळालेले नाही. परंतु या गिरणी कामगारांच्या बाबतीत आपण जाणीवपूर्वक वेगळी कमिटमेंट केलेली आहे. गिरणी कामगारांबद्दल तुम्हाला आम्हाला आणि सर्वांनाच जिव्हाळा आहे. म्हणून तुम्ही आम्ही एकत्र बसून याबाबतीत काही नियोजन केले तर या गिरणी कामगारांचे प्रश्न सुटणार आहेत. त्यांच्या अपेक्षा फार वाढविणे योग्य ठरणार नाही. कायद्याच्या आणि नियमांच्या मर्यादेमध्ये राहून आपण काय करू शकतो याबाबतचा पर्याय विरोधी पक्षाने देखील सुचवावा. कारण ही मुंबई माझ यापेक्षा तुम्हाला जास्त माहीत आहे. मी मुंबई बाहेरचा आहे, पण परप्रांतीय नाही. तुम्ही या मुंबईतील आहात. म्हणून तुम्ही मुंबईकरांनी एखादा पर्याय सुचवा. आपण दोघांनी मिळून मार्ग काढूया. या प्रश्नी आपण दोघांनीही प्रतिष्ठा आणि पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवू या आणि या गिरणी कामगाराला कशी मदत करता येईल हे पाहू या, तसेच ही मदत करताना त्या बाबतीतील मर्यादा दोघांनी लक्षात घेऊ या एवढेच या निमित्ताने मला सांगावयाचे आहे. धन्यवाद.

...3..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

K-3

MSS/ KGS/ MMP/

पूर्वी श्री. खंदारे

10:50

श्री. दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री.विलासराव देखमुख यांनी गिरणी कामगारांच्या संदर्भात या ठिकाणी भावना व्यक्त केल्या. या भावना व्यक्त करताना गिरणी कामगारांच्या बदल त्यांच्या मनामध्ये आकस नसला, गैरसमज असे मी म्हणणार नाही, पण योग्य समजुतीतून त्यांनी विचार मांडलेले नाहीत असे मला खेदाने म्हणावेसे वाटते. व्ही.आर.एस. देणे आणि गिरणी कामगाराला गिरणीला टाळे लावून बाहेर काढणे यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. जमिनीचे भाव प्रचंड वाढल्यामुळे जमिनी विकण्यासाठी गिरण्या बंद करण्यात आल्या. यासाठी निमित्त मात्र संपाचे झाले. प्रत्यक्षात या धनदांडग्यांना गिरण्यांच्या जमिनी विकून त्याचा लाभ त्यांना देण्यासाठी गिरण्या बंद करून गिरणी कामगाराला बाहेर काढण्यात आलेले असल्यामुळे हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. पक्षाभिनिवेश बाजूला ठेवण्याच्या भूमिकेतून माननीय मुख्यमंत्री या प्रश्नाकडे पहात आहेत. या गिरणी कामगाराला व्हीआरएसशी जुळवणे हे अत्यंत अयोग्य आहे असे माझे ठाम मत आहे.

...नंतर श्री. गिते...

श्री.दिवाकर रावते...

यासंदर्भात गिरणी कामगार उद्धवस्त झाले आहेत, त्यांना सरकार म्हणून आपण सांभाळले पाहिजे. या उद्धवस्त कामगारांसाठी जेवढे काही करता येईल तेवढे करणे भाग आहे अशी भूमिका आपल्या भाषणातून मला दिसून आली नाही. आपण यु.एल.सी.ची जमीन देण्याचे मान्य केले आहे त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो.

गिरणी कामगारांना 1 लाख, 2 लाख एवढीच रक्कम मिळालेली आहे. त्या गिरणी कामगारांनी 5 ते 10 लाख रुपयांची घरे कशी घ्यावयाची हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. तो प्रश्न कसा सोडवावयाचा या दृष्टीने शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काल सुपीम कोर्टने 2000 सालार्प्यतच्या झोपडया रेग्युलार्इज करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. ज्यांनी महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी रक्त सांडले, त्या लोकांना सन्माननीत करणे हा त्यातील एक भाग आहे आणि त्या भावनेतून या विषयाकडे पाहिले पाहिजे. मुंबई शहरात परप्रांतीय आले आणि त्यांनी येथे झोपडया बांधल्या, त्या लोकांना मोफत सदनिका मिळत आहेत. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या बाजूला असलेल्या झोपडपट्टीतील लोकांना एम.एम.आर.डी.ए.कडून मोफत सदनिका दिल्या गेल्या. बेकायदेशीरपणे मुंबईत येऊन ज्यांनी बस्तान बसविले त्यांचे भले झाले आहे. परंतु ज्यांनी मुंबई घडविली त्यांच्याकडे बघताना मात्र हा दृष्टीकोन परवडणारा नाही अशी भूमिका घेतली जाते. अशी भूमिका घेणे हे बरोबर नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अधिका-यांनी ब्रिफिंग व्यवस्थित केलेले दिसत नाही. मी या ठिकाणी गिरणी कामगारांना दिल्या जाणा-या सदनिकांच्या मेंटनन्सचा विषय काढला. गिरणी कामगारांना घरे दिल्यानंतर त्यांच्या मेंटनन्सचे पैसे देखील शासनाने द्यावेत असे मी म्हटले नाही. गिरण्यांच्या जागेवर 35 मजल्याचे टॉवर्स उभे राहणार आहेत आणि त्या इमरतीमधील 35 मजल्यावर त्या गिरणी कामगारास 225 चौ.फुटाची सदनिका दिली तर त्याला मेंटनन्स भरणे कसे शक्य होईल. समजा त्या टॉवरमधील लिफ्ट बंद पडली आणि तेथील कामगार एकत्र आले नाही तर तो गिरणी कामगार 35 व्या मजल्यापर्यंत चालत जाईल काय ? गिरणी कामगारांना टॉवरमध्ये सदनिका द्यावयाच्या नाहीत काय असे अविर्भावात या ठिकाणी आपण सांगितले. गिरणी कामगारांसाठी पाच मजल्याच्या इमारती बांधा आणि त्या ठिकाणी त्यांना घरे उपलब्ध करून द्या. लहान इमारत राहिली तर मेंटनन्स देखील अवाक्यात राहील. तेवढा खर्च तो गिरणी कामगार सहन करु शकतो. एवढाच मेंटनन्सचा मुद्दा उपिस्थित करण्यामागचा माझा हेतू

2...

श्री. दिवाकर रावते...

होता. टॉवरमधील 30 व्या मजल्यावर डेनेजचे काम निघाले तर त्यासाठी गिरणी कामगार परात बांधण्याचा खर्च कसा करु शकतो. गिरणी कामगारांना पडवडतील अशीच घरे बांधून देण्यात यावीत अशी माझी मागणी आहे. कामगारांच्या घरांच्या संदर्भामध्ये अपेक्षित देकार नाही. त्यांना यूएलसीची जमीन उपलब्ध करून देणार आहात. गिरण्याच्या प्रिमायसेसमध्ये जुन्या इमारती राहिल्या आहेत, त्या ठिकाणी 4 चा एफ.एस.आय. देऊन तेथील जास्तीत जास्त कामगारांना ॲकोमोटेड करता येईल अशा प्रकारचा चांगला विचार या ठिकाणी मांडला. माननीय मुख्यमंत्री साहेब, गिरणी कामगारांच्या बाबतीत आपण निगेटिव नाहीत, परंतु असावे तेवढे पॉझिटिव देखील नाहीत अशी आपण भूमिका घेतलेली दिसते. मी आपणास अतिशय तळमळीने सांगतो की, आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात, मराठी मुलखावे मुख्यमंत्री आहात. तुमच्यासारख्या मराठी राज्यकर्त्याकडून गिरणी कामगारांची मोठी अपेक्षा आहे. या गिरणी कामगारांसाठी चांगली भूमिका शासनाने घ्यावी अशी मी प्रामाणिकपणे इच्छा व्यक्त करतो.

सभापती महोदय, गिरणी कामगारांची कायदेशीर देणी हा एक विषय आहे. 1000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी या ठिकाणी केली. मुंबईतील गिरण्या 1984 पासून बंद झालेल्या आहेत. गिरणी कामगाराला 58 वर्ष पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना पेन्शन मिळू शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये अशा कामगारांना 1000 रुपये देण्याची व्यवस्था केली आहे, त्याच धर्तीवर या ठिकाणच्या गिरणी कामगाराला देखील दरमहा 1000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी आमची भूमिका आहे. त्या कामगारांना पोसणे अशी मुळीच भूमिका नाही. 1984 सालापासून गिरण्या बंद झाल्या आहेत. गिरणी कामगारांची दुसरी पिढी संपत आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सरकारकडून अशा कामगारांसाठी आर्थिक मदत देण्याची भूमिका घेतली जाते, तर तशी भूमिका या सरकारने घेतली पाहिजे. या भावनेतून तो विषय मांडला आहे. गिरणी कामगारांचा नोक-यांचा विषय आहे. गिरणी कामगार आणि त्यांची मुळे अनस्किल्ड आहेत, त्यांना नोक-या दिल्या पाहिजेत. यासंदर्भात समिती निर्माण करीत आहात त्याबद्दल सरकारला धन्यवाद देतो. परंतु यासंदर्भात को-आर्डीनेशन कोण करणार ? ही समिती 15 दिवसात निर्माण करावी. त्यात नंतर सुधारणा करता येईल. 15 दिवसात समिती निर्माण करा आणि तो विषय काही प्रमाणात मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करा. ती भूमिका चांगली आहे, त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी

3...

श्री. दिवाकर रावते...

अशी माझी विनंती आहे. या ठिकाणी व्ही.आर.एस.इत्यादी बाबतची माहिती दिली गेली. श्री.बजाज यांनी कारखाना बंद केला. श्री. बजाज यांनी तो कारखाना आपल्या इच्छेने बंद केला. त्यांनी सांगितले की, व्ही.आर.एस. घेणार नाहीत त्यांना ते नोकरीत असेपर्यंत पगार देईन. परंतु त्या कारखान्यात मध्यस्थी आदरणीय श्री. शरद पवार यांनी केली. एखादा विषय असला तर असेही होऊ शकते. गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या मुलांना नोक-या उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत आपण यंत्रणा उभी करीत आहात. आज खरोखरच जाहीर करा की, आम्ही ही यंत्रणा 15 दिवसात उभी करतो. अनस्कील्डची काम त्या कामगारांना करता येणार नाही काय ? त्या लोकांना काच झाडण्याचे काम करता येणार नाही काय ? गिरणी कामगार अनस्कील्ड आहेत, त्यांना अनस्कील्डच्या नोक-या ताबडतोबीने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. कोणत्याही परिस्थितीत या कामगारांना नोक-या मिळाल्या पाहिजेत हा सगळा एक भूमिकेचा भाग आहे...

यानंतर श्री. कानडे...

श्री. दिवाकर रावते.

बीपीएलच्या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही. आम्ही सांगितले होते गिरणी कामगार म्हणून बीपीएल हा विषय हाताळता येतो काय ते शासनाने पहावे. पूर्ण बीपीएलची यंत्रणा करता येणार नाही हे मान्य आहे. परंतु प्राप्त परिस्थितीमध्ये सरकारने याबाबतीत काही करता येईल काय हे पाहिले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. एक गोष्ट आपण मांडली की, आमच्या शासनाने 5 वर्षात काय केले हा विषय आता नको. आम्ही असे म्हटले की आघाडी शासनाने 9 वर्षात काय केले ते जाहीर करा. आपण ती चर्चाच करीत आहोत. आम्ही काय केले आणि तुम्ही काय केले अशी उणीदुणी काढण्यापेक्षा कामगारांसाठी काहीतरी करु या. आपण क्लोजरचा विषय सांगताना असे म्हटले की देणी दिल्याशिवाय क्लोजर करता येत नाही आणि चालू ठेवा असे सांगता येत नाही. जमीन सरकारची आहे ती काढून घ्या. लीज रद्द करा. डायव्हर्सिफिकेशन होत असेल तर लीज रद्द करा. क्लोजर विषय नाही. मॉल बांधण्याकरिता जमीन वापरत असतील तर टेक्सटाईलकरिता दिलेले आहे ते लीज रद्द करा. क्लोजर देता येत नाही आणि त्यांनी गिरणी चालू ठेवा असे सांगता येत नाही. 5-6 गिरण्यांची मी यादी दिली होती. त्यांचे लीज संपलेले आहे त्यांची जमीन ताब्यात घ्या. चारही बाजूंनी सदिच्छा आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे होऊ शकते. याप्रश्नासंबंधी निळूभाऊंनी जे लिहिले होते ते मी वाचून दाखविले. टीकेचा विषय नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री. शक्रराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली आणि काही गिरणी मालकांना जमीन विकू दिली नाही. आपण त्यांचे राजकीय शिष्य आहात अशी आपली महाराष्ट्रात ओळख आहे. चव्हाण साहेबांचा आपल्यावर पगडा आहे. तशा प्रकारचा निर्धार आपल्याकडून व्हावा अशी अपेक्षा आहे. घरांचा विचार केला तर इ गोपडपट्टीधारकांना घरे फुकट मिळतात मग ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबईत रक्त सांडून ती उभी केली, संयुक्त महाराष्ट्र घडविला त्यासाठी 32 कामगार महाराष्ट्र मिळविताना धारातिर्थी पडले त्यादृष्टीकोनातून त्यांच्याकडे पहावे. त्यांच्याकडे सुध्दा एका भावनेने पहावे अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. घरे मोफत मिळणार नाहीत, बीपीएल कार्ड मिळणार नाही, नोक्या मिळणार नाहीत, त्यांच्या ट्रेनिंग बाबत करु बघू असे सांगितले. नक्की आश्वासन नाही. टर्म्स आणि रेफरन्सप्रमाणे 33 हजार लोकांना ट्रेनिंग द्यावयाचे आहे. एवढे मोठे काम आहे. कधी चालू होणार ? 2001 साली याबाबत घोषणा केली होती. अधिकांच्यांच्या माध्यमातून होण्यापेक्षा अमुक इतक्या महिन्यात ते झाले

.....2

श्री. दिवाकर रावते..

पाहिजे असे सांगा तरच हा विषय मार्गी लागेल. कामगारांची कायदेशीर देणी 18-19 कोटी रुपयांची राहिली आहेत. ती देण्याच्या बाबतीत समर्थपणे पाठपुरावा करावा. 58 वर्षे झाल्याशिवाय पेन्शन मिळत नाही त्याबाबतीत पहावे. कामगारांना विमा योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे लाभ आहेत ते मिळविण्यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली पाहिजेत. यासंदर्भात त्यांना किमान निवृत्ती नंतर जो लाभ मिळतो तो न देता त्यांना जबरदस्तीने घरी पाठविले आहे त्यांना लाभ कसा मिळेल आणि कायद्यात त्यादृष्टीने बदल करावा लागला तरी तो केला पाहिजे. आपल्या उत्तरातून 100 टक्के अमुक होईलच अशी जी आपल्या उत्तरातून आशा होती ती आशा सफल झाली नाही. आपल्या उत्तरातून गिरणी कामगारांच्या विषयावर ही चर्चा अखेरची ठरावी अशा दृष्टीने सरकारची भूमिका असेल असे वाटत होते. ती ठरवू इच्छित नाही अशी सरकारची भूमिका दिसते. परंतु त्याबाबतीत खेद होतो. पुन्हा एकदा शासनाने विचार करून याबाबतीत ठोस भूमिका घ्यावी. गिरणी कामगारांची तुलना इतर कारखान्यातील कामगारांशी कृपा करून करू नये अशी आर्जवाची विनंती करतो.

श्री. विलासराव देशमुख : सभापती महोदय, श्री. रावते साहेबांचा गैरसमज झालेला दिसतो. गिरणी कामगारांसाठी वेगळी यंत्रणा उभी करीत आहोत. गिरणी कामगारांची तुलना इतर कारखान्यातील कामगारांशी केलेली नाही. व्हीआरएस आहेच.

नंतर श्री. भोगले

श्री.विलासराव देशमुख.....

व्हीआरएस दोघांनाही लागू केली आहे. परंतु इंजिनिअरिंग कंपन्या आहेत, फॅक्टर्न्या आहेत त्या आणि कापड गिरण्या यामध्ये फरक केला असून एवढ्यावरच थांबलेलो नाही. कापड गिरण्यांसाठी वेगळी स्पेशल ट्रिटमेंट दिलेली आहे. डीसी रूल्सच्या कलम 58 मध्ये केलेली तरतूद गिरणी कामगारांसाठी लागू आहे, इतरांना ती लागू नाही. इंजिनिअरिंग कंपनी बंद झाली तर त्या कंपनीच्या जागेवर 1/3, 1/3, 1/3 ही अट लागू नाही. कापड गिरणीच्या जागेसाठी लागू आहे. कामगारांच्या मुलांना नोकरी देण्याच्या संदर्भात वृत्तपत्रात जाहिराती दिल्या आहेत. ट्रेनिंग कधी सुरु करणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. माध्यमिक शाळेचा प्लॉट आहे, त्याचे रिझर्व्हेशन बदलले. 'व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट' असा बदल केला आहे. इफेकिटव्ह स्टेप्स सरकारने धेतल्या आहत. फक्त आश्वासन देऊन शांत बसलेलो नाही. आरक्षण बदलण्याचे काम केले. मिटकॉनकडून अहवाल घेण्यात आला आहे. कशाप्रकारचे व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर असावे हे त्यांनी शासनाला सांगितले आहे. त्याची सुरुवात लवकरच करू.

श्री.अरविंद सावंत : सभापती महोदय, दुःख एकाच गोष्टीचे आहे ते म्हणजे मागील वेळेला 2006 मध्ये माननीय मुख्यमंत्रांनी केलेले भाषण वाचले तर आपल्या लक्षात येईल, हेच मुद्दे त्यावेळच्या भाषणात मांडले होते. आज शासनाने कबूल केले की, स्वतंत्र यंत्रणा त्यावेळी व्हायला हवी होती. ती यंत्रणा निर्माण झाली असती तर आज निदान एवढे सांगता आले असते की, 5 हजार गिरणी कामगारांच्या मुलांना नोकर्या देण्यात आल्या. कुशल आणि अकुशलचा मुद्दा मांडला होता. माननीय उच्च न्यायालयाने सरकारला निदेश दिले होते. परंतु आज शासनाकडे यादी तयार नाही. ट्रेनिंग सेंटर सुरु करतो असे 2006 मध्ये सांगितले होते. आजही ते सुरु झालेले नाही. अकुशल आहेत, ज्यांनी 10 वी पर्यंत शिक्षण घेतले अशा लोकांना सहज नोकरी देता येणे शक्य आहे. जे कोणते उद्योग उभे राहतील त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कामगारांची आवश्यकता आहे याची माहिती घेतली पाहिजे. मिटकॉन काय करते याची आम्हाला माहिती आहे. ते उद्या प्रशिक्षण देतील. ते प्रशिक्षण तिथे येणाऱ्या उद्योगांना पूरक नसेल तर उपयोग होणार नाही. नक्की कोणता उद्योग उभा करणार आहेत त्याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. अन्यथा वेगळे प्रशिक्षण देण्यात आले आणि तिथे येणाऱ्या उद्योगाला सर्विस सेक्टरमधील व्यक्ती हव्या असतील तर उपयोग होणार नाही. एनटीसीच्या गिरण्यांचे जेव्हा राष्ट्रीयीकरण झाले

.2..

श्री.अरविंद सावंत.....

त्यानंतरची कामगारांची देणे दिली गेली. पण त्यापूर्वीच्या काळातील देणी शिल्लक राहिली आहेत. यासाठी 'कमिशनर ऑफ पेमेंट्स' ही यंत्रणा निर्माण केली होती. त्यांच्याकडे हा मुद्दा पेंडिंग आहे. 25 गिरण्यातील कामगारांची त्यापूर्वीची देणी आजही दिली गेली नाहीत. ती देण्यासाठी प्रयत्न करावा एवढी विनंती करतो. एका गोष्टीचे मनापासून स्वागत करतो. नोकच्यांच्या संदर्भात 75 टक्के आरक्षण गिरणी कामगारांच्या मुलांना ठेवणार आहात ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. कदाचित हे आरक्षण अधिकाअधिक वाढवावे. 75 टक्क्यावरच थांबू नये. युएलसी जागेची घोषणा स्वागतार्ह आहे. परंतु अंमलबजावणी होत नाही यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे. परंतु शासनाने निदान एक महिन्याच्या आत यादी जाहीर करावी म्हणजे कोणाची नावे प्रतिक्षा यादीत आहेत हे कळून येईल. एनटीसी गिरण्यातील कामगारांची देणी 25 वर्षे होऊनही दिली गेली नाहीत ती देण्यासाठी काय करणार आहात?

(नंतर श्री.खर्च.....

श्री. मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दोन-चार गोष्टी प्रामाणिकपणे कबूल केल्या त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. मी त्यांचे भाषण लक्ष्यपूर्वक ऐकत होतो. आपण विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम 58 च्या माध्यमातून बदल केला त्यानुसार बीएमसी आणि म्हाडाला जमीन मिळालीच नाही, मग हा बदल कशासाठी केला हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न म्हणजे हा बदल करण्यापूर्वी मिलची जी जागा होती, जो परिसर होता, समजा 1/3 जागा बीएमसीला, म्हाडाला 1/3 जागा असे ठरले परंतु यामुळे आपले नुकसान झाले कारण मिलमध्ये जे बांधकाम आहे ते तसेच ठेवले. उदा. कंपाऊंड वॉल आणि कन्स्ट्रक्टेड वॉलच्या मध्ये 100 चौरस फूट जागा असेल तर त्यातील 1/3-1/3 अशी विभागणी व्हावी असा बदल आपण केला पण तसे झाले नाही, त्याचे कारण काय? ज्या मिलची जागा शासनाच्या ताब्यात आली नाही असे आपण म्हणालात, मग त्यांचे जे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभे राहिले त्याला परवानगी कशी देण्यात आली? बिल्डिंग प्रपोझल विभागाने त्याला स्टे का दिला नाही, की आपण या ठिकाणी सेलेबल इमारत बांधू शकत नाही. परंतु तसेही झाले नाही. त्यांनी त्यांचा हिस्सा घेतला, तुमचा हिस्सा मात्र तुम्हाला दिलाच नाही, त्याचे पुढे काय करणार आहात? या गिरणी कामगारांच्या दुर्दवाला सुदैवात रुपांतर आपण करु शकणार नाहीत निदान त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना फायदा मिळेल यादृष्टीने गिरण्यांच्या जमिनीतून शासनाला 200 एकर जमीन मिळायला पाहिजे होती, अद्याप ती फक्त 18 एकर एवढीच जमीन मिळाली आहे. तसेच आपण ज्युपिटर आणि इतर तीन अशा चार मिल्सचा उल्लेख केला त्या गिरण्यांनी तर सरळ लिहून कळविले आहे की, "आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही" अशा प्रकारे मिल मालकांची मुजोरी शासन का सहन करीत आहे? त्यांना कायद्याचा हिसका का दाखवत नाही? मिल कामगारांच्या मुलांना तंत्रशिक्षण व वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून या मुलांसाठी किमान एक दोन जागा ठेवण्याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच स्वदेशी मिलच्या ठिकाणी एक शाळा चालू आहे, त्या शाळेने आठवी ते दहावीच्या वर्गासाठी शासनाकडे अनेक वर्षांपासून परवानगी मागितली आहे, परंतु अद्यापही त्या शाळेला अशी परवानगी मिळाली नाही, त्याचे कारण काय? तसेच मिल मालकाने प्रपोझल पाठविले की, मिलची अतिरिक्त जागा आहे तेथील जागा आम्ही न देता त्याबदल्यात उपनगरात अथवा उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी जागा देऊ, असे प्रपोझल्स शासन धुडकावून का लावत नाहीत? ज्या ठिकाणी मिल आहे त्याच ठिकाणची 1/3 जागा आम्हाला पाहिजे, असे शासन का म्हणत नाही?

यानंतर श्री. सख्यद जामा यांचे भाषण.....

श्री सच्चद जामा : सभापति महोदय, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी दी है। महाराष्ट्र में जो भी सरकार आई, सभी सरकारों ने कामगारों के हित में ही कानून बनाए हैं। बीआयआर एक्ट बनाया गया। रोजगार हमी कायदा बनाया गया। इस प्रकार के अनेक कायदे कामगारों के लिए बनाए गए। मुंबई में कपड़ा मिलें बंद हो जाने के कारण अनेक कामगार बेकार हुए। आय. डी. एक्ट के तहत क्लोजर के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। कई कंपनियों को सरकार ने क्लोजर के लिए अनुमति नहीं दी। 1991 के बाद से ही उद्योगों के मालिकों ने राज्य सरकार एवम् केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वे आय.डी.एक्ट में संशोधन करें ताकि फेक्टरी बंद करने के लिए मालिकों को अनुमति मिल सके। लेकिन सरकार ने फेक्टरी मालिकों की विनती मान्य नहीं की। ऐसी स्थिति में मालिकों ने व्हीआरएस का विकल्प रखा। व्हीआरएस के तहत फिर बारगेनिंग भी हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कामगारों के हित में ही निर्णय लिया है और पॉलिसी बनाई है। लेकिन इंजीनियरिंग वर्कर्स और मीडियम एवम् स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के कामगारों को सुविधा नहीं मिल पायी है। उदाहरण के लिए कामगार बीमा योजना का फायदा नहीं मिला है। राज्य कामगार बीमा योजना के पास फंड है, बहुत सारी योजनाएं हैं। हिन्दुस्तान में किसी भी जगह इतनी बड़ी संख्या में मजदूर बेकार नहीं हुए हैं जितनी बड़ी संख्या में मुंबई में हुए हैं। इसलिए मेरी सरकार से यह विनती है कि राज्य कामगार बीमा योजना (कार्पोरेशन) से समन्वय करके कामगारों के लिए स्पेशल बीमा योजना बनाई जाए, जिसमें कामगारों का शेयर होगा, महाराष्ट्र सरकार का शेयर होगा और राज्य कामगार बीमा योजना(कार्पोरेशन) का शेयर होगा। सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करें।

यानंतर श्री जुनरे ..

श्री. विलासराव देशमुख : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी डी.सी. रुलमधील कलम 58 चा या ठिकाणी उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, यासंबंधीचा जो मूळ नियम आहे आहे त्यामध्ये असे होते की, फॅक्ट्री आज ज्या क्षेत्रात आहे ते स्ट्रक्चर व मिलची मोकळी जागा असे ते एकत्रितपणे मोजले जाईल परंतु ही जमीन फॅक्ट्री जेव्हा पाडली जाईल तेव्हा ती जमीन मोजली जाईल. जोपर्यंत ती व्हॅकेट लँड होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला ही जमीन मोजता येत नाही. व्हॅकेट लँडच्या 1/3, 1/3 अशी विभागणी केली जाईल. काही मिल मालकांनी लँड व्हॅकेट केलीच नाही. बॉर्डर तशीच ठेवून फॅक्ट्री बांधली अशा प्रकारे त्यांनी पळवाट काढली. सन 1991 ते 2000 या कालावधीत 58 च्या नियमात काही बदल झाला नाही, कोणाचा एक पैसाही मिळाला नाही. कामगार मोर्चे काढून थकले, आत्महत्या व्हायला लागल्या, त्यासंबंधीच्या बातम्या रोज वृत्तपत्रात यायला लागल्या. पैशाची व्यवस्था व्हावी म्हणून त्यासाठी एक कमिटी नेमण्यात आली. किमिटीने संघटनेबरोबर, मिल मालकाबरोबर चर्चा केली, त्यांचे प्रस्ताव आले या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली त्यानंतर बदल करण्यात आले व बदलानंतर असे ठरले की, जेथे तुमची अँकव्युअल....

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, हे सभागृह आहे. या सभागृहाची मंजूरी घेतांना हाईट मंजूर केली आहे परंतु या ठिकाणचा बिल्टअप एरिया आणि कार्पेट एरिया एवढाच राहणार आहे परंतु जेव्हा फ्लोअर टाकले जातात तेव्हा कार्पेट एरिया मान्य झालेला नाही त्यामुळे त्याला जी मान्यता दिलेली आहे म्हणून आपण म्हणतो की, त्यांनी आतून बांधले काय करणार, नाही परंतु आतून बांधकाम करतांना हाईटला जी मान्यता द्यावी लागते त्यासंदर्भात आजही रुलमध्ये तसेच आहे. एखादी इंडस्ट्रीज, एखादे गॅरेजची हाईट 14 फूट दुकानासाठी 12 फूट ठरली आहे परंतु सया ठिकाणचे काम मोजतांना बिल्टअप एरियाच मोजला जातो. परंतु त्यांनी त्या स्ट्रक्चरमध्ये फ्लोअर टाकून हाईटचा फायदा घेऊन आतून ज्या इमारती बांधल्या ते गैरच आहे. म्हणून ती जमीन अँकसेस झाली. त्यांची बिल्टअपची लँड मोजली तर ती अँकसेस लँड आहेच ती त्यांनी आपल्याकडून बनावटीने, गफलतीने काढून घेतलेली आहे हा महत्वाचा विषय आहे.

श्री. विलासराव देशमुख : सभापती महोदय, 58 च्या नियमाप्रमाणे बांधकाम करण्याला मान्यता देण्याचे काम मुंबई महानगरपालिकेने केलेले आहे. जे प्रचलित नियम होते त्यामध्ये

श्री. विलासराव देशमुख

फारशी काही सुधारणा झाली नाही. त्याला फारसा कोणी रिस्पॉन्स दिला नाही त्यामुळे त्यात बदल करणे अपरिहार्य होते म्हणून बदल करण्यात आले. यामध्ये नवा बदल असा झाला की, बिल्टअप एरिया जो असेल तो एरिया सोडून जी मोकळी जमीन आहे त्याच्यातून 1/3, 1/3 करण्यात आली. आपण सुरुवातीला अपेक्षा केली होती की, 200 हेक्टर जमीन मिळेल ती एंटायर जमीन लक्षात घेऊन त्या जमिनीची 1/3 जमीन असा तो विषय होता. नियमात बदल झाल्यानंतर त्याला हायकोर्टात चॅलेंज करण्यात आले, सुप्रीम कोर्टात चॅलेज झाले व नंतर सुप्रीम कोर्टने सांगितले की, राज्यसरकारचा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे या विषयावर आता चर्चा करणे योग्य होणार नाही. आता आपण फार पुढे गेलेलो आहोत. जेव्हा हे सगळे झाले तेव्हाच खरे म्हणजे ही चर्चा झाली असती तर ते अधिक उपयोगाचे झाले असते. आता नोटीफिकेशन झाले, ऑब्जेक्शन्स मागवले, कामगारांनी व मालकांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यामुळे आता मागे जाण्यात काही अर्थ नाही. ज्यांनी आपल्याला जमिनी दिल्या नाहीत अशा सर्वांचे आपण परवाने थांबविलेले आहेत. यासंदर्भात शासनाने सक्त सूचना दिलेल्या आहेत. यापुढे जाऊन बिल्डींग पूर्ण झाल्यानंतर कंप्लीशन सर्टीफिकेटच्या अगोदर नोक-यांच्या संदर्भात तुम्ही नेमके काय केलेले आहे हे सुधा आम्ही विचारू आणि त्यानंतरच आम्ही पुढचे काम करू. महानगरपालिका, सरकार असे मिळून....

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, कंप्लीशन हा विषय नको आहे. आयओडी दिली असेल तर सीसी देऊ नका आणि सीसी दिली असेल तर ताबडतोब स्टॉपवर्क ऑर्डर द्यावयास पाहिजे.

श्री. विलासराव देशमुख : प्रश्न असा आहे की, जोपर्यंत इमारत बांधणार नाही, जोपर्यंत कंपनी येणार नाही तोपर्यंत या ठिकाणी उद्योग कसे काय येऊ शकतील. मालकाने बांधकाम केले आणि आयटी किंवा इतर व्यवसाय करणारे लोक असतील तर ते उद्योग ही जागा घेऊन तेथे आपला उद्योग सुरु करतील.

यानंतर श्री. गायकवाड....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

Q1

VTG/ SBT/ KTG/

ग्रथम श्री.जुन्नरे

11.20

श्री.विलासराव देशमुख...

तेथे उद्योग येणार आहेत परंतु नक्की कोणते उद्योग येणार आहेत वा आले आहेत हे आपल्याला कळण्यापूर्वीच हे बांधकाम थांबविले तर काहीच होणार नाही. तेव्हा या संदर्भात प्रॅकटीकली विचार करावा लागेल. सुरुवातीला अमलगमेशनची परवानगी दिली होती. एखाद्या मिल मालकाची जमीन शहरामध्ये आहे आणि उपनगरामध्येसुध्दा आहे अशा वेळी अमलगमेशनची परवानगी दिली होती परंतु नंतर ते बंद करण्यात आले होते. गिरणी मालक शहरातील महागडी जमीन घेतील आणि दहिसर, बोरिवलीला जमीन देतील. तेव्हा हा प्रकार सुध्दा थांबविण्यात आला आहे. पूर्वीच्या नियमामध्ये ही तरतूद करण्यात आली होती. परंतु नंतर तो नियम रद्द करण्यात आला होता आणि या गिरणी मालकांची बांधकामेसुध्दा थांबविण्यात आली होती. तसेच या गिरणी मालकांना असेही सांगण्यात आले होते की, आम्हाला येथील जमीन देण्यात यावी. त्यानंतर काही गिरणी मालकांनी येथे जमीन दिली आहे. अजूनही पाच ठिकाणाचे अमलगमेशन थांबविण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांनी जमिनी दिल्या नाहीत अशा तीन मिळाली कामे थांबविण्यात आलेली आहेत. कामगारांना, म्हाडाला तसेच मुंबई महानगरपालिकेला या कापड गिरण्यांची जमीन दिली पाहिजे. आता जी काही जमीन उपलब्ध आहे त्याच्या 1/3 जमीन मिळाली पाहिजे. या संदर्भात आपल्या हातामध्ये जेवढे अधिकार आहेत त्याचा वापर करून पूर्णपणे सक्ती करण्यात आलेली आहे. जमीन ताब्यात मिळाल्याशिवाय शासन त्यांना पुढची परवानगी देणार नाही.

श्री.अरविंद सावंत : एन.टी.सी.च्या कामगारांना द्यावयचा पेमेन्ट संबंधी तसेच ट्रेनिंगच्या संबंधी खुलासा करावा.

श्री.विलासराव देशमुख : ट्रेनिंगच्या बाबतीत सन्माननीय सदस्य जे काही म्हणाले ते खरे आहे. त्या भागामध्ये येणा-या ज्या कंपन्या किंवा जे उद्योग असतील त्यांना कोणते कर्मचारी लागणार आहेत याचा पहिल्यांदा सर्व्हे करावा लागणार आहे. तेव्हा हा सर्व्हे ताबडतोबीने करण्यात येईल. त्याचबरोबर ट्रेनिंग इन्स्टिटयूट लवकरात लवकर म्हणजे शक्यतो पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे जून वा जुलै महिन्यापासून सुरु करण्यात येईल.

श्री.दिवाकर रावते : को-ऑर्डिनेशन कमिटी पंधरा दिवसात करण्यात येणार आहे काय ?

श्री.विलासराव देशमुख : एक महिन्यात को-ऑर्डिनेशन कमिटी करण्यात येईल.

2==

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

Q2

श्री.मधुकर चव्हाण : स्वदेशी मिलच्या कम्पाऊन्डमध्ये एक शाळा चालवली जाते आणि आठवी, नववी आणि दहावी पर्यंत शाळा चालविली जात आहे त्या शाळेला मान्यता देण्यात आलेली नाही. या शाळेमध्ये गिरणी कामगारांची मुले शिक्षण घेत आहेत. अनेक वर्षापासून तेथे शाळा सुरु आहे. तेव्हा या शाळेला मान्यता देण्यात येणार आहे काय ?

श्री.विलासराव देशमुख : शाळेला मान्यता देण्यास सांगण्यात येईल.

श्री.मधुकर चव्हाण : अनुदान तत्वावर..

श्री.विलासराव देशमुख : शाळेला जरुर मान्यता देण्यात येईल पण अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यासंबंधीची बाब तपासून पाहण्यात येईल.

सभापती : सभागृहाने प्रस्तावावर विचार केला आहे.

आता सभागृहाची विशेष बैठक स्थगित होऊन नियमित बैठक 12.15 वाजता पुनः भरेल.

(सभागृहाची बैठक सकाळी 11.22 ते 12.15 वाजेपर्यंत स्थगित झाली)

(सभागृह रथगितीनंतर ..)

सभापतीस्थानी - माननीय सभापती

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तरे.

सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी खोच्यातील पवनचक्की कंपनीच्या जमीन घोटाळ्याबाबत

(1) * 37761 श्री.जैनुदीन जव्हेरी, श्री. संजय दत्त, श्री.राजन तेली, श्री.सथ्यद जामा : दिनांक 23 नोव्हेंबर, 2007 रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या दिनांक 20 नोव्हेंबर, 2007 रोजीच्या यादीमधील प्रश्न क्रमांक 35187 ला दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय महसूल मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (1) सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी खोच्यातील पवनचक्की कंपनीच्या जमीन घोटाळ्याबाबत जमीन खरेदीची दुर्यम निबंधक, पाटण यांनी तहसिलदार पाटण यांचेकडे तपासणीसाठी पाठविलेल्या कांही प्रकरणामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने दुर्यम निबंधक, पाटण यांनी पोलीस स्टेशन पाटण येथे संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय,
- (2) असल्यास, या प्रकरणातील संबंधितांविरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
- (3) अद्याप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे, श्री.नारायण राणे यांच्याकरिता : (1) होय.

(2) दुर्यम निबंधक, पाटण यांवे फिर्यादीवरून पाटण पोलीस ठाणेला एकूण 13 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्या गुन्ह्यातील 125 आरोपी पैकी 114 आरोपिंना अटक करण्यात आली असून, 2 आरोपी मयत आहेत व 9 आरोपी परागंदा आहेत. त्यांना अटक करण्यासाठी पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत.

(3) विलंब झालेला नाही.

श्री. जैनुदीन जव्हेरी : सभापती महोदय, या प्रकरणात जे आरोपी पकडण्यात आले आहेत ते राजकीय स्वरूपाचे आहेत काय तसेच या घोटाळ्याचा तपशील काय आहे ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, सातारा जिल्ह्यातील मौजे ढेबेवाडी येथील पवनचक्की कंपनीच्या जमीन घोटाळ्या संबंधीचा प्रश्न येथे उपस्थित करण्यात आलेला आहे. या संबंधात मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, यामध्ये जवळपास 14-15 साठेकरार आणि कुलमुखत्यारपत्रांच्या आधारे व्यवहार झालेला होता. त्याबाबत दैनिक पुढारीमध्ये तक्रार आली होती तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.विलासराव पाटील यांनीही तक्रार केली होती आणि त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तहसिलदा यांनी संपूर्ण प्रकारणातील साठेकरार आणि कुलमुखत्यारपत्रांची तपासणी केली त्यात 29 प्रकरणांमध्ये सदोषता आढळून आली आणि 148 प्रकरणांतील करार नोंदणीसाठी

..... आर 2 ...

डॉ. शिंगणे (पुढे चालू...)

ता.प्र.क्र. 37761

प्रलंबित आहेत. याबाबत 114 आरोपींना अटक झालेली आणि 9 आरोपींना अटक होणे बाकी आहे. हे सर्व आरोपी राजकीय आहेत काय असे या ठिकाणी विचारण्यात आले आहे, त्याबाबत मी सांगू इच्छितो की, हे सर्व आरोपी राजकीय वगैरे म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसून सर्वसामान्य नागरिक आहेत.

श्री. संजय दत्त : सभापती महोदय, यामध्ये म्हटले आहे की, 9 आरोपी परांदा आहेत आणि त्यांना अटक करण्याबद्दल केवळ सूचना दिल्याचे दिसते आहे. तरीसदर आरोपींना अटक करण्यासाठी कोणती ठोस कृती करण्यात आलेली आहे ? तसेच या संबंधात पोलीस ठाण्यात जी मूळ फिर्याद दाखल झाली आहे ती केव्हा दाखल झाली आहे ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, 22.9.2007, 23.9.2007, 24.9.2007, 27.9.2007, 28.9.2007 ला या बाबतीतील पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तसेच जे फरार आरोपी आहेत त्याबाबत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, या बाबत मी सकाळीच पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून माहिती घेतली असून यातील काही आरोपी सातारा जिल्ह्यातील असले तरी सध्या ते मुंबईत राहत आहेत आणि येत्या 8-10 दिवसात ज्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्या आरोपींना पकडण्याच्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत.

श्री. राजन तेली : सभापती महोदय, या संदर्भातील जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर आपण कोठल्या प्रकारची कलमे लावलेली आहेत ?

(यानंतर श्री. सरफरे एस 1 ..

ता.प्र.क्र. 37761....

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी प्रश्नामध्ये विचारल्याप्रमाणे आय.पी.सी. च्या सेक्षन 419, 420, 467, 468, 471 आणि 34 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

डॉ. नीलम गोळे : सभापती महोदय, सन 2007 मध्ये हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. ही घटना 7 ते 8 महिन्यापूर्वी घडली आहे. असे असतांना तिसऱ्या उत्तरामध्ये "विलंब झालेला नाही" असे उत्तर दिले आहे. तेव्हा या विलंबाची कारणे काय आहेत? एखादी घटना घडल्यानंतर तीन महिन्यापेक्षा जास्त विलंब झाला तर तो आपण मान्य केला पाहिजे. याठिकाणी या कंपनीला परवानगी देतांना त्यावेळी कंपनीचे मुख्य संचालक कोण होते व आता ते कुठे आहेत? याठिकाणी 114 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. परंतु त्यामुळे ही केस दुबळी होऊन यामध्ये कुणालाही शिक्षा होणार नाही. या आरोपींना अटक न झाल्यामुळे आज हे आरोपी बाहेर फिरत आहेत त्यांचा जामीन रद्द झाला पाहिजे. यातील बरेच आरोपी नवी मुंबईमध्ये फिरत आहेत. त्यांचा प्रमुख सूत्रधार कोण आहे? त्याला आपण अटक केली काय?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी येथे हे प्रकरण घडल्यानंतर दैनिक पुढारीमध्ये बातमी ठापून आली. त्यानंतर याबाबत तपास करण्यात आला. याठिकाणी 364 दस्त तपासण्याचे काम तहसिलदार यांचे माध्यमातून झाले आहे. माननीय सदस्यांनी सांगितले की, तक्रार आल्यानंतर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत विलंब लागतो हे मान्य केले पाहिजे. म्हणून याबाबत शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी न करता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आणि चौकशी पोलीस खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सर्जन रिअलाईटीज लिमिटेड या कंपनीमार्फत या जमिनीची खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी बोगस रितीने झाल्याचे आढळून आले असल्यामुळे या कंपनीची चौकशी करण्यात येईल.

श्री. सुरेश नवले : सभापती महोदय, या पवन चक्की कंपनीच्या जमीन घोटाळ्याचे एकंदर स्वरूप काय आहे त्याबाबतची माहिती देण्यात येईल काय?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, या कंपनीच्या माध्यमातून ढेबेवाडी येथे जी जमीन खरेदी करण्यात आली. दुय्यम निबंधक यांच्यासमोर उभे राहून जमिनीच्या दस्ताची नोंदणी करीत असतांना ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी करावयाची होती त्याएवजी दुसऱ्या खातेदारांना उभे करून

ता.प्र.क्र. 37761....

डॉ. राजेंद्र शिंगणे....

त्यांच्या बोगस सहया आणि अंगठे घेऊन साठे करार किंवा कुल मुख्यारपत्र करण्याचा प्रयत्न झाला. त्या अनुषंगाने तक्रार दाखल करण्यात आली.

श्री. प्रकाश शेंडगे : सभापती महोदय, पवन चक्की जमीन खरेदीचा घोटाळा केवळ सातारा जिल्ह्यापुरता मर्यादीत नाही. याबाबत प्रत्येक अधिवेशनामध्ये मी देखील तक्रार करीत आलो आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये साडे तीन हजार तक्रारीची नोंद झाली आहे. परंतु एकाही केसमध्ये निवाडा झालेला नाही. त्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार कार्यालयामध्ये वारंवार खेटे घालावे लागत आहेत. यासंबंधी मागील अधिवेशनामध्ये धोरण जाहीर करण्यात येईल असे शासनाने सांगितले होते. परंतु ते जाहीर करण्यात आलेले नाही. स्थानिक आमदारांची देखील बैठक घेण्यात आली नाही. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की, या जमीन घोटाळयाचा मालक कोण आहे? या कंपनीचे डायरेक्टर कोण आहेत? त्यांची नावे सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आली पाहिजेत. या कंपनीवर आपण कारवाई करणार की नाही? माझा सरळ प्रश्न असा आहे की, सांगली जिल्ह्यामध्ये साडे तीन हजार केसेस पेंडींग आहेत. त्यासंबंधी केव्हा निकाल लागणार आहे? आणि या कंपनीवर आपण कारवाई करणार आहात की नाही?

(यानंतर सौ. रणदिवे)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

T-1

APR/ KGS/ MMP/

पूर्वी श्री.सरफरे

12:25

ता.प्र.क्र.37761

डॉ.राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, तो मूळ प्रश्नाशी संबंधित नसला तरी देखील, त्यांनी प्रश्न उपस्थित करताना असे सांगितले आहे की, सांगली जिल्हयामध्ये अशाच प्रकारे पवनचक्कीसाठी जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये घोटाळा झालेला आहे. तसेच सांगली जिल्हयातील या प्रकरणांच्या बाबतीत पूर्वी शासनाच्यावतीने आश्वासने देण्यात आली आहेत. मी याबाबतीत सांगू इच्छितो की, जर अशा प्रकारे शासनाच्या वतीने आश्वासने देण्यात आली असतील, मग ते या प्रकरणाची चौकशी करण्यासंबंधात असेल तर त्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल, तसेच कंपनीचे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आणि संचालक यांच्या नावाची यादी इ.अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.

श्री.चंद्रकांत रघुवंशी : सभापती महोदय, पवनचक्की कंपन्यांनी फक्त शेतकऱ्यांना फसविले असे नाही तर शासनाला देखील फसविलेले आहे. नंदूरबार जिल्हयामध्ये 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार एकर या दराने जमीन खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर लगेव एका महिन्यामध्ये ही जमीन दुसऱ्या कंपनीच्या नावाने ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. तसेच याच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये जमिनीचा दर 9 ते 10 लाख रुपये एकर असा दाखविण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे त्यांनी या माध्यमातून शासनाचा टँक्स देखील बुडविलेला आहे. याबाबतीत महाग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करून दिला

सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री.चंद्रकांत रघुवंशी : सभापती महोदय, नंदूरबार जिल्हयामध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना लुबाडून पवनचक्कीसाठी फार मोठया प्रमाणात जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच या कंपन्यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देण्यात येणार होती, पण त्या देखील दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की, नंदूरबार जिल्हयातील संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहात काय ?

डॉ.राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रकांत रघुवंशीसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे नंदूरबार जिल्हयामध्ये पवनचक्क्यांच्या बाबतीत तक्रारी असतील तर त्यांनी त्या शासनाकडे, माझ्याकडे द्याव्यात. त्याची संपूर्ण चौकशी केली जाईल. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नोकरी देण्याच्या बाबतीत, जमिनीचा मोबदला देण्याच्या बाबतीत किंवा इतर जी आश्वासने दिलेली

. . . .टी-2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

T-2

APR/ KGS/ MMP/

12:25

ता.प्र.क्र.37761

डॉ.राजेंद्र शिंगणे

आहेत, ती पाळली नसतील, शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असेल तर ताबडतोब चौकशी केली जाईल. तसेच याबाबतीत अगोदर देखील गुन्हे दाखल झाले असतील, तक्रारी दाखल झाल्या असतील तर त्याची चौकशी झाली आहे काय ? याचीही माहिती घेऊन ती सन्माननीय सदस्यांना दिली जाईल.

श्री.विलासराव शिंदे : सभापती महोदय, याठिकाणी दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असे म्हटलेले आहे की, "दुख्यम निबंधक, पाटण यांचे फिर्यादीवरुन पाटण पोलीस ठाणेला एकूण 13 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत." मात्र माननीय मंत्री महोदयांनी मघाशी एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये असे सांगितले की,"यासंबंधात "दैनिक पुढारी" या वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली आहे." माझा असा प्रश्न आहे की, या जमिनी ज्या मूळ मालकांच्या होत्या, त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती काय ? तसेच संबंधितांना त्या जमिनीमध्ये जाऊ दिले नाही, असे झाले आहे काय ? तसेच दुख्यम निबंधकांकडे तक्रार दिल्यानंतर त्याची दाद केव्हा घेण्यात आली ?

डॉ.राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, याबाबतीत दि.17-4-2004 रोजी "दैनिक प्रभात" मध्ये पहिली तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर विधानसभेचे सन्माननीय सदस्य श्री.विलासराव पाटील यांनी दि.10-7-2004 ला यासंदर्भात तक्रार केलेली आहे. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी देखील खाजगी स्वरूपामध्ये दुख्यम निबंधकांकडे तक्रार केली होती. मी सदनाला सांगू इच्छितो की, दुख्यम निबंधकांनी व्यवहार करीत असताना तपासणी केली नाही, फोटो लावले नाहीत म्हणून श्री.विजय म्हसकर यांनी दुख्यम निबंधकांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली होती. याबाबतीत दुख्यम निबंधक श्रीमती रजनी कुमठेकर यांना दि.3-9-2007 रोजी सदरहू गुन्ह्याबद्दल अटक झाली होती.त्यामुळे याबाबतीत कारवाई सुरु आहे.

यानंतर कु.गायकवाड

DVG/ MMP/ KGS/ प्रथम श्रीमती रणदिवे..

12:30

मौजा पिंपळखुटा (मोठा), ता. मोर्शी, जि. अमरावती येथील कुबराबी शेख मदार व शेख मदार यांनी शेत स.नं ११२ मध्ये नाल्याचा प्रवाह बदल्याबाबत

(२) * ३९५९१ श्री. जगदीश गुप्ता, श्री. नितीन गडकरी, श्री. पांडुरंग फुंडकर : सन्माननीय महसूल मंत्री पुढील गोष्टीचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुबराबी शेख मदार व शेख मदार यांनी मौजा पिंपळखुटा (मोठा), ता. मोर्शी, जि. अमरावती येथील शेत स.नं ११२ मधून बारमाही वाहत्या नाल्याच्या तोंडावर जे.सी.पी. मशीनने विना परवानगी मुरुम माती ढीग लावून पाण्याचा प्रवाह बदलविल्याची बाब जिल्हाधिकारी, अमरावती, मा. महसूल मंत्री, मा. गृहमंत्री यांच्या निर्दर्शनास दिनांक २१ नोव्हेंबर, २००७ रोजी वा त्यासुमारास आलेली आहे अथवा आणण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नाल्याची दिशा पूर्ववत करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केलेली आहे वा कार्यान्वित आहे,

(३) नसल्यास, विलंबाची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे, श्री. नारायण राणे यांच्याकरिता: (१) व (२) दिनांक २१ नोव्हेंबर, २००७ चे निवेदन जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना प्राप्त झाले असून त्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली असून श्रीमती कुबराबी शेख मदार यांनी नाला वळविल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून नाला पूर्ववत करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री. जगदीश गुप्ता : सभापती महोदय, या प्रश्नासंदर्भात दंडात्मक कारवाई झालेली आहे असे उत्तरात म्हटलेले आहे. मी आपणास विचार इच्छितो की, दंडात्मक कारवाई म्हणजे नेमकी कोणती कारवाई झालेली आहे ? हा नाला आता पूर्ववत झालेला आहे काय ? ज्या तलाठयाने पैसे घेऊन ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे त्या तलाठयावर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, मौजा पिंपळखुटा, ता. मोर्शी, जि. अमरावती येथील कुबरानी शेख मदार व शेख मदार यांनी नाल्याचा प्रवाह बदलविल्याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री. जगदीश गुप्ता यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. कुबरानी शेख मदार व शेख मदार यांनी नाल्याचा प्रवाह बदलला अशी तक्रार करण्यात आली होती. या संदर्भात नायब तहसिलदार, तलाठी यांनी चौकशी केली होती. ही तक्रार खरी आहे असे चौकशीमध्ये आढळून आले आहे. त्यामुळे २ हजार रुपयांचा दंड कुबरानी शेख व मदारी शेख यांना लावण्यात आला आहे. नाला सरळ करण्याच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाबाबत एसडीओ यांच्याकडे अपील सुरु आहे. हा निर्णय आल्यानंतर नाला सरळ करण्याचे काम केले जाईल. तसेच तलाठयाने या कामास एनओसी दिल्याचे निष्पन्न

2..

डॉ.राजेंद्र शिंगणे..

झाल्यास त्याची देखील चौकशी केली जाईल. चौकशी मध्ये जे लोक दोषी आढळून येतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

प्रा. सुरेश नवले : सभापती महोदय, हा नाला परत पूर्ववत करण्याचे काम कोण करणार आहे ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, नाल्याचा प्रवाह बदलण्याचे काम कुबरानी शेख मदार व शेख मदार यांनी केले आहे. त्यामुळे नाला पूर्ववत करण्याचे काम देखील त्यांच्याकडूनच करून घेतले जाणार आहे.

श्री. जगदीश गुप्ता : सभापती महोदय, नाल्या संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे माननीय मंत्री महोदय श्री. नारायण राणे यांनी मान्य केलेले आहे. त्यामुळे दोषी व्यक्तिवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे काय ?. तसेच एसडीओकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे असे सांगितले आहे. हा नाला तातडीने पूर्ववत करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात येणार आहे ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, नाला पूर्ववत करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्या संदर्भातील अपील एसडीओकडे प्रलंबित आहे. त्यांनी स्टे दिलेला नाही. नाला सरळ करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात येतील.

सभापती : अपील एसडीओ यांच्याकडे केलेले आहे. त्यास अजून स्टे दिलेला नाही. त्यामुळे नाला पूर्ववत सरळ करण्याचे काम तातडीने सुरु केले जाईल.

..3..

**मुंबई सहकारी बोर्डच्या संचालकांनी मुंबई विभागीय सहनिबंधकांच्या कार्यालयात बेकायदेशीरपणे
खरेदी केलेल्या मूळ मुद्रांक पेपर वरील केलेली खाडाखोड**

(३) * ३७३०४ श्री. संजय दत्त, श्री. गोविंदराव आदिक, श्री. सव्यद जामा, श्री. सुरेशदादा देशमुख, श्री. राजन तेली : दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००७ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या दिनांक २० नोव्हेंबर, २००७ रोजीच्या यादीमधील प्रश्न क्रमांक ३४०३६ ला दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय सहकारी मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुंबई सहकारी बोर्डच्या संचालकांनी मुंबई विभागीय सहनिबंधकांच्या कार्यालयात बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या मूळ मुद्रांक पेपर वरील तारखांमध्ये खाडाखोड केल्याप्रकरणी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांनी भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४२०, १२० व ४७१ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे तसेच संचालक मंडळातील सदस्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ अन्वये नोटीस बजावण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणातील दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(३) अद्याप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर, डॉ. पतंगराव कदम यांच्याकरिता : (१) होय.

(२) सदर गुन्ह्याबाबतची कार्यवाही व तपास संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत करण्यात येत आहे. तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ (१) अन्वये बजावण्यात आलेल्या नोटीसीबाबतची सुनावणी प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांचे कार्यालयाच्या स्तरावर सुरु आहे.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री. संजय दत्त : सभापती महोदय, उप निबंधक सहकारी संस्था यांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूप काय आहे ? त्यामध्ये किती व्यक्तिचा समावेश आहे ? हा प्रश्न नागपूर अधिवेशनामध्ये दिनांक 20/11/2007 रोजी उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी असे उत्तर दिले होते की, नोटीसेस पाठविण्यात आलेल्या आहेत. परंतु हा गुन्हा प्रत्यक्षात ॲंगस्ट 2007 रोजी घडल्याचे उघडकीस आलेले आहे. गुन्हा होऊन इतका काळ लोटल्यानंतर देखील त्याबाबत अजून सुनावणी झालेली नाही. याबाबत शासनाकडून माहिती देण्यात यावी.

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, मुंबई सहनिबंधकाच्या कार्यालयात बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या मूळ मुद्रांक पेपर वरील केलेल्या खोडाखोडी बाबत 24 लोकांवर

4..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

U 4

भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 465,467,468,420,120 व 471 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. डीडीआर यांच्याकडे या संदर्भात चार सुनावण्या झालेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळामध्ये ही सुनावणी आयुक्तांनी घ्यावी असा अर्ज केला होता. 25/10/2007 रोजी आयुक्तांनी तो अर्ज नामंजूर केला होता. त्यांनंतर माननीय सहकार मंत्री यांच्याकडे देखील अशाच प्रकारचा अर्ज करण्यात आला. त्यांनी देखील तो अर्ज नामंजूर केलेला आहे. उपनिबंधकांनी सुनावणी घ्यावी असे आदेश त्यांनी दिलेले आहेत. त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.

श्री. अरविंद सावंत : सभापती महोदय, कसे बनावट मुद्रांक कसे तयार केले जातात हे दाखविण्याकरिता नागपूर अधिवेशनामध्ये मी तसे मुद्रांक आणून दाखविले होते. या संदर्भातील गुन्हे दाखल केल्यानंतर किती लोकांना अटक झालेली आहे ? तसेच हे संचालक मंडळ सध्या अस्तित्वात आहे काय, नसल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे ?

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, मूळ मुद्रांक पेपरवर खाडाखोड करण्यात आलेली आहे. याबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सहकार खात्याच्या कायद्यानुसार कलम 78 (1) नुसार नोटीसेस देण्यात आलेल्या आहेत.

यानंतर श्री. बरवड..

ता. प्र. क्र. 37304

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर...

त्यानंतर ते उच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. उच्च न्यायालयाने एका डी.डी.आर.ऐवजी दुसऱ्या डी.डी.आर.कडे सुनावणी घ्यावी असे आदेश दिले. ही सुनावणी लवकरात लवकर घेऊन कारवाई करण्यात येईल. आता संचालक मंडळ अस्तित्वात आहे.

श्री. अरविंद सावंत : सभापती महोदय, यामध्ये कलम 420 खाली गुन्हा नोंदविलेला आहे आणि हा गुन्हा नॉन बेलेबल आहे. त्यांना आजपर्यंत अटक का केली नाही ? हे मंडळ आता अस्तित्वात आहे काय ?

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, मंडळ अस्तित्वात आहे. मंडळाला नॅचरल जस्टीसप्रमाणे कलम 78(1) ची नोटीस देणे चालू आहे. ते उच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. उच्च न्यायालयाने एका डी.डी.आर. ऐवजी दुसऱ्या डी.डी.आर. ने सुनावणी घ्यावी असे आदेश दिले. त्या डी.डी.आर. कडे सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईल. अटकेच्या बाबतीत आता माझ्याकडे माहिती नाही. ती माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल.

सभापती : याबाबतीत संबंधित पक्षकार उच्च न्यायालयामध्ये गेले होते आणि आता दुसरे डी.डी.आर. कलम 78 प्रमाणे अँकशन घेणार आहेत. ती अँकशन लवकर घेण्याच्या बाबतीत चौकशी पूर्ण होऊन त्यामध्ये ते संचालक मंडळ दोषी ठरले तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली किंवा काय कारवाई करणार आहात ?

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, सकृतदर्शनी यामध्ये चूक आहे, ते दोषी आहेत हे दिसले आहे पण नॅचरल जस्टीसप्रमाणे गुन्हेगाराला सुध्दा नोटीस घ्यावी लागते त्याप्रमाणे नोटिसेस दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात वेगवेगळ्या ठिकाणी अपील झाले त्यामध्ये वेळ गेलेला आहे. आता ती बाब दुसऱ्या डी.डी.आर. कडे आलेली आहे आणि ती चौकशी दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

डा. नीलम गोळे : सभापती महोदय, नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये असा प्रश्न विचारला होता की, गुन्हेगारी कायद्याप्रमाणे जी प्रक्रिया चालू आहे त्यामध्ये किती आरोपी आहेत तसेच त्यांचा जामीन रद्द करणार काय ? याबाबत असे उत्तर देण्यात आले होते की, जामीन झाला असेल तर

ता. प्र. क्र. 37304

डॉ. नीलम गोरे

तो रद्द करून त्यांना अटक केली जाईल. माननीय मंत्रिमहोदय परत पाठीमागे जात आहेत. या आरोपींना ताबडतोब अटक होण्याच्या संदर्भात शासनाने काय पावले उचलली आहेत ?

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, मी आताच सांगितले की, अटक झाली की नाही ही माहिती आता माझ्याकडे नाही. ती माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. त्या कलमाप्रमाणे लवकरात लवकर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात येतील.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, आपण हा प्रश्न राखून ठेवावा.

सभापती : हा प्रश्न मी राखून ठेवत आहे.

तारांकित प्रश्न क्रमांक 39837

(सन्गाननीय सदस्य अनुपस्थित)

....3...

वर्धा जिल्ह्यातील मुकबधिर प्रवर्गाच्या ७ शाळांचे सन १९९७-९८

पासूनचे वेतनेतर अनुदान प्रलंबित असणे

(५) * ३७३७२ **श्री. व्ही. यू. डायगव्हाणे**, प्रा. बी. टी. देशमुख, श्री. वसंतराव खोटरे, श्री. जी. एल. ऐनापूरे : सन्माननीय सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य मंत्री पुढील गोष्टीचा खुलासा करतील काय :-

- (१) वर्धा जिल्ह्यातील मुकबधिर प्रवर्गाच्या ७ शाळांचे सन १९९७-९८ पासून थकित असलेले परिक्षण अनुदान, वेतनेतर अनुदान रु. ५९,६६,८८५ अदा करावे अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीचे दिनांक ६ नोव्हेंबर, २००७ चे सभेत एका लोकप्रतिनिधींनी केली आहे, हे खरे आहे काय,
- (२) आयुक्त अपंग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. २२५७, दिनांक २ नोव्हेंबर, २००७ अन्वये सदर थकित अनुदानासाठी शासनाकडे २३ कोटी २९ लक्ष ३९ हजार तरतुदीची मागणी करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
- (३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कारवाई केलेली आहे,
- (४) कार्यवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : (१) होय.

(२),(३) व (४) थकीत वेतन व वेतनेतर अनुदानासाठी रूपये ३६४४.९० लाखाची पुरवणी मागणी मंजूर केली असून, जिल्हा पातळीवर सर्व जिल्हा परिषदेच्या मागणी नुसार निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.

श्री. व्ही. यू. डायगव्हाणे : सभापती महोदय, मुकबधिर विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या अनुदानाचा हा प्रश्न आहे. वेतनेतर अनुदान आणि परिरक्षण अनुदान म्हणजे भोजन व्यवस्थेसाठी जे अनुदान दिले जाते या दोन्ही अनुदानाच्या बाबतीत हा संयुक्त प्रश्न आहे. १ एप्रिलला माननीय मंत्रिमहोदयांना असा प्रश्न विचारला होता की, दोन दिवसात हे अनुदान वितरित करणार काय ? त्याबाबत त्यांनी "तातडीने" असे उत्तर दिले होते. आज असे उत्तर दिले आहे की, सर्व निधी जिल्ह्यांना वितरित केलेला आहे. त्याबाबत मी माननीय मंत्रिमहोदयांना धन्यवाद देतो. कारण 1997 पासून हे अनुदान देणे आहे. या ठिकाणी वर्धा वर्धा जिल्ह्यातील ७ शाळांच्या संदर्भात प्रश्न विचारलेला आहे. या सातही शाळांची 1997 पासून किती थकबाकी आहे आणि आपण खरोखर दोन दिवसात ती देणार काय ?

ता. प्र. क्र. 37372

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : सभापती महोदय, अपेंगांच्या शाळांच्या बाबतीत सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा बरोबर आहे. आम्ही वित्त विभागाकडे सातत्याने वेतनेतर अनुदानाची मागणी करीत होतो. त्यांना वेतन मिळत होते. आतापर्यंत वेतन अदा करण्यात आलेले आहे परंतु सन्माननीय सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देऊ शकलो नाही तसेच परिपोषण आहार देऊ शकलो नाही. याबाबतीत मी सातत्याने माननीय वित्त मंत्री तसेच वित्त सचिवांकडे पाठपुरावा करून मागच्या अधिवेशनामध्ये आम्ही बजेटमध्ये ॲडिशनल 36 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आणि वर्धी जिल्हासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अंग संस्थाना हे वेतनेतर अनुदान आणि परिपोषण आहार वितरित करण्यात आला आहे.

यानंतर श्री. खंदारे

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

W-1

NTK/ MMP/ KGS/

श्री.बरवडनंतर

12:40

ता.प्र.क्र.37372....

श्री.चंद्रकांत हंडोरे....

ते वेतनेतर अनुदान, परिरक्षण अनुदान वितरित केलेले आहे. वर्धा जिल्हयामध्ये स्पेसिफिकली या 7 शाळा आहेत, यामध्ये संत केजाजी मुकबधिर शाळा, सेलू, जिल्हा वर्धा या शाळेची जवळपास 11 लाख इतकी रक्कम थकित आहे. सभापती महोदय, वर्धा जिल्हयासाठी जवळजवळ 2.41 कोटी रुपये द्यावयाचे होते, प्रत्यक्षात 2.51 कोटी रुपये दिलेले आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी या विषयासंबंधी नियम 93 ची सूचना दिली होती त्यावेळी मी 10 दिवसामध्ये कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अंग आयुक्तांना कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. केवळ बीडीएस सिस्टमच्या बिलाची किलअर माहिती मिळत नव्हती, आता तो मुद्दा किलअर झालेला आहे, अनुदान मंजूर झालेले असून ते आठवडयामध्ये वितरित केले जाईल.

2.....

राज्यातील गटई कामगारांना पत्राचे स्टॉल देण्याबाबतचा प्रस्ताव

(६) * ३९१८४ श्री. नितीन गडकरी , श्री. विनोद तावडे , श्री. मधुकर चक्राण , श्री. सव्यद पाशा पटेल , श्री. जगदीश गुप्ता , श्री. गुरुमुख जगवानी : तारांकित प्रश्न क्रमांक ३४६४७ ला दिनांक २७ नोव्हेंबर, २००७ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

- (१) राज्यातील गटई कामगारांना पत्राचे स्टॉल देण्याची योजना राबविण्याच्या शासनाच्या विचाराधीन प्रस्तावावर करण्यात येत असलेली कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे काय,
- (२) असल्यास, सदर कार्यवाहीचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे,
- (३) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : (१) होय,

- (२) दिनांक १३ फेब्रुवारी, २००८ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
- (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, मी असा प्रश्न विचारला होता की, राज्यातील गटई कामगारांना पत्राचे स्टॉल देण्याची योजना राबविण्याच्या शासनाच्या विचाराधीन प्रस्तावावर करण्यात येत असलेली कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे काय ? त्याला होय असे उत्तर दिलेले आहे. दुस-या प्रश्नाच्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, "दिनांक 13 फेब्रुवारी, 2008 च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. कार्यवाही म्हणजे काय ? त्या लाभार्थ्याना स्टॉल मिळाले तर ती कार्यवाही पूर्ण झाली असे म्हणता येईल. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एकाही लाभार्थ्याला स्टॉल मिळालेला नाही. या स्टॉलसाठी टेंडर काढण्यात आले होते त्यात 22 गेज नमूद केले होते, प्रत्यक्षात 20 गेजचा पत्रा घेतला, त्यामुळे वजन वाढले आहे. माननीय समाजकल्याण मंत्र्यांना माहीत नाही, त्यांच्याच खात्यातील लोक पैसे काढून घेतात, पण काम मात्र काही करीत नाहीत. सभागृहामध्ये मंत्रिमहोदयांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, त्यानुसार किती लाभार्थ्याना स्टॉल मिळाले आहेत त्याची माहिती घावी.

श्री.चंद्रकांत हंडोरे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी स्टॉलसंबंधी प्रश्न विचारलेला आहे. इतक्या मोठ्या अडचणीचे हे प्रकरण सोडविता सोडविता आमच्या नाकी नऊ आले आहे.

3...

ता.प्र.क्र.39184....

श्री.चंद्रकांत हंडोरे.....

ही योजना पूर्वी शासनाकडे होती. काही काळानंतर ती बंद पडली, त्यानंतर शासनाने लिडकॉमकडे ती हस्तांतरित केली. पण तेथे सुधा ती बंद पडली. मी मंत्री झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमातीतील सर्व घटकांना या योजनेचा फायदा मिळावा म्हणून गेली 3-4 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करीत आहे....

सभापती : गटई कामगारांना हे स्टॉल देण्याचे ठरल्यानंतर आतापर्यंत किती स्टॉलचे वितरण केले आहे इतका मर्यादित प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला आहे, त्याला आपण पॉइन्टेड उत्तर द्यावे.

श्री.चंद्रकांत हंडोरे : सभापती महोदय, एवढी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्यानुसार या स्टॉलचे ते उत्पादन करतील. स्टॉल चेक करून झाल्यावर ते गटई कामगारांना वितरित केले जातील.

श्री.सुरेश जेथलिया : सभापती महोदय, राज्यातील गटई कामगारांना पत्राच्या स्टॉलचे वाटप करण्यासाठी बजेटमध्ये किती तरतूद केलेली आहे ? प्रत्येक जिल्ह्यातील गटई कामगारांना किती स्टॉल वितरित केले जातील ?

श्री.चंद्रकांत हंडोरे : सन 2006-07 या वर्षासाठी 1 कोटीची तरतूद केली होती. परंतु मागणी मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे महाराष्ट्रातील 10 हजार गटई कामगारांना स्टॉल देण्याचा प्रयत्न करू असे ठरविण्यात आले. याकरिता जी रक्कम शिल्लक होती त्यातून 13 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे त्या वर्षासाठी 14 कोटी रुपये तरतूद झाली आणि सन 2008-09 या वर्षासाठी 10 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

नंतर श्री.शिगम

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

X-1

MSS/ MMP/ KGS/ पूर्वी श्री. खंदारे

12:45

(ता.प्र.क्र. 39184.....

श्री. जगदीश गुप्ता : छापील उत्तरामध्ये निर्णय घेतलेला आहे, आदेश निर्गमित केलेले आहेत असे नमूद केलेले आहे. तेव्हा कोणता निर्णय घेतलेला आहे आणि कोणाला आदेश निर्गमित केलेले आहेत ?

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : वर्कऑर्डर आणि जी.आर.काढलेला आहे. समाजकल्याण संचालक यांच्या मार्फत लिडकॉमला ही योजना कार्यान्वित करण्यास सांगितलेले आहे. ही संपूर्ण योजना लिडकॉम कार्यान्वित करील.

श्री. सुभाष चव्हाण : सभापती महोदय, मी या समाजाचे नेतृत्व करतो कारण या समाजामध्ये मी जन्माला आलो आहे. मला काही लोकांनी विचारले की गटई कामगार म्हणजे काय ? तर गटई कामगार म्हणजे चर्मकार समाजातील दुर्बल घटक जो रस्त्याच्या कोप-यावर बसून फाटक्या तुटक्या चपला शिवून देतो तो गटई कामगार. माझ्या माहिती प्रमाणे या गटई कामगारांच्या यादीमध्ये काटछाट करण्यात आलेली आहे. तसेच जी 30 कोटी रु. रक्कम मंजूर झालेली आहे त्यातील निम्मी रक्कम दुसरीकडे वर्ग झालेली आहे. तेव्हा एकूण किती लोकांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे ? तसेच एकूण मिळालेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम दुसरीकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे हे खरे आहे काय ?

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : सन्माननीय सदस्य श्री. सुभाष चव्हाण हे त्या समाजातील आहेत असे त्यांनी सांगितले. मी त्यांची कदर करतो. त्यांचे म्हणणे खरे आहे की, रस्त्यावर ऊन, वारा, पावासात बसून छपला, छत्र्या दुरुस्त करून देणा-यांना गटई कामगार म्हटले जाते. अशा या गटई कामगारांना चांगल्या प्रकारचे स्टॉल मिळावेत, चांगल्या प्रकारचे शेल्टर मिळावे यासाठी मीच या योजनेसाठी प्रयत्न सुरु केला. एकूण 2848 अर्ज आमच्याकडे आलेले आहेत. आम्ही 10 हजार गटई कामगारांना स्टॉल देण्याचे ठरविलेले आहे. माझी सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या भागामध्ये या गटई कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्याबाबतीत शासन निश्चितपणे मदत करील.

.2..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

X-2

श्री. राम पंडागळे : आदरणीय मंत्री महोदयांनी याबाबतीत निर्णय घेतला ही चांगली गोष्ट आहे. राज्यातील कोणकोणत्या महानगरपालिकांमध्ये या गटई कामगारांना स्टॉल देण्यात येणार आहेत ? "क" वर्ग नगरपालिकांना देखील हा नियम लागू करता येईल काय ? लिडकॉमला हे स्टॉल बनविण्यास सांगितले आहे. लिडकॉम ही संस्था आहे. ती उत्पादन करीत नाही. तेव्हा ज्यांचे अर्ज आलेले आहेत त्यांनाच ही रक्कम स्टॉल बनविण्यासाठी देण्यात येईल काय ?

श्री. चंद्रकांत हंडोरे : कोणकोणत्या महानगरपालिकेपर्यंत या योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे असा सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न आहे ? मी सांगू इच्छितो की, ही योजना 1997साली सुरु झाली त्यावेळी ती ग्रामीण भागात "क" वर्ग नगरपालिकेपुरतीच मर्यादित होती. हे गटई कामगार महाराष्ट्रभर आहे. म्हणून या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचे मीच ठरविले. म्हणून "अ" वर्ग आणि "ब" वर्ग महानगरपालिका आणि कॅण्टोनेण्ट बोर्ड अशी महाराष्ट्रभर या योजनेची व्याप्ती वाढविलेली आहे. लिडकॉम ही फक्त कर्ज पुरवठा करणारी संस्था नसून ती उत्पादन देखील करते. तसेच त्या समाजाशी संबंधित असणारी ही संस्था असल्यामुळे ही योजना ती संस्था अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक चालविल या उद्देशाने त्या संस्थेकडे ही योजना वर्ग करण्यात आलेली आहे.

....नंतर श्री. गिते...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

Y-1

ABG/ KGS/ MMP/ प्रथम श्री.शिगम

12:50

ता.प्र.क्र. 39184...

श्री. मधुकर चव्हाण : राज्यातील गटई कामगारांना पत्राचे स्टॉल देण्याचे काम किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल ?

श्री. चंद्रकांत हंडारे : सभापती महोदय, यासंबंधी जी.आर.काढलेला असून त्यांना सांगितले आहे की, याबाबतीत लवकर काम सुरु करा. पुरवठादाराकडून लिडकॉमला दुसरे एक पत्र मिळाले आहे. तुम्ही रॉ मटेरियल तपासणीसाठी समिती तयार केली आहे. समितीकडून रॉ मटेरियल तपासल्याशिवाय आम्हाला स्टॉल कर्से बनविता येतील. तर त्याबाबतीत त्यांचे म्हणणे असे आहे की, रॉ मेटेरियल तपासल्यानंतर स्टॉल बनविण्यासंदर्भात 45 दिवस पुढे मुदत घावी. त्यासंबंधीचा आम्ही विचार करीत आहोत. गटई कामगारांना स्टॉल मिळवून देण्यासाठी मी स्वतः लक्ष घालतो आहे. मला असे वाटते की, ही योजना काही लोकांच्या कचाटयात सापडली आहे. ती योजना चांगल्या प्रकारे सुरु व्हावी या मताचा मी आहे. म्हणून या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा असा माझा प्रयत्न आहे.

श्री. विनोद तावडे : ज्यांना स्टॉल बनविण्यास सांगितले आहे, त्यांनी काय लिहिले आहे ते मी या ठिकाणी वाचून दाखवितो. ही योजना कशी डब्यात गेली आहे ही बाब मी सभागृहाच्या निर्दर्शनास आणून देऊ इच्छितो. ज्यांना स्टॉल बनविण्यास सांगितले आहे, त्यांनी पत्रात असे लिहिले आहे की, "Please note our negotiations and all calculations are based on 22 gauge, it shall not be possible to supply stalls of 20 gauge, It is requested kindly to amend the same." ज्यांना टॅंडर मिळाले आहे, ज्यांना लेटर ऑफ इंडेंट दिले आहे. संत रोहिदास लेदर इंडंस्ट्रीज ॲन्ड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी असे म्हटले की, आम्ही 20 गेजचे पत्रे उपलब्ध करून देऊ शकणार नाही. स्टॉल बनविण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली त्यावेळी 22 गेजचा पत्रा देण्यात येईल असे ठरले होते. ॲग्रीमेट करताना 22 गेजचा पत्रा देण्याचे ठरले होते आणि प्रत्यक्षात मात्र 20 गेजचा पत्रे देण्यासंबंधीचा जी.आर.काढला. ही वरतुस्थिती असेल तर हे प्रकरण प्रोसेसमध्ये आहे, मी प्रयत्न करीत आहे, या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळावा अशी माझी इच्छा आहे, ती योजना कचाटयात आहे, त्यातून सोडविण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे असे माननीय मंत्री महोदयांनी सांगून हा प्रश्न सुटणार नाही.

2...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

Y-2

ता.प्र.क्र. 39184...

श्री.विनोद तावडे...

20 आणि 22 गेजच्या पत्रांची भानगड मध्येच निर्माण झाली आहे, ती भानगड कशी सोडविणार आहात ? यासंबंधीचा जी.आर.कशाला बदलला ? कोणासाठी बदलला ? इतक्या दिवसाच्या आत प्रत्यक्षात स्टॉल्स रस्त्यावर दिसतील यासंबंधीची तारीख माननीय मंत्री महोदयांनी सांगावी.

श्री. चंद्रकांत हंडारे : 20 आणि 22 गेजच्या पत्रासंबंधीची बाब मी तपासून बघतो आणि ही योजना कार्यान्वित होईल असा प्रयत्न करतो.

सभापती : सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न असा आहे की, स्पेसिफिकेशनमध्ये 22 गेजचा पत्र देण्यात येईल असे सांगितले गेले आणि संबंधित कंपनी म्हणते की, 20 गेजचा पत्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा तांत्रिक मुद्दा आहे, म्हणून हा मुद्दा माननीय मंत्री महोदयांनी जरुर तपासून घ्यावा.

श्री. चंद्रकांत हंडारे: स्पेसिफिकेशनमध्ये 22 गेज आहे आणि जी.आर.20 गेजचा काढण्यात आला आहे ही तफावत कशी काय आली ती बाब मी तपासून घेतो. ती तफावत दूर करून त्यासंबंधात तात्काळ कार्यवाही करतो.

श्री. चंद्रकांत रघुवंशी : या गटई कामगारांना दुकाने देतो. ती दुकाने त्या व्यवसायासाठीच वापरली जातील यासंबंधीची शासन काळजी घेणार काय ? अशा दुकानांमध्ये थंड पेय व इतर वस्तू देखील विक्रीसाठी ठेवल्या जातात. गटई कामगाराला उद्योग मिळावा, त्याला उन्हात बसावे लागू नये,यासाठी आपण त्यांना दुकाने देत आहोत. सदरहू स्टॉलचे क्षेत्रफळ त्या व्यवसायाला शोभेल असे दिले तर रस्त्यावरील अतिक्रमण कमी होऊ शकते. या व्यवसायासाठी शोभेल एवढयाच क्षेत्रफळाची दुकाने त्यांना देण्यात येतील काय ? एका दुकानाची किंमत किती ? जिल्हा स्तरावर या दुकानांचे वाटप कोण करणार आहे ?

श्री. चंद्रकांत हंडारे : या स्टॉलची साईज $4\times5\times6.50$ अशा क्षेत्रफळाचे हे स्टॉल्स आहेत. गटई कामगारांना या स्टॉलमध्ये चर्माद्योगाशिवाय दुसरा कोणताही व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. सदरहू स्टॉल त्यांना ट्रान्सफर करता येणार नाही. लाभार्थ्याला फोटोसह सटिफिकेट देण्यात येणार आहे, ते सर्टिफिकेट त्यांने त्या स्टॉलमध्ये लावणे आवश्यक आहे. लाभ देण्याचे अर्ज जिल्हाच्या ठिकाणी समाजकल्याण अधिका-यांकडे स्वीकारले जातील. या स्टॉलचे वाटप समाजकल्याण अधिका-यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.

यानंतर श्री. कानडे..

नांदेड जिल्ह्यातील कासराळी येथे पुनर्वसन भूखंड वाटपात झालेल्या घोटाळ्याबाबत

(७) * ४०७६४ श्री. सुरेश जेथलिया : सन्माननीय पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :

(१) नांदेड जिल्ह्यातील कासराळी येथील साठेनगर व आंबेडकरनगर मधील पुनर्वसन भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचे नुकतेच फेब्रुवारी, २००८ मध्ये वा त्यासुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत लाभधारकाने तीस वेळा उपोषण करूनही अद्याप दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे,

(३) तदनुसार, त्यात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे,

(४) असल्यास, लाभधारकांना न्याय मिळवून देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे अथवा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. पतंगराव कदम यांच्याकरिता : (१) या गावांचे पुनर्वसन प्रस्तावित असल्यामुळे घोटाळ्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री. सुरेश जेथलिया : सभापती महोदय, नांदेड जिल्ह्यातील कासराळी गावाचे पुनर्वसन केव्हा होणार आहे ? तेथील लोकांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांचे पुनर्वसन का करण्यात आले नाही ? पुनर्वसन होणाऱ्या लाभार्थींची संख्या किती ? १९९० मध्ये किती लाभार्थी पात्र होते आणि सद्यस्थितीत किती लाभार्थी पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील कासराळी येथील साठेनगर व आंबेडकरनगर मधील पुनर्वसनाचा मूळ प्रश्न विचारलेला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कासराळी गावाचे पुनर्वसन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याला अजून मान्यता मिळालेली नाही. कासराळी हे बिलोली तालुक्यातील गाव असून गावाजवळील नाल्यामुळे पूर येतो आणि त्यामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भातील अंशतः पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने कार्यकारी अभियंता(लघुपाटबंधारे) नांदेड यांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. सर्वेक्षणासाठी निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुनर्वसन करण्याचा

.....२

ता.प्र.क्र.४०७६४.....

डॉ. राजेंद्र शिंगणे...

निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे. यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

श्री. अरविंद सावंत : सभापती महोदय, दलितवस्तीच्या पुनर्वसनाचा हा प्रश्न आहे. बिलोली शहराजवळ मातंग आणि दलित वस्ती आहे. या वस्तीचे पुनर्वसन करण्याचे १९९० साली ठरविण्यात आले होते. शहराच्या उत्तरेकडील १२२ आणि १२३ सर्वमधील जमीन यासाठी अधिग्रहित करण्यात आली. एकूण जमिनीपैकी ५ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी निवडण्यात आली. भूसंपादनाचा निवाडा १७.१०.१९९० रोजी झाला. आज आपण २००८ सालामध्ये आहोत तरीसुध्दा या लाभार्थीचे पुनर्वसन झालेले नाही. यासंदर्भात नायब तहसीलदार, तलाठी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता या जमिनीच्या वाटपामध्ये घोटाळा केल्याची तक्रार श्री. भीमराव लाखे यांनी पुनर्वसन आयुक्त श्री. दिलीप जामदार यांच्याकडे केली होती हे खरे आहे काय ? त्यांनी याप्रश्नासाठी जवळजवळ ३० ते ३५ वेळा उपोषण केले होते हे खरे आहे काय ? भूखंड वाटपामध्ये घोटाळा झाला आहे ही गोष्ट खरी आहे काय ? याबाबतीत चौकशी करून कारवाई कधी करण्यात येईल आणि पुनर्वसन किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल ?

डॉ. राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, मूळ प्रश्न विचारला होता तो कासराळी येथील पुनर्वसनाच्या संदर्भात आहे. साठेनगर आणि आंबेडकरनगर हा बिलोली शहराजवळील पुनर्वसनाचा भाग आहे. यासंदर्भात ही वस्तुस्थिती आहे की, १९९०-९१ मध्ये पुनर्वसनाचा निर्णय झाला होता. सन्माननीय सदस्य श्री. जेथलिया यांनी कासराळीच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. सन्माननीय सदस्य आता साठेनगर आणि आंबेडकरनगर या वस्तीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विचारीत आहेत. यासंदर्भात त्यांनी जी माहिती दिली ती वस्तुस्थिती आहे. १२२ आणि १२३ सर्व नंबरची जमीन पुनर्वसनासाठी निश्चित करण्यात आली. त्यातील ४० आर जमीन सोडून इतर जमीन संपादित केली. १८८ भूखंड पुनर्वसनासाठी तयार केलेले आहेत. त्यावर नागरी सुविधा पूर्ण आहेत किंवा अपूर्ण आहेत याची आता माझ्याकडे माहिती नाही. नागरी सुविधा अपूर्ण असतील तर त्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले जातील. भीमराव लाखे यांनी यासंदर्भात उपोषण केले होते ही गोष्ट माहीत आहे. किती वेळा केले याची माहिती नाही. परंतु अनेक वेळा उपोषण केले होते. त्यांनी केलेल्या

.....३

ता.प्र.क्र. ४०७६४....

डॉ. राजेंद्र शिंगणे...

उपोषणाच्या संदर्भात आणि तक्रारीच्या संदर्भात चौकशी केलेली आहे. भूखंड वाटपात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. गरजू लोकांना गरजेप्रमाणे भूखंड वाटप केलेले आहे.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, माननीय मंत्रीमहोदयांनी मान्य केले की, श्री. भीमराव लाखे यांनी अनेकदा उपोषण केले आहे. परंतु यामागची कारणमिमांसा सांगितली नाही. श्री. लाखे यांच्याकडून निवेदन प्राप्त झाले होते काय ? एकूण पुनर्वसनाचा कार्यक्रम केव्हा पूर्ण होईल ?

नंतर श्री. भोगले

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

AA.1

SGB/ KGS/ MMP/

13:00

ता.प्र.क्र.40764.....

डॉ.राजेंद्र शिंगणे : सभापती महोदय, श्री.भिमराव लाखे यांनी भूखंड वाटपामध्ये अनियमितता होती यासाठी उपोषण केले होते. 40 आर जमीन वगळून इतर जमीन संपादित केली त्या संदर्भात त्यांचा प्रश्न होता. 40 आर जमिनीमध्ये ज्यांची वडिलोपार्जित जमीन घेतली त्यांच्या आजोबांचा संबंध होता, ती जमीन वगळून इतर जमीन संपादित करावी अशी त्यांनी मागणी केली होती. शासनाने ती मागणी मान्य केली. त्याठिकाणी 188 भूखंडांचे वाटप केले आहे.

श्री.अरविंद सावंत : सभापती महोदय, सुरुवातीला 86 लाभार्थी होते, ती संख्या 260 पर्यंत कशी वाढत गेली?

डॉ.राजेंद्र शिंगणे : 188 भूखंडांचे वाटप केले आहे. लाभार्थीची संख्या आणि भूखंडांचे वाटप यामध्ये शासनाच्या माध्यमातून निश्चित मेळ घालण्यात येईल. या ठिकाणच्या जमिनीमध्ये भूखंड शिल्लक नसतील तर इतर ठिकाणी जमीन संपादित करून लाभार्थ्यांना भूखंड देण्यात येतील.

..2..

**बेलेवाडी (हु) (ता.आजरा, जि.कोल्हापूर) येथील पत संस्थेने
श्रीमती रामाणे यांची जमिन जबरदस्तीने घेतल्याबाबत**

- (८) * ३९३०८ श्री. विनोद तावडे , श्री. मधुकर चव्हाण , श्री. संजय केळकर , श्री. रामनाथ मोते , श्री. सव्यद पाशा पटेल : सन्माननीय सहकार मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-
- (१) कोल्हापूरातील आजरा तालुक्यातील बेलेवाडी (हु) गावात राहणाऱ्या लक्ष्मी दत्तु रामाणे यांनी १९९५ साली चंद्रोदय पतसंस्थेकडून ५००० रु.इतके कर्ज घेतले, हे खरे आहे काय,
- (२) असल्यास, कर्ज फेडता न आल्याने २००१ साली या पत संस्थेने पाठविलेल्या नोटीसीमध्ये १७,२२८ रु.इतकी रक्कम व्याजासह दाखवण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, असल्यास, व्याजदरात काही अनियमितता असल्याचे लक्षात आल्याने लक्ष्मी रामाणे यांनी सदरहू रक्कम भरली नाही, हे ही खरे आहे काय,
- (३) असल्यास, सदरहू रक्कम भरली नसल्याने पत संस्थेने १,४८,०००/- रु. कर्ज झाल्याचे सांगून ही रक्कम भरण्यास कर्जदार सक्षम नसल्याने सदर महिलेच्या पतीवर दबाव आणून जमिनीसंबंधी कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या व ही जमीन सावकार शिवाजी दत्त हातकर यांच्या नांवे केली, हे ही खरे आहे काय,
- (४) असल्यास, कर्ज फेडण्याची तयारी दाखवूनही या पतसंस्थेने कोणताही हिशोब न दाखवता सदर महिलेच्या सासऱ्याकडून जबरदस्तीने सह्या घेऊन १९ गुंठे जमीन ताब्यात घेऊन त्यांना घराबाहेर काढल्याने सदर पतसंस्थेचे अधिकारी नारायण देसाई व सुरेश हातकर यांनी कर्जदारांना लुबाडणे थांबवावे व कर्जदारांना न्याय द्यावा यासाठी उत्तूरचे मंडळ अधिकारी व मा.उपमुख्य मंत्री यांच्याकडे निवेदने दिली आहेत, हे खरे आहे काय,
- (५) असल्यास, निवेदनाच्या अनुषंगाने पुढे कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री.जयप्रकाश दांडेगावकर, डॉ.पतंगराव कदम यांच्याकरिता : (१) होय.

- (२) नाही.
- (३) नाही.
- (४) होय. निवेदन दिलेले आहे.
- (५) निवेदनाच्या अनुषंगाने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, आजरा यांनी महिलेच्या कर्जखात्याची चौकशी केली असता, चौकशीत सदर महिलेच्या ४ कर्जखात्यांची पूर्ण परतफेड झाल्याचे निर्दर्शनास आलेले आहे.

श्री.विनोद तावडे : सभापती महोदय, ५ ते १० हजार रुपयांच्या कर्जासाठी जमीन बळकावण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. अशी तक्रार आल्यानंतर चौकशी होते व सारवासारव केली जाते. परंतु या संदर्भात शासन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार आहे का?

..३..

ता.प्र.क्र.३९३०८.....

श्री.जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, उत्तरात म्हटल्याप्रमाणे या महिलेने चारवेळा कर्ज घेतले होते. १९९६ साली पहिल्यांदा २३०० रुपये कर्ज घेतले, ते व्याजासहित परत केले. २०.९.९६ रोजी ५ हजार रुपये कर्ज घेतले ते परत केले. १९९८ मध्ये ५ हजार रुपये कर्ज घेतले ते परत केले. चौथ्या वेळी ७.२.२००० रोजी ५ हजार रुपये कर्ज घेतले ते कर्ज व्याजासहित परत केले. त्यामुळे जमीन खरेदी विक्री व कर्जाचा तसा काही संबंध नाही. जमीन खरेदीच्या संदर्भात वेगळी तक्रार असेल तर त्याची जरुर चौकशी करून कारवाई केली जाईल.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, प्रश्नामध्ये म्हटल्याप्रमाणे या महिलेने जमीन हड्डप केल्याच्या संदर्भात किंवा जबरदस्तीने घेतल्याच्या संदर्भात सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली का? निवेदनाच्या अनुषंगाने सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, आजरा यांनी कर्जखात्याची चौकशी केली असे उत्तरात म्हटले आहे. त्या निवेदनामध्ये अन्य तक्रारी होत्या त्याची चौकशी झाली आहे काय? असल्यास काय निष्पन्न झाले? या महिलेने चारवेळा कर्ज घेतले व त्याची परतफेड देखील केली असे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले. चारवेळा घेतलेल्या कर्जावर पतसंस्थेने एकूण किती व्याज वसूल केले?

श्री.जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, तक्रार माननीय उपमुख्यमंत्र्यांकडे केलेली नसून सहकारमंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांच्याकडे २९.९.२००७ रोजी प्राप्त झाली होती, त्या अनुषंगाने चौकशी केली. तक्रार अशी होती की, १७०० रुपयांचे कर्ज १.४८ लाख झाल्याचे म्हटले होते. त्या अनुषंगाने चौकशी करून मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे चारवेळा कर्ज घेतले व ते सर्व परतफेड केले. पहिल्यांदा २३०० रुपयांचे कर्ज घेतले त्यावर १७४ रुपये व्याज भरले. २०.९.९६ ला ५ हजार रुपये कर्ज घेतले होते त्यावर १३१७ रुपये व्याज भरले. तिसऱ्या वेळी ५ हजार रुपये कर्ज घेतले त्यावर १९८२ रुपये व्याज भरले आणि चौथ्या वेळी ७.२.२००० रोजी ५ हजार रुपये कर्ज घेतले त्या कर्जाची परतफेड २६.१०.०४ रोजी केली त्या कर्जावर ६४८३ रुपये व्याज आकारले आहे. अशा पद्धतीने व्याजाची आकारणी केली गेली आहे.

(नंतर श्री.खर्च....)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

BB-1

PFK/KT/SBT

पूर्वी श्री. भोगले.....

13:05

ता. प्र. क्र. 39308.....

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर....

आणि जमिनीच्या वेगळ्या तक्रारी असल्या तर मी सांगितल्याप्रमाणे यासंबंधीची चौकशी करण्यात येईल.

सभापती : सहकार विभागाशी संबंधित सहाय्यक निबंधकांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी केली व त्यानुसार किती कर्ज धेतले व त्यावर व्याज किती लागले असे त्यांनी सांगितले. परंतु आपल्या म्हणण्याप्रमाणे महसूल विभागाशी संबंधित जी बाब आहे त्याबाबत महसूल विभागाला चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल, असे मंत्री महोदय म्हणाले.

.....2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

BB-2

PFK/KT/SBT

पूर्वी श्री. भोगले.....

13:05

गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील बुरुड कामगारांना

वनविभागाने बांबू पुरविणे बंद केल्याबाबत

(9) * 41213 श्री. पांडुरंग फुंडकर , श्री. नितीन गडकरी , श्री. केशवराव मानकर , श्री. गोपीकिसन बाजोरिया , डॉ. दीपक सावंत : सन्माननीय वने मंत्री पुढील गोष्टीचा खुलासा करतील काय :-

(1) गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील बुरुड कामगारांना वनविभागाने बांबू पुरविणे सध्या बंद केले त्यामुळे हजारो बुरुड कामगारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, एका बुरुड कामगाराला वनविभागाच्या आगारातून प्रकरणनिहाय अंदाजे 200 तसेच 1500 बांबू पुरविण्याचे शासनाचे आदेश असताना गेल्या काही महिन्यापासून बांबू मिळणे बंद इत्यामुळे उदरनिर्वाह चालविण्याकरीता चोरटचा मार्गाने बांबू तोडून त्यापासून वस्तु बनविण्याचे प्रमाण या भागात अलिकडे वाढले आहे हे ही खरे आहे काय,

(3) असल्यास, गोंदिया जिल्ह्यात 50 हजाराहून अधिक बुरुड कामगार असतांना शासन दरबारी फक्त 522 बुरुड कामगारांची शासन दरबारी नोंद आहे हे ही खरे आहे काय,

(4) असल्यास, या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती काय आहे व या प्रकरणी शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?

श्री. बबनराव पाचपुते : (1) हे खरे नाही.

(2) हे खरे नाही.

(3) हे खरे नाही.

(4) बुरुड कामास उपयोगी ठरणारा शक्य तितका अधिकाधिक बांबू गोंदिया व भंडारा मधील बुरुडांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, जवळपास 50 हजार बुरुड कामगारांचा हा प्रश्न आहे. गोंदिया जिल्ह्यात अर्जुनी-मोरगाव, अर्जुनी, सडक-अर्जुनी अशा अनेक तालुक्यात बुरुड लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात व बांबूपासून वेगवेगळ्या वस्तू म्हणजेच चट्या, सुप, टोपल्या, अशा अनेक गृहोपयोगी वस्तू बनविण्याचे काम ते करतात. म्हणून माझा प्रश्न आहे की, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये एकूण बुरुडांची संख्या किती आहे ? तसेच शासन दरबारी त्याची नोंद आहे काय ? या कामगारांच्या किती संस्था रजिस्टर्ड झालेल्या आहेत व बांबू न मिळाल्यामुळे बंद पडलेल्या संस्था किती आहेत ?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी माहिती दिल्याप्रमाणे या दोन जिल्ह्यात अनेक बांबू कामगार आहेत, पण मर्यादित लोकांची नोंद झालेली आहे. विशेषत: नागपूर, वर्धा, गोंदिया आणि भंडारा या तीन चार जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 109, 130, 3522 आणि 710 अशी एकूण 4473 बुरुडांची संख्या असल्याची नोंद आहे. या नोंद झालेल्या बुरुडांना प्रत्येकाला बांबू देण्यात यावेत अशी मागणी आहे. त्यानुसार बांबू पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून यावर्षी सुध्दा त्यांना बांबू पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

BB-3

ता. प्र. क्र. 41213.....

श्री. पांडुरंग फुंडकर : महोदय, बुरुडांच्या किती संस्था रजिस्टर्ड झाल्या ? बांबू न मिळाल्यामुळे ज्या संस्था बंद पडल्या त्यांची संख्या किती ? असा प्रश्न मी विचारला आहे, त्याचे उत्तर मंत्री महोदय देतील काय ?

श्री. बबनराव पाचपुते : महोदय, बुरुडांच्या संस्था रजिस्टर्ड करण्याचा अधिकार वन विभागाला नाही तर बुरुडांची संख्या आपण नोंद केलेली आहे व ती संख्या 4473 एवढी आहे आणि त्यांना बांबू पुरविण्याची व्यवस्था देखील आपण केली आहे.

श्री. नितीन गडकरी : महोदय, मुळात या जिल्ह्यांमध्ये बांबूपासून चटया व इतर गृहोपयोगी वस्तू बनविणाऱ्या बुरुड कारागिरांची संख्या खूप मोठी आहे. एकीकडे मंत्री महोदय सांगतात की, बुरुडांच्या संस्था रजिस्टर्ड करण्याचे आमचे काम नाही. दुसरीकडे या बुरुडांचा उदरनिर्वाह ज्या धंद्यावर चालतो त्यासाठी त्यांना बांबू बाहेरुन जास्त भावाने खरेदी करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून या बुरुडांची संख्या आपण काऊंट करून त्यांना आपलेच वनौपज असलेला बांबू पुरविला तर त्यातून अनेक लोकांना रोजगार मिळतो म्हणून या लोकांची नावे शोधून काढावीत म्हणून प्रत्येकाला 2500 बांबू कसे देता येतील यादृष्टीने शासनाने धोरण आखावे. शेवटी हे वन खात्याचे उपज आहे, अधिकारी सांगतील त्यांच्यावर संपूर्णपणे विश्वास न ठेवता बुरुडांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना शासनामार्फत कमी दरात बांबू पुरविला जाईल काय ?

यानंतर श्री. जुन्नरे

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

CC-1

SGJ/ SBT/ KTG/

प्रथम श्री. खर्च.....

13:10

ता.प्र.क्र. : 41213

श्री. नितीन गडकरी

दुसरा प्रश्न असा आहे की, बल्लारपूर पेपर मिलवर आपल्या नेत्यांचे जास्त प्रेम असल्यामुळे या ठिकाणी फार मोठया प्रमाणात बांबू पुरवला जातो. आता मंत्री नसलेल्या एका माजी मंत्र्यांने पर राज्यात 6 कोटी रुपयांचे बांबू दिलेले आहेत. गडचिरोली मध्ये सुध्दा मोठया प्रमाणात बांबू पुरवला जातो. परंतु बुरुडांना जेव्हा बांबू देण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांना बांबूचा दर जास्त लावला जातो त्यामुळे बुरुडांना स्वस्त दरात बांबू उपलब्ध करून दिले जातील काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, बुरुडांना स्वस्त दराने बांबू पुरवण्याच्या संदर्भात विभागाने प्रस्ताव दिला होता कि सेल टॅक्स आणि व्हॅट कमी करावे परंतु या प्रस्तावांना एफ.डी.ने मान्यता दिली नाही त्यामुळे खास बाब म्हणून माननीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून बुरुडांना स्वस्त दरात बांबू मिळेल यासाठी प्रयत्न केला जाईल. बांबूपासून वस्तू बनवणारे, कामगार, कलाकार यांना बांबू द्यावयाचे झाले तर त्यांना 67 लाख बांबूची आवश्यकता पडेल. मागच्या वर्षी बांबूचे उत्पादन कमी झाले होते यावर्षी साधारण 15 लक्ष बांबूचे उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे. भंडारामध्ये 2007-2008 मध्ये 710 लोकांपैकी 568 लोकांना व गोंदियामध्ये 3500 पैकी 645 लोकांना बांबू देण्यात आले आहेत तसेच कारागिरांना बांबू देण्याचे काम सुरु असून या कारागिरांना ओल्या बांबूची आवश्यकता असते. 70-80 कि.मी. लांब अंतरावरून नक्षलग्रस्त भागातून हा बांबू आणावा लागतो. बांबू तोडण्याचे काम हे त्या ठिकाणच्या आदिवासी लोकांना द्यावे लागते. तसेच हा बांबू 12 से.मी. च्या खाली असेल तर तो त्यांना दिला जात नाही. या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांनी चीनचा उल्लेख केलेला आहे. केंद्रीय शिष्टमंडळ बांबूच्या संदर्भात चीनला भेट देण्यासाठी गेले होते व शिष्टमंडळाबरोबर मी सुध्दा गेलो होतो. या वर्षी केंद्रशासनाने आपल्याला बांबूसाठी 12 कोटी रुपये दिलेले आहेत. बांबूचे काम करणा-या संरथेच्या संदर्भात दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांची मिटिंग घेऊन बांबू पॅलिसी तयार केली जाईल.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मी प्रश्न विचारला होता की, बुरुडांची संख्या किती आहे? नोंदणीकृत बुरुड लोकांच्या संस्था किती आहेत, तसेच बांबूचा उद्योग जवळपास 50 हजार लोक करीत असतात त्यामुळे यासंदर्भात माननीय मंत्री महोदय माहिती देतील काय ?

...2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

CC-2

ता.प्र.क्र. : 41213

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, बुरुडाचा व्यवसाय करणा-यांची संख्या बरीच आहे परंतु वन खात्यामध्ये बुरुडांची रजिस्ट्रेशन केलेली संख्या 4473 आहे .चीनमध्ये 1100 एकरावर बांबू लावण्यात आलेला आहे. बांबूच्या संदर्भात 15,16,17 रोजी दिल्लीमध्ये सेमिनार आहे. आपण सुध्दा या सेमिनारला आलात तर चांगले होईल. त्यामुळे बुरुडांना बांबू जास्तीत जास्त स्वस्त किंमतीत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच बांबूच्या संशोधनाचे काम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतलेले आहे.

श्री. मधुकर सरपोतदार : सभापती महोदय, वन मंत्र्यांनी वन संवर्धनाच्या बाबतीत माहिती दिली असून बांबूवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही असेही त्यांनी सांगितलेले आहे, बुरुडांची संख्या व बुरुडांच्या संस्था किती आहेत असे विचारले असता त्याचीही त्यांनी माहिती दिलेली नाही. जे प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारले आहेत त्या प्रश्नांना माननीय मंत्रीमहोदयांनी उत्तरे न देता अनावश्यक माहिती दिलेली आहे. बुरुडांना बांबूची आवश्यकता असतांना त्यांना बांबू उपलब्ध करून दिले जात नाहीत परंतु दुस-या राज्यात मात्र बांबू पाठवायला यांच्याकडे बांबू शिल्लक असतात. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की, बांबू विक्रीच्या संदर्भात नियम करून ज्या संस्था रजिस्टर्ड आहेत अशाच संस्थातील लोकांना बांबू दिला जाईल यासंदर्भात शासन निर्णय घेणार आहे काय?

यानंतर श्री. गायकवाड....

ता.प्र.क्र.41213...

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, तशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या बुरुडांची नोंद करण्यात आलेली आहे त्यांनाच बांबू देण्यात येतो. त्यांना ओला बांबू लागतो. त्यामुळे जंगलातून काढण्यात आलेला सगळाच बांबू त्यांना दिला जात नाही. त्यांना ओला बांबू देऊन उर्वरित बांबू लिलावात विकावा लागतो. महाराष्ट्रातील बुरुडांची संख्या किती आहे असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्याबाबतीत मी सांगू इच्छितो की, ज्यांचे रजिस्ट्रेशन झालेले आहे त्यांचीच नावे शासनाकडे आहेत. त्यांचे नाव रजिस्टर्ड करण्याचा अधिकार आमचा नाही.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : बांबू न दिल्यामुळे 40 बुरुड काम करणा-या संस्था बंद पडल्या आहेत हे खरे आहे काय ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी असा प्रश्न विचारला आहे की राज्यात बुरुडांची संख्या किती आहे. त्याबाबतीत मी त्यांना सांगू इच्छितो की राज्यामध्ये भरपूर बुरुड आहेत परंतु ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेले नाही त्यांच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. वन विभागाचा त्यांच्याशी संबंध येत नाही. ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेले आहे त्यांना स्वरूप आणि चांगला बांबू देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीला 1500 बांबू द्यावयाचे असतात त्याप्रमाणे ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेले आहे त्यांना डेपोवर बांबू देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. चार पाच वर्षांपासून हे काम केले जात आहे. संस्था रजिस्टर्ड करणे हे शासनाचे काम नाही तो विषय शासनाकडे येत नाही.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : बांबू न दिल्यामुळे 40 संस्था बंद पडल्या आहेत हे खरे आहे काय

सभापती : सन्माननीय वन मंत्र्यांना मी सांगू इच्छितो की, बांबूच्या संदर्भात वन विभागाचे जे काही धोरण आहे ते आपण येथे सांगितलेले आहे. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांचा प्रश्न असा आहे की, बांबूचे काम करणाऱ्या ज्या 40 सहकारी संस्था आहेत तेव्हा त्यांना वेगळ्या प्रकारची ट्रिटमेन्ट दिली जाणार आहे काय ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, या बाबतीत मी मघाशीच सांगितले आहे की दोन्ही बाजूच्यामंडळी बरोबर एकत्र बसून स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य श्री.नितीन गडकरी यांची एक सहकारी संस्था असून तेथे उत्तम प्रकारे बांबूच्या वस्तू तयार केल्या जात आहेत. या सगळ्या संस्थांच्या बाबतीत एकत्र बसून निर्णय घेण्यास शासन तयार आहे.

ता.प्र.क्र.41213...

श्री.जैनुदीन जव्हेरी : सभापती महोदय, आमच्या विभागामध्ये खास करून गडचिरोली विभागातील ओला बांबू आपल्या मंत्र्यांनी पर राज्यात नेऊन विकला होता यासंबंधी ॲडिट होऊन चौकशी करण्यात आली होती. परंतु अजूनही मंत्री महोदय हे पैसे भरत नाहीत तेव्हा त्यांच्या विरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, हा विषय या प्रश्नाशी संबंधित नाही त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांना वेगळा प्रश्न विचारावा लागेल.

श्री.नितीन गडकरी :या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे.

(एकाच वेळी अनेक सन्माननीय सदस्य प्रश्न विचारतात)

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला प्रश्न मूळ प्रश्नाशी संबंधित नाही. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे असा अनेक सन्माननीय सदस्यांचा आग्रह आहे व त्याचे उत्तर माझ्याकडे आहे.त्यामुळे मी त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास तयार आहे.... या संस्थेला बांबू देण्याचे ॲग्रिमेन्ट रद्द करण्यात आलेले आहे. ॲग्रिमेन्ट रद्द करण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेलेले आहे तेथे ही केस सुरु आहे त्यामुळे त्या संदर्भातील जास्त माहिती देता येणार नाही.

(विरोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन घोषणा देतात)

श्री.पांडुरंग फुडकर : सभापती महोदय, या विषयाला न्याय न मिळाल्यामुळे आम्ही सभात्याग करतो .

(विरोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्यांनी सभात्याग केला)

सभापती :प्रश्नोत्तराचा तास संपला आहे.

3..

पु.शी : लेखी उत्तरे

मु.शी:: अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 14 ते 24
सभागृहासमोर ठेवणे

विशेष कार्य अधिकारी : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तराची
यादी क्रमांक 14 ते 24 सभागृहासमोर ठेवतो.

सभापती : अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 14 ते 24 सभागृहासमोर ठेवण्यात आली
आहे.

(प्रेस : येथे सोबत जोडलेली यादी छापावी)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

DD 4

VTG/ KTG/ SBT/

पृ.शी.मु.शी. अंदाज समितीचा अहवाल सादर करणे

श्रीमती मंदा म्हात्रे (समिती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अंदाज समितीचा सोळवा अहवाल सभागृहाला सादर करते. अहवाल सादर करीत असतांना मी सदर अहवालातील महत्वाच्या बाबीचा येथे उल्लेख करु इच्छिते.

सभापती महोदय, पुणे जिल्हयातील पुरंदर किल्ला हे संभाजी महाराजाचे जन्मस्थळ असल्यामुळे या किल्ल्याचे संवर्धन करून विकास करण्यासाठी केलेली आर्थिक तरतूद याबाबत अभ्यास करून समितीने हा अहवाल तयार केला आहे.

सभापती महोदय, पुरंदर किल्ल्याचा - " पर्यटन स्थळ" म्हणून विकास करण्यासाठी तेथे रस्ते, पाणी, शौचालये, वीज इत्यादी प्राथमिक सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या पाहिजेत असे समितीचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात आवश्यक ती सर्व कार्यवाही संबंधित विभागांनी करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

सभापती महोदय, पुरंदर किल्ल्याच्या विकासाची व सवर्गाची कामे करतांना ती बांधा - वापरा व हस्तांतरित करा (BOT) या तत्वावर कामे करण्यास हरकत नाही. गरज असल्यास तेथे टोल घेण्याचा देखील विचार करावयास हरकत नाही. या माध्यमातून पुरंदर किल्ला पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती कारबाई करावी अशीही समितीची शिफारस आहे.

सभापती महोदय, सद्यःस्थितीत या किल्ल्याचा काही भाग हा सेना दलाच्या ताब्यात असल्यामुळे संरक्षित स्मारक घोषित करण्याच्या संदर्भात अडचण निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग) तसा केन्द्र शासनाला या संदर्भात एक सविस्तर प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, माननीय वित्त मंत्रांनी या विकास कामासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबत घोषणा केली आहे या किल्ल्यावर पर्यटनाच्या दृष्टीने वीज, पाणी पुरवठा, पाणी साठवण व्यवस्था, शौचालय, विश्रांतीगृह व अनुषंगिक कामे पूर्ण करण्यासाठी इतकेच नव्हे तर माननीय पालक मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 30.5.2007 रोजी याबाबत झालेल्या आढावा बैठकीनुसार सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, ऊर्जा विभाग इत्यादी संबंधित विभागांना

आपापल्या कामांची अंदाजपत्रके देखील सादर केलेली आहेत. तेव्हा त्या त्या विभागाशी समन्वय साधून या कामाची विभागणी करण्यात यावी. त्याची जबाबदासरी त्या त्या विभागाला देण्यात यावी व त्यासाठी राज्य शासनाने (वित्त विभागाने) जास्तीत जास्त निधी या कामांसाठी मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करावी अशीही समितीची शिफारस आहे.

सभापती महोदय, पुरंदर किल्ल्यास " संरक्षित स्मारक " म्हणून घोषित करण्याबाबत अधिसूचना काढण्याच्या संदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांनी समिती समोर मान्य केले आहे तेव्हा ही अधिसूचना काढल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत वित्त विभागालाही काही अडचण निर्माण होणार नाही अशी समितीची धारणा आहे. तेव्हा विभागीय सचिवांनी समिती पुढे कबूल केल्याप्रमाणे या संदर्भातील अधिसूचना (नोटीफिकेशन) विना विलब काढावी आणि या किल्ल्याचे संवर्धन व जतन होण्याच्या दृष्टीने वर उल्लेख केलेल्या बाबीसंबंधी संबंधित सर्व विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी अशी समितीची आग्रहाची शिफारस आहे.

सभापती : अंदाज समितीचा सोळावा अहवाल सभागृहास सादर करण्यात आला आहे.

नंतर श्री.सुंबरे

पृ.शी./मु.शी. : उपविधान समितीचा अहवाल सादर करणे.

श्री. केशवराव मानकर (समिती सदस्य) : महोदय, मी आपल्या अनुमतीने उपविधान समितीचा चौथा अहवाल सभागृहाला सादर करीत आहे. या अहवालात समितीने 48 अंतिम अधिसूचना व 17 प्रारूप अधिसूचना विचारात घेतल्या. तसेच गृह विभाग, महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेच्या संदर्भात विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्यात आली. उपविधान समितीकडे अधिसूचना विचारार्थ पाठविण्यास बच्याचदा विभागास 1 वर्ष, 2 वर्ष एवढा प्रदीर्घ विलंब लागतो. उपविधान समिती ही महत्त्वाची समिती असल्याने अधिसूचना निर्गमित झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत समितीकडे वेळेत पाठविणे आवश्यक आहे. अधिसूचना विलंबाने पाठविण्याबाबत जे अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार आहेत त्यांच्या विरुद्ध कार्यवाही करण्यात यावी अशी शिफारस समितीने अहवालात केली आहे.

सभापती : उपविधान समितीचा अहवाल सभागृहास सादर झाला आहे.

पृ.शी./मु.शी. : महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा अहवाल सादर करणे.

डॉ. नीलम गोळे (समिती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा तेरावा अहवाल सभागृहास सादर करीत आहे. हा अहवाल सादर करीत असताना मला आपल्या निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, समितीने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेतील महिला अधिकारी/कर्मचारी यांची भरती, आरक्षण, अनुशेष व पदोन्नती तसेच महानगरपालिकेटर्फे त्यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना, तसेच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांचे लैंगिक छळ होत असल्याच्या आलेल्या तक्रारी आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालया अंतर्गत महिला पोलीस विशेष सुरक्षा कक्ष याबाबत समितीने 21 जुलै 2006 रोजीच्या बैठक घेतली आणि 17 ऑगस्ट 2006 रोजी प्रत्यक्ष जाऊन भेट दिली आणि आपल्या तेराव्या अहवालात त्या संबंधात काही शिफारशी केल्या आहेत. सभापती महोदय, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेच्या 600 कोटी रुपये तरतुदीपैकी 50 टक्के खर्च आस्थापनेवर वजा जाता शिल्लक 300 कोटीपैकी 5 टक्के निधी म्हणजे महिला व

..... इइ 2 ...

डॉ. गोळे
 अस्त्रांगतपत्र

बाल कल्याणासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात मात्र त्याएवजी केवळ 65 लाख रुपयांची तरतूद नवी मुंबई महापालिकेतर्गत महिला व बाल कल्याणासाठी वापरली जात आहे. तेव्हा ही तरतूद वाढवावी अशी शिफारस समितीने आपल्या अहवालात केलेली आहे. त्याचबरोबर महिला बचत गटांनी ज्या वस्तू तयार केलेल्या आहेत त्या स्वतः नवी मुंबई महापालिकाच विकत घेत नाही ही बाब देखील समितीच्या निदर्शनास आली आहे. तसेच तेथे महिलांची अनेक पदे रिक्त आहेत. महिला लोकप्रतिनिधींसाठी नवी मुंबई महापालिकेमध्ये स्वतंत्र कक्ष देखील नाही. तरी याबाबत ताबडतोब सुधारणा कराव्यात अशा प्रकारच्या शिफारशी समितीने अहवाल केलेल्या आहेत. सभापती महोदय, या कामासाठी समितीने गृह विभाग, नगरविकास विभाग, पणन विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग या विभागांच्या सचिवांच्या साक्षी देखील घेतल्या आहेत. सभापती महोदय, समितीच्या शिफारशीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाबत देखील समितीच्या असे निदर्शनास आलेले आहे की, तेथील 850 पैकी केवळ 97 महिला कर्मचारी आहेत व बाकी पदे रिक्त आहेत.

(यानंतर श्री. सरफरे2एफ 1 ..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

FF 1

DGS/ SBT/ KTG/

13:25

डॉ. नीलम गोहे...

ही पदे रिक्त आहेत, त्याचप्रमाणे कांदा बटाटा मार्केटमध्ये 20 वर्षापूर्वी जास्त काम करणाऱ्या असंघटीत महिला आहेत त्यांना संरक्षण मिळत नाही. त्यांच्यावर अत्याचार होणाऱ्या अनेक घटना घडतात. म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कंत्राटी पृष्ठीने काम करणाऱ्या महिला कामगारांवर लैगिक अत्याचार झाल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी माथाडी कोड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी परस्परांमध्ये समन्वय ठेवून पोलिसांकडून या महिलांना संरक्षण व सहाय्य मिळाले पाहिजे अशी शिफारस केली आहे. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महिला सहाय्य कक्ष उभारण्यात आला आहे, परंतु त्याचा लाभ तिथे काम करणाऱ्या महिला घेत नाहीत. त्याकरिता राज्याच्या पोलीस दलाच्या सहभागासह नाशिक पोलीस आयुक्तालयाच्या धर्तीवर महिला सुरक्षा विशेष कक्ष उभारण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. धन्यवाद.

सभापती : महिलांचे हक्क व कल्याण समितीचा तेरावा अहवाल सादर झाला आहे.

DGS/ SBT/ KTG/

पृ.शी./मु.शी.: अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा सहावा अहवाल सादर करणे

श्री. प्रकाश शेंडगे (समिती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा सहावा अहवाल सादर करतो.

असे करीत असतांना या अहवालातील काही महत्वाच्या शिफारशी सभागृहाच्या माहितीकरिता सांगू इच्छितो. समितीने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील रिक्त पदे भरण्याबाबत शिफारस केली आहे. या महामंडळाच्या वतीने मागासवर्गीयांच्या विकासाकरिता निरनिराळ्या योजना राबविण्यात येतात. परंतु एकंदरीत लाभार्थ्यांची संख्या पहाता या योजना कागदावरच रहात असल्याचे दिसून येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महामंडळाकडे कार्यरत असलेल्या सर्व योजनांना व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नसल्यामुळे मागासवर्गीयांना या योजनांची माहिती मिळत नाही व ते त्यांचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता महामंडळाकडे कार्यरत असलेल्या सर्व योजनांच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी सविस्तर व सर्वसमावेशक माहिती पुरितका तयार करण्यात यावी. व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजनांची माहिती जाण्याच्या दृष्टीने प्रसिद्धी माध्यमामार्फत वितरीत करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावरून महामंडळाच्या योजनांची माहिती केबल वाहिनीवरून प्रसिद्ध करण्यात यावी. महामंडळाच्या योजनांविषयी वेबसाईट तयार करण्यात यावी व इतर अनेक प्रकारे राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आर्थिक सहाय्य योजनांना व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी. जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात मागासवर्गीयांचे वस्ती मेळावे गावोगावी आयोजित करून योजनांची माहिती द्यावी अशी शिफारस केली आहे.

सभापती महोदय, महामंडळाकडे प्रचंड निधी उपलब्ध असतांना तो कां वापरला गेला नाही, अशी समितीने साक्षीच्या वेळी विचारणा केली असता लाभार्थी मिळत नाहीत असे समितीला सांगण्यात आले. परंतु लाभार्थी मिळत नाही असे म्हणणे समितीला बरोबर वाटत नाही. आणि त्यामुळे महामंडळातील अधिकाऱ्यांची उदासीन वृत्ती दिसून येते. महामंडळाकडे कार्यरत असलेल्या सर्व योजनांना व्यापक प्रसिद्धी दिली जात नसल्यामुळे मागासवर्गीयांना या योजनांची माहिती मिळत नाही व ते त्यांचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकत नाहीत. तसेच महामंडळ प्रचारामध्ये कुठे तरी कमी पडते असे समितीला वाटते.

सभापती : अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा सहावा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

पृ.शी./मु.शी.: विधानपरिषद आश्वासन समितीचा एकशे चव्हेचाळीसावा अहवाल
सादर करणे

श्री. चंद्रकांत रघुवंशी (समिती प्रमुख) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानपरिषद आश्वासन समितीचा एकशे चव्हेचाळीसावा अहवाल सभागृहाला सादर करीत आहे.

असे करीत असतांना मी आपल्या अनुमतीने या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधतो. वेतनेतर अनुदान न देण्याबाबत शासनाने घेऊन शाळांना वेतनेतर अनुदान पुनर्विचारार्थ दिलेली टिप्पणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारात घेऊन शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासनाने लवकरात लवकर पुनर्विचार करावा, अशी शिफारस केलेली आहे. नंदूरबार तालुक्यात "जवाहर विहिरी योजनेतर्गत झालेला भ्रष्टाचार" या विषयाबाबत समितीने शिफारस केली आहे की, आयुक्त स्तरावरून आलेला अहवाल तपासून दोषी लोकांवर तात्काळ दोषारोपपत्र दाखल करण्यात यावे, तसेच ज्यांनी गैरप्रकार केलेले आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे आणि जे अपात्र लाभार्थी आहेत त्यांच्याकडून तात्काळ वसुली करण्यात यावी. "पवना धरणाखालील बुडीत 17 गावांच्या पुनर्वसनाबाबत" या विषयाबाबत समितीने शिफारस केली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे बुडीत क्षेत्राच्या वरची एक-एक एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याबाबतचा पुनर्वसन विभागाने जलसंधारण विभागाकडे पाठविलेला पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांबाबतचा प्रस्ताव जलसंधारण विभागाने त्वरीत स्वीकारून त्याबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर समितीस सादर करावा. व पवना धरणाखालील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा. तारापूर प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्याबाबत" या विषयाबाबत समितीने शिफारस केली आहे की, तारापूर येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून जेवढी जमीन घेतली आहे, तेवढी जमीन त्यांना देण्याबाबतीत सीमांकन केले असेल तर ज्या 276 प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे भरलेले आहेत त्यंचे सीमांकन अगोदर करून त्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. त्यांना जमिनींचे वाटप केल्यानंतर ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे भरलेले नाहीत ते त्यातून प्रेरणा घेतील आणि पैसे भरतील.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

GG-1

APR/ SBT/ KTG/

पूर्वी श्री.सरफरे

13:30

श्री.चंद्रकांत रघुवंशी

76 प्रकल्पग्रस्तांनी पैसे भरले नाहीत म्हणून ज्या लोकांनी पैसे भरले आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये. म्हणून यामध्ये दुरुस्ती करून 276 प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या रकमा भरल्या आहेत, त्यांना लवकरात लवकर भूखंड दिले जातील यादृष्टीने शासनाने कारवाई करावी.

समितीने फेब्रुवारी 2008 अखेर पावेतो झालेल्या बैठकींमध्ये सन 2005 च्या दुसऱ्या अधिवेशनातील आश्वासनांबाबत शासनाकडे केलेलया कार्यवाही बाबतच्या प्राप्त झालेल्या माहितीच्या विवरणांच्या छाननीचे काम पूर्ण केले आहे.

या अहवालात सन 2000 चे पहिले अधिवेशन ते सन 2004 च्या पाचव्या अधिवेशनातील आश्वासनांवर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची छाननी करून त्याबाबतच्या त्रुटी विशेष अभिप्राय म्हणून या अहवालात नमूद केलेल्या आहेत.

सभापती : विधानपरिषद आश्वासन समितीचा एकशे-चव्वेचाळीसावा अहवाल सभागृहाला सादर झाला आहे.

. . . . 2 जी-2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

GG-2

पू.शी./मु.शी.: नियम 93 अन्वये सूचना.

सभापती : सन्माननीय सदस्य सर्वश्री गोपीकिशन बाजोरिया, सुरेश जेथलिया, किशनचंद तनवाणी यांनी "सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अकोला महानगरपालिकेने कोणतेही शिक्षक न नेमता रु.10,000 प्रति शिक्षक प्रमाणे रु.10 लाख आपल्या खात्यातून काढणे, स्थानिक आमदार समितीत असताना त्यांना डावलण्यात येणे, शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी असलेला 20 लाख रुपयांचा निधी अन्यत्र वळविणे." या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, जगदीश गुज्जा यांनी "चेंबूर, मुंबई येथील मूलचंद झवेरचंदवाडी या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या बेचर भिका मकवाना या वृद्ध दलित व्यक्तिची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या वादातून श्री.ललित धारमानी या विकासकाने व त्यांच्या साथीदारांनी केलेली हत्या"या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मला एक बाब आपल्या निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे की, मी पंतप्रधान सडक योजनेच्या संदर्भात नियम 93 अन्वये सूचना दिली होती. परंतु मागच्या शुक्रवारी या विषयाच्या संदर्भातील निवेदन पुढे ढकलण्यात आले होते. परंतु आजही त्या विषयाच्या संदर्भातील निवेदन आलेले नाही.

सभापती : या विषयाच्या संदर्भातील निवेदन आज देण्यात आले असेल.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, या विषयाच्या संदर्भातील निवेदन आजही देण्यात आलेले नाही.

सभापती : जर या विषयाच्या संबंधातील निवेदन आज देण्यात आले नसेल तर ते उद्या होईल.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री जयंत प्र.पाटील, शरद पाटील, रामनाथ मोते यांनी "मुंबईला दूध पुरवठा करणाऱ्या टँकरमध्ये साखर, सोडा, तेल इ.पदार्थांची करण्यात आलेली भेसळ, सदर भेसळयुक्त टँकर महानंदा संरथेने दिनांक 8 एप्रिल 2008 रोजी परत पाठविणे, जनतेला भेसळयुक्त दूध पुरविण्यात येत असल्याबद्दल जनतेत निर्माण झालेले संतापाचे वातावरण." या

. . . 2 जी-3

सभापती . . .

विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री श्रीकांत जोशी, पाशा पटेल, नितीन गडकरी, पांडुरंग फुंडकर यांनी "श्री संत नामदेव महाराज यांचे जन्मगाव नरसी नामदेव जि.हिंगोली यास शासनाने तीर्थक्षेत्राचा "ब" दर्जा नाकारणे, येत्या ऑक्टोबरमध्ये नांदेड येथे गुरु-ता-गद्दी या कार्यक्रमासाठी लाखो शीख भाविक येणार असून संत नामदेवांचे पंजाबमधील कार्य पहाता हे सर्व भाविक त्यांच्या जन्मगावी भेट देण्याची शक्यता असल्याने तेथे सोयी-सुविधा पुरविण्याची आवश्यकता." या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री रामनाथ मोते, संजय केळकर, प्रतापराव सोनवणे, श्रीकांत जोशी यांनी "उल्हासनगर येथील डॉ.बाबासाहेब शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे जेवण मिळत असून जेवणात किडे, अळ्या आढळून येणे तसेच विद्यार्थ्यांना इतर सोयी-सुविधा नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाकडे तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली न जाणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री पाशा पटेल, नितीन गडकरी, श्रीकांत जोशी यांनी "सोमनाथ बोरगाव, जि.बीड येथील शेतकरी श्री.उग्रसेन शकर किर्दत यांनी भगवानदास भंसाळी या सावकाराकडून सन 2002 मध्ये 42 हजार रुपयांचे कर्ज घेणे, सदर रकमेपोटी सावकाराने 2 लाख रुपयांची व्याजासह मागणी करणे, यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या करण्याचा दिलेला इशारा" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री प्रतापराव सोनवणे, रामनाथ मोते, संजय केळकर, श्रीकांत जोशी यांनी "खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून 16 रुपये 50 पैसे प्रति हजारी लिटर पाण्याचे बिल वसूल केले जात असून

. . . 2 जी-4

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

GG-4

APR/ SBT/ KTG/

13:30

सभापती . . .

घरगुती वापरासाठी हाच दर 7 रुपये 50 पैसे असल्याने यात भेदभाव होऊन शैक्षणिक संस्थांवर होत असलेला अन्याय" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री नितीन गडकरी, संजय केळकर, विनोद तावडे, मधुकर चव्हाण यांनी "मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मंजूर विकास योजनांतर्गत बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वावर सर्वे नं.75 पार्ट मिरा गांव या आरक्षित जागेवर स्मशान भूमी, जॉर्गस पार्क इ.उभारण्यासाठी मेसर्स असिता कन्स्ट्रक्शन कंपनीला महापालिकेने निविदा न काढता 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देणे व गैरव्यवहार करणे." या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर कु.गायकवाड

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

HH 1

DVG/ SBT/ KTG/

ग्रथम श्रीमती रणदिवे..

13:35

सभापती...

यानंतर सन्माननीय सदस्य डॉ. नीलम गोळे, यांनी "विदर्भीतील मेळधाट तालुका कुपोषणग्रस्त भाग असून या भागात आदिवासी मजुरांना रोजगार हमीची कामे न मिळणे, त्यामुळे हजारो कुटुंबे कामासाठी इतरत्र स्थलांतर करित असणे " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र याबाबत शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी " राज्य शासनामार्फत मतदार याद्यांचे पुनर्सर्वेक्षण हेत असताना या पुनर्सर्वेक्षणात मुंबईतील अनेक लोकांची नावे नसणे, फोटो काढण्याचा दुसरा हप्ता अजूनही न होणे, व इतर अनेक त्रुटी आढळून येणे " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र याबाबत शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री गुरुमुख जागवानी, विनोद तावडे, मधुकर चव्हाण, संजय केळकर, यांनी " दिनांक 9 एप्रिल, 2008 रोजी रायगड जिल्हयातील मानगाव परिसरातील बिगर मौसमी पाऊस पडल्याने बागायतदार घ वीट भट्टी उत्पादकांचे तसेच शेतकऱ्याच्या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणे. " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र याबाबत शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री विनोद तावडे, मधुकर चव्हाण, रामनाथ मोते, संजय केळकर, यांनी " पनवेल मधील बल्लाळेश्वर उर्फ वडाळे तळ्याकडील पूर्वकडील 30 एकर जागा दिनांक 22 जानेवारी, 1912 मध्ये तत्कालीन मामलेदारांनी सदाशिव हरी बापट यांना कबूलायतेद्वारे देणे, 1950 मध्ये या मालमत्तेवर बेकायदा नावे दाखल करून ती आजही कायम असणे, या मालमत्तेस बिनशेती परवानगी देण्यात येणे, सदर जमीन विक्री करताना कबूलायतीच्या नियमांचा भंग झाल्यामुळे शासनाचे सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकासन " या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र याबाबत शासनाने निवेदन करावे. इतर सूचनांना मी दालनातच अनुमती नाकारलेली आहे.

..2..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

HH 2

DVG/ SBT/ KTG/

13:35

पृ. शी. : नागपूर येथील प्रस्तावित रिंगरोडच्या बाह्य सीमेपासून 5 किमीच्या अंतर्गत असलेल्या गावठाणापासून 750 मी. सीमेपर्यंत रहिवाशांचा विकास होण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता.

मु. शी. : नागपूर येथील प्रस्तावित रिंगरोडच्या बाह्य सीमेपासून 5 किमीच्या अंतर्गत असलेल्या गावठाणापासून 750 मी. सीमेपर्यंत रहिवाशांचा विकास होण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता याबाबत सर्वश्री. नितीन गडकरी, विनोद तावडे, पांडुरंग फुंडकर, मधुकर चव्हाण, वि.प.स. यांनी नियम 93 अन्वये दिलेली सूचना.

श्री. राजेश टोपे (नगर विकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सर्वश्री. नितीन गडकरी, विनोद तावडे, पांडुरंग फुंडकर, मधुकर चव्हाण यांनी "नागपूर येथील प्रस्तावित रिंगरोडच्या बाह्य सीमेपासून 5 किमीच्या अंतर्गत असलेल्या गावठाणापासून 750 मी. सीमेपर्यंत रहिवाशांचा विकास होण्याकरिता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्ष्ण, आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

..3..

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, नागपूर प्रादेशिक विकास योजनेमध्ये 60 मिटर रुंदीच्या प्रस्तावित रिंगरोडच्या बाह्य सीमेपासून 5 किमीच्या अंतर्गत असलेल्या गावांच्या गावठाणापासून 750 मी. सीमेपर्यंत रहिवासाचा विकास होण्याकरिता परवानगी देण्यात यावी असे नमूद आहे. शासनाने जी तरतूद केलेली आहे त्या संदर्भात हे अधिवेशन संपण्याच्या आत शासनाकडून नोटीफिकेशन काढण्यात येईल काय ? तसेच या रिंगरोडच्या जवळपास जी गावे आहेत ती गावे पुन्हा एकदा मोजून घेतली जाणार आहेत काय ? 200 मिटर परिसरात ग्रोथ सेंटर तयार करण्याची तरतूद आहे. यासंदर्भात सरसकट रिंगरोडचे नियम लावून मान्यता देणार आहे काय ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांनी येथे 3 प्रश्न विचारलेले आहेत. रिजनल प्लान 2000 साली मंजूर करण्यात आलेला आहे. या बाबत 15/3/2008 रोजी एक क्लॅरिफिकेशन शासनाकडे विचारण्यात आला होते. त्यावेळी समितीने रिजनल प्लान रिंगरोड असे क्लॅरिफिकेशन दिले. या रिंगरोडला एक्सप्रेस हायवे व एक्सप्रेस वे अशी नावे देऊन मंजुरी देण्यात आली. याबाबत क्लॅरिफिकेशन विचारण्यात आले होते. शासनाकडून हे क्लॅरिफिकेशन 15 दिवसाच्या आतमध्ये पाठविण्यात येईल.

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, जे उपसंचालक क्लॅरिफिकेशन देतात त्यांचे तर खरोखर कौतुकव केले पाहिजे. एक्सप्रेस हायवे हे नाव आणण्याचे काहीच कारण नाही. येथे कशाकरिता शब्दच्छल करण्यात येत आहे. रिंगरोड करिता तरतूद करण्यात आलेली आहे.

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, येथे कोणताही शब्दच्छल मी करीत नाही. ज्यांना अडवण आली होती त्यांनी शासनाकडे क्लॅरिफिकेशन विचारले होते. तसेच हे क्लॅरिफिकेशन किती दिवसात दिले जाईल असे सन्माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांनी विचारले होते. रिजनल प्लानिंगच्या संदर्भात 15 दिवसात क्लॅरिफिकेशन दिले जाईल असे उत्तर मी दिलेले आहे.

यानंतर श्री. बरवड..

श्री. राजेश टोपे

जेणेकरुन रींगरोडपासून 5 किलोमीटर पर्यंतच्या बाह्य भागामध्ये गावठाणापासून 750 मीटर पर्यंत रेसिडेंशियल अनुज्ञेय होऊ शकणार आहे. सन्माननीय सदस्यांनी दुसरा प्रश्न त्या ठिकाणी गावांच्या संख्येमध्ये छोटामोठा बदल होऊ शकणार आहे त्यासंदर्भात विचारलेला आहे. मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की, शासनाने रिजनल प्लॅन मंजूर करीत असताना थोडीफार अलाईन्मेंट चेंज झालेली आहे. अलाईन्मेंट चेंज झाल्यामुळे रींगरोडपासून बाह्य बाजूने 5 किलोमीटरपर्यंत काही प्रमाणात गावांमध्ये बदल झालेला आहे. त्यासंदर्भात एमआरटीपी ॲक्टप्रमाणे सेवक्षण 20 ची कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असते. त्यासंदर्भातील निर्णय सुध्दा ताबडतोबीने घेतला जाईल. गावांमध्ये जो बदल होईल तो बदल ताबडतोबीने करुन त्यासंदर्भातील फायनल नोटिफिकेशन लवकर काढण्यात येईल.

श्री. नितीन गडकरी : लवकर म्हणजे हे अधिवेशन संपूर्णाच्या आधी नोटिफिकेशन काढणार काय ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, पंधरा दिवसात क्लॅरिफिकेशन करू असे मी सांगितले आहे तसेच पंधरा दिवसात गावांच्या बदलाच्या बाबतीत सेवक्षण 20 च्या अनुषंगाने जी वैधानिक कार्यवाही सुरु करावयाची आहे ती ताबडतोबीने सुरु करणे शक्य आहे. सन्माननीय सदस्यांनी रींगरोडच्या बाबतीत जो नियम आहे तो इतर ग्रोथ सेंटरच्या गावठाणाला लागू करावा याबाबत प्रश्न विचारलेला आहे. शेवटी जे ग्रोथ सेंटर असते त्यामध्ये रेसिडेंशियल भाग अगोदरपासूनच प्लॅनमध्ये घेतलेला असतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रेसिडेंशियल एरिया असल्यामुळे त्या गावठाणामध्ये 200 मीटरचा नियम असतो. त्यामुळे ग्रोथ सेंटरची जी गावठाणे आहेत त्या ठिकाणी सगळीकडे 750 मीटरचा नियम लागू करणे योग्य ठरणार नाही. प्लॅनिंगच्या दृष्टीने ते योग्य असू शकणार नाही.

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, रींग रोडच्या पलीकडे वस्त्या वाढविण्याकरिता परवानगी देत आहेत आणि ग्रोथ सेंटरमध्ये असलेल्या गावठाणांना 200 मीटरचा कायदा लागू करतो. त्या ठिकाणी आपण रिलीफ देत नाही. वर्धा रोडवर रेसिडेंशियल एरियाच होत आहे.

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, रींग रोडच्या आत जो भाग आहे तो सेक्टर प्लॅनमध्ये आहे. ज्यावेळी ग्रोथ सेंटरचे प्लॅनिंग करतो त्यावेळी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रेसिडेंशियल एरिया गृहीत धरलेला आहे. हा रेसिडेंशियल एरिया कमी पडला तर त्यामध्ये वाढ करता यावी यादृष्टीने नियोजन पाहिजे. त्यामुळे गावठाणाच्या बाबतीत 200 मीटरपर्यंत परवानगी दिलेली आहे. रींग रोडच्या आतील जो भाग आहे तो नागपूर शहराचा जो सेक्टर प्लॅन आणि नॉन सेक्टर प्लॅन करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर रेसिडेंशियल एरिया गृहीत धरलेला आहे. त्यामुळे ग्रोथ सेंटरमध्ये असलेली जी गावठाणे आहेत त्यासाठी 200 मीटरची अट आहे.

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, रींग रोडमध्ये ज्या गावांना फायदा होतो त्या ठिकाणी ही तरतूद माहीत नव्हती. ही तरतूद आपण समोर आणलेली आहे. हे आधी माहीत असते तर रेकॉर्डवर आले असते. ते माहीत नव्हते म्हणून ते रेकॉर्डवर आले नव्हते. या भागामध्ये काही ग्रोथ सेंटर रींग रोडच्या मर्यादेमध्ये येणारे आहेत. यामध्ये रिपिटेशन आहे. रींग रोडच्या सीमेत येणाऱ्या ग्रोथ सेंटरमध्ये दोन्ही तरतुदी लागू आहेत. त्यांना ग्रोथ सेंटरऐवजी रींग रोडचा नियम लागू करावा. जे कायदेशीर आहे ते करावे.

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, कदाचित हा सभागृहातील चर्चेचा भाग नाही. हा तांत्रिक भाग आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांच्याबरोबर बसून यासंदर्भात चर्चा करून निश्चितपणे उचित निर्णय लवकर घेण्यात येईल.

...3...

पृ. शी. : बंदी असतानाही कंपन्यांकडून मँग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त गुटख्याचे उत्पादन सुरु असणे

मु. शी. : बंदी असतानाही कंपन्यांकडून मँग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त गुटख्याचे उत्पादन सुरु असणे याबाबत सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, जगदीश गुप्ता, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना

श्री. बाबा सिद्धीकी (अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, जगदीश गुप्ता यांनी "बंदी असतानाही कंपन्यांकडून मँग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त गुटख्याचे उत्पादन सुरु असणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस ; येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...4 ...

श्री. पांडुरंग फुळकर : सभापती महोदय, निवेदनातील परिच्छेद क्रमांक 2 मध्ये थोडी विसंगती आहे. या परिच्छेदामध्ये असे म्हटले आहे की, अन्न व औषध प्रशासनाने मँग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त गुटख्याच्या उत्पादन, विक्री व साठचावर बंदी घातलेली नाही. तथापि, अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार अन्न पदार्थात मँग्नेशियम कार्बोनेट हे धटकद्रव्य वापरण्यास प्रतिबंध आहे.

यानंतर श्री. खंदारे....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

JJ-1

NTK/ SBT/ KTG/

श्री.बरवडनंतर

13:45

श्री.पांडुरंग फुंडकर....

त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासनाने गुटखा या पदार्थात मँग्नेशियम कार्बोनेट या घटकाबाबत गुटख्याची तपासणी करण्यात यावी, अशा गुटख्याचे नमुने घेऊन त्यात मँग्नेशियम कार्बोनेट आढळून आल्यास साठा जप्त करावा, तसेच गुटखा उत्पादकाने उत्पादनाचे लेबल अन्न व औषध प्रशासनाकडून मान्य करून घ्यावे असे आदेश काढले होते." हे आदेश केव्हा काढण्यात आले होते ? पुढे असे म्हटले आहे की, " या आदेशास राज्यातील गुटखा व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच मँग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त गुटख्यावरही राज्यात बंदी नाही." एकीकडे अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार मँग्नेशियम कार्बोनेट घालू नये. ते शरीराला हानीकारक आहे, त्याच्यातून रोग होतो. त्यामुळे राज्यात बंदी असताना त्याला हायकोर्टने स्थगिती केव्हा दिली आणि अंतरिम आदेश केव्हा दिले ? तसेच ज्या 18 उत्पादकांवर खटले दाखल केलेले आहेत त्या उत्पादकांची नावे काय आहेत ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, 23 जुलाई, 2002 को पूरे महाराष्ट्र में गुटखा उत्पादन पर बॅन लगाया गया था. यह टेक्नीकल मामला हो गया था क्योंकि गुटखा उत्पादन पर बॅन लगाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं था. उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने सम्माननीय सदस्य का सम्मान रखने के लिए एवम् अदालत के निर्णय का सम्मान रखने के लिए पी.एफ. एक्ट के तहत कार्रवाही की थी. सरकार द्वारा गुटखा उत्पादन पर बॅन लगाने के बाद 20.12.2005 को मुंबई उच्च न्यायालय की ओरंगाबाद खंड पीठ ने सरकार के आदेश को अंतरिम स्थगिती दी थी. उसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय में 27.03.2006 को सिविल अप्लिकेशन दाखिल की गई थी जो पेंडिंग है. क्योंकि राज्य सरकार गुटखा उत्पादन को बॅन नहीं कर सकती थी लेकिन अन्न भेसळ प्रतिबंधक कानून के प्रावधान के अनुसार अन्न पदार्थ में मँग्नेशियम कार्बोनेट इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंध है इसलिए राज्य सरकार ने इस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. इसलिए हमने बॅन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था. पी.एफ. एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसके अन्तर्गत स्टे नहीं है. उसके बाद केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार नियम 44 जे के तहत मुंबई उच्च न्यायालय में 17.01.2008 को रिट पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर उच्च न्यायालय ने 28.02.2008 को अंतरिम आदेश दिया.

...2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

JJ-2

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, हायकोर्टने अंतरिम आदेशात काय म्हटले आहे ?

Shri Baba Siddiqui :In the interim Order it is stated that you cannot ban Gutkha because it is under Central Act.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : गुटखा बंद करण्यासंबंधी मी प्रश्न विचारलेला नाही. आपल्या राज्यात अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणत्याही पदार्थामध्ये मँग्नेशियम कार्बोनेट टाकता येत नाही. हायकोर्टने गुटखा बंद करू नका असा आदेश दिला आहे काय ? बॅन करू नका असा हायकोर्टने आदेश दिला आहे काय ?

श्री.नितीन गडकरी : सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी गुटख्यावर बंदी घालावी असे म्हटलेले नाही. परंतु त्यामध्ये मँग्नेशियम कार्बोनेट हा पदार्थ टाकला जातो, तो आरोग्याला धोकादायक आहे. हा पदार्थ अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायद्यामध्ये येत आहे. त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करून तो धोकायदाक असल्यामुळे त्याच्यावर बंदी का आणत नाही ? गुटख्यावर बंदी आणणे ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीत आहे, त्यात आपण जाऊ नका. मँग्नेशियम कार्बोनेट गुटख्यात घातले जात आहे ते फूड अॅण्ड ड्रग्ने तपासल्यानंतर जर माणसाच्या प्रकृतीला अपायकारक असेल तर ते घालण्यावर का बंदी केली नाही किंवा बंदी करणार आहात काय ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, उच्च न्यायालय ने 'बॅन' शब्द इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंध किया है. लेकिन कानून के तहत सरकार की कार्रवाई चालू है. अब तक 4042 मुकदमें दर्ज किए गए हैं. जिन 18 उत्पादकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं, मेसर्स कोठारी प्रॉडक्ट्स, संकेत फुड प्राडक्ट्स, घोडावत इंडस्ट्री प्रा.लि. इत्यादि.

नंतर श्री.शिगम

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

KK-1

MSS/ SBT/ KTG/

पूर्वी श्री. खंदारे

13:50

श्री. नितीन गडकरी : सेंट्रल लिस्ट, कन्करण्ट लिस्ट आणि स्टेट लिस्ट अशा तीन लिस्ट आहेत. फूड अॅण्ड ड्रगज डिपार्टमेंट राज्य शासनाचे आहे. त्या गुटख्यामध्ये मँगेशियम कॉर्बनेट हा पदार्थ आहे. उद्या त्यामध्ये शेण टाकलेले असेल तर त्या बाबतीत शासन कारवाई करणार नाही काय ? गुटख्याच्या प्रॉडक्टवर महाराष्ट्र सरकारला बंदी घालता येणार नाही असे जजमेंट हायकोर्टने दिलेले आहे. परंतु ज्या पदार्थामध्ये भेसळ आहे त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करून तो पदार्थ आरोग्यास धोकादायक असेल तर त्याबाबतीत कारवाई करण्याचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला आहेत.

Shri Baba Siddiqui : We cannot use the word "Ban"....Prosecution is going on....

Shri Nitin Gadkari : We just want to say that you take the sample and send it to the Laboratory and if magnesium Carbonate is found in it, you ban it.

Shri Baba Siddiqui : We have done 73 prosecutions. We have lodged 15 FIRs.

सभापती : अन्न व औषध प्रशासनाने या बाबतीत प्रॉसिक्युशन केलेले आहे. मंत्रांना आपले उत्तर पूर्ण करू द्यावे.

Shri Baba Siddiqui : Hon. Chairman, Sir, we have done prosecution in 73 cases and we have lodged 15 FIRs.

श्री. नितीन गडकरी : गुटख्याचे सॅम्पल घेतले, रिपोर्ट प्राप्त झाला, खटले दाखल केले, परंतु त्यांचे प्रॉडक्ट बनविण्याचे काम सुरु आहे. ज्या कंपनीचे प्रॉडक्ट इंज्युरिअस टु हेत्थ आहे त्या कंपनीला सील का लावत नाही ? भेसळयुक्त उत्पादन का थांबवत नाही ?

श्री बाबा सिद्धीकी : एक तरफ कहा जा रहा है कि बैन शब्द का प्रयोग मत कीजिए और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई करिए. हम तो कार्रवाई कर रहे हैं. सरकार ने 73 प्रासीक्यूशन और 15 एफआयआर मालिकों के खिलाफ दाखिल की है.

.....2

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

KK-2

MSS/ SBT/ KTG/

पूर्वी श्री. खंदारे

13:50

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सन्माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितल्या प्रमाणे खटले भरून प्रश्न सुटणार नाहीत., गुटख्यामध्ये मँगनेशियम कार्बोनेटची भेसळ करू नये हा आमचा मूळ प्रश्न हा आहे. हायकोर्टने दिलेल्या स्थिरी विषयी आमचे काहीही म्हणणे नाही. मँगनेशियम कार्बोनेटची भेसळ करणा-या कारखान्यांवर आपण बंदी घालणार आहात काय ?

Shri Baba Siddiqui : There is not a single manufacturing Unit in Maharashtra. Formerly, there was one Manufacturing Unit but the manufacturer has stopped his activities. All the products are coming from out of Maharashtra. अगर सम्माननीय सदस्य सहयोग करें तो हम कुछ कर सकते हैं. गुजरात में उत्पादन हो रहा है, मध्यप्रदेश में उत्पादन हो रहा है.

श्री. नितीन गडकरी : इतर राज्यातील विष असणारे उत्पादन आपल्या राज्यात विकले जात असेल तर फुड एंड ड्रग एक्टप्रमाणे विक्री थांबविणार काय ?

श्री बाबा सिद्धीकी : यह टेक्नीकल मुद्दा है. मैं इस सदन में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी. संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, एफआयआर दायर करेगी. इस मामले में जितने भी होलसेलर, रिटेलर संबंधित हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और मुख्य आदमी तक भी पहुंच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यानंतर श्री गिते

पॉइंट ऑफ इनफर्मेशनसंबंधी

डॉ.वसंत पवार : सभापती महोदय, म.वि.प.नियम 93 अन्वये सन्माननीय सदस्यांकडून ज्या सूचना देण्यात येतात, त्यातील कोणत्या सूचना स्वीकारावयाचा यासंबंधी आपल्याला अधिकार आहेत. नियम क्रमांक 94 त्यातील (1) मध्ये असे म्हटले आहे की, एकाच बैठकीत अशा प्रकारचे एकाहून अधिक प्रस्ताव मांडता येणार नाहीत. मला आपल्याकडून एवढीच माहिती हवी आहे की, एका सन्माननीय सदस्याला एकाच बैठकीमध्ये दोन प्रस्ताव मांडता येतात काय ? हा अँकडमिक विषय आहे.

सभापती : सन्माननीय सदस्य नियम 93 च्या सूचना देतात, त्या अनुषंगाने शासनाने निवेदन करावे असा निर्णय दिला तर त्यासंबंधीची निवेदने सभागृहात होत असतात. त्या निवेदनावर फक्त एक, दोन प्रश्न सन्माननीय सदस्यांना विचारता येतात. यासंबंधी सभागृहात पूर्वी चर्चा झाली होती आणि त्यावेळी देखील म.पि.स.93 च्या निवेदनावर फक्त एक किंवा दोन प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारावेत असा निर्णय दिला होता.

डॉ. वसंत पवार : एकाच सदस्याचे दोन प्रस्ताव आहेत तर ते प्रस्ताव एकाच दिवशी मांडता येतात काय ? आत्ताच सन्माननीय सदस्य श्री. गडकरी साहेबांच्या एका निवेदनावर चर्चा झाली आणि दुसरे निवेदन देखील त्यांचेच आहे.

श्री. विनोद तावडे : सन्माननीय सदस्य डॉ. वसंत पवार म्हणत आहेत त्यात तथ्य एवढेच आहे की, नियम 93 ची सूचना सादर करताना एक असली पाहिजे. शासनाचे मंत्री वेळेवर उत्तरे देत नाहीत म्हणून एकाच दिवशी दोन-तीन निवेदनांवर चर्चा घ्यावी लागते.

श्री. सतीश चतुर्वेदी : सभापती महोदय, मंत्री महोदय वेळेवर उत्तरे देत नाहीत म्हणून निवेदने जमा होतात असे सन्माननीय सदस्यांचे म्हणणे आहे ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. नियम 93 च्या सूचना मान्य करण्याचे अधिकार आपणाला आहेत. नियम 93 च्या अनुषंगाने आपणाकडून निवेदन करण्याचे निदेश दिले जातात, निवेदने वितरीत करून त्या अनुषंगाने मंत्री महोदय उत्तरे देत असतात.

2...

श्री. मधुकर सरपोतदार : सभापती महोदय, मला या नियमासंबंधी बोलावयाचे आहे. या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य डॉ. वसंत पवार यांनी नियम क्रमांक 93 आणि नियम 94 संबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नियम 93 प्रमाणे जो प्रस्ताव देण्यात येतो, तो प्रस्ताव चर्चेला घेतला तर एका सदस्याला एका पेक्षा जास्त विषय चर्चेला घेता येत नाहीत. सन्माननीय सदस्यांची नियम 93 ची निवेदने घ्यावयाची आणि त्यावर पीठासीन अधिका-यांनी निवेदन करण्याचे निदेश दिल्यानंतर त्या निवेदनाचे वितरण सभागृहात झाल्यावर त्यावर सन्माननीय सदस्यांना एक किंवा दोन प्रश्न विचारता येतात अशी सध्या पध्दत आपण सुरु केली आहे. त्या निवेदनांवर सविस्तर चर्चा होत नाही. सन्माननीय सदस्य डॉ.वसंत पवार यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे तो या ठिकाणी लागू होत नाही.

श्री. सतीश चतुर्वेदी : सभापती महोदय, विधान परिषदेमध्ये नियम 93 च्या अनुषंगाने जी निवेदने वितरीत होतात, त्यावर लक्षवेधी सूचनेपेक्षा जास्त प्रश्न विचारले जातात. विधानसभेत निवेदनांवर प्रश्नोत्तरे होत नाहीत. या ठिकाणी वितरीत करण्यात आलेल्या निवेदनावर माननीय मंत्र्यांना अर्धा अर्धा तास उत्तरे घावी लागतात. नियम 93 च्या निवेदनासंदर्भात उत्तरे देण्यासाठी आम्हाला सभागृहात उपस्थित रहावे लागते.

अॅड. गुरुनाथ कुलकर्णी : सन्माननीय सदस्य डॉ.वसंत पवार यांनी थोडा वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नियम 93 अन्वये वितरित केलेल्या निवेदनावर सन्माननीय सदस्यांकडून एक, दोन प्रश्न विचारले पाहिजेत असा त्यांचा मुद्दा नाही. सभापती महोदय, नियम 93 ची सूचना आपणाकडे दाखल झाल्यानंतर, त्यासंदर्भात आपण शासनास निवेदन करण्याचे निर्देश देता. त्यानंतर विभागाकडून नियम 93 ची निवेदने सभागृहात वितरीत केली जातात आणि त्यावर सन्माननीय सदस्य एक, दोन प्रश्न विचारीत असतात. परंतु नियम 94 असे म्हणतो की, एकाच बैठकीत अशा प्रकारचे एकाहून अधिक प्रस्ताव मांडता येणार नाहीत. त्याचे म्हणणे असे आहे की, एका सन्माननीय सदस्यांच्या नियम 93 च्या सूचनेवर चर्चा झाल्या नंतर त्यांच्या दुस-या निवेदनावर सभागृहात चर्चा होता कामा नये.

यानंतर श्री. कानडे....

प्रा.बी.टी.देशमुख : सभापती महोदय, नियम 93 अन्वये घेण्यात येणाऱ्या निवेदनासंदर्भात याठिकाणी चर्चा चालू आहे. निकडीचा विषय 93 च्या माध्यमातून मांडण्यासाठी सन्माननीय सदस्य प्रस्ताव देतात. त्यावर जर चर्चा मान्य केली तर त्याला 94 चा नियम लागतो. परंतु 93 ची सूचना नाकारण्यात आली किंवा निवेदन करावयाला सांगितले तर निवेदन हा काही प्रस्ताव होत नाही. मंत्रीमहोदयांनी त्यावर प्रश्नोत्तरे किती होतात हे सांगितले तो भाग वेगळा. निवेदनावरील प्रश्नाच्या संदर्भात माननीय सभापतींनी अनेक वेळा सदनात सांगितले आहे की यावर 1/2 प्रश्न विचारले जातील. एखादा महत्वाचा विषय असेल तर माननीय सभापतींच्या अनुमतीने 1 किंवा 2 प्रश्न जास्त विचारले जाऊ शकतात. सन्माननीय सदस्य डॉ. वसंतराव पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रस्ताव चर्चेसाठी मान्य झाल्यानंतर एका वेळी एका सदस्याचे दोन प्रस्ताव होणार नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ आहे. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, नियम 93 अन्वये प्रस्तावावर चर्चा मान्य करणे हा वेगळा विषय आहे. एका सदस्याचे दोन प्रस्ताव 93 च्या चर्चेच्या माध्यमातून मान्य झाले नाहीत आणि निवेदन करा असे निदेश दिले तर त्याला तो नियम लागू होत नाही.

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, आम्ही सचिवांकडे एक तास आधी प्रस्ताव दाखल करतो. ते याठिकाणी वाचून दाखविले जातात. प्रस्ताव मंजूर करून सभागृहात चर्चेला परवानगी दिली जाते त्याच्याकरिता नियम लागू नाही. माझी 93 ची दोन निवेदने सदनात आली. माझे एक निवेदन दोन वेळा सभागृहात आले. एकदा मंत्रीमहोदयांनी अडचण सांगितली म्हणून येऊ शकले नाही. परवा एका निवेदनावर मंत्रीमहोदयांनी सांगिते की नंतर घ्या. आम्ही नेहमीच को-ऑपरेशन करीत असतो. कधी कधी ओव्हरलॅपिंग होते. दररोज नियम 93 ची किती निवेदने चर्चेला घ्यावीत हा माननीय सभापतींचा अधिकार आहे. लक्षवेधी, 93 ची निवेदने, अर्धा-तास चर्चा याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार माननीय सभापतींचा आहे. कोणतेही कामकाज नियमबाह्य नाही. प्रस्ताव मान्य करून त्यावर चर्चा झाली तर गोष्ट वेगळी आहे. निवेदनावर किती प्रश्न विचारण्यास परवानगी घ्यावी हा माननीय सभापतींचा अधिकार आहे. आम्ही विरोधी पक्षात असताना निवेदनावर चर्चेसाठी आग्रह घरीत होतो. मंत्री असताना किती निवेदने करायची आता आटपते घ्या असे म्हणत होतो. खुर्चीची ही भूमिका आहे. आम्ही ती दोन्ही बाजूंनी वटविली आहे. प्रा. देशमुख आयुष्यभर विरोधी पक्षात असल्यामुळे अधिक खोलात जाऊ नये. माननीय सभापतींचा अधिकार आहे त्याप्रमाणे कामकाज चालू घ्या.

.....2

ॐ. गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे माननीय सभापतींना व्यापक अधिकार आहेत हे मान्य आहे. त्याठिकाणी व्यापक अधिकार असले तरी नियम 289 अन्वये जी चर्चा आहे ती चर्चा रेझ करू शकत नाही. ती चर्चा प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून घ्यावयाची किंवा नाही हा पूर्ण अधिकार माननीय सभापतीचा आहे. हे अधिकार असताना नियम 93 आणि नियम 94 कशा पध्दतीने.....

श्री. नितीन गडकरी : सभापती महोदय, सभागृहाच्या कामकाजाचा अजेंडा मी ठरविला नाही. माझी 93 नियमाखालील 10/20 निवेदने पेंडींग आहेत. 15 दिवसापूर्वी दिलेली निवेदने आहेत.

नंतर श्री. भोगले

प्रा.बी.टी.देशमुख : सभापती महोदय, गोंधळ होऊ नये म्हणून मी या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करतो. नियम 93 हा मुळात नव्हता. तो स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेला पर्याय म्हणून याठिकाणी आला. त्याच्या सायटेशनमध्ये 'हे सभागृह तीव्र चिंता व्यक्त करीत आहे' असे आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर तो व्होटेबल मोशन आहे. एखाद्या सूचनेबाबत माननीय सभापती नियम 93 चा प्रस्ताव मान्य करतात आणि त्यावर चर्चा घेण्यास अनुमती देतात. काही बाबतीत असा निर्णय होतो की, हा नियम 93 चा विषय होत नाही, परंतु शासनाने यावर निवेदन करावे. तीन प्रकारे माननीय सभापती निर्णय घेतात. नियम 93 चा विषय होत नाही. हा नियम 93 चा विषय होत नसला तरी शासनाने निवेदन करावे. नियम 94 हा व्होटेबल मोशनला लागू आहे. निवेदनाला तो लागू होत नाही एवढेच मला निर्दर्शनास आणावयाचे आहे.

सभापती : सन्माननीय सदस्य डॉ.वसंत पवार यांनी ज्या पध्दतीने नियम 93 व नियम 94 च्या अनुषंगाने याठिकाणी पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा मांडला, सुदैवाने दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी मला निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने योय पध्दतीने यावर आपली मते मांडली आहेत. नियम 93 अन्वये निकडीच्या सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीवर चर्चा उपस्थित करू इच्छिणारा सदस्य नियोजित प्रस्तावाचे लेखी निवेदन विधानपरिषदेच्या ज्या बैठकीत चर्चा उपस्थित करण्याचे त्याने योजिले असेल त्या बैठकीच्या सुरुवातीपूर्वी निदान एक तास अगोदर सचिवांच्या स्वाधीन करील आणि विधानपरिषदेच्या बैठकीस सुरुवात होण्यापूर्वी नियोजित प्रस्तावास सभापतींची संमती मिळवील. जर प्रस्ताव चर्चेला येणार असेल, सभापतींची संमती मिळाल्यानंतर सभापती त्यांना अनुमती देतील आणि मग तो प्रस्ताव मांडला जाईल. याठिकाणी नियम 93 अन्वये माझ्याकडे सूचना येतात, त्यापैकी अनेक सूचनांना मी माझ्या दालनात अनुमती नाकारतो. काही सूचना अशा असतात की त्यावर निवेदन केले गेले तर सार्वजनिक प्रयोजनाच्या दृष्टीने सूचनेत मांडलेले मुद्दे आहेत त्यावर शासनाच्या माध्यमातून रप्षीकरण होईल, या अनुषंगाने मी निवेदन करण्याबाबत निदेश देत असतो. यापूर्वीही मी सांगितले, आजही सांगतो की, ज्यांनी नियम 93 अन्वये सूचना मांडल्या आणि त्यावर निवेदन करावयास सांगितले, अशा निवेदनावर एक किंवा दोन प्रश्नामध्येच माननीय सदस्यांनी मुद्दा मांडला पाहिजे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जर एखादा तिसरा प्रश्न

..2..

सभापती.....

विचारला तर त्यांचा मान राखणे हे माझे काम आहे आणि सदनाचे देखील ते काम आहे. यादृष्टीने एखादा अपवाद वगळता इतर निवेदनांवर एक किंवा दोन प्रश्न झाल्यानंतर पुढील निवेदन विचारात घेतले जाते. मी माझे रुलिंग दिलेले आहे.

डॉ.वसंत पवार : नियम 94 च्या संदर्भात काय झाले?

सभापती : सन्माननीय सदस्य डॉ.वसंत पवारसाहेब, मी मघाशी नियम 93 अन्वये प्राप्त झालेल्या 12 सूचना वाचून दाखविल्या. या सर्व सूचना मान्य केल्या असे म्हटले नाही. फक्त प्राप्त झालेल्या सूचना वाचून त्यावर शासनाने निवेदन करावे ही ॲक्षन घेतली. एखादा अपवाद म्हणून अशी सूचना मान्य झाली तर नियम 94 अन्वये प्रस्ताव चर्चेला घेतला जातो. तो व्होटेबल मोशन राहतो.

डॉ.वसंत पवार : आज 93 च्या सूचनेवरील निवेदने आहेत, अशी निवेदने एकाच बैठकीत एका सदस्याबाबत किती मांडता येतील हा माझा मुद्दा आहे.

श्री.नितीन गडकरी : या अधिवेशनात अद्याप नियम 93 अन्वये मांडलेल्या सूचनेवरील एकही प्रस्ताव चर्चेला आलेला नाही. सगळ्या सूचना अमान्य केलेल्या आहेत. फक्त शासनाने निवेदन करावे असे म्हटले गेले आहे. व्होटेबल प्रस्ताव असतो तो वेगळा असतो. तो नियम याठिकाणी लागू होत नाही. ही फक्त निवेदने आहेत.

(नंतर श्री.खर्च....)

पृ. श्री. : सेवाखंड हजेरी सहायकांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत

मु. श्री. : सेवाखंड हजेरी सहायकांना नोकरीत सामावून घेणे याबाबत सर्वश्री नितीन गडकरी, विनोद तावडे, पांडुरंग फुंडकर, केशवराव मानकर, श्रीकांत जोशी, गुरुमुख जागवानी, जगदीश गुप्ता वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री.हर्षवर्धन पाटील (रोजगार हमी योजनामंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सर्वश्री नितीन गडकरी, विनोद तावडे, पांडुरंग फुंडकर, केशवराव मानकर, श्रीकांत जोशी, गुरुमुख जागवानी, जगदीश गुप्ता यांनी "सेवाखंड हजेरी सहायकांना नोकरीत सामावून घेणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

OO-2

PFK/ KGS/ MMP/

पूर्वी श्री. भोगले.....

14:10

श्री. नितीन गडकरी : महोदय, नागपूर उच्च न्यायालयाने गोंदिया येथील रोजगार हमी योजनेच्या कामावर असलेल्या हजेरी सहाय्यकांच्या बाबतीत दिनांक 15 जून, 2006 रोजी निर्णय दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी गोंदिया जिल्हापरिषदेला परिपत्रक क्र. अंकंपा 1003/प्र.क्र.59/2003/आठ, दि. 30 जानेवारी, 2004 नुसार कार्यवाही करण्याबाबत निदेश दिले आहेत. परंतु त्या आदेशांचे पालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोंदिया जिल्हा परिषद यांनी अद्यापही केले नाही त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाले. म्हणून या प्रकरणी त्वरित अंमलबजावणी करण्यासंबंधीचे आदेश शासन देणार काय ?

श्री. हर्षवर्धन पाटील : महोदय, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जो निर्णय दिला, त्या निर्णयाची प्रत माझ्याकडे नाही. परंतु तसे आदेश असतील तर निश्चितपणे त्यानुसार संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

श्री. नितीन गडकरी : महोदय, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर ती प्रत शासनाकडे आली आणि शासनाच्या सामान्य प्रशासनल विभागाने त्यावर अभ्यास करूनच उपरोक्त परिपत्रक काढले आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सी.ई.ओ. ना आदेश दिले. त्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात येणार काय ?

श्री. हर्षवर्धन पाटील : महोदय, उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि सुप्रीम कोर्टाचे आदेश अशा दोन गोष्टी यामध्ये आहेत. मूळ आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत.....

श्री. नितीन गडकरी : महोदय, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा येथे संबंध नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची छाननी केल्यानंतरच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सी.ई.ओ. ना आदेश दिलेले आहेत. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय शासनाने तपासलाच असेल. म्हणून मंत्री महोदयांनी फक्त सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार काय ?

श्री. हर्षवर्धन पाटील : महोदय, पहिल्या उत्तरातच मी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.

.....3

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

OO-3

पृ. शी. : राज्यातील विणकरांना सानुग्रह अनुदान मिळणे

मु. शी. : राज्यातील विणकरांना सानुग्रह अनुदान मिळणे याबाबत सर्वश्री नितीन गडकरी, पांडुरंग फुंडकर, मधुकर चव्हाण, विनोद तावडे, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. सतीश चतुर्वेदी (वस्त्रोद्योग मंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य सर्वश्री सर्वश्री नितीन गडकरी, पांडुरंग फुंडकर, मधुकर चव्हाण, विनोद तावडे यांनी "राज्यातील विणकरांना सानुग्रह अनुदान मिळणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

.....4

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

OO-4

PFK/ KGS/ MMP/

पूर्वी श्री. भोगले.....

14:10

श्री. नितीन गडकरी : माननीय सभापती महोदयांनी उदार अंतःकरणाने बैठक बोलावून त्या बैठकीसाठी माननीय वित्त मंत्री सुध्दा आले होते व त्यामुळे राज्यातील विणकरांना न्याय मिळाला, त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. सन 1998 च्या पूर्वीच्या विणकरांना आपल्याला फक्त 25 हजार रुपयेच द्यावयाचे आहेत, माननीय मंत्री महोदयांकडे ही रकम सेव्हिंगज आहे. म्हणून माझी विनंती आहे, सुप्रीम कोर्टने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेऊन सहानुभूतीने विचार करून या विणकरांना 25 हजार रुपयाचे सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय माननीय मंत्री महोदय घेणार काय ?

श्री. सतीश चतुर्वेदी : महोदय, सन 1998 मध्ये माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी हे मंत्री होते. त्यांनीच पुढाकार घेऊन चार हजार विणकरांना सानुग्रह अनुदान दिले होते, त्यापूर्वी ही योजना नव्हती. युती शासनाच्या काळात 8 हजार विणकरांपैकी एनरोलमेंटवर वयोमर्यादा टाकून 4 हजार विणकरांना 15 हजार सानुग्रह अनुदान दिले.

यानंतर श्री. जुन्नरे

श्री. सतीश चतुर्वेदी.....

तसेच 4 हजार लोकाना सानुग्रह अनुदान देण्याच्या संदर्भात मागणी केलेली आहे. सुरुवातीला काही लोकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते परंतु यासंदर्भात पुन्हा चर्चा करून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 25 हजार रुपयांची सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते व त्या प्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली. 1998 चे जे विणकर आहेत त्यांच्या संदर्भात दालनात झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने त्यांनाही राशी देण्यात आलेली आहे. ही राशी देत असतांना माननीय गडकरी साहेबांच्या उपस्थितीत चेकचे वाटप झालेले आहे. या सभागृहाच्या भावनांचा आदर करून शासनाने विणकरांना पैसे दिलेले आहेत. 1998 मधील आपण जो 8 हजाराचा आकडा दिला होता त्यांना पैशाचे वाटप करण्यात आलेले असून 300-400 लोकांच्या याद्या आल्या होत्या त्यांना पैसे देण्यात आलेले आहेत. ज्या लोकांचे आमच्याकडे रेकॉर्ड नाही त्यांना पैसे देण्याचा प्रश्न येत नाही. कामठीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विणकर बांधवाच्या संघटना आहेत. त्यामुळे विणकर बांधवांबरोबर चर्चा करतांना माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांना सुध्दा आमंत्रित केले जाईल व त्यामध्ये यासंदर्भातील आकडा फायनल केला जाईल. शेवटी शासनाच्याही काही मर्यादा आहेत. शासनाने 1998 च्या रेकॉर्ड प्रमाणे पैसे दिलेले आहेत. या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी आधिवेशन झाल्यानंतर माननीय सदस्य श्री. नितीन गडकरी यांना आमंत्रित करून यातून मार्ग काढला जाईल.

श्री. सत्यद जामा : सभापति महोदय, जिन विणकरों का रिकॉर्ड नहीं है, उनको सानुग्रह अनुदान का पैसा देने के बारे में माननीय मंत्री महोदय की परेशानी में समझ सकता हूँ, लेकिन 1,500 विणकर ऐसे हैं, जिनका रिकॉर्ड महामंडल के पास है. क्या मंत्री महोदय ऐसे लोगों को सानुग्रह अनुदान का वितरण अविलम्ब करेंगे ?

श्री. सतीश चतुर्वेदी : या ठिकाणी श्री. जामा साहेबांनी ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्याबाबत सहानुभूतीने विचार केला जाईल. यासंदर्भात आमच्याकडे रेकॉर्ड असेल तर त्यांना निश्चित पैसे दिले जातील व सन्माननीय सदस्यांच्या सूचनांचा निश्चितपणे विचार केला जाईल.

नियम 93 अन्वयेच्या निवेदन क्रमांक 6 बाबत

सभापती : सन्माननीय मंत्रीमहोदय श्री. दिलीप वळसे-पाटील यांच्या संदर्भातील सहावे निवेदन आहे ते खालच्या सभागृहात असल्यामुळे सदर निवेदन माननीय मंत्रीमहोदय आल्यानंतर घेण्यात येईल.

पृ. शी. : वसई तालुक्यात पाईपने नैसर्गिक वायू मिळणे

मु. शी. : वसई तालुक्यात पाईपने नैसर्गिक वायू मिळणे याबाबत श्री संजय केळकर, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील (उद्योग राज्य मंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री संजय केळकर यांनी "वसई तालुक्यात पाईपने नैसर्गिक वायू मिळणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...3...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

PP-3

SGJ/ KGS/ MMP/

ग्रथम श्री. खर्चे.....

14:15

श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, समुद्र किनारी असलेल्या पश्चिम पट्ट्या आणि वसईच्या भागात गॅस उपलब्ध आहे. महानगर गॅस कंपनी तर्फे वसई-विरारला गॅस मिळावा म्हणून संघर्ष समितीने आंदोलन आणि उपोषणही केलेले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, " महानगर गॅसने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले असून सध्या आवश्यक त्या प्रमाणात उपभोक्ते उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे" असे म्हटलेले आहे. महानगर गॅस भाईदर व उर्वरित महाराष्ट्रात गॅसच वितरण करीत असते असे असतांना आमच्या येथे गॅस तयार होत असतांना वसई -विरारला गॅस कधी उपलब्ध करून देणार आहात व वसई-विरारमध्ये गॅस उपभोक्त्यांची संख्या किती आहे ?

यानंतर श्री. गायकवाड....

श्री.राणा जगजितसिंह पाटील : सभापती महोदय, मुंबई महानगर गॅस कंपनीकडे 1.62 एम.एम.सी.एम.डी. एवढा गॅस रोज उपलब्ध होत असून त्यापैकी 1.2.एम.एम.सी.एम.डी.गॅस सी.एन.जी.वर चालणारी वाहने, रिक्षा वा टॅक्सीज यांना दिला जातो .0.2.एम.एम.सी.एम..डी. गॅस इन्डस्ट्रीज अॅन्ड कमर्शिअल एस्टेबिल्शमेन्टसाठी दिला जातो आणि 0.2.एम.एम.यी.एम.डी. गॅस डोमेस्टिकसाठी दिला जातो. मुंबई महानगर गॅस कंपनीच्या मार्फत हा गॅस कुलाब्या पासून दहिसर आणि ठाणे, मीरा - भाईदर या ठिकाणी दिला जातो त्यामुळे या कंपनीकडे सध्या जो काही गॅस उपलब्ध आहे तो सगळ्या वापरला जातो.आता हा गॅस वसई पर्यंत पाईप लाईन व्हारे देण्यासाठी त्या ठिकाणी क्रीक क्रॉस करावा लागणार आहे त्यासाठी पाईप लाईन टाकण्याकरिता किती खर्च येणार आहे याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी अॅन्कर लोड करण्याची देखील गरज आहे. हे काम 100 टक्के अनुदानातून केले जात नाही तेव्हा या कामासाठी एकूण किती खर्च येणार आहे याचा अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. पुढच्या सहा महिन्यात प्रिलिमीनरी स्टडी करून त्याचा अहवाल येईल व तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.

श्री.मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, नियम 93 च्या सूचनांवरील 8 ते 9 निवेदने अजूनही यावयाची आहेत. त्यातील काही निवेदने उद्या घेण्यात यावीत आणि काही निवेदने सोमवारी घेण्यात यावीत अशी माझी आपल्याला विनंती आहे.

सभापती : नेहमी पेक्षा या वेळी सभागृहात अधिक निवेदने झालेली आहेत.

श्री.मधुकर चव्हाण : ते मला मान्य आहे.

सभापती : नियम 93 ची सूचना देणारे सन्माननीय सदस्य काही वेळा अनुपस्थित असल्यामुळे ते निवेदन नंतर घेण्यात येते त्याचप्रमाणे काही वेळा माननीय मंत्री महोदयांना खालच्या सभागृहात जावे लागत असल्यामुळे वा अन्य काही अपरिहार्य कारणामुळे निवेदन नंतर घेण्यात यावे अशी विनंती ते करतात त्यामुळे निवेदने करावयाची राहिलेली आहेत त्यातील काही निवेदने उद्या व राहिलेली निवेदने सोमवारी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

आता सभागृहाची बैठक मध्यंतरासाठी स्थगित होईल आणि 2 वाजून 55 मिनिटांनी पुन्हा भरेल.

(2.22 ते 2.55 मध्यंतर)

नंतर श्री.सुंबरे

(मध्यंतरा नंतर ...)

सभापतीस्थानी - माननीय उपसभापती

पृ. शी. : मेळघाटातील सेमाडोह येथील आदिवासी वन मजुरांवर काम मिळत नसल्याने आलेली उपासमारीची पाळी.

मु. शी. : मेळघाटातील सेमाडोह येथील आदिवासी वन मजुरांवर काम मिळत नसल्याने आलेली उपासमारीची पाळी यासंबंधी सर्वश्री गोविंदराव आदिक, संजय दत्त, शरद रणपिसे, राजन तेली, वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री. गोविंदराव आदिक (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय वन मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

" मेळघाटातील सेमाडोह गावातील कंत्राट पद्धतीवर काम करणाऱ्या हजारो आदिवासी वन मजुरांना गेल्या एक वर्षापासून काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची पाळी, यामुळे सदर रोजगार बंद झाल्याने रोजगार मिळविण्याच्या आशेने मेळघाटातील सुमारे 600 मजूर जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित होत असल्याचे माहे फेब्रुवारी 2008 मध्ये निर्दर्शनास येणे, उर्वरित शेकडो मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दिनांक 7 फेब्रुवारी 2008 रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे सदर प्रकरणी तातडीची उपाययोजना करण्याची केलेली मागणी, सदर प्रकरणी वन विभागाकडून कार्यवाही करण्यात होत असलेली दिरंगाई, टाळाटाळ, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, परिणामी मेळघाटातील हजारो आदिवासी वन मजुरांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कार्यवाही व उपाय योजना."

श्री. बबनराव पाचपुते (वन मंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

.... आरआर 2 ..

(लक्षवेधी सुचनेवरील मा. वनमंत्रांच्या निवेदनानंतर ...)

श्री. गोविंदराव आदिक : सभापती महोदय, या लक्षवेधी सुचनेद्वारा उपस्थित केलेला प्रश्न आहे हा केवळ मेळघाटातील आदिवासी वन मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत नाही एवढ्या पुरताच मर्यादित नाही तर त्यांना रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने त्या विभागात कुपोषणाचे जे संकट तेथील बालकांवर आणि पालकांवर आलेले आहे त्याच्याशी हा प्रश्न निगडित आहे, संबंधित आहे. माननीय वन मंत्रांनी येथे उत्तर देताना गेल्या 11 महिन्यात जी काही कामे उपलब्ध करून दिली आहेत त्याची आकडेवारी दिलेली आहे. त्यांनी एका बाजूने आकडेवारी दिलेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूने गेल्या 11 महिन्यात सहा वेळा येथील गावकच्यांनी आणि तेथील आदिवासी जनतेने अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महिन्याच्या महिन्याला वेळोवेळी निवेदने देऊन कामाची मागणी केलेली आहे. या निवेदनात सांगितले आहे की, या लोकांना कामे देण्यात आली आहेत पण ती कामांवर 400-500 पेक्ष जास्त लोकांना काम दिलेले दिसत नाही. तेव्हा ही माहिती पुन्हा तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे, तशी ती आपण घ्यावी अशी माझी या निमित्ताने त्यांना सूचना आहे. सभापती महोदय, दुसरे म्हणजे जानेवारी महिन्यात जेव्हा या भागातील कुपोषणाच्या संदर्भात सर्व झाला त्या सर्वमध्ये जवळपास 25 हजार बालके कुपोषित आहेत आणि त्यापैकी तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यावर पोहोचलेल्या बालकांची संख्या 4 हजाराच्या वर आहे असे शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमार्फत आलेल्या अहवालातून समोर आलेले आहे. तेव्हा एवढी कुपोषणाने ग्रस्त झालेली जनता असताना हे कुपोषण मुळात कशामुळे निर्माण होते तर केवळ तेथे त्यांना रोजगार नाही, जीवन जगण्यासाठी लागणारी उत्पन्नाची साधने नाहीत म्हणूनच तेथे कुपोषणाचा परिणाम दिसून येत आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला या लोकांना रो.ह.योजनेची कामेदेखील उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे माननीय वनमंत्रांनी याबाबत जातीने लक्ष देऊन या बाबत फेरमाहिती घेतील काय ? आणि ती माहिती सभागृहासमोर ठेवतील का ?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.आदिक साहेब यांनी जी माहिती येथे सांगितली आहे त्या माहितीच्या अनुषंगाने बरेच प्रश्नही येथे निर्माण केलेले आहेत. विशेषत: कुपोषणाचा प्रश्न त्यात प्रामुख्याने आहे. सभापती महोदय, जेव्हा माझ्याकडे हा विभाग आला त्यानंतर मी मेळघाटातील सेमाडोह येथे दोन वेळा गेलो आहे आणि आताच दोन महिन्यापूर्वी मी त्या परिसरात जाऊन दोन दिवस ज्या भागात जाता येत नाही अशा ठिकाणी जाऊनही पाहणी

..... आरआर 3 ...

श्री. पाचपुते

केलेली आहे. सेमाडोह येथे थांबलो आहे, तेथील काही लोकांना भेटलो आहे. आता सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की, मी निवेदनात दिलेल्या माहितीची खात्री करून घ्या. ...

(यानंतर श्री. सरफरेएसएस 1 ..

श्री. बबनराव पाचपुते...

तशाप्रकारची खात्री करून घेतली आहे. त्याठिकाणी जे पुर्नवसित गाव होते त्या गावामध्ये काम सुरु होते, म्हणून त्या प्रत्येक गावामध्ये जाऊन बैठक घेतली आहे. सेमाडोहच्या परिसरामध्ये असलेल्या सर्व गावांना भेटी दिल्या आहेत. त्याठिकाणी लोकांना आज कामे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे उपलब्ध करून दिलेल्या कामामधून मनुष्य दिवस निर्माण करण्यात आले आहे. तसेच, जंगलामध्ये सी.सी.टी. ची कामे करण्याकरिता खास परवानगी दिलेली आहे. त्या गावांना भेट दिली असतांना तेथील गावकच्यांची तक्रार एका विशिष्ट अधिकाच्याविरुद्ध होती. त्याकरिता त्यांच्याबरोबर बसून चर्चा करून त्यांच्या मनामध्ये असलेला गैरसमज दूर करण्यात आला आहे. आणि मोठया प्रमाणावर कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. सभापती महोदय, ही गोष्ट खरी आहे की, त्या भागामध्ये आणखी कामे उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. रोजगार हमी योजनेमधून वन विभागामध्ये पूर्वी कामे घेण्यात येत नव्हती. परंतु दोन वर्षांपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. आणि आता त्या विभागामध्ये पाझर तलाव, नाला बंडींग, कंटूरबंडींग, सी.सी.टी.गावतळे, के.टी.वेअर, साठवण बंधारे या कामांबरोबर जोड रस्त्यांची कामे सुध्दा घेण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी कल्वर खत तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणालाही कामापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही.

श्री. जगदीश गुप्ता : सभापती महोदय, मंत्रिमहोदयांनी कामे उपलब्ध करून दिली आहेत आणि भविष्यातही करून देण्यात येणार आहेत असे सांगितले. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की, किती किलोमीटरच्या अंतरामध्ये ही कामे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, योगा योगाने मी स्वतः तेथील सिपना या गावाला भेट दिली, त्याठिकाणी इको टुरिझमचे काम सुरु आहे. त्याठिकाणी 30-35 लोकांना कायम स्वरूपी काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे काम करण्यासाठी आता त्यांना फार लांब जावे लागणार नाही. त्या जंगल परिसरामध्ये बाकीची कामे करण्यास परवानगी नव्हती, आता ही कामे करण्याकरिता विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. आजही त्या परिसरामध्ये वनतळे, छोटे तलाव, बंधारे यांची कामे करता येऊ शकतात. ही कामे करण्यामध्ये मोठया प्रमाणावर अडचण येत होती ती आता सोडविण्यात आली आहे. त्यामध्ये मुख्य अडचण म्हणजे तेथील परिसराचा सर्व करण्याकरिता लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात येत होते. परंतु आता त्यासाठी स्वतंत्र जी.आर. काढण्यात आला आहे. त्यामध्ये आर.एफ.ओ., डी.एफ.ओ. एस.एफ.ओ. यांनाही मंजुरीचे अधिकार

श्री. बबनराव पाचपुते...

दिले आहेत, तसेच तांत्रिक मान्यतेचे अधिकारही दिले आहेत. त्याचप्रमाणे त्या परिसरामध्ये सी.सी.टी. ची कामे करण्याकरिता स्वतंत्र जी.आर. काढण्यात आला असल्यामुळे त्या परिसरातील लोकांना आपल्याला दोन वर्ष काम देता येईल. कामासाठी आता त्यांना बाहेर जाण्याची आवश्यकता रहाणार नाही.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, मेळघाट येथील सेमाडोह येथे मंत्रिमहोदयांनी भेट दिली आहे, त्याप्रमाणे दरवर्षी दोन-तीन वेळा मी त्या भागामध्ये जात असतो. त्याबाबतची ताजी माहिती आपणास सादर करतो. त्याठिकाणी शासनाची कामे ठेकेदारामार्फत करण्यात येतात. त्यामुळे रोजंदारीवरील मजुरांची नावे फक्त कागदावरच दाखविली जातात. त्यामुळे त्यांना वेतन मिळत नाही. जे खरोखरच लाभार्थी आहेत त्यांना वेतन मिळत नाही. तेव्हा या प्रकरणी आपण चौकशी करणार काय? आणि चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर आपण कारवाई करणार काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी सभागृहामध्ये सांगितलेली माहिती सत्य आहे असे गृहीत धरून याबाबत चौकशी केली जाईल. मी त्या परिसराला भेट देऊन दीड महिना झाला आहे. त्याठिकाणी चालू असलेल्या कामावरील मजुरांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. तसेच, शेजारच्या गावामध्ये जाऊन तेथील सहा-सात कामे तपासली आहेत. त्याठिकाणी इको टुरिझमची कामे ठेकेदारामार्फत सुरु होती. त्याठिकाणी एक छोटासा बांध करावयाचा होता त्याचे काम ठेकेदारामार्फत सुरु होते. परंतु रोजगार हमी योजनेची कामे मस्टरवर केली गेली आहेत. तरीसुध्दा माननीय सदस्यांनी याठिकाणी सांगितलेली माहिती सत्य आहे असे गृहीत धरून या प्रकरणी चौकशी केली जाईल. आणि चौकशीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

श्री. संजय दत्त : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री. गोविंदराव आदिक यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या रूपाने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. तेथील मजुरांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. तेथील मजुरांचे कामासाठी स्थलांतर सुरु झाले आहे व ते राखण्यासाठी शासनाला यश आले नाही ही वास्तविकता आहे. मंत्रिमहोदयांनी त्यांच्य निवेदनामध्ये यासंबंधी आकडेवारी जरी दिली तरी हा प्रश्न कां निर्माण झाला? आणि याबाबतीत वस्तुस्थिती काय आहे असा माझा प्रश्न आहे?

(यानंतर सौ. रणदिवे)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

TT-1

APR/ SBT/ KTG/

पूर्वी श्री.सरफरे . . .

15:05

श्री.संजय दत्त . . .

याबाबतीत पूर्ण चौकशी करून माहिती घेण्याची गरज आहे. माझा खेडिक प्रश्न असा आहे की, फेब्रुवारी 2008 मध्ये सेमाडोह गावातील रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे कामाच्या मागणी संदर्भात निवेदन दिले होते. त्याचा तपशील काय आहे ? तसेच निवेदनामध्ये म्हटल्याप्रमाणे 16.56 लाख रुपयांची कामे उपलब्ध आहेत. माझा प्रश्न असा आहे की, प्रत्यक्षात या कामांना सुरुवात झाली आहे काय ? असल्यास, या कामांना केवळापासून सुरुवात झाली आहे ? तसेच या कामावर किती मंजूरांना काम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, मी मधाशी विस्ताराने उत्तर दिलेले आहे. फेब्रुवारी 2008 मध्ये सेमाडोह गावातील रहिवाशांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्यारे कामाची मागणी केलेली आहे, त्यासंबंधीचे पत्र माझ्याजवळ आहे. त्यानंतर त्यांनी जी तक्रार केलेली आहे, त्याची प्रत देखील माझ्याकडे आहे. या शिवाय ज्या अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी केली होती, त्याची प्रत देखील माझ्याकडे आहे. याबाबतीत सांगावयाचे तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे काही कामगारांनी कामाची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, याठिकाणी चार दिवसांनी काम बंद होईल, त्यानंतर आम्हाला येथे काम द्यावे. नाहीतर परत काम शोधावे लागणार आहे. याबाबतीत ते संबंधित अधिकारी श्री.कावरे यांच्याकडे गेले. त्यांनी असे सांगितले की, मी यासंदर्भात एस्टीमेट तयार करून डेप्युटी कलेक्टर (ई.जी.एस.) यांच्याकडे पाठविलेले आहे. येथील काम बंद पडू न देता, तुम्हाला काम देतो. त्यावर अशी चर्चा झाली की, नक्की कशावरुन काम देणार आहात ? असे बोलता-बोलता त्यांच्यामध्ये बाचाबाची सुरु झाली. मग काही कामगारांनी या अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली. मग अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले की, ठीक आहे. जर तुम्ही असे करणार असाल तर मी कामच देणार नाही. पण पुढे सर्वांनी एकत्र बसून चर्चा केली आणि मग यामध्ये समेट झाला. सन्माननीय सदस्यांनी कुपोषणाच्या आणि कामाच्या बाबतीत मूळ प्रश्न विचारलेला आहे. हा सर्वांचा एकत्रित असा प्रश्न आहे. शासन म्हणून त्याचा विचार केलाच पाहिजे. यासंदर्भात आपण तेंदू पत्त्याचे पैसे परत देण्यास सुरुवात केली आहे. वनवासी आणि आदिवासी यांना पूर्ण वर्षभर वनामध्ये काम करण्याच्या संदर्भात कार्य योजना मंजूर केलेली आहे. त्या योजनेतून खूप ठिकाणी कामे सुरु करीत आहोत. त्यामुळे यांना पूर्ण वर्षभर काम मिळू शकेल. मध्यांतरीच्या काळामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्याचा हा परिणाम आहे. परंतु आता तसा परिणाम होणार नाही. वन विभागाकडून जास्तीतजास्त काम मिळू शकेल.

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

TT-2

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, निवेदनामध्ये म्हटलेले आहे की,"अधिकची 16.56 लाख रुपये रकमेची 19240 मनुष्य दिवस निर्मिती क्षमता असलेली कामे उपलब्ध आहेत." कामे सुरु आहेत, पण त्यासाठी आतापर्यंत 16.56 लाख रुपयांपैकी किती खर्च झालेला आहे ?

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, काम मंजूर होऊन आल्यानंतर, जसे लोक येतील त्याप्रमाणे बिल द्यावे लागते. ही कामे सुरुव रहातात. शेवटी आपल्या सेल्फवर मंजूर असलेली किती कामे आहेत? ते महत्वाचे आहे. निवेदनामध्ये तिसऱ्या रकान्यामध्ये जी कामे मंजूर झालेली आहेत, त्यावर किती खर्च झाला आहे ? याची माहिती दिलेली आहे. मंजूरीवर जो खर्च झालेला आहे, त्यामध्ये "1) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत 9 लाख 73 हजार, 2) योजना यामध्ये 10 लाख 57 हजार आणि योजनेतर यामध्ये 1 लाख 84 हजार अशा प्रकारे 22 लाख 14 हजार रुपये एकूण खर्च झालेला आहे, म्हणजे शेवटी काम दिल्याशिवाय खर्च होत नाही. तसेच मंजूरीची कामे एकत्र होत नाहीत. काम जसे होईल तशा प्रकारे पगार दिला जातो.

श्री.गोविंदराव आदिक : सभापती महोदय, याठिकाणी माननीय वन मंत्रांनी जी उत्तरे दिली, ती त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार योग्य आहेत. त्याबद्दल कोणाची तक्रार असण्याचे कारण नाही. प्रश्न एवढाच आहे की, मेळघाट हा अतिशय संवेदनशील असा एरिया आहे. त्या भागातील कुपोषणासंबंधी केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशपातळीवर आणि जागतिक स्तरावर देखील त्याची चर्चा झालेली आहे. येथील आदिवासीच्या कुपोषणचा प्रश्न याच्याशी निगडीत आहे. माझ्याकडे आकडेवारी आहे. अमरावती जिल्ह्यातून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत लोक स्थलांतरीत झालेले आहेत. साधारणपणे 2 लाख 9 हजार 164 एवढे लोक एका वर्षामध्ये दुसऱ्या भागामध्ये स्थलांतरीत झालेले आहेत. एका बाजूला बालकांचे कुपोषण, महिलांचे कुपोषण आणि दुसऱ्या बाजूला तेथील लोकांनी दुसरीकडे स्थलांतर करणे या दोन्ही गोष्टी कोणालाही अमान्य करता येणार नाही. हे लक्षात घेऊन शासन म्हणून या विभागाला प्राधान्य देऊन काही वेगळी योजना आखण्याचा शासन विचार करणार आहे काय ? कारण त्याला प्राधान्य देण्याची आणि विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसेच यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची देखील आवश्यकता असल्यामुळे शासनाने याबाबतीत उपाययोजना करावी अशी मी सूचना करतो. धन्यवाद.

श्री.बबनराव पाचपुते : सभापती महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.गोविंदराव आदिक यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्याबाबत जरुर विचार केला जाईल. याठिकाणी आदिवासींच्या

. . . 2 टी-3

श्री.बबनराव पाचपुते

रथलांतराबाबत सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मेळघाट मध्ये वन विभागात 22 गावे असून त्यांना बाहेर काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

यानंतर कु.गायकवाड

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

UU 1

DVG/ SBT/ KTG/

15:10

श्री. बबनराव पाचपुते...

त्यासाठी निधीची मोठया प्रमाणात उपलब्धता झालेली आहे. हा वनवासीयांचा विषय आहे. या प्रश्नाबाबत इतर खात्याचा देखील संबंध आहे. आदिवासी लोकांना संपूर्ण वर्षभर काम मिळवून देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येणार आहे. मोहाची फुले गोळा करण्यासाठी, मध गोळा करण्यासाठी शासनाकडून योजना तयार करण्यात येत आहे. यासाठी वन औषधी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. इको टुरिझम व रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी जनतेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. तसेच या संदर्भात चार ते पाच विभागांची एकत्र बैठक घ्यावी लागेल. तसेच आपण दिलेल्या सूचनांचा विचार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही शासनाकडून करण्यात येईल.

2..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

UU 2

पृ. शी. : ठाणे जिल्हयातील बंद पडणाऱ्या कंपन्याची जागा मूळ शेतकऱ्यांना,

भूमिपूत्रांना परत करणे

मु. शी. : ठाणे जिल्हयातील बंद पडणाऱ्या कंपन्याची जागा मूळ शेतकऱ्यांना,

भूमिपूत्रांना परत करणे यासंबंधी श्री मधुकर सरपोतदार, डॉ. नीलम गोळे, डॉ. दीपक सावंत, श्री. अरविंद सावंत, ॲड अनिल परब, श्री. जितेंद्र आव्हाड, डॉ. वसंत पवार, प्रा. फौजीया खान, श्री. लक्ष्मण जगताप, श्री. भास्कर जाधव, श्री. रणजितसिंह मोहिते पाटील वि. प. स. यांनी दिलेली लक्ष्येधी सूचना.

श्री. मधुकर सरपोतदार (विधानसभा सदस्यांद्वारा निर्वाचित) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय उद्योगमंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"ठाणे शहरातील अनेक कंपन्या बंद पडत असणे, या कंपन्या सुरु करताना त्यांना अत्यल्य दरात भूमिपूत्रांच्या जागा उपलब्ध करून देण्यात येणे, आता या जागांचे भाव तेजीने वाढत असल्याने या कंपन्याचे मालक या जागा विकून त्यावर बांधकाम करीत असणे, जागा उद्योगधंद्यासाठी संपादित करीत असतांना या जागेचा संपूर्ण वापर उत्पादन निर्मितीसाठी करू असे या कंपन्यांनी शासनाला लेखी स्वरुपात लिहून देणे, असे असतांनाही आता या जागावर आलिशान सोसायट्या, मॉल, आयटी पार्क, रो हाऊसेस उभी करणे, या कंपनी मालकांनी या जागेवर करोडो रुपये कमविले असून या जमिनीच्या मूळ मालकांना त्याचा फायदा न होणे, त्या जमिनी शेतकऱ्यांना तसेच भूमिपूत्रांना परत देण्याची तेथील भूमिपूत्रांनी केलेली मागणी, ही मागणी पूर्ण न आल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा दिलेला इशारा, याबाबत शासनाने करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना."

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील (उद्योग राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्ष्येधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

3...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

UU 3

DVG/ SBT/ KTG/

15:10

श्री. मधुकर सरपोतदार : सभापती महोदय, ठाणे जिल्हयातील वागळे इस्टेट ही संपूर्ण आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखली जाते. सध्या या भागातील अनेक कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. त्या कंपन्यापैकी काही कंपन्याचा दुरुपयोग सुध्दा होत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. लक्षवेधी सूचनेच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, " या व्यतिरिक्त इतर खाजगी जमिनीचा दर त्यावेळच्या गणकाप्रमाणे निश्चित करून त्याप्रमाणे भूसंपादनाचा दर निश्चित करण्यात आला." येथील कंपनीच्या मालकांनी जमिनीची विक्री करून करोडो रुपये कमाविलेले आहेत त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. या लक्षवेधी सूचनेचा विषय हा एमआयडीसी व खाजगी मालकांच्या संदर्भात देखील आहे. 1958 साली वागळे इस्टेटमध्ये एचआरएन जॉन्सन्स नावाची कंपनी होती. त्यांनी देखील खाजगी लोकांकडून जमीन विकत घेतली होती. या कंपनीमध्ये 9 हजार कर्मचारी काम करीत होते. या जागेवर आता रहेजा हा मोठा रहिवासी कॉलेक्स उभा राहिलेला आहे. या ठिकाणी घरांचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत. ठाण्यातील सन्माननीय सदस्यांना तेथील घरांच्या वाढलेल्या दराची कल्पना असेल. वागळे इस्टेटमध्ये आज अनेक कारखाने बंद अवरथेत आहेत. परंतु उत्तरात असे म्हटले आहे की, " शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणानुसार विकास आयुक्त यांनी 3.6.2006 च्या आदेशान्वये वागळे औद्योगिक वसाहत माहिती व तंत्रज्ञान पार्क म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 10 उद्योजकांनी शासनाच्या या योजनेचा फायदा घेतलेला असून त्यांचे उद्योगांना माहिती व तंत्रज्ञान प्रयोजनासाठी महामंडळाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. "

सभापती महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की, ज्या 10 उद्योजकांनी शासनाच्या योजनेचा फायदा घेतला आहे तेथे किती कर्मचाऱ्यांना सध्या रोजगार देण्यात आलेला आहे ? वागळे औद्योगिक वसाहतीमध्ये आज काय परिस्थिती आहे ? पूर्वी तेथे किती कर्मचारी काम करीत होते व आता किती कर्मचारी काम करीत आहेत, किती कर्मचारी बेकार झालेले आहेत ?

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील : सभापती महोदय, निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, वागळे औद्योगिक वसाहतीमध्ये 556 भूखंडावर कारखाने सुरु आहेत तसेच 120 कारखाने त्यांच्या

..4..

वैयक्तिक कारणांमुळे बंद आहेत. सन्माननीय सदस्य श्री. मधुकर सरपोतदार यांनी येथे प्रश्न विचाराला आहे की, तेथे किती कर्मचारी काम करीत आहेत या बाबतची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल. तेथे आयटी पार्क उभारण्यारिता 10 उद्योजकांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

यानंतर श्री. बरवड..

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील ...

त्या आय.टी.पार्कमध्ये कोणते उद्योग सुरु आहेत काय आणि त्या ठिकाणी किती लोक काम करीत आहेत याची माहिती पटलावर ठेवण्यात येईल.

श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, ही अतिशय महत्वाची लक्षवेधी सूचना आहे. ठाणे शहराच्या आसपासच्या परिसरामध्ये ज्या अनेक कंपन्या आहेत त्या बंद पडलेल्या आहेत. त्या कंपन्या विकून झाल्या तरी कामगारांची देणी दिली गेलेली नाहीत. मी तीन कंपन्यांची नावे सांगतो. पॅयशा कंपनी 20 वर्षांपूर्वी बंद झाली. 1998 मध्ये त्या ठिकाणी टाळेबंदी झाली. त्या कंपनीत 850 कामगार होते. गेल्या 20 वर्षात 152 कामगार मयत झाले. परंतु अजून त्यांची देणी दिली गेलेली नाहीत. तेथील कामगार, त्यांचे कुटुंबीय यांची निरनिराळी आंदोलने चालू आहेत. पॅयशा कंपनीची जागा एमआयडीसीची आहे. त्या कंपनीने जागा विकली. त्या ठिकाणी पाच सहा प्रकारच्या इंडस्ट्रीज चालू आहेत. अजूनही त्या ठिकाणी काम चालू आहे. लेबर कमिशनरने एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले की, त्यांच्या कामाला स्थगिती द्यावी. शासनाचे असे धोरण आहे की, कामगारांची देणी दिल्याशिवाय त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे काम होता कामा नये. त्या ठिकाणी अजूनही काम चालू आहे ते थांबविणार काय ? त्यानंतर ठाण्याला सँडोज कंपनी आहे. त्या ठिकाणी सुधा कामगारांची देणी दिली गेलेली नाहीत. एक तर त्या ठिकाणी इडस्ट्रीयलचे रेसिडेंशियल केले. ते रेसिडेंशियल कसे केले ? कामगारांची देणी देण्याच्या आधी त्या ठिकाणी काम सुरु झालेले आहे त्यामुळे त्याला शासन स्थगिती देणार काय ? या कंपन्यांचे जे कामगार आहेत ते दरदर भटकत आहेत. त्यांना कोणी वारसदार नाही अशी परिस्थिती आहे. ते कामगार मरत आहेत. त्यांची देणी त्यांना मिळालेली नाहीत. अशा ज्या ज्या कंपन्यांमध्ये असे काम सुरु असेल ते काम बंद करणार काय ? त्यांचे लायसन्स रद्द करणार काय ? आधी कामगारांची देणी द्यावीत आणि त्यानंतर पुढचे काम चालू करावे. यामध्ये मोठे रँकेट चाललेले आहे. यामध्ये फार मोठा गैरव्यवहार आहे. यामध्ये अनेक लोक आहेत. माझे जे तीन प्रश्न आहेत त्याबाबत माननीय मंत्रिमहोदयांनी उत्तर द्यावे.

...2...

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील : सभापती महोदय, या तीनही प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे. शासनाचे असे स्थायी आदेश आहेत की, एखादी कंपनी जेव्हा बंद होते ती बंद झाल्यानंतर त्यांची जागा त्या ठिकाणी दुसऱ्या कोणाला हस्तांतरित करावयाची असेल तर किंवा परपज बदलावयास असेल तर लेबर कमिशनर किंवा त्यांचे जे प्राधिकृत अधिकारी असतील त्यांची एन.ओ.सी. घ्यावी अशी अपेक्षा असते. एन.ओ.सी. न घेता दुसऱ्या कोणाला जमीन विकली असेल तर निश्चितपणे रथगिती देण्यात येईल.

श्री. जितेंद्र आहाड : सभापती महोदय, हा प्रश्न व्यापक आहे. हा प्रश्न एमआयडीसीपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाच्या लाटेमध्ये जसा मुंबईचा महत्वाचा भाग होता तसाच ठाण्याचाही होता. यामध्ये जसा एमआयडीसीचा भाग आहे त्याचप्रमाणे औद्योगिक कारणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचाही भाग आहे. खाजगी लोकांकडून जी जमीन संपादित केली ती बाब एमआयडीसीच्या पर्व्ह्यूमध्ये नाही. तिसरी बाब म्हणजे काही कंपन्यांच्या मालकांनी डायरेक्ट जमीन मालकांकडून जमिनी विकत घेतलेल्या आहेत. एचआरएन जॉन्सन कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. त्यांचे कूळ आजही कोपरीत राहतात. टेल्को कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. त्याच्या बाजूला जी ग्लास कंपनी होती त्यांनी डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे.. कॅडबरी कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. कोरस कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. देवीदयाल इंजिनिअरिंगने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. क्लेरियंट कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. बायर कंपनीने डायरेक्ट जमीन विकत घेतलेली आहे. या कंपन्यांनी डायरेक्ट जमिनी विकत घेतलेल्या आहेत. यातील ज्या मेजर कंपन्या आहेत त्या ठिकाणी अजून डेव्हलपमेंट झालेली नाही. या जमिनी सरकारने संपादित करून त्याच्या ताब्यात दिलेल्या आहेत. सरकारने औद्योगिक कारणासाठी जमीन मालकांकडून स्वस्त दरामध्ये महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी ज्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या जमिनी बिल्डर यूजर चेंज करून बाहेरच्या बाहेर विकणार असतील तर शासनाच्या धोरणाशी तो द्रोह आहे. 1963 साली ती जमीन संपादित झालेली आहे. संपादित करताना त्या जमिनी इंडस्ट्रीयल

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

VV-3

RDB/ SBT/ KTG/

श्री. जितेंद्र आव्हाड

डेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या आहेत. जवळजवळ 750 एकर जमीन आहे. त्या सगळ्या मालकांनी जमिनी इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्ससाठी जमिनी आहेत. या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे सायटेशन वारंवार दिले जाते. या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाचे उदाहरण दिले जाते. केरळच्या एका केसमध्ये सुप्रीम कोर्टने सांगितले की, एकदा अँकवायर केलेली जमीन परत करता येत नाही.

यानंतर श्री. खंदारे...

श्री.जितेंद्र आव्हाड.....

परंतु त्याबरोबर सुप्रीम कोर्टने सांगितलेले आहे की, चेंज ऑफ यूजर करता येत नाही. मग हे यूजर चेंज कसे होतात ? एमआयडीसीची जमीन मिळणार नाही. तेथे रो हाऊसेस होणार नाहीत. हे आम्हाला माहिती आहे, त्याबद्दल आमच्या मनात शंका नाही. पण प्रायव्हेट ओनर्सनी जमिनी घेतलेल्या आहेत. शेतक-यानी शेतक-यास जमीन न विकल्यामुळे जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी 700 एकर जमीन रद्द केलेली आहे. त्यांनी 7/12 च रद्द करून टाकला आहे. ज्या जमिनी शेतक-याने शेतक-यास न विकता महसूल खात्याने त्या जमिनी फॅक्टरीजच्या नावावर केलेल्या आहेत. त्या व्यवहारात गैरव्यवहार झाला आहे त्याची चौकशी करणार काय ? तो व्यवहार जुना असेल, त्याच्याशी आम्हाला कर्तव्य नाही. आता तो उघडकीस आला असेल, तांत्रिकदृष्ट्या, that is not permissible under the Agriculture Act. तो व्यवहार शासन रद्द करणार काय ? त्याचबरोबर शासनाने औद्योगिकरणासाठी जमिनी संपादित केल्या होत्या, त्या जमिनी अमूक अमूक व्यक्तीला दिल्या असतील किंवा देण्यात आलेल्या आहेत. तेथील कंपनी बंद पडली असेल तर तेथे शासन नवीन प्रकल्प सुरु करणार का अथवा संपादित केलेल्या जमिनी असल्या कारणाने शासन त्या ताब्यात घेणार का ?

श्री.राणा जगजितसिंह पाटील : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी स्पेषिफिक प्रश्न विचारला असता तर त्याला उत्तर देणे शक्य झाले असते. माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ठाण्यामध्ये दोन इंडस्ट्रीसाठी जागा संपादित केली होती त्यात शासकीय आणि संपादित क्षेत्र आहे. त्यात मफतलाल इंजिनिअरिंग लिमिटेड यांना 58 हेक्टर कळव्याला संपादित करून दिली होती. औद्योगिक वापरासाठी 4 हेक्टरच्या आसपास शासकीय जमीन त्यांना हस्तांतरित केली होती. ॲंग्रीमेंटमध्ये ज्या काही शर्ती होत्या त्याचा भंग केल्यामुळे हे जे क्षेत्र आहे त्यापैकी 25 हेक्टर क्षेत्र शासनाकडे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही कंपनी कोर्टमध्ये गेल्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता दि.26.3.2007 च्या आदेशानुसार 25 हेक्टर जमा केलेली आहे. ती जमीन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून मुक्त करून शासनास देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. टीआयएलआर च्या मोजणीनंतर सदर जमीन कोर्ट रिसिव्हरकडून शासनास हस्तांतरित

2....

श्री.राणा जगजितसिंह पाटील...

होणार आहे. त्याचबरोबर व्होल्टास लिमिटेड कंपनीसाठी पाचपाखाडी व माजीवाडा या दोन ठिकाणी शासनाने जमीन संपादित केली होती. हे प्रकरण सुध्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दावा दाखल केलेला आहे. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. तिस-या केसमध्ये त्यांनी 3 कोटी 25 लाख रुपये भरलेले आहेत. सभापती महोदय, सांगण्याचा हेतू हा आहे की, शासनाने जर औद्योगिकरणाच्या कारणासाठी कोणाची जमीन संपादित केली असेल आणि त्याचा वापर दुसऱ्या कारणासाठी होत असेल तर त्याबाबत शासन नियमाप्रमाणे कारवाई करील. सन्माननीय सदस्य श्री.आव्हाड हे जनरल बोलले आहेत, पण त्यांनी स्पेसिफिक प्रकरणाची माहिती दिली तर त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

श्री.जितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.मधुकर सरपोतदार हे एच.आर.जॉन्सन या कंपनीत पर्सोनेल ऑफिसर म्हणून होते. तेथे आगरी कूळ होते, ते कूळ आजही जीवंत आहे. ते कोपरी गावात राहतात. टेल्को कंपनीचे कूळ आजही कोळीवाड्यात राहते. व्होल्टास कंपनीची नवीन 17-18 एकर जमीन आहे ते कोळी आहेत. ते उथळसरमध्ये राहतात. किरण स्पिनिंग मिल 25 एकर, बॉम्बे वायर रोप्स 36 एकर, कॅटलिस्ट इंडिया लि., बोरगर नॉल लि., सँडोज, क्लेरियंट, नोव्हार्टीज, इंडोफिल, कॅप्रिहंस, ब्लॅडनकोल, वुल रिसर्च, कोरस, इंडियन स्पेल्टिंग, डॅगरफोर्स, ग्लॅक्सो, रेमण्डस, कॅडबरी इंडिया अशा अनेक कंपन्या आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला ज्यांचा हातभार लागला, त्या जमिनी एक तर खाजगी मालकांकडून घेण्यात आल्या होत्या. 1963 साली शासनाने संपादित करून औद्योगिक विकासासाठी या मालकांना दिल्या होत्या. त्यापैकी बोरगर नॉल लि.ही कंपनी विक्रीला निघाली आहे. त्या कंपनीसाठी संपादित करून जमीन दिलेली आहे. एमआयडीसीची जमीन देता येत नाही असे आपले म्हणणे आहे. मग संपादित केलेली जमीन विशिष्ट उद्देशासाठी दिली असेल तो उद्देश संपवून त्या जमिनीवर फायद्यासाठी इमारती बांधल्यामुळे एकालाही नोकरी मिळणार नसेल तर त्याबाबात शासनाची काय भूमिका आहे हे आम्हाला समजले पाहिजे.

नंतर श्री.शिगम

उपसभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री. जितेंद्र आव्हाड : उपसभापती महोदय, शासनाची भूमिका काय आहे हे आम्हाला समजायला हवे. 11 हजार एकर जमीन संपादित केलेली आहे. त्या जमिनीवर जी बांधकामे सुरु आहेत ती शासन थांबविणार आहे काय ? माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की, या लक्षवेधीला दिलेले उत्तर चुकीचे आहे. माननीय उपसभापती महोदय, आपण मुलुंड हायवेरुन जेथे आत येतो तेथपासून कंपन्या लागून होत्या. किरण रिपनिंग मिल पासून ते बोरिगर नॉल लि. पर्यंत शेतक-यांच्या जमिनी आहेत. या शेतक-यांनी त्यांच्या जमिनी परत मिळण्यासंबंधी निवेदने दिलेली आहेत. श्री. शरद पवारसाहेब हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे निवेदने दिलेली आहेत. आंदोलने केलेली आहेत. त्यामुळे शेतक-यांनी आंदोलने केलेली नाहीत असे म्हणणे चुकीचे आहे. तेव्हा या संपादित केलेल्या जमिनीबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार आहे ?

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील : शासनाने औद्योगिक कारणासाठी ज्या जमिनी संपादित केल्या त्या जमिनीचा वापर दुस-या कोणत्या कारणासाठी होत असेल तर..... सन्माननीय सदस्यांनी कंपन्यांची जी नांवे सांगितली त्या सर्व कंपन्यांच्या बाबातीत नेमके काय झाले, त्यांचे क्षेत्र किती आहे आणि ते कशासाठी त्याचा वापर करीत आहेत याची माहिती घेऊन ती पुढच्या बुधवार पर्यंत पटलावर ठेवण्यात येईल.

श्री. जितेंद्र आव्हाड : संपादित केलेल्या जमिनीबाबत काय कारवाई करण्यात येणार आहे ?

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील : मी माहिती पटलावर ठेवतो, त्यानंतर त्याबाबतीत चर्चा करून कारवाई करू.

श्री. मधुकर सरपोतदार : मी या लक्षवेधीच्या मुख्य गाभ्याकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो. लक्षवेधीमध्ये असे नमूद केलेले आहे की, "जागा उद्योगधंद्यासाठी संपादित करीत असताना या जागेचा संपूर्ण वापर उत्पादन निर्मितीसाठी करु असे या कंपन्यांनी शासनाला लेखी स्वरूपात देणे, असे असतानाही आता या जागावर आलिशान सोसायट्या, मॉल, आय.टी. पार्क, रो हाऊसेस उभी करणे, या कंपनी मालकांनी या जागेवर करोडो रुपये कमविलेले असून या जमिनीच्या मूळ मालकांना त्याचा फायदा न होणे" हा या लक्षवेधीचा मूळ गाभा आहे. तेव्हा अशाप्रकारे संपादित

.2..

(श्री. मधुकर सरपोतदार....)

करुन निरनिराळ्या कंपन्यांना विकलेली जमीन किती आहे ? त्याची सद्यःस्थिती काय आहे ? तेथील कामगारांची परिस्थिती काय आहे ? यासंदर्भात ज्यांनी गैरकारभार केलेला आहे अशा मालकांवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे ?

श्री. राणा जगजित सिंह : ज्या बंद पडलेल्या आणि ज्या ठिकाणी रेसिडेन्शीयल कॉम्प्लेक्स उभे राहिले आहेत अशा दोन फॅक्टरीज आहेत. जॉन्सन टाईल्स आणि डब्ल्यू.जी. फोर्ज या त्या दोन कंपन्या आहेत. या दोन कंपन्यांची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. या दोन कंपन्यांनी खाजगी शेतक-यांकडून जमीन घेतली होती.

...नंतर श्री. गिते....

श्री.राणा रणजितसिंह पाटील...

आणि त्यांनी सदर जमिनी अकृषिक करण्यासंबंधी 1960 साली परवानगी घेतली. चेंज ऑफ पर्पज साठी त्यांना यू.एल.सी.ची परवानगी 2000 साली मिळाली होती. या जमिनीवर कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी जॉन्सन टाईल्स कंपनीने सुधारित एनएसाठी परवानगी मागितली होती, त्या कंपनीस सुधारित एनए परवानगी 24.11.2003 मध्ये मिळाली होती. सुधारित एनए परवानगी प्राप्त इ आल्यानंतर सदर कंपनीने कन्स्ट्रक्शनचे काम त्या जमिनीवर सुरु केले. त्याचप्रमाणे डब्ल्यू.जी.फोर्ज या कंपनीला 2000 साली सुधारित एनएची परवानगी मिळाली होती. त्यांना सुधारित एनएची परवानगी मिळाल्यानंतर त्या कंपनीने त्या जमिनीवर कन्स्ट्रक्शनचे काम चालू केले आहे. ही जमीन शासनाने संपादित केलेली नव्हती एवढी बाब मी विलअर करू इच्छितो.

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, ठाणे जिल्ह्यात बरेच मोठमोठे उद्योग बंद पडलेले आहेत. बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनीवर मोठ मोठया निवासी इमारती उभ्या होत आहेत. या ठिकाणी नगरविकास राज्यमंत्री उपस्थित आहेत. मुंबई शहरात इंडस्ट्री टू रेसीडेन्सी अशी पॉलिसी इंडस्ट्रीमधील कामगारांचे हित जपून मुंबईत लागू करण्यात आली आहे. तशाच प्रकारची इंडस्ट्री टू रेसीडेन्सी पॉलिसी ठाणे येथे राबविण्याबाबत उद्योग विभागाकडून नगरविकास विभागाकडे मागणी करण्यात येईल काय ?

श्री. राणा रणजितसिंह पाटील : सन्माननीय सदस्यांनी केलेली सूचना अतिशय चांगली आहे. त्यामुळे ती सूचना निश्चितपणे स्वीकारली जाईल.

श्रीमती मंदा म्हात्रे : सभापती महोदय, या ठिकाणी अतिशय महत्वाची लक्ष्येधी सूचना उपस्थित करण्यात आली आहे. ज्यावेळी औद्योगिक वसाहती निर्माण करावयाच्या होत्या, त्यावेळी नवीन मुंबईत देखील मोठया प्रमाणात कारखाने उभे राहिले. नवीन मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्यामुळे तेथे मोठमोठे कारखाने उभे राहिले. या कारखान्यांसाठी ज्या ज्या भूमिपुत्रांनी जमिनी दिल्या आहेत, त्या जमिनीवरील मोठ मोठे कारखाने कारखानदारांनी जाणीवपूर्वक बंद पाडले आहेत. नवीन मुंबईत नोसील, स्टॅन्डर्ड अल्कली, फायझर असे अनेक मोठे कारखाने आजच्या परिस्थितीत बंद आहेत. बंद पडलेल्या कारखानदारांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीला विकण्यात आल्या आहेत. बंद पडलेल्या कारखानदारांच्या मालकांनी रिलायन्स कंपनीला जमिनी

2...

श्रीमती मंदा म्हात्रे...

विकून कोटयावधी रुपयांची संपत्ती जमा केली आहे. सदर कारखाने जाणीव पूर्वक बंद करून त्या कारखान्यातील भूमिपुत्र असलेल्या कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम मोठया प्रमाणात केले गेले आहे. आज त्या कारखान्यातील भूमिपुत्र कामगारांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. त्यातील बरेच कामगार वयोवृद्ध झालेले आहेत. त्यांना एक वेळ अन्न मिळत नाही, अशी त्यांची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज त्या परिसरातील अनेक कारखाने बंद करून तेथील जमीन विक्री करून कारखानदार दुसरीकडे कारखाने सुरु करीत आहेत. त्यामुळे कारखान्यातील कर्मचा-यांवर बेरोजगाराची वेळ येत आहे, त्यामुळे या महत्वाच्या गोष्टीकडे शासन लक्ष देईल काय ? ज्या भूमिपुत्रांनी एम.आय.डी.सी.साठी जमीन दिली असेल त्यांना साडेबारा टक्केतून भूखंड देण्यात यावा अशा प्रकारचा निर्णय आदरणीय श्री. शरद पवार यांनी घेतला आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे काही प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना भूखंड वितरीत करण्यात आले आहेत. परंतु अजून अनेक प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील भूखंड वितरीत केले गेलेले नाहीत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापर्यंत साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील भूखंड दिले गेले नाहीत, त्यांना तातडीने भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील काय ? कूळ कायद्याखाली नावावर असलेल्या जमिनी विकता येत नाहीत, अशी माझी माहिती आहे परंतु मला शासनाकडून उत्तर हवे आहे की कूळ कायद्याखाली नावावर असलेल्या जमिनी विकता येत नाहीत काय ?

श्री. राणा जगजितसिंह पाटील : नवीन मुंबईतील एम.आय.डी.सी.साठी भूमिपुत्रांनी जमिनी दिल्या आहेत, त्यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील भूखंड अद्याप मिळाले नाहीत अशा प्रकारचा विषय सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केली तर त्यांच्या मागणीचा निश्चितपणे विचार करण्यात येईल.

श्रीमती मंदा म्हात्रे : सभापती महोदय, प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी करण्याचा प्रश्न येत नाही. काही प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतून भूखंड दिले आहेत. काही प्रकल्पग्रस्तांना अजून भूखंड मिळालेले नाहीत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वितरीत केले गेले नाहीत त्यांना तात्काळ भूखंड देण्यात येतील काय ?

यानंतर श्री. कानडे....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

ZZ-1

SSK/ SBT/ KTG/

15:35

लक्षवेधी सूचना क्र. 2 पुढे सुरु....

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्रीमती उषा दराडे)

राणा जगजितसिंह पाटील : सभापती महोदया, 12.5 टक्के योजनेतील जे अर्ज प्रलंबित आहेत ते तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

श्री. जितेंद्र आव्हाड : सभापती महोदया, जॉन्सन टाईल्स आणि वायमन गार्डन या दोन कंपन्यांची उदाहरणे देण्यात आली. परंतु ज्या खाजगी जमिनी आहेत आणि शासनाने ॲक्वायर केलेल्या आहेत त्याठिकाणी बांधकामे होत आहेत. त्याठिकाणी एव्हरेस्ट नावाचा प्रकल्प सुरु झालेला आहे. ॲक्वायर जमिनीवर बांधकामे होत असतील तर ती थांबवून त्याची चौकशी शासन करणार आहे काय ?

(उत्तर आले नाही)

तालिका सभापती : आता पुढील लक्षवेधी सूचना पुकारण्यात आली आहे.

.....2

पृ. श्री. : मुंबईतील डंपिंग गाऊंडच्या परिसरातील नागरिकांना होणारे विविध आजार

मु. श्री. : मुंबईतील डंपिंग गाऊंडच्या परिसरातील नागरिकांना होणारे विविध आजार यासंबंधी सर्वश्री चरणसिंग सप्रा, संजय दत्त, एस.क्यु.जामा, सुभाष चव्हाण, गोविंदराव आदिक,वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री. संजय दत्त (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदया, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"मुंबई येथील गोराई, मुळुंड आणि देवनार अशी एका पाठोपाठ एक क्षेपणभूमिवर डंपिंग ग्राऊंड उभारण्यात आल्याने परिसरातील सुमारे २५ लाख नागरीकांना श्वसनाचा, डोळ्यांचा व घशाचा आजार झाल्याचे माहे मार्च, २००८ मधील शेवटच्या आठवड्यात आढळून येणे, तसेच काही नागरीकांना हृदय विकाराचाही धोका निर्माण झाल्याचे आढळून येणे, काही ठिकाणी कच्यांचे सात मजल्याएवढे ढीग वाढल्याचे आढळून येणे, तसेच या डंपिंग ग्राऊंडवर बेकायदेशीररित्या कचरा जाळण्यात येत असल्याचे आढळून येणे, त्यामुळे या परिसरातील नागरीकांनी तीव्र निर्दर्शने व एक दिवसाचे उपोषण करण्यात येणे, तसेच पालिका आयुक्तांना वारंवार निवेदने देऊनही यासंबंधी पालिकेचे याकडे होत असलेले दुर्लक्ष, यामुळे या परिसरातील २५ लाख रहिवाशांमध्ये होत असलेला तीव्र असंतोष व संतापाची भावना, सबब या डंपिंग ग्राऊंडवर वाढत असलेले कच्यांचे ढीग तसेच नागरीकांच्या आरोग्याला होत असलेला धोका रोखण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कार्यवाही व शासनाची भूमिका."

श्री. राजेश टोपे (नगरविकास मंत्री) : सभापती महोदया, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

तालिका सभापती (श्रीमती उषा दराडे) निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...3

निवेदनानंतर

श्री. संजय दत्त : सभापती महोदया, अत्यंत महत्वाच्या आणि जिल्हाळाच्या विषयावर मी लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली आहे. यापूर्वीच्या अधिवेशनात सुध्दा डंपिंग ग्राउंड आणि त्याच्या रिलेटेड प्रॉब्लेम्स् विषयी सभागृहात चर्चा उपस्थित केली होती तरी सुध्दा परिस्थिती जैसे थे आहे. परंतु येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, लक्षवेधी सूचनेवर जे निवेदन करण्यात आले आहे ते वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. मूळ समस्येकडे डोळेझाक करण्याचा हा प्रकार आहे. सभापती महोदया, मी प्रामुख्याने दोन मुद्दे शासनाच्या निर्दर्शनास आणून देऊ इच्छितो. निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे की कोणतेही आंदोलन झालेले नाही. परंतु डंपिंग ग्राउंडच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे एवढे हाल होत आहेत की येथील नागरिक स्थलांतर करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. डंपिंग ग्राउंडवर कोणत्याही प्रकारची ट्रीटमेंट करून कवऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरु झालेले आहे. त्यामध्ये स्थानिक डॉक्टरसुध्दा सामील आहेत. Smoke affected Residents Federation संघटना स्थापन झालेली आहे. श्वसनाचा आजार, घसा सुजणे, डोळयांमध्ये जळजळ होणे असे आजार पसरू लागले आहेत. याबाबतीत Municipal solid waste management and handling Rules प्रमाणे डंपिंग ग्राउंड कशी असावीत यासंबंधी नियम आहेत. विशेषत: डंपिंग ग्राउंड लोकवस्तीपासून दूर असावे, पाण्याच्या स्त्रोतापासून दूर असावे, शहराच्या विकासामध्ये अडथळा येणार नाही हे पाहिले जावे. परंतु नियमाचा भंग करून विकासाची कामे सुरु झालेली आहेत. नियमांचे पालन होत नाही. त्यामुळे आरोग्याचा कचरा झालेला आहे. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की, याबाबातचे नियम पाळले जातात किंवा नाहीत हे तपासण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती स्थापन करून या डंपिंग ग्राउंडची तपासणी केली जाईल काय ?

नंतर श्री. भोगले

लक्षवेधी सूचना क्र.3.....

श्री.संजय दत्त.....

नवी मुंबईमध्ये देखील हा प्रश्न भेडसावत आहे. ही केवळ मुंबईची समस्या नसून राज्यातील अनेक शहरात ही समस्या निर्माण झालेली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने युकेमधील एका कंपनीबरोबर टायअप करून एक प्रकल्प तयार केला आहे. त्या प्रकल्पाद्वारे वीज निर्मिती होत आहे याची शासनाला जाणीव आहे. अशा प्रकारचा प्रकल्प मुंबईमध्ये कार्यान्वित करण्याचा शासन विचार करील काय? जेणेकरून कच्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लागेल आणि वीज निर्मिती होऊ शकेल. सभापती महोदया, मला बोलण्यास अधिक वेळ दिल्याबदल धन्यवाद.

श्री.राजेश टोपे : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सन्माननीय सदस्यांनी या प्रश्नाबाबत अर्धातास चर्चा उपस्थित केली होती, परंतु वेळेअभावी त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मुंबईतील डंपिंग ग्राऊंडचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. मुंबईमध्ये देवनार, मुलुंड व गोराई येथे डंपिंग ग्राऊंड असून कांजूरमार्ग येथे नवीन डंपिंग ग्राऊंड तयार करीत आहोत. गोराई येथील डंपिंग ग्राऊंड बंद करीत आहोत. देवनार आणि मुलुंड येथील डंपिंग ग्राऊंड सध्या वापरात आहेत. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, 2000 नुसार जी कारवाई करावयास पाहिजे ती आज होत नाही हे स्पष्टपणे मी सांगू इच्छितो. आजच्या परिस्थितीत शॉर्ट टर्म प्लॅन आणि लॉग टर्म प्लॅनचा विचार करीत असताना शॉर्ट टर्म प्लॅनच्या माध्यमातून दुर्गंधी पसरू नये म्हणून डिऑडरंटची फवारणी करणे, आग लागल्यास पाण्याची फवारणी करणे या गोष्टी केल्या जातात. हा तात्पुरता उपाय आहे. लॉग टर्म प्लॅनिंग करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महानगरपालिकेने दोन-तीन महत्वाच्या गोष्टी करण्याचा निश्चय केलेला आहे. यात प्रामुख्याने बिल्ट ऑपरेट अँड ओन या धर्तीवर नवी मुंबई महापालिकेचे उदाहरण सांगितले त्या धर्तीवर मुंबईमध्ये वीज निर्मिती प्रकल्प आणि खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. देवनार येथे खत निर्मिती करण्याचे नियोजन केले असून मुलुंड येथे वीज निर्मिती करण्याचे नियोजन केले आहे. कांजूरमार्ग येथे 4500 हजार मे.टनचा नवीन डंपिंग ग्राऊंड तयार करीत आहोत, तेथे खत निर्मिती प्रकल्प उभारणार आहोत. त्यासाठी 70 हेक्टर जमीन ताब्यात आलेली आहे. वीज निर्मिती आणि खत निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आम्ही नियोजन करीत आहोत. पुढील 4-5 महिन्याच्या आत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट, बिल्ट ऑपरेट अँड ओन या पद्धतीने टेंडर मागविले आहेत. त्याचे

..2..

श्री.राजेश टोपे.....

फायनलायझेशन आणि ॲक्च्युअल प्रक्रिया पुढील चार महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल. खन्या अर्थाने प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल त्यावेळी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आणि हॅण्डलिंग रूल्सचे पालन होईल. तीन-चार महिन्याच्या आत या सगळ्या बाबी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावरुन महानगरपालिकेला कडक पद्धतीच्या सूचना दिल्या जातील. सन्माननीय सदस्यांनी सभागृहावी समिती नेमणार का? असा प्रश्न उपरिथित केला आहे. निश्चितपणे सभागृहाची समिती करण्यास कोणतीही हरकत नाही. जरुर एखादी समिती तयार केली जाईल. समितीने त्याठिकाणी भेट देऊन समितीच्या माध्यमातून म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हॅण्डलिंग रूल्स ॲड रेग्युलेशन्स पाळले जात नाहीत त्या संदर्भात समितीच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. त्या सूचनांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हॅण्डलिंग रूल्स 100 टक्के पाळले पाहिजेत या संदर्भात कारवाई करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या वतीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील.

(नंतर श्री.जुन्नरे....)

श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, डंपिंग ग्राऊंडचा विषय गंभीर बनलेला आहे. मुंबईची सर्व घाण ठाण्यामध्ये टाकली जाते. मुंबईमधून कुत्रे हलविणार, तबेले हलविणार, ठाण्याचे पाणी मुंबईला घेऊन जाणार असे काम सुरु आहे. मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडमुळे ठाणे रहिवाशयांना त्या दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. मागील अधिवेशनामध्ये माननीय मंत्रीमहोदयांनी मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंड टेंपररी आहे व ते लवकरच हलवणार आहोत असे सांगितले होते. त्यामुळे मुलुंडचे डंपिंग ग्राऊंड आपण कधी हलविणार आहात? ठाणे जिल्हयाला 6 महापालिका आहेत त्यामुळे या इतक्या तारखेपर्यंत डंपिंग ग्राऊंड उपलब्ध केले पाहिजे यासंदर्भात शासन काही निश्चित भूमिका घेणार आहे काय? अनेक ठिकाणी डंपिंग ग्राऊंड उपलब्ध नाही त्यामुळे कच-याच्या गाडया कचरा उचलतात आणि आपल्या सोयीनुसार कोठेही टाकतात त्यामुळे माझ्या दोन प्रश्नाचे उत्तर माननीय मंत्रीमहोदयांनी द्यावे अशी विनंती आहे.

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडमुळे ठाणेकरांना त्रास होतो हे कोणीही नाकारु शकणार नाही, यासंदर्भात ठाणेकरांची नेहमीच तक्रार असते. मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येते आणि त्यापासूनच ठाणे महानगरपालिका सुरु होते. मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडमुळे ठाणेकरांना त्रास होतो हे मी मागे सुध्दा कबूल केले होते. हे डंपिंग ग्राऊंड केव्हा हलवणार आहात असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. कांजूरमार्ग येथे डंपिंग ग्राऊंड करू पाहत आहोत. हे डंपिंग ग्राऊंड हलवण्याचा आज तरी निश्चय केलेला नाही. प्रत्येक डंपिंग ग्राऊंडची एक वयोमर्यादा असते. मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडची वयोमर्यादा अजून संपलेली नाही नसून पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी जागा उपलब्ध झालेली नाही. कांजूरमार्ग येथे डंपिंग ग्राऊंडसाठी जमीन मिळावयास पाहिजे होती परंतु खारपान पट्टा आणि सीआरझेडमुळे अडचणी निर्माण झालेली असल्यामुळे या ठिकाणची पूर्ण जमीन मिळत नाही. कांजूरमार्ग येथे काही हेक्टर जमीन आम्हाला डंपिंग ग्राऊंडसाठी मिळावयास मिळणार आहे. एमएमआर रिजनमध्ये मुंबई, ठाणे आणि रायगड येथे कॉमन फॅसेलिटी डेव्हलप करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मुंबई शहरात डंपिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध होत नाही. यासंदर्भात एमएमआरडीएने जे प्लॅन केलेले आहे त्याबाबतीत सभागृहात चर्चा झालेली आहे की, कॉमन फॅसेलिटी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटसाठी करण्याचा निश्चय केलेला आहे. हे काम लवकर कसे केले जाईल यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करू इच्छितो कारण हा गंभीर

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3B-2

SGJ/ KTG/ SBT/

15:45

श्री. राजेश टोपे....

असा विषय आहे. मुंबईत जमीन मिळत नाही परंतु मुंबईच्या बाहेर का होईना जमीन लवकर उपलब्ध करून शास्त्रोक्त पद्धतीने डंपिंग ग्राऊंड कसे असावे याचा विचार केला जात आहे. ओलासुका कच-याचा उपयोग कसा करून घेता येईल हे पाहिले जात आहे. खरे म्हणजे ओळ्या कच-यापासून चांगल्या प्रकारचे गांडूळखत तयार होऊ शकते व वाढलेल्या कच-यापासून वीज तयार होऊ शकते. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचे नियोजन आम्ही करीत आहोत. तसेच डंपिंग ग्राऊंडच्या दुर्गंधीचा त्रास होऊ नये यासाठी डिओइंट आणि पॉवडर फवारणी केली जात असते. एवढे मात्र नक्की केले जाईल की, त्या ठिकाणची एअर क्वॉलिटी एमपीसीबीच्या नियमाप्रमाणे व्यवस्थित राहील याची तपासणी करून त्या प्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

श्री. जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. संजय दत्त यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्या प्रश्नाचे उत्तर माननीय मंत्रीमहोदयांकडून मिळालेले नाही. माननीय मंत्रीमहोदयांनी डंपिंग ग्राऊंडच्या संदर्भात ज्या अडचणी सांगितल्या आहेत त्यापेक्षा किती तरी जास्त अडचणीना महानगरपालिकेला तोंड द्यावे लागत असते. शहरापासून डंपिंग ग्राऊंड किती अंतरावर असावे यासाठी जे नॉर्म्स आहेत ते नॉर्म्स आपण बदलणार का? त्यासाठी वाहतुकीचा जो खर्च येतो त्यासाठी आपण नॉर्म्स बदलले तरच काही तरी सुधारणा होऊ शकते. त्यामुळे शासन निश्चित असे धोरण जाहीर करणार आहे काय?

यानंतर श्री. गायकवाड....

श्री.जयंत प्र.पाटील ...

हे डम्पीग ग्राऊन्ड लोकवस्तीपासून किती दूर अंतरावर असले पाहिजे.या बाबतीत जे नॉर्म्स ठरविण्यात आलेले आहेत ते बदलण्यात येणार आहे काय ? अलिबाग नगरपालिकेचे डम्पीग ग्राऊन्ड हे गावापासून दहा किलोमिटर्स अंतरावर नेण्याचा प्रस्ताव आहे त्या ठिकाणी करावयाची वाहतूक मात्र नॉम्समध्ये बसत नाही म्हणून तो प्रकल्प थांबलेला आहे. मुरुड तालुका माझ्या तालुक्यापासून जवळ आहे आणि मुरुड नगरपालिकेने लोकवस्तीपासून दहा फुटावर डम्पीग ग्राऊन्डला परवानगी दिली आहे तेव्हा तेथील मुख्य अधिका-यांनी विरोध केला होता काय ? अधिकारी ऐकत नाहीत अशा प्रकारे मघाशी सन्माननीय मंत्री महोदयांनी गोलगोल उत्तर दिले आहे.ते उत्तर चुकीचे आहे. जेथे डम्पीग ग्राऊन्ड लोकवस्तीपासून जवळ आहे त्या संदर्भात मुख्य अधिकारी किंवा महानगरपालिकेचे आयुक्त या दोघांनी विरोध केला होता काय ? आणि जर विरोध केला नसेल तर सबंधिताविरुद्ध आपण कोणती कारवाई करणार आहात ? त्याचप्रमाणे या संदर्भात जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्या समितीमध्ये सदस्य म्हणून काम करण्याची माझी इच्छा आहे याची नोंद माननीय मंत्री महोदयांनी घ्यावी.

श्री.राजेश टोपे : सभापती महोदया, डम्पीग ग्राऊन्ड वस्तीपासून किती दूर असले पाहिजे असा सन्माननीय सदस्य सर्वश्री जयंत प्र.पाटील , संजय दत्त या दोघांचाही प्रश्न आहे. म्युनिसिपल सॉलीड वेस्ट रुल्स 2000 साली बनविण्यात आले असून त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी अतिशय सुस्पष्टपणे सांगितलेल्या आहेत. मुलुड, देवनार या ठिकाणी डम्पीग ग्राऊन्ड असून ते अतिशय जुने आहेत. 1968 आणि 1927 साली तेथे डम्पीग ग्राऊन्ड तयार करण्यात आले होते. परंतु आता नव्याने जे डम्पीग ग्राऊन्ड तयार करण्यात येईल तेव्हा 2000 च्या एम.एस.डब्ल्यू.मधील रुल्स, अटी, शर्टी,आहेत त्या 100 टक्के पाळल्या जातील असे मी सभागृहाला आश्वासित करू इच्छितो. मुख्य अधिकारी अलिबाग.....

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदया, मुरुडमध्ये डम्पीग ग्राऊन्डच्या बाबतीत तेथील नगरपालिकेच्या मुख्य अधिका-यांनी किंवा सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे मुलुंड येथे डम्पीग ग्राऊन्डच्या बाबतीत महानगर पालिकेच्या आयुक्तांनी काय केले आहे ? ...

श्री.राजेश टोपे : मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, मुलुंड येथील डम्पीग ग्राउन्ड 1968 सालातील आहेत. त्या काळात डम्पीग ग्राउन्ड ठरविण्यात आलेले असल्यामुळे त्याकाळात कदाचित तेथे वस्ती नसेल. आज पासून 40 वर्षांपूर्वी तेथे किती वस्ती असेल हे आताच सांगता येणार नाही परंतु मी एवढेच सांगू इच्छितो की, या डम्पीग ग्राउन्डचे आयुर्मान दोन वर्षांचे राहिलेले आहे. दोन वर्षांनंतर मुलुंडचे डम्पीग ग्राउन्ड शास्त्रीय पद्धतीने बंद करण्यात येईल. त्याचबरोबर नवीन जे डम्पीग ग्राउन्ड करण्यात येणार आहे त्यावेळी एम.एस.डब्ल्यू.2000 च्या रुल्सचे ततोतंत पालन केले जाईल. एवढा विश्वास मी देऊ इच्छितो. या संदर्भात नेमण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये या सभागृहातील ज्या सन्माननीय सदस्यांची काम करण्याची इच्छा असेल त्यांनी त्याप्रमाणे कळवावे म्हणजे त्यांची नावे या समितीमध्ये घेण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांना या समितीमध्ये नक्कीच घेण्यात येईल.

डॉ.वसंत पवार : सभापती महोदया, आपल्या मार्फत मला माननीय मंत्री महोदयांना असा प्रश्न विचारावयाचा आहे की, मुंबईची लोकसंख्या 2030 साली 1 कोटी 71 लाख एवढी गृहीत घरण्यात आलेले आहे आणि प्रती दिन 10 हजार टन कचरा राहील असे गृहीत घरलेले आहे कच-यापासून खत आणि वीज निर्मिती प्रकल्प करण्यात येणार आहे. नागरी घन कचरा नियमावली ही केन्द्र शासनाची असून त्यांच्याकडे आपला प्रोजेक्ट रिपोर्ट त्यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ डॉ.वसंत गोवारीकर यांनी बायो मेडिकल वेस्टच्या संदर्भात एक अहवाल मुंबई महानगरपालिकेला किंवा शासनाला सादर केला आहे काय ? या ठिकाणच्या डॉक्टरांच्या हॉस्पिटल्सच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये अनेक रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून निकामी झालेले अवयव काढून कच-यात टाकले जातात. तेव्हा त्या अवयवाची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायो मेडिकल वेस्ट कायदा आहे त्यानुसार डम्पीग ग्राउन्डमध्ये किंवा मुंबईमध्ये

नतर श्री.सुंबरे

डॉ. वसंत पवार

इन्सुलेटरची काही व्यवस्था आपल्याकडे आहे काय ? असल्यास, त्या ठिकाणी ती कोठे कोठे केलेली आहे ? सभापती महोदया, हे दोन महत्वाचे प्रश्न मी येथे विचारले आहेत. मात्र आपल्या निवेदनामध्ये आजूबाजूच्या लोकांना श्वसन, हृदय विकाराचा तसेच घशाचे आजार वगैरेचा त्रास होत नाही असे जे उत्तर दिलेले आहे ते विश्वास ठेवण्यायोग्य वाटत नाही. कारण डंपिंग ग्राउंड म्हटले म्हणजे त्या भागामध्ये डास, माशा वगैरे मोठ्या प्रमाणात असतात कारण त्या ठिकाणी कुजण्याची क्रिया ही सतत चालू असते आणि त्यामुळे त्या परिसरात रोगराई वाढू शकते. तेव्हा त्या दृष्टीनेही आपण तेथे काही उपाय करणार आहात काय ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.पवार यांनी बायो-मेडिकल वेस्ट संबंधात प्रश्न विचारला आहे त्याबाबत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, बायो-मेडिकल वेस्ट हॅंडलिंग अँण्ड मॅनेजमेंट रूल्स हा देखील एक कायदा आहे आणि त्या कायद्यांतर्गत तळोजा येथे इन्सुलेटर ठेवून मुंबई शहरातील सर्व रुग्णालये व दवाखान्यांतून निघणारा बायो-मेडिकल वेस्ट आहे तो तेथे जमा केला जातो आणि ऑटो-फ्लिअर करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदया, या डंपिंग ग्राउंड संबंधात एक पीआयएल श्री.संदीप राणे या नागरिकाने केली होती आणि त्या संदर्भात कोर्टाने काही निकष दिले होते. म्हणजे तेथील वायूची गुणवत्ता किती असावी म्हणजे थोडक्यात त्याची मोजणी करणारी यंत्रणा बसविण्यास सांगितले होते जेणे करून अशा प्रकारची दुर्गंधी त्या परिसरात येऊ नये आणि हवेतील सर्व दूषित वायूंचे प्रमाण कमी व्हावे, त्याची मोजणी व्हावी. तर अशी जी यंत्रणा तेथे लावण्यास कोर्टाने सांगितले होते तशी आपण ती लावणार काय ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदया, कोर्टाच्या सूचना असतील तर जरुर तशा प्रकारची यंत्रणा लावली जाईल.

श्री. अरविंद सावंत : सभापती महोदया, हा प्रश्न मुळात कशातून निर्माण होतो ? यामध्ये सरकार वा महापालिका कोणीही असू घात, जसे वनखात्याच्या जमिनीवर आम्ही घरे बांधणार आणि नंतर त्याबद्दल ती तशीच रहावीत म्हणून ओरडही करणार असा हा प्रकार आहे. पूर्वी जी ही डंपिंग ग्राउंडस् होती ती मुंबईच्या बाहेर दूर अंतरावरच होती. मुलुंड येथील डंपिंग ग्राउंडही त्याला अपवाद नाही. पण असे असतानाही त्याच्या जवळ, शेजारी निवासी गाळे बांधण्यासाठी

..... 3डी 2 ..

श्री. अरविंद सावंत

परवानगी कोणी दिली ? म्हणजे सुरुवातीला लोकच कोठेच जागा नाही म्हणून तेथे येतात आणि नंतर ते डंपिंग ग्राऊंड तेथून हलवावे म्हणून तक्रार करतात. म्हणून आपण त्या डंपिंग ग्राऊंडचा एक परीघ आखून घावा आणि त्या परिघाच्या आत कोणालाही निवासी गाळे बांधता येणार नाहीत असे करा. तर असा कायदा आपण करणार का ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्यांची सूचना चांगली आहे, तेहा त्या प्रकारे कारवाई केली जाईल.

श्रीमती अलका देसाई : सभापती महोदया, मुलुंड मधील डंपिंग ग्राऊंड आता कांजूरमार्ग मध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ते स्तुत्य आहे. परंतु याचे काम केव्हा पूर्ण होणार आहे ? कारण आज त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता देखील नाही, अगदी गाडी देखील तेथे जाऊ शकत नाही. दुसरे असे की, मुंबई महापालिका यासाठी फारसे उत्सुक नाही हे खरे आहे का ?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदया, कांजूरमार्ग या ठिकाणी आपण नवीन डंपिंग ग्राऊंड करीत आहोत, मुलुंडचे तेथे स्थलांतरित केले जात नाही. त्यासाठी तेथे 70 हेक्टर जमीन आपल्याला मिळालेली आहे आणि त्या ठिकाणी त्यातून नवीन खत निर्मितीचे काम देखील करण्यात येणार आहे.

श्री. रमेश शेंडगे : सभापती महोदया, मुलुंड हे मुंबईचे प्रवेशद्वार आहे आणि त्यात काय दुर्घटित होते ते सन्माननीय सदस्य श्री. केळकर यांनी सांगितले आहे. सभापती महोदया, मुलुंड येथे हे डंपिंग ग्राऊंड आहे आणि त्याच्या जवळच ठाण्याच्या परिसरात मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांची वस्ती आहे तेथे अनेक मोठे अधिकारी लोक राहतात.

(यानंतर श्री. सरफरे 3इ 1 ..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3E 1

DGS/ KTG/ SBT/

16:00

श्री.रमेश शेंडगे...

त्याठिकाणी 1927 सालापासून डंपिंग ग्राऊंड आहे. तेथील अनेक लोकांना श्वसनाचा त्रास होत आहे, अनेक लहान मुले श्वसनाच्या त्रासामुळे हॉस्पिटलमध्ये अँडमिट आहेत. मी स्वतः मुलुंडचा रहिवाशी आहे. या डंपिंग ग्राऊंडच्या विरोधात मी अनेक वेळा आंदोलन केले आहे. असे असतांना निवेदनात आंदोलन, उपोषण करण्यात आले नाही असे म्हटले आहे. माझा प्रश्न असा आहे की, एकदा डंपिंग ग्राऊंडची जागा निश्चित केल्यानंतर त्या जागेवर किती कवरा टाकावा याची क्षमता ठरविण्यात आली आहे काय? या जागेवर 1968 सालापासून कवरा टाकला जात आहे. तो थांबवून आपण हे डंपिंग ग्राऊंड किती दिवसात दुसरीकडे हलविणार आहात?

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा आहे. जे झाले आहे ते आपण मान्य केले आहे. एम.एस.डब्लू. रुलप्रमाणे आपण एखादी गोष्ट ठरविल्यानंतर ती तातडीने उद्या करु शकत नाही. परंतु याकरिता आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दुसरीकडे जमीन कशी मिळविता येईल याबाबत विचार करण्याकरिता मी स्वतः या वरिष्ठ सभागृहातील तज्ज्ञ व या क्षेत्रामध्ये काम करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वच माननीय सदस्यांचे विचार ऐकून घेऊन त्यादृष्टीने यावर्षी तातडीने पावले उचलली जातील. आणि या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला तीन महिन्यांचा टाईम बाऊंड कालावधी दिला असून या कालावधीत कांजुरमार्ग, देवनार आणि मुलुंड या तीनही ठिकाणी बी.ओ.ओ. पृथक्तीने कचन्यावर प्रक्रिया करावयाच्या कामासंबंधीचा निर्णय तीन महिन्यात निश्चितपणे घेतला जाईल.

DGS/ KTG/ SBT/

पृ.शी. : हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला शासनातर्फे करावयाचा भागभांडवल पुरवठा

मु.शी. : हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला शासनातर्फे करावयाचा भागभांडवल पुरवठा यासंबंधी सर्वश्री. मधुकर चव्हाण, विनोद तावडे, रामनाथ मोते, संजय केळकर, वि.प.स. यांनी दिलेली लजवेधी सूच-गा

श्री. मधुकर चव्हाण (मुंबई स्थानिक प्राधिकारी संस्था) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अ-वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिज महत्वाच्या बाबीजडे आपल्या अनुमतीने स-मा-नीय अन्न व औषधिद्रव्ये प्रशासन मंत्रांचे लज वेधू इच्छितो आजि त्याबाबत त्यांनी निवेदन जरावे. अशी विनंती जरतो.

"मुंबईतील हाफकिन संस्थेची स्थापना सन १९४० मध्ये होणे, या संस्थेमध्ये विविध प्रकारच्या जीवनावश्यक औषधांचे व लसींचे उत्पादन करण्यात येणे, या उत्पादनाचा दर्जा इतर खाजगी उत्पादनाच्या तुलनेत उच्च असूनही ती औषधे रास्त भावाने जनतेला उपलब्ध करून देणे, देशातील गोरगरीब जनतेला विविध आरोग्य सेवांतर्गत या औषधांचा पुरवठा केला जाणे, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ उत्पादन सुविधांमध्ये अनुसुचि (Revised Schedule M) प्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी अधिकचे भाग भांडवल देऊन मदत करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविणे, या मदतीअंतर्गत होणारा खर्च अंदाजे १०० कोटी रुपये असून त्यातील सुमारे ५० कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाने भाग भांडवल म्हणून उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी संचालक मंडळाकडून करण्यात येणे, परंतु शासनाने मात्र मार्च २००८ च्या अर्थसंकल्पामध्ये निव्वळ दोन कोटी रुपयांचीच तरतूद करणे, परिणामतः राज्यातील गोर-गरीब जनतेला कमी दरात पुरविण्यात येणाऱ्या जीवरक्षक औषधांच्या व लसींच्या निर्मितीवर परिणाम होणे, त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाला करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत जनतेच्या मनात निर्माण झालेली अविश्वासाची व संतापाची भावना यावर शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची प्रतिक्रिया."

श्री. बाबा सिद्धीकी (अन्न व औषधिद्रव्ये प्रशासन राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महाराज, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरीत केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3E 3

DGS/ KTG/ SBT/

तालिका सभापती : निवेद-न सभाजृहाच्या पटलावर ठेवज्यांत आले आहे.

निवेद-न

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेद-न छापावे)

श्री. मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, हाफकिन इंस्टिटयुटमध्ये हे शासन भ्रष्टाचाराला कसा वाव देत आहे, आणि खाजगी कंपनीला कोटयावधी रुपयांची लूटमार करण्याची कशी संघी देत आहे याचे उदाहरण माझ्याजवळ आहे. हाफकिन इंस्टिटयुटमध्ये जीव रक्षक औषधे व वेगवेगळ्या लसींची निर्मिती होते. त्यामधे घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, टॉयफॉईड इत्यादी आजारांच्या बाबतीत लसीकरण केले जाते. ही लक्षवेधी सूचना दिनांक 26 नोव्हेंबर 2007 रोजी नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आली होती. त्यावेळी दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. एक तर औषध निर्माण महामंडळाचे उत्पादन अनुज्ञाप्ती "एम" प्रमाणे सुधारण न केल्यामुळे 27 एप्रिल 2007 रोजी बंद केले. तेव्हा प्रश्न असा आहे की, उत्पादन बंद केल्यामुळे महामंडळाचे किती नुकसान झाले आहे? हाफकिन दरवर्षी 4 ते 5 कोटी मुलांना लस देते. सन 2001-02 मध्ये 2 कोटी 54 लाखाची ऑर्डर होती, सन 2002-03 मध्ये 4 कोटी 39 लाखाची ऑर्डर होती, आणि सन 2003-04 मध्ये 2 कोटी 60 लाखाची ऑर्डर होती. असे असतांना दुसऱ्या खाजगी कंपनीचा टी.टी.व्हॅक्सिनचा भाव 15 रुपये आहे तर हाफकिनचा भाव 6 रुपये आहे. यामध्ये एका व्हाईलच्या किंमतीमध्ये 8 रुपयांचा फरक आहे. केंद्र सरकारची वार्षिक मागणी 150 लाखाची आहे. खाजगी कंपनीचे डी.टी. व्हॅक्सिन 9 रुपयांना मिळते तर हाफकिन इंस्टिटयुटचे 7.49 पैशयांना मिळते. खाजगी कंपनीचे डी.पी.टी. व्हॅक्सिन 37 रुपयांना मिळते, व हाफकिन इंस्टिटयुटचे 13 रुपयांना मिळते. यामध्ये 24 रुपयांचा फरक आहे. अशाप्रकारे आपले अधिकारी एक वर्षापासून बदमाशगिरी करीत आहेत. खरे म्हणजे त्यांना मंत्रालयामध्ये बेडया घालून खाली आणले पाहिजे, त्यांना अंडा सेलमध्ये ठेवले पाहिजे. एक वर्षभर उत्पादन बंद ठेवल्याबदल तुमच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना लाज वाटत नाही? अशाप्रकारे खाजगी कंपनीला कोटयावधी रुपयांची उधळपट्टी करावयास देता. त्याठिकाणी व्हॅक्सिनची किंमत 37 रुपये असतांना हाफकिन इंस्टिटयुट 13 रुपयांना देते. सभापती महोदय, आज 10 एप्रिल ही तारीख आहे.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

श्री.मधुकर चव्हाण

शासनाने एक वर्ष उत्पादन बंद केलेले आहे. दोन कारणे होती. त्यांनी 100 कोटीचा एक प्रोजेक्ट दिला. यामध्ये ते 50 कोटी रुपये उभे करणार आणि 50 कोटी रुपये शासनाने द्यावयाचे आहेत. पण शासनाने बजेटमध्ये किती प्रोहीजन केली ? त्यादिवशी माननीय मंत्र्यांनी सांगितले की, बजेटमध्ये 2 कोटी रुपयांची प्रोहीजन करण्यात आली आहे. तसेच त्यादिवशी माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील सांगत होते की, आमच्या तिजोरीमध्ये खणखणाट आहे, पैसा कशासाठीही कमी पडणार नाही. बजेटच्या पुस्तकातील पान क्र.23 वर क्रमांक-16 मध्ये असे म्हटलेले आहे की, "हाफकीन संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धनसाठी-रुपये 2 कोटी." एवढे खर्च केले जाणार आहेत. यापूर्वी जेव्हा या विषयाच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती, तेव्हा शासनाने असे उत्तर दिले होते की, "सदर पत्र शासनास नुकतेच प्राप्त झाले आहे.

(काही सन्माननीय सदस्य खाली बसून बोलतात.)

मी प्रश्नच विचारत आहे. मघाशी लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चा 40 मिनिटे झाली आहे. मी जी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करीत आहे, ती सर्वसामान्य माणसांसाठी आहे. यापूर्वीची चर्चा चिड्या पाठवून 40 मिनिटे सुरु होती. याठिकाणी गैरहजर असलेल्यांच्या नावाने येथे मेंटल चिटींग करतात आणि आपली सूचना मंजूर होण्यापूर्वीच आपण काय बोललो, याची प्रेसमध्ये नोट पाठवितात अशी स्थिती आहे. आम्ही तसे करीत नाही.

तालिका सभापती (श्रीमती उषा दराडे) : सन्माननीय सदस्यांनी सभापतींना उद्देशून बोलावे.

श्री.मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, याठिकाणी असे म्हटलेले आहे की, "सदर पत्र शासनास नुकतेच प्राप्त झाले आहे. महामंडळाच्या वरील प्रस्तावामध्ये त्यांच्या विविध विभागाचे उन्नतीकरण/श्रेणीवर्धन करण्यासाठी आराखडा तयार केलेला आहे. यामध्ये विविध लसी तसेच जीवरक्षक औषधांचे उत्पादन करणे, त्यासाठी प्रयोगशाळेचे नुतनीकरण करणे इत्यादी विविध बाबीं साठीचा समावेश आहे. महामंडळास रु.50 कोटी भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रस्तावाची सखोल छाननी केली असता, त्यामध्ये बच्याच त्रुटी आढळून आल्या. माननीय मंत्री महोदयांनी मी काय वाचून दाखवतो ते नीट ऐकावे. पूर्वी दिलेले उत्तर आणि आता दिलेले जे उत्तर आहे, त्यासाठी मी बदमाशी असा शब्द वापरतो, लबाडी हा शब्द वापरत नाही. मी जबाबदारीने शब्द बोलत आहे. पुढे असे म्हटलेले आहे की, प्रामुख्याने प्रस्तावित खर्चाची रक्कम

. . . . 3 एफ-2

श्री.मधुकर चव्हाण

कोणकोणत्या बाबींसाठी खर्च होणार आहे, नेमका आराखडा काय आहे? याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी महामंडळाकडून शासन पत्र क्र.एचबीपी-2007/प्र.क्र.270/परि-उपक्रम, दिनांक 14-11-2007 च्या पत्रान्वये माहिती मागविण्यात आली आहे. तसेच हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ ही स्वायत्त संस्था असून, त्यास स्वतंत्र अधिकारीता आहे." त्यादिवशी आम्ही माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारला. मी माननीय मंत्री महोदयांचे अभिनंदन करतो. कारण ही जमीन रिलायन्सच्या घशात जाणार होती, पण आपण ती वाचविली. 50 कोटी रुपयांच्या बाबतीत त्यांनी काय केले ? तर आम्ही बाजारातून वित्तीय संस्थांमधून पैसे उपलब्ध करू. त्यासाठी 7/12 च्या उताऱ्यावर हाफकीनचे नाव द्यावे. पण केवळ 7/12 च्या उताऱ्यावर नाव देऊन चालणार नाही तर तसा जी.आर.काढला पाहिजे. पण माननीय मंत्री महोदयांनी 1 डिसेंबर रोजी असे उत्तर दिले की,

तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री.मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, मी प्रश्नच विचारत आहे आणि तो सन्माननीय सदस्यांप्रमाणे डेव्हल्प करीत आहे. त्यावेळी असे उत्तर दिले आहे की, "विचार-विनिमय करून मी जी.आर.काढणार आहे." यासंदर्भात मी विनंती केल्यानंतर आपण हिवाळी अधिवेशनामध्ये निवेदन केले आहे, त्यामध्ये असे म्हटलेले आहे की, "जमीन महसूल अभिलेख 7/12 च्या उताऱ्यामधील नोंदीनुसार कॉर्पोरेशनचे सदर 68.78 एकर जमिनीचे मालकी हक्क विचारात घेऊन कॉर्पोरेशनने वित्तीय संस्थेकडे कर्जासाठी अर्ज केला असता, जमीन हस्तांतरणाबाबतच्या अटी व शर्ती समाविष्ट असलेल्या हस्तांतरण करार पत्राची मागणी वित्तीय संस्थेने केली. त्याकरिता सदर जमिनीचे हस्तांतर कॉर्पोरेशनला करण्याच्या सविस्तर अटी व शर्ती असलेला शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित होणे आवश्यक आहे आणि तो मी जरुर करीन .

तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री.मधुकर चव्हाण : सभापती महोदया, आज जे निवेदन करण्यात आले आहे, त्यामध्ये असे म्हटलेले आहे की,"हाफकीन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने दि.27 मार्च 2008 रोजी इ आलेल्या बैठकीत असा निर्णय घेतला आहे की, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात इत्यादी लसीचे उत्पादन करण्याचा नवीन प्रकल्प उभारणे ही महामंडळाची प्राथमिकता असल्याने त्यासाठी सन

. . . .3 एफ-3

श्री.मधुकर चव्हाण

2008-2009 मध्ये शासनाने रु.15 कोटीचे भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य करावे आणि उर्वरित रु.35 कोटीचे अर्थसहाय्य टप्प्याटप्प्याने पुढील चार वर्षात हेपोटेटीस-बी लस, डीपीटीएच लस, गोवर लस वगैरेचे उत्पादन आणि संशोधन व विकास इत्यादीसाठी द्यावे. त्यानुसार अर्थ सहाय्य मिळण्याची विनंती महामंडळाने दिनांक 1-4-2008 रोजी शासनाकडे केली आहे. त्यास अनुलक्षून रुपये 15 कोटी अर्थसहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे दि.2 एप्रिल 2008 च्या पत्रान्वये महामंडळास कळविण्यात आले आहे." म्हणजे तसे तुम्ही पत्र पाठविलेले आहे ? माझा प्रश्न असा आहे की, तुम्ही त्यांच्याकडून नोव्हेंबरमध्ये सर्व माहिती मागविली. त्याप्रमाणे त्यांनी तुम्हाला सर्व माहिती दिली. मग तुम्ही त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची प्रोव्हीजन केली. त्यांनी तुमच्याकडे 50 कोटी रुपये मागितले नाहीत. तुम्ही त्यांना 15 कोटी रुपये देतो असे सांगितले. माझा प्रश्न असा आहे की, तुम्ही यासंबंधात जी.आर.काढला आहे का ? जर जी.आर.काढला नसेल तर का काढण्यात आला नाही ? हा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा की, या कंपनीला मान्यता न देता गेल्या वर्षभरात खाजगी कंपनीकडून भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून लुटण्यासाठी तुम्ही किती कोटी रुपयांची औषधे बाहेरुन गोळा केली ? तुम्ही ही फाईल पुन्हा का पाठविली ? तसेच तुम्ही 15 कोटी रुपये त्वारित कधी देणार आहात ? जी.आर.काढून 15 दिवसामध्ये त्यांच्या नावावर जपीन करणार आहात काय ? जेणेकरून त्यांना वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेता येईल.

यानंतर कु.गायकवाड

04-10-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3G 1

DVG/ MMP/ KGS/ प्रथम श्रीमती रणदिवे..

16:10

श्री. मधुकर चव्हाण...

वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जी.आर. काढण्याची आवश्यकता आहे. हा जी.आर. कधी काढला जाणार आहे ?

श्री. बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है. जब नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पूछा था तो मैंने आश्वासन दिया था कि रिलायन्स कंपनी के पास हाफकिन इन्सिटिट्यूट जाएगा. माननीय सदस्य ने जी.आर. निकालने के बारे में पूछा है. मैं इस बारे में सभागृह को बताना चाहता हूँ कि, We have to take conveyance from the Revenue and Finance Department. इस बारे में 10.03.2008 को मीटिंग ली गई और 14.03.2008 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास प्रस्ताव सभिट किया है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फायनेंस डिपार्टमेंट की कन्करेंस आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. माननीय सदस्य का कहना है कि एक लॅटर के तहत "सात-बारा" पर हाफकिन इन्सिटिट्यूट का नाम आएगा. कोलेट्रोल लेने के लिए प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फायनेंस डिपार्टमेंट का कन्करेंस आने के बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा.

सभापति महोदय, ऐसे बहुत से आयटम हैं, जिनकी रेट खाजगी कंपनी की कम है और हाफकिन इन्सिटिट्यूट की ज्यादा है. मैं यह जानकारी सभागृह के पटल पर रख सकता हूँ.

सभापति महोदय, यह बात सही है कि भारत सरकार ने जी.एम.पी. मतलब 'Government Manufacturing Process' का नियम 'Good Governance' और 'Good Management' के लिए बनाया है. जब हम वही नियम दूसरी फैक्टरी पर लागू करेंगे और खुद की फैक्टरी पर लागू नहीं करेंगे तो एक गलत संदेश जाएगा. इसलिए यह निर्णय लिया गया. हाफकिन इन्सिटिट्यूट ने जो रिपोर्ट भेजी थी, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी नहीं थी. मंजूरी लेने के बाद 1.4.2008 को लैटर आया और इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने दूसरे दिन ही हाफकिन इन्सिटिट्यूट को लैटर भेज दिया है कि आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजें. मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 15 दिन के अन्दर हाफकिन इन्सिटिट्यूट से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगा. इसको फायनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजकर योग्य तरतुद की जाएगी.

.2..

04-10-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3G 2

DVG/ MMP/ KGS/ प्रथम श्रीमती रणदिवे..

16:10

श्री. विनोद तावडे : सभापती महोदय, या प्रकरणास आता एक वर्ष होत आलेले आहे. मागील वर्षी जे उत्तर दिले होते, तशाच प्रकारचे उत्तर माननीय मंत्री महोदय आता देत आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारला आहे की, जी.आर. कधी काढला जाणार आहे ? एक महिन्यात जी.आर. काढला जाईल असे सांगण्याची हिंमत शासनाकडे आहे काय ? माननीय मंत्रीमहोदयांनी जी.आर. कधी काढला जाणार आहे याची तारीख केवळ सांगावी.

श्री. बाबा सिद्दीकी : सभापति महोदय, कोई भी चीज नियमानुसार होती है और . . .

श्री. विनोद तावडे : आपके क्या नियम हैं ? आप इसके लिए कितना समय लगाएंगे ?

श्री. बाबा सिद्दीकी : मला संरक्षण द्या.

श्री. विनोद तावडे : आपण नियमात काय कामे करतात व नियमाच्या बाहेर काय करीत असता है मला माहीत आहे.

श्री. बाबा सिद्दीकी : सभापति महोदय. मैंने पहले ही कहा है कि 15 दिन के अन्दर हाफकिन इन्सिटिट्यूट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के साथ फायरेंस डिपार्टमेंट के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा जाएगा और आकस्मिकता निधि या पूरक मांगाणी के द्वारा पैसे की व्यवस्था की जाएगी.

श्री. मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, 26 एप्रिल 2007 रोजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आलेला आहे असे माननीय मंत्री महोदयांनी हिंवाळी अधिवेशनामध्ये सांगितले होते.

Shri Baba Siddique : Mr. Deputy Chairman Sir, we want detail project report.

यानंतर श्री. बरवडा..

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदया, माननीय मंत्रिमहोदयांनी अतिशय गोलगोल उत्तर दिलेले आहे. हे कसे होणार नाही असे त्यांनी सांगितलेले आहे. त्यांनी डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. चा उल्लेख केला, मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री. विनोद तावडे तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. मधुकर चव्हाण यांनीही सांगितले की, बाहेरुन औषधे घेतात. आपल्याकडे डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. चे काय नॉर्म्स आहेत हे आपल्याला माहीत आहे काय ? 'एम' मध्ये काय आहे हे आपल्याला माहीत आहे काय ? या निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, महामंडळाचे उत्पादन अनुज्ञाप्ती अनुसूची 'एम' मधील तरतुदीची पूर्तता होईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आल्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्या कोणकोणत्या त्रुटी आहेत हे माननीय मंत्रिमहोदयांना माहीत आहे काय ? दुसरा प्रश्न असा की, आपण डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. न पाळणाऱ्या कंपन्यांकडून परराज्यातून, कर्नाटक अऱ्टी बायोटिक्स सारख्या लोन लायसन्सवर काम करणाऱ्या कंपनीकडून औषधे कशी घेता ? मग हाफकीनने काय चूक केलेली आहे ? आपण एका बाबीवर त्यांना कॅन्सल करता आणि कर्नाटक अऱ्टी बायोटिक्सला आणि किरण सोमलवालला सपोर्ट करण्यासाठी कोट्चवधी रुपयांची औषधे घेता. हे बरोबर आहे काय ? हाफकीन ही महाराष्ट्रातील कंपनी आहे. हाफकीन कंपनी महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे वैभव आहे. सचिव महोदयांनी अशा प्रकारचे पत्र शासनाला लिहिले की नाही याची माहिती माननीय मंत्रिमहोदयांनी द्यावी.

श्री. बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, महाराष्ट्र में शेड्युल एम के अंतर्गत 713 are complied and 42 are on the compliance. इतनी प्रगति महाराष्ट्र राज्य ने की है. जी.एम.पी. के बारे में केन्द्रीय सरकार का कानून है तो यह कानून कर्नाटक में भी लागू होना चाहिए.

डॉ. दीपक सावंत : आप इस बारे में इन्क्वायरी कीजिए.

श्री. बाबा सिद्धीकी : जी.एम.पी. का पालन कर्नाटक सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कानून है.

डॉ. दीपक सावंत : या वर्षात देखील कर्नाटक अन्टिबायोटिक्सकडून औषधे घेतलेली आहेत.

श्री. बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, अगर कर्नाटक सरकार से कोई चीज आती है तो कर्नाटक सरकार को हमारे सेक्रेटरी लिखेंगे कि जी.एम.पी अगर सेंट्रल कानून है तो वहाँ भी लागू होना चाहिए.....

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदया, माझ्या प्रश्नाला उत्तर आलेले नाही. माननीय सचिव महोदयांनी 50 कोटी रुपयांच्या मागणीसाठी राज्य शासनाला पत्र लिहिले होते काय ?

श्री. बाबा सिद्धीकी : मी हे तपासून घेतो.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदया, उत्तर देण्याची ही पृष्ठत आहे काय ? एक तर लक्षवेधी सूचना लावण्यासाठी किती मेहनत करावी लागते हे आपल्याला माहीत आहे. यामध्ये एका हॅरिटेज वास्तूचा संबंध आहे. ही औषध निर्माण करणारी कंपनी आहे. यामागे ती जागा विकण्याचा घाट आहे. या लोकांना ती जागा विकावयाची आहे.

श्री. बाबा सिद्धीकी : मी सांगितले की, तपासून घेतो. रेट कॉन्ट्रॅक्ट उसी कंपनी के साथ होता है, जिसका जी.एम.पी. कम्पलायंस है.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. मी माननीय मंत्रिमहोदयांना घेऊन जातो. कर्नाटक अॅन्टिबायोटिक्स ही लोन लायसन्सवर काम करते. लोन लायसन्सवर काम करावयाचे म्हणजे दुसऱ्या कंपनीकडून औषधे बनवून घ्यावयाची आणि आपल्या नावाखाली, आपल्या बॅनरखाली ते विकावयाचे. डब्ल्यू.एच.ओ.जी.एम.पी. ने लोन लायसन्स बंद केलेले आहे. तरीही आपण कर्नाटक अॅन्टिबायोटिक्सकडून औषधे घेता. आपण स्वतः जाऊन कर्नाटक अॅन्टिबायोटिक्स कंपनी कोठे आहे ते शोधून काढा आणि ती कंपनी औषध बनवते काय हे सांगावे.

श्री. बाबा सिद्धीकी : ते शोधून काढणार. अगर शेड्यूल एम के रिक्वायरमेंट मे लोन बेसिस पर काम करता होगा तो तुरंत अँक्षण लिया जायेगा.

श्री. अरविंद सावंत : सभापती महोदया, हाफकीन इंस्टिट्यूट परळ व्हिलेजला शिवडी आणि परळच्या मध्ये आहे. या हाफकीन इन्सिटट्यूटची जी वास्तु आहे ती पूर्वी मुंबईच्या गव्हर्नरचे निवासस्थान होते. त्या ठिकाणी हाफकीन इन्सिटट्यूट सुरु झाली. ती अतिशय अप्रतिम जागा आहे.

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3H-3

RDB/

श्री. अरविंद सावंत

त्या हाफकीन इन्स्टट्यूट सुरुवातीला रिसर्च इन्स्टट्यूट होती. त्या ठिकाणी घोडे, साप इत्यादी सगळे असावयाचे. या हाफकीन इन्स्टट्यूटमध्ये नंतर औषध निर्माण करणारे महामंडळ सुरु केले आणि एका बाजूला रिसर्च इन्स्टट्यूट ठेवली. तिथून खरे हे वाद सुरु झालेले आहेत. याचा खरा डोळा त्या जमिनीवर आहे.

यानंतर श्री. खंदारे....

श्री.अरविंद सावंत.....

माझा प्रश्न असा आहे की, या हाफकिन इन्स्टिटयूला 100 कोटी रुपये देऊ असे डिसेंबर महिन्यात उत्तर दिले होते. गेले कित्येक वर्षामध्ये हाफकिन इन्स्टिटयूट विकासासाठी पैसे मागत आहे. त्याबाबत विस्ताराने अहवाल यापूर्वीच आलेला आहे. त्यांनी या कामासाठी 15 कोटी रुपये मागितलेले आहेत. माझा असा दावा आहे की, देशात सर्वात स्वरूप दरात औषधे देणारी ही संस्था आहे, तिला डबघाईला आणावयाचे आणि खाजगी संस्थांना मदत करावयाची हे कटकारस्थान चालले आहे ते निपटून काढणार आहात काय ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : होय.

श्री.अरविंद सावंत : त्या संस्थेला 15 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत काय ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : याबाबत सविस्तर अहवाल आल्यानंतर मी माननीय वित्त मंत्रांकडे प्रस्ताव घेऊन जाणार आहे.

श्री.प्रकाश शेंडगे : राज्यातील गोरगरीब जनतेला स्वरूप दरामध्ये औषधे देणारी ही हाफकिन इन्स्टिटयूट आहे. महागडी औषधे खाजगी कंपन्यांकडून घ्यावयाची आणि सरकारी कंपनी बंद पाडावयाची हे षड्यंत्र आहे. या अहवालातील त्रुटी एक वर्षापूर्वी लक्षात आल्या होत्या. त्या त्रुटी या इन्स्टिटयूटने पूर्ण केल्या नसतील तर त्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने काय प्रयत्न केले आहेत ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : तेच प्रयत्न केले आहेत, त्यांना नोटीस इश्यू केली आहे.

श्री.मधुकर चव्हाण : सभापती महोदय, शासनाने मागील वेळी असे म्हटले होते की, प्रस्तावित खर्चाची रक्कम कोणकोणत्या बाबीवर खर्च होणार आहे त्याचा नेमका आराखडा काय आहे त्याची माहिती मागविली आहे. आता असे म्हटले आहे की, "त्या मागणीला अनुलक्षून 15 कोटी रुपये देण्याबाबत अर्थसहाय्य देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे दि.2.4.2008 च्या पत्रान्वये महामंडळास कळविण्यात आले." हे 15 दिवसात केले तरी काही म्हणणे नाही. जर 15 कोटी रुपये दिले तरी जी.आर.काढून देत नाही तोपर्यंत उर्वरित रक्कम वित्तीय संस्थांकडून आणू शकत नाही. म्हणून 15 कोटी रुपये 15 दिवसात द्यावे आणि खाजगी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढण्यासाठी जी.आर.काढला जाईल काय ? त्या संस्थेमध्ये

2....

श्री.मधुकर चव्हाण....

ए.सी.नाही, इन्क्रास्ट्रक्चर नाही, अशा परिस्थितीत तेथे उत्पादन सुरु होण्यासाठी विशेष बाब म्हणून या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून देणार काय ?

श्री.बाबा सिद्धीकी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की भावना को मैं समझता हूँ. मैंने सभागृह को बताया है कि पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कन्करेंस आना चाहिए. मैं अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को सूचना दूँगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनका कन्करेंस लें. 15 दिन के अन्दर यह प्रस्ताव हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद फायरेंस डिपार्टमेंट के सामने यह प्रस्ताव रखकर 15 करोड़ रुपए हमारे पास आ सकते हैं. मगर इसका काम टप्पे टप्पे से शुरु होने की जरूरत है.

(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

पृ. शी. : नांदूर मध्यमेश्वर परिसर अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याची होत असलेली मागणी

मु. शी. : नांदूर मध्यमेश्वर परिसर अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याची होत असलेली मागणी यासंबंधी डॉ.वसंत पवार, वि.प.स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

डॉ.वसंत पवार (नाशिक स्थानिक प्राधिकारी संस्था) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय वने मंत्रांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"नाशिक जिल्ह्यातील नांदूर मध्यमेश्वर या परिसरात मुबलक जमीन, पाणी आणि पक्षांना पुरेपूर खाद्य उपलब्ध असल्यामुळे या भागात पक्षांचे मोठ्या प्रमाणावर आगमन होऊ लागल्यामुळे सन 1986 साली वन्यजीव विभागाने या परिसराला अभयारण्य म्हणून घोषित करणे, परंतु दोन तपाहूनही अधिक काळ उलटूनही या **अभयारण्याचा विकास** न होणे, 17 हजार हेक्टर क्षेत्रफळ व अनुकूल परिस्थिती असूनही याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला सादर करूनही त्यावर अद्यापि कोणताच निर्णय न होणे, नांदूर मध्यमेश्वर परिसरात अभयारण्य उभारण्यासाठी निसर्गाची विपूल देणारी असल्याने पर्यटक व स्थानिक रहिवाशांकडून अभयारण्य होणेबाबत सतत होत असलेली मागणी, याकडे शासनाने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, याबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही वा करावयाची उपाययोजना."

श्री.बबनराव पाचपुते (वने मंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

4....

डॉ.वसंत पवार : सभापती महोदय, नाशिक जिल्हयातील निफाड तालुक्यात खानगांवथडी येथे गोदावरी व कादवा नदीच्या संगमावर पाणी अडविण्यासाठी बांधलेला बांधारा नांदूर मध्यमेश्वर धरण म्हणून ओळखले जाते. सध्या तेथे 220 प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली आहे. ही संख्या जवळपास 30 हजारापर्यंत पोहोचली आहे. या अभयारण्यासाठी दिनांक 25.2.1986 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्याच्या जवळच 11 गावांचे क्षेत्र आहे आणि अभयारण्याचे क्षेत्र 10012.73 हेक्टर आहे.

नंतर श्री.शिगम

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3J-1

MSS/

पूर्वी श्री. खंदारे

16:25

(डॉ. वसंत पवार...)

नांदूर मधमोश्वर हे धरण आहे काय ? या धरणाच्या बँक वॉटर क्षेत्रामध्ये गाळपेराची जमीन आहे. ही 10012.73 हेक्टर जमीन यामधून सुटणार आहे काय ? आमच्या आदिवासी शेतक-यांना गाळपेराची जमीन मिळत नाही. तेव्हा हे क्षेत्र यामधून कमी करणार आहात काय ? या मॅनेजमेंट प्लॅनसाठी 8.11 लाख रु. खर्च केलेले आहेत. चापडगाव येथे पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र उभारण्यासाठी 30 लाख रु. अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. निरीक्षण मनोरे, चिन्हांचे फलक, पेडल बोट व बोटीचा धक्का, प्रसिद्धी इत्यादी कामे करण्यात येत आहेत. निसर्ग पर्यटन व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ - इको टुरिझम बोर्ड - स्थापन करण्यात आलेले आहे. तेव्हा या सर्व गोष्टींचा समावेश करून हा संपूर्ण भाग विकसित करण्यात येणार आहे काय ? त्यासाठी निश्चित किती कालावधी लागणर आहे ? ग्लोबल वॉर्मिंगची वॉर्निंग लक्षात घेऊन अशा कामांकडे दुर्लक्ष करणे गैर ठरेल. तेव्हा या दृष्टीनेही शासन गांभीर्याने विचार करील काय ?

श्री. बबनराव पाचपुते : हे धरण आहे काय असा सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारला. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील खानगावथडी येथे गोदावरी व कादवा नदीच्या संगमावर बंधारा बांधून पाणी अडविलेले असून त्याला मधमोश्वर धरण म्हणून म्हटले जाते. सध्या तरी याचे धरणामध्ये रुपांतर झालेले आहे. सन्माननीय सदस्यांनी अनेक प्रश्न विचारलेले आहेत. या क्षेत्रामध्ये 10012.73 हेक्टर क्षेत्र 1986 साली अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यासंदर्भातील सर्व चौकशी पूर्ण झालेली आहे. चौकशी पूर्ण होऊन यामधील क्षेत्र सिंचन विभाग 1757 हेक्टर महसूल विभाग 150 हेक्टर आणि वन विभाग 55 हेक्टर असे 1962.996 इतके क्षेत्र शिल्लक राहणार आहे. बाकीचे वगळले जाणार आहे. आपण मास्टर प्लॅन तयार केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाची इको टुरिझमची पॉलिसी झालेली आहे. त्यामधूनही मोठ्या प्रमाणात पैसे उपलब्ध होऊ शकतील. मनोरे, चिन्हांचे फलक, पेडल बोट व बोटीचा धक्का बांधणे, इत्यादीसाठी 1 कोटी 73 लाख 11 हजार रु. इतका खर्च अपेक्षित केलेला आहे. पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र उभारण्यासाठी 30लाख रु. अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. ग्लोबल

..2..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3J-2

(श्री. बबनराव पाचपुते....

वॉर्मिंग हे वसुंधरेवर आलेले संकट आहे. याबाबतीत सर्वांनीच लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. निसर्गाचे चक्र बदलत चालले आहे. अवेळी पाऊस, निसर्ग बदल या गोष्टी होत आहेत. हे थांबवायचे असेल तर प्रदुषण कमी केले पाहिजे आणि निसर्गाची जपणूक केली पाहिजे. त्यामध्ये अनेक गोष्टी येतात. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडांचे संवर्धन करणे ही बाब आहे. त्याबाबतीत शासन गंभीर आहे. याबाबतीत इको टुरिझममधून कायमस्वरूपी योजना तयार करून चांगला निधी देण्याचा प्रयत्न करू.

डॉ. वसंत पवार : 10012.73 हेक्टर इतके क्षेत्र वगळून ते शेतक-यांना देण्यात येणार आहे काय ?

श्री. बबनराव पाचपुते : 1962.996 हेक्टर एवढे क्षेत्र अभयारण्यात राहाणार आहे आणि बाकीचे क्षेत्र खाजगी लोकांना मिळेल,

...नंतर श्री. गिते...

श्री. बबनराव पाचपुते...

सरकारची जी जमीन आहे ती सरकारकडे राहणार आहे. सिंचन विभागाची जमीन त्यांच्या ताब्यात राहणार आहे. वन विभागाची जमीन वन विभागाच्या ताब्यात राहणार आहे. या जमिनींचा वापर कशा पृष्ठदतीने करता येईल ते आपल्याला बघावे लागेल. 10 हजार 400 हेक्टर क्षेत्र 2 हजार हेक्टर क्षेत्र याअंतर्गत आणलेले आहे.

श्री. प्रतापराव सोनवणे : सभापती महोदय, नाशिक जिल्ह्या नांदूर मध्यमेश्वर धरण आहे. सदर धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. त्या धरणाचे गेट बंद झाले आहेत, त्यामुळे या धरणातून पाण्याचा निचरा होत नाही. तीन वर्षांपूर्वी या धरणाच्या कॅचमेंट एरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. या धरणाचे गेट बंद असल्यामुळे धरणातून पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही त्यामुळे धरणाच्या बँक वॉटरमुळे सायखेडा, व इतर काही गावे पूर्णपणे पाण्याखाली आली आणि त्यामुळे त्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वित्त व मनुष्यहानी झाली. नांदूर मध्यमेश्वर धरणाच्या गेटस्ची दुरुस्तीची कामे तात्काळ हाती घेण्यात यावीत, तसेच या धरणावर नवीन गेटस् बसविण्याचे काम एका वर्षात पूर्ण करावे आणि त्या धरणाच्या परिसरातील गावांचे भविष्यातील नुकसान टाळावे अशा प्रकारची मी मागणी शासनाकडे केलेली आहे. या धरणाच्या बँक वॉटरमुळे किती नुकसान इ आले आहे यासंबंधीची पाहणी सन्माननीय सदस्य श्री. विनोद तावडे यांनी नावेतून फिरुन पाहिली आहे. शासनाने या धरणाच्या गेटच्या कामास सुरुवात केली आहे. परंतु त्या धरणाचे काम अद्यापही पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे या धरणाच्या परिसरातील गावांवर महापुराची टांगती तलवार राहणार आहे. म्हणून येत्या पावसाळ्याच्या आत धरणाच्या गेटस्ची कामे पूर्ण करण्यात येतील काय? त्याचप्रमाणे गाळ काढणे व इतर दुरुस्तीची कामे आहेत ती देखील पावसाळ्याच्या आत पूर्ण करण्यात येतील काय?

श्री. बबनराव पाचपुते : संबंधित विभागाकडे यासंबंधीची विनंती करण्यात येईल. तसेच धरणाच्या गेट दुरुस्तीच्या संदर्भात देखील सूचना दिल्या जातील.

श्री. जगदीश गुप्ता : सन्माननीय वन मंत्र्यांनी इको टुरिझमचा संदर्भात उल्लेख केला. वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात इको टुरिझम डेव्हलप करण्यात येणार आहे. परंतु अभयारण्य पाहण्यासाठी पर्यटक येतात, त्या पर्यटकांकडून प्लॉस्टिकच्या पिशव्यांच्या वापर करतात. अभयारण्य परिसरात पर्यटकांना प्लॉस्टिक पिशव्या वापरण्यात बंदी घालण्यात येईल काय?

2...

श्री. बबनराव पाचपुते : अभयारण्यामध्ये पर्यटकांना प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरण्यावर पूर्वीपासूनच बंदी घालण्यात आली आहे. निसर्गाचा कोणत्याही प्रकारे बॅलन्स बिघडणार नाही अशा प्रकारच्या सूचना अभयारण्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ बोर्डवर लिहिलेल्या असतात. तसेच अभयारण्याच्या परिसरातील मुख्य रस्त्यांवर देखील तशा सूचना लिहिलेल्या असतात. परंतु सन्माननीय सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे अभयारण्य परिसरामध्ये पर्यटकांना प्लॅस्टिक पिशव्या वापरण्यात येऊ नयेत अशा प्रकारच्या सूचना पुन्हा देण्यात येतील.

3...

विशेष उल्लेख

पृ. शी. : पुणे-मुंबई टॅक्सी स्टॅन्डजवळून प्रवाशांची होत असलेली
अवैध वाहतूक

मु. शी. : पुणे-मुंबई टॅक्सी स्टॅन्डजवळून प्रवाशांची होत असलेली
अवैध वाहतूक याबाबत डॉ. नीलम गोहे, वि. प. स. यांनी
दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मानीय सदस्या डॉ.नीलम गोहे यांनी विशेष उल्लेजासंबंधीची सूचना दिली
आहे. त्यांनी ती मांडावी.

डॉ. नीलम गोहे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने
पुढील विशेष उल्लेजासंबंधीची सूचना मांडते.

" गेली 36 वर्षे मुंबई- पुणे टॅक्सी प्रवासी वाहतूक करीत असलेल्या प्रवासी टॅक्सी, पुणे
स्टेशन परिसरातील बेकायदा वाहतूक मोठया प्रमाणावर सुरु असून या बेकायदा वाहतुकीची तक्रार
मुंबई-पुणे टॅक्सी युनियने बंडगार्डन पोलीस स्टेशन, पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे यांना वारंवार करूनही
त्याकडे पोलीस यंत्रणा करीत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, अधिकृत टॅक्सी बुर्किंग कार्यालयाजवळ
खाजगी बस चालक येऊन प्रवाशांना घेऊन जातात, अशा प्रकारे अवैध प्रवासी वाहतुकीला पुणे
परिसरात आळा घालण्याकरिता शासनाने तातडीने करावाई करून तसे निवेदन करावे"

सभापती महोदय, गेली 36 वर्षे मुंबई-पुणे व पुणे-मुंबई टॅक्सी प्रवासी वाहतूक सुरु आहे.
तसेच टॅक्सी स्टॅन्डवरुन कूल कॅब टॅक्सीची देखील सेवा सुरु आहे. या ठिकाणी मानीय गृहमंत्री
महोदय सभागृहात उपस्थित आहेत. त्यांच्या निर्दर्शनास एक बाब मी आणून देऊ इच्छितो. पुणे येथे
"पुणे-मुंबई" टॅक्सी स्टॅन्ड आहे. ते टॅक्सी स्टॅन्ड रेल्वेच्या बाहेरच्या बाजूला आहे. या टॅक्सी स्टॅन्ड
वरुन दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करीत असतात. परंतु या टॅक्सी स्टॅन्डजवळ खाजगी बससचे
एजन्ट येतात आणि टॅक्सीचे प्रवासी खाजगी बसमध्ये घेऊन जातात. हा प्रकार दिवसें दिवस वाढत
आहे. या प्रकारामुळे टॅक्सी चालक आणि बसचे एजन्ट यांच्यामध्ये रोज भांडणे होत आहेत.

4...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3K-4

ABG/ KGS/ MMP/

प्रथम श्री.शिगम

16:30

डॉ.नीलम गोहे...

यासंदर्भात मुंबई-पुणे टॅक्सी युनियनने बंडगार्डन येथील पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारी दाखल केल्या आहेत. परंतु त्या पोलीस स्टेशनकडून यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही. संबंधित पोलीस स्टेशनने याबाबतीत तात्काळ कार्यवाही करावी म्हणून मी ही विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे. आपण मला ही सूचना उपरिथित करण्याची संधी दिल्याबदल मी आपली आभारी आहे.

5....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3K-5

ABG/ KGS/ MMP/ प्रथम श्री.शिगम

16:30

पृ. श्री. : मुंबई शहरात भीक मागणाच्या लहान मुलांना व महिलांना

आळा घालणे

मु. श्री. : मुंबई शहरात भीक मागणाच्या लहान मुलांना व महिलांना
आळा घालणेबाबत याबाबत श्री. अरविंद सावंत, वि. प. स. यांनी
दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मा-नीय सदस्य श्री.अरविंद सावंत यां-ी विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा दिली
आहे. त्यां-ी ती मांडावी.

श्री. अरविंद सावंत (मुंबई रथानिक प्राधिकारी संस्था) : सभापती महोदय, मी आपल्या
अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा मांडतो.

सभापती महोदय, मी एका अतिशय गंभीर विषयासंबंधीचा मुद्दा या सूचनेच्या माध्यमातून
उपस्थित करीत आहे. मुंबई शहरामध्ये 10 हजारापेक्षा जास्त भिकारी आहेत. त्यात 50 ते 60 टक्के
लहान मुले आहेत आणि 40 टक्के महिला व पुरुष भिकारी आहेत. मुंबई शहराच्या प्रत्येक
रस्त्याच्या सिगनलवर, रेल्वेत, रेल्वे प्लॉटफार्मवर महिला व लहान मुले भीक मागत असताना दिसून
येतात. भीक मागण्यासाठी लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला जातो आहे. या
लहान मुलांचे खेळण्याचे, बागडण्याचे दिवस आहेत त्यांना भीक मागावयास लावले जात आहे.

यानंतर श्री. कानडे....

ॐ नमः शिवाय

श्री. अरविंद सावंत

सभापती महोदय, खरे पाहिले तर भिकाच्यांच्या संदर्भात कायदा आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जी काही थोडी फार होते ती म्हणजे बालभिकाच्यांना बालसुधार गृहात पाठविले जाते. परंतु तेथून त्यांना त्यांचे पालक परत नेतात. कालांतराने त्यांना बाहेर पाठविले जाते आणि पुन्हा भीक मागताना आढळला तर 5000 रु. दंड आकारला जातो. सभापती महोदय, काही नाक्यावरील भिकारी आज सम्राट झालेले आहेत. यासंदर्भात काही दिवसापूर्वी मिड डे या वृत्तपत्रात बातमी देखील आली होती. एक भिकारी दुसऱ्या भिकाच्याला त्याच्या हृदीत येऊ देत नाही. विशेषत: मुलांच्या आणि महिलांच्या बाबतीत हे थांबविता येईल काय याबाबात शासनाने तातडीने विचार करावा. परदेशी पाहुणे थांबतात त्या हॉटेलजवळ म्हणजे ताजमहाल सारख्या हॉटेलजवळ हे भिकारी वावरत असतात त्यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा सुध्दा मलीन होते. म्हणून याबाबतीत शासनाने तातडीने लक्ष घालावे यादृष्टीने मी ही विशेष उल्लेखाची सूचना दिली आहे. माननीय गृहमंत्री सदनामध्ये उपस्थित आहेत त्यांनी समर्येकडे यामध्ये लक्ष घालावे अशी विनंती आहे.

श्री. आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ. नीलम गोळे यांनी मुंबई-पुणे येथील बेकायदा खाजगी वाहतुकीच्या संदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक शाखेला सूचना देण्यात येतील आणि प्रवाशांची पळवापळवी होणार नाही यादृष्टीने शासन लक्ष देईल.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अरविंद सावंत यांनी बालभिकाच्यांच्या संदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईतील ही एक गंभीर समस्या आहे. काही महिन्यापूर्वी मी जाणीवपूर्वक या विषयामध्ये लक्ष घातले होते. 450 बालभिकारी पकडून ते सुधारगृहात टाकण्यात आले होते. परंतु यापेक्षा विदारक माहिती शासनाला प्राप्त झाली. याधंद्यामध्ये काही मुले भाड्याने घेतली जातात. झोपडपट्ट्यांमधून अशी मुले भाड्याने दिली जातात. विकली जातात. लोकांची सहानुभूती मिळावी म्हणून त्यांना वापरले जाते. यापेक्षा यातील क्रुरता आढळून आली ती म्हणजे या मुलांना अपेक्षित बनविले जाते, त्यांच्या तोडावर जखमा केल्या जातात, त्यांना विद्रुप केले जाते, त्यांचे डोळे काढले जातात जेणेकरून समोरच्या माणसाला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटावी अशा पद्धतीने या मुलांचा वापर करण्यात येतो. याबाबतीत मोठया प्रमाणावर मोहीम हाती घेत

.....2

श्री. आर.आर.पाटील ...

असताना आणि ही मुले पकडत असताना दुर्दवाने एक भिकारी नसलेला मुलगा यामध्ये सापडला आणि पोलिसांवर खूप मोठी टीका झाली. पोलिसांवरच बूमरँग झाले. अशी टीका झाली तरी हरकत नाही. यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभाग सक्षम आहे. परंतु त्यांच्याकडील मनुष्यबळ अतिशय कमी आहे. या धंद्यातील अमानुषता लक्षात घेऊन मुंबई पोलिसांनी जी मोहीम सुरु केली होती ती मोहीम पुन्हा राबविण्यात येईल. लहान मुलांना अपंग करून आणि त्यांना विद्वुप करून भीक मागण्याचे प्रकार मुंबईमध्ये बंद केले जातील.

.....3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3L-3

SSK/ MMP/ KGS/

16:35

पृ.शी. : 'धामापूर' ता.मालवण हे गाव पर्यटनस्थळ म्हणून

घोषित करणे

मु.शी. : 'धामापूर' ता.मालवण हे गाव पर्यटनस्थळ म्हणून
घोषित करणे याबाबत श्री. सुभाष चव्हाण,वि.प.स. यांनी
दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्य श्री. सुभाष चव्हाण यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री. सुभाष चव्हाण (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखाची सूचना मांडतो.

सभापती महोदय, पर्यटनाशी निगडीत असा हा विषय आहे. शासनाने सिंधूदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. या जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील धामापूर हे नैसर्गिकदृष्टया अतिशय सुंदर व रमणीय असे गांव आहे. हे गांव पर्यटनगाव गाव म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्या गावामध्ये अतिशय सुंदर असा रमणीय तलाव आहे. पुरातन तलाव आहे. या तलावाचा आजुबाजूचा परिसर वनविभागाच्या अखत्यारित येतो. पर्यटन विभागाने पर्यटकांसाठी मध्यंतरी काही कॉटेजेस बांधलेले आहेत. याचे रितसर उद्घाटन देखील झालेले आहे. या कार्यक्रमाला पर्यटनमंत्री, राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी हजर होते. परंतु बांधकाम न होताच याचे उद्घाटन झालेले आहे. आता याकामाची बरीचशी पूर्तता झाली असून ते पर्यटकांसाठी खुले होणार आहे. या पर्यटनस्थळापासून गोवा हे 70-75 कि.मी.अंतरावर असल्यामुळे मे महिन्यात अनेक पर्यटक याठिकाणी आकर्षित होण्याच्या दृष्टीने तातडीने हे गाव पर्यटनक्षेत्र म्हणून घोषित करावे अशी मी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनास विनंती करीत आहे.

नंतर श्री. भोगले

पृ. शी. : इयत्ता 9 वी 10 वीच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने
गणित या विषयासाठी तासिका वाढविणे

मु. शी. : इयत्ता 9 वी 10 वीच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने
गणित या विषयासाठी तासिका वाढविणे याबाबत
श्री.विक्रम काळे,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष
उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : यानंतर मानीय सदस्य श्री.विक्रम काळे यांनी एज विशेष उल्लेजाची सूचना
दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री.विक्रम काळे (औरंगाबाद विभाग शिक्षक) : महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष
उल्लेजाची सूचना मांडतो.

"सन 2006-07 साली इयत्ता 9 वी व सन 2007-08 साली 10वीचा नवीन अभ्यासक्रम सुरु झाला आहे. अगोदरच आठवड्याच्या सात तासिका गणित विषयाला कमी पडत होत्या व आता तर अभ्यासक्रम इतका वाढला आहे की, आठवड्याच्या किमान 9 तासिका निश्चित न केल्यास गणित विषयाचा अभ्यासक्रम शिकविताना शिक्षक गणित विषयाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. खेड्यात बच्याच विद्यार्थ्यांना एक उदाहरण किमान दोनदा समजावले तरच समजते. मग 30 मिनिटांच्या तासिकेत एक उदाहरण दोनदा समजावण्यापर्यंत 15 ते 20 मिनिटे वेळ जातो. त्याचप्रकारे दोन-तीन उदाहरणे सोडविली तर ती उदाहरणे विद्यार्थ्यांना कायमस्वरूपी समजतात अन्यथा विद्यार्थी गोंधळून जातात. प्रत्येक उदाहरण थोडेफार वेगळे असतेच व थोडाफार बदल विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावा लागतो व मार्गदर्शन करावे लागते. त्यासाठी गणित विषयाची तासिका 40 मिनिटांची करावी, अन्यथा आठवड्यात गणित विषयाच्या किमान 9 तासिका निश्चित कराव्यात. हे खेड्यातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहे. कारण त्यांना शहरातील विद्यार्थ्यप्रमाणे खाजगी/वैयक्तिक क्लासेसच्या सुविधा नसतात. गणित या विषयात इतर विषयाप्रमाणे फक्त चिंतन व मनन करून अभ्यास होत नाही, तर सोबत प्रत्यक्ष कृतीही (सराव) तितकीच महत्वाची आहे व कृतीला (सरावाला) जास्त वेळ द्यावा लागतो हे सर्वश्रुत आहे याची विशेष नोंद घ्यावी. मी आपल्या माध्यमातून माननीय शालेय शिक्षणमंत्री सभागृहात उपस्थित आहेत, त्यांनी या विषयाबाबत लक्ष घालावे अशी मी या विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून विनंती करतो.

पृ. शी. : खापा, ता.तुमसर, जि.भंडारा येथील उषा राईस
मिलमधून पुणे येथे पाठविण्यात आलेला 100
किंवटल तांदूळ गहाळ होणे

मु. शी. : खापा, ता.तुमसर, जि.भंडारा येथील उषा राईस
मिलमधून पुणे येथे पाठविण्यात आलेला 100
किंवटल तांदूळ गहाळ होणे याबाबत श्री.केशवराव मानकर,
वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : यानंतर मा-िय सदस्य श्री.केशवराव मानकर यां-ी एज विशेष उल्लेजाची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री.केशवराव मानकर (विधानसभेने निवडलेले) : महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेजाची सूचना मांडतो.

"भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुकांतर्गत खापा (भंडारा रोड) येथील उषा उद्योग राईस मिलमधून 100 किंवटल तांदूळ गोंदिया येथील लोकसेवा ट्रान्सपोर्टच्या एमएच 31/एम 4555 क्रमांकाच्या ट्रकने दिनांक 28 मार्च, 2008 रोजी पुणे येथे रवाना करणे, परंतु सदर क्रमांकाच्या ट्रकमध्ये टाकलेला माल पुणे येथे अद्यापही न पोहोचणे, यासंबंधात ट्रकमालक आणि ट्रकचालकाच्या संगनमताने संपूर्ण तांदूळ रस्त्यात गहाळ झाल्याची तक्रार उषा उद्योग राईस मिलच्या मालकाने नागपूर येथील वाडी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविणे, ट्रकमालक श्री.सैनी व ट्रकचालक, परवाना क्र.178924, नागपूर यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवूनही सदर प्रकरणाची अद्याप चौकशी न होणे, त्यामुळे गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल मालकांमध्ये पसरलेला असंतोष लक्षात घेता शासनाने तातडीने करावयाची कार्यवाही व शासनाची प्रतिक्रिया."

सदर विषय अत्यंत महत्वाचा असून तो मी आज विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित करीत आहे.

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3M.3

SCB/ MMP/ KGS/

16:40

पृ. शी. : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे
अनुदानित शिक्षण संस्थातील शिक्षक व शिक्षकेतरांना
एकस्तर वेतनवाढ मिळणे

मु. शी. : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे
अनुदानित शिक्षण संस्थातील शिक्षक व शिक्षकेतरांना
एकस्तर वेतनवाढ मिळणे याबाबत श्री.रामनाथ मोते,
वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : यानंतर मा-नीय सदस्य श्री.रामनाथ मोते यां-नी एज विशेष उल्लेजाची सूच-ना
दिली आहे. त्यां-नी ती मांडावी.

श्री.रामनाथ मोते (कोकण विभाग शिक्षक) : महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष
उल्लेजाची सूच-ना मांडतो.

सभापती महोदय, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना
एकस्तर वेतनवाढ दिली जाते. दिनांक 6 ऑगस्ट, 2002 च्या शासन निर्णयानुसार ही सवलत
शासकीय कर्मचाऱ्यांना व वेगवेगळ्या विभागामध्ये जे काम करतात त्यांना ही सवलत लागू आहे.
त्याचप्रमाणे अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आदिवासी
भागामध्ये किंवा नक्षलग्रस्त भागामध्ये किंवा अतिसंवेदनशील भागामधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये काम
करतात त्यांना सुधा ही सवलत लागू आहे. या संदर्भातील तरतुदी दिनांक 6 ऑगस्ट, 2002 च्या
आदेशामध्ये आहेत. या संदर्भात दिनांक 14 डिसेंबर, 2006 रोजी हा विषय सभागृहात चर्चेला
आला होता. दिनांक 29 जून, 2007 रोजी सन्माननीय सभापती महोदयांकडे या संदर्भात सर्व
प्रमुखांची बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये सन्माननीय शिक्षणमंत्रांनी दोन महिन्याच्या आत सामान्य
प्रशासन विभागाशी चर्चा करून या संदर्भात निर्णय घेऊ असे सांगितले होते. अद्यापही तसा निर्णय
झालेला नाही.

सभापती महोदय, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की,
इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सवलती मिळतात त्या आम्हाला मात्र मिळत नाहीत.

(नंतर श्री.जुनरे....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3N-1

SGJ/ KGS/ MMP/

ग्रथम श्री. भोगले.....

16:45

श्री. रामनाथ मोरे

त्यामुळे या विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो की, नियमाप्रमाणे देय असेल तर ते कृपाकरुन देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. नियमात बसत नसेल तर विचाराधीन आहे, एक महिन्यात देतो, दोन महिन्यात देतो असे सभागृहात सांगितले जात असल्यामुळे आम्हाला वेगवेगळ्या माध्यमातून हा प्रश्न सभागृहात मांडावा लागत असतो त्यामुळे सभागृहात असा विषय वारंवार मांडणे बरे नाही. त्यामुळे शक्य नसेल तर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि नियमात बसत असेल तर तातडीने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा असे मी या विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून विनंती करतो.

....2

पृ. श्री. : होमगार्डस् यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत

मु. श्री. : होमगार्डस् यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत श्री.
प्रतापराव सोनावणे, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची
सूचना.

उपसभापती : मानीय सदस्य श्री. प्रतापराव सोनावणे यांनी विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री. प्रतापराव सोनावणे (नाशीक विभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा मांडतो.

भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या अधिपत्याखाली मा. मुरारजी देसाई गृहमंत्री असतांना 1946 साली होमगार्ड संघटना स्थापन झाली होती. राज्यात विशेषत: मुंबईमध्ये ज्या ज्या वेळी जातीय दंगलीनी थैमान घातले त्या त्या वेळेस होमगार्ड संघटनेच्या सहाय्याने त्यांना "गृहरक्षक दल" असे नाव देवून या दंगली आटोक्यात आणल्या गेल्या आहेत. हे आपणा सर्वाना माहीत आहे. समाजामध्ये राहून सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यात ज्या संघटनेचे मोठे योगदान आहे आणि म्हणूनच राज्यातील दंगली हळूहळू कमी होत गेल्या हा इतिहास आहे. मुंबईत लोकल गाडयांमध्ये होम गार्डसची नियुक्ती केल्यावर गुन्हयांमध्ये कमालीची घट झालेली आहे ही सुधा कमालीची बाब आहे. पोलीस दलाला सर्वात मदत करणारा घटक म्हणून गृहरक्षक दलाच्या संघटनेकडे पाहिले जाते या संघटनेची जबाबदारीही वाढलेली आहे. जे शिक्षण पोलीस दलाला दिले जाते तेच शिक्षण गृहरक्षक दलाला सुधा दिले जाते. या गृहरक्षक दलाला पाहिजे तेव्हा बोलावले जाते आणि कर्तव्यावर पाठविले जाते. सभापती महोदय, वापरा आणि सोडून द्या हे शासनाचे होमगार्डच्या बाबतीतले धोरण हे आता बंद झाले पाहिजे. होमगार्डस् मधील तरुणांना शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देवून खाजगी सुरक्षेसाठी त्यांचा उपयोग करून घ्यावा हा एक चांगला पर्याय शासनापुढे उपलब्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहरक्षक दलाच्या सर्व कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे हा त्यांना खरा न्याय दिल्यासारखे होईल. अन्यथा

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3N-3

SGJ/ KGS/ MMP/

ग्रथम श्री. भोगले.....

16:45

श्री. प्रतापराव सोनावणे.....

- 1) होमगार्ड जवानाना किमान रु. 5000/- महिना मानधन देण्यात यावे.
- 2) कर्तव्यावर असतांना होमगार्ड जवानांना बससेवा ही मोफत दिली जावी.
- 3) होमगार्ड जवानांना कर्तव्यावर असतांना अपघात झाल्यास किमान 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
- 4) होमगार्ड जवानांना 55 वर्ष वयाची पूर्ण झाल्यावर 2 लाख रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा.

सभापती महोदय, होमगार्ड जवानांच्या कामगिरीची योग्य दखल घेऊन त्यांना शासनाने न्याय द्यावा व त्यांच्या योग्य, रास्त आणि हक्काच्या मागण्या विनासायास मान्य कराव्यात अशी आग्रहाची मागणी विशेष उल्लेखाद्वारे करतो आहे.

....4

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3N-4

SGJ/ KGS/ MMP/

ग्रथम श्री. भोगले.....

16:45

पृ. शी. : महामंडळाना कोटयावधी रुपयांची करण्यात आलेली घोषणा

मु. शी. : महामंडळाना कोटयावधी रुपयांची करण्यात आलेली घोषणा

याबाबत श्रीमती उषा दराडे, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष

उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मा-नीय सदस्य श्रीमती उषा दराडे यांनी विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्रीमती उषा दराडे (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेजासंबंधीची सूच-गा मांडते.

"मागासवर्गीय महामंडळासांठी त्यामध्ये महात्मा फुले महामंडळाला 10 कोटी, वसंतराव नाईक महामंडळाला 11 कोटी, अण्णाभाऊ साठे आणि लिडकाँम मिळून 15 कोटी देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी करणे.

यानंतर श्री. गायकवाड....

ॐ नमः शिवाय

या तरतुदीनुसार निधी देण्याच्या फाईलवर अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या सहया होणे, दिनांक 31 मार्च रोजी पैसे देण्याबाबतचा जी.आर. निधणे, त्याच दिवशी ट्रेझरीला 36 कोटींची बिले सादर होणे, ट्रेझरीमधील अधिकाऱ्यानी 3 एप्रिल पर्यंत बिले ठेऊन देणे आणि नंतर बिलांना उशीर झाल्याने पैसे लॅप्स झाल्याचे कारण सांगून ती बिले महामंडळांना परत पाठविणे, बजेटमध्ये तरतूद करून जी.आर. निधाल्यानंतर ट्रेझरीतील अधिकाऱ्यांनी बिले परत पाठविल्यामुळे घटनेने स्थापन झालेल्या मंत्री मंडळाचे राज्य आहे की नोकरशाहीचे आहे अशी संतात प्रतिक्रिया वसंतराव नाईक महामंडळाचे अध्यक्ष श्री.लक्ष्मण माने यांनी देणे, त्यामुळे 2008-2009 साठीचा मंजूर केलेला निधी महामंडळाना न मिळणे, यामुळे इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय व सामान्य जनतेत निर्माण झालेला असंतोष व या बाबत शासनाने करावयाची तातडीची उपाययोजना ही सार्वजनिक महत्वाची बाब मी या विशेष उल्लेखाअन्वये उपस्थित करीत आहे. "या संदर्भात आजच्या महाराष्ट्र टाईम या वर्तमानपत्राच्या पान नंबर 12 वर बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. या महामंडळाना निधी देण्याच्या फाईलवर माननीय अर्थ मंत्री आणि माननीय अर्थ मंत्र्यांनी सहया केल्यानंतर जी.आर. निधाला होता त्या प्रमाणे महामंडळानी बिले बनवून ट्रेझरीकडे दिली होती परंतु त्यांनी बिले तशीच ठेवून दिली आणि उशीर झाला म्हणून हा निधी लॅप्स झाला आहे असे सागितलेले आहे. या वर्षा या महामंडळाना निधी मिळणार नाही त्यामुळे या संदर्भात शासनाने गंभीर दखल घ्यावी. त्या बातमीच्या शेजारीच " आमदार निधी वापरण्याची मुदत जून अखेर पर्यंत " अशी बातमी देखील प्रसिद्ध झालेली आहे. तेहा मी जी विशेष उल्लेखाची सूचना मांडलेली आहे त्याची शासनाने गंभीर्याने दखल घ्यावी अशी मी विनंती करते.

पृ.शी : जिल्हा परिषदेच्या अंशकालीन स्त्री परिचराच्या विविध मागण्या

मु.शी : जिल्हा परिषदेच्या अंशकालीन स्त्री परिचराच्या विविध मागण्याबाबत
श्रीमती उषा दराडे,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखासंबंधीची
सूचना

उपसभापती : माननीय सदस्या श्रीमती उषा दराडे यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली
आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्रीमती उषा दराडे (विधान सभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने
पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडते :-

" महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केन्द्र आणि उप केन्द्राच्या ठिकाणी जिल्हा
परिषदेच्या अंशकालीन स्त्री परिचर म्हणून (पार्ट टाईम) सदरील महिला अत्यंत चांगली आणि
मोलाची सेवा देत आहेत. आठ तास काम करूनही त्यांना अंशकालीन संबोधले जाते व केवळ 600
रुपये दरमहा कामाचा मोबदला दिला जातो. काही जिल्ह्यात तर फक्त 500 रु. दरमहा मोबदला
दिला जातो किमान वेतन कायद्यावचीसुधा अंमलबजावणी होत नाही. राज्यात या पवरिचारीका
जवळपास दहा हजारापर्यंत आहेत. यामध्ये अनेक आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, विधवा, परित्यक्त्या,
सामाजिक दृष्ट्या अनुसूचित जाती,अल्प संख्याक जाती इतर मागासवर्गीय महिला आहेत. त्यांना
मागणीप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कायम न करणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-याइतके मानधन देणे,
शासन निर्णय क्रमांक 31.10.98 च्या नुसार 80 टक्के वाढीची वस्तुनिष्ठ अंमलबजावणी न होणे
शासन निर्णय दिनांक 21.7.03 च्या नुसार ना.आर.आर.पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार
1200 रुपये वेतन आणि वाढीव फरकाचे बिल न देणे, रजा, सुट्याचा लाभ,प्रवास भत्ता, सेवा पुस्तक
भरणे, भविष्य निर्वाह निधी कपात करणे, पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त जागा भरणे, वारसांना
नोक-या देणे, अनुकंपा लागू करणे या सर्व मागण्यांवर शासनाचे झालेले दुर्लक्ष परिचारिकांमध्ये
पसरलेला असंतोष या सार्वजनिक महत्वाच्या व निकटीच्या बाबीवर विशेष उल्लेखाची सूचना देत
आहे."

पृ.शी : सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्हयाचे विभाजन करून नव्याने
कायम दुष्काळग्रस्त जिल्हा निर्माण करणे

मुशी. : सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्हयाचे विभाजन करून
नव्याने कायम दुष्काळी जिल्हा निर्माण करण्याबाबत श्री.प्रकाश
शेंडगे,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना

उपसभापती : माननीय सदस्य श्री.प्रकाश शेंडगे यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली
आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री.प्रकाश शेंडगे (विधान सभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील
विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडतो .

सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्हयाचे विभाजन करून सांगोला, मंगळवेढा,कवठे
महांकाळ,जत, खानापूर, आटपाडी, तासगाव,माण, खटाव हे तालुके कायम दुष्काळग्रस्त असून या
तालुक्यांचा जिल्हा करण्यात यावा. हे अती तुटीचे खोरे असून पावसाचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे.
सदर तालुके डी.पी.ए.पी.खाली आहेत तसेच अवेळी पाऊस व अत्यल्प पावसाचे प्रमाण, परिणामी
पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, 10 टक्क्यापेक्षा कमी इरिगेशन असलेला भाग, शैक्षणिक, औद्योगिक
आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा उदरनिर्वाहासाठी, हजारो कुटुंबियाना जगण्यासाठी सहा
सहा महिने भटकंती करावी लागणे, उदा. ऊस तोड, मेंढपाळी, हमाल व शेतमजूर, त्यामुळे या
तालुक्यांचा दुष्काळी जिल्हा निर्माण करून या तालुक्यातील नागरिकांचे जीवन उंचावण्याच्या दृष्टीने
आर्थिक तरतूद करून दुष्काळी जिल्हा निर्माण करावा. त्या जिल्हयास वेगळा स्टेट्स देऊन या
भागातील लोकांना न्याय द्यावा अशी मी विनंती करतो .

नंतर श्री.सुंबरे

पृ. शी. : मराठी वाहिन्या सर्व कंपन्यांच्या केबल टीव्ही द्वारे प्रक्षेपित करणे.

मु. शी. : मराठी वाहिन्या सर्व कंपन्यांच्या केबल टीव्ही द्वारे प्रक्षेपित करणे याबाबत श्री. संजय दत्त वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मा-नीय सदस्य श्री. संजय दत्त यांनी विशेष उल्लेजासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री. संजय दत्त (विधानसभेने निवडलेले) : महोदय, मी पुढील विशेष उल्लेजासंबंधीची सूचना मांडतो.

"केबल चालकांची मनमानी आणि खराब प्रक्षेपणामुळे अनेक ग्राहक काही महिन्यातच टाटा स्काय टीव्ही आणि डिश टीव्ही कडे वळले आहेत. डीव्हीडी पिकवर क्वालिटी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुरेख प्रसारण हे या दोन्हींचे वैशिष्ट्य आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यात ज्या नव्या मराठी वाहिन्या सुरु झाल्या आहेत त्या अद्याप टाटा स्काय टीव्ही आणि डिश टीव्ही वर पहावयास मिळत नाहीत. या दोन्ही सेवांकडून दाखविण्यात येणाऱ्या अन्य प्रादेशिक भाषांच्या वाहिन्यांच्या तुलनेत मराठी भाषिक वाहिन्यांची संख्या अत्यल्प आहे. डिश टीव्ही वर 'स्टार माझा' आणि 'आयबीएम लोकमत' या वाहिन्या तर टाटा स्कायवर 'झी टॉकीज', 'झी 24 तास' आणि 'आयबीएम लोकमत' पहायला मिळत नाही. मराठीमध्ये सध्या 8 वाहिन्या आहेत आणि आणखी 2 ते 4 वाहिन्या सुरु होतील. असेच होत राहिले तर हजारो ग्राहकांना सध्या सुरु असलेले आणि भविष्यात सुरु होणाऱ्या मराठी वाहिन्यांपासून वंचित रहावे लागेल. ग्राहक संरक्षण कायदा आणि एमआरटीपी अन्वये सर्व वाहिन्या दाखविण्याबाबतचे नियम लागू असताना ते पाळले जात नाहीत. केबल टीव्ही, टाटा स्काय, डिश टीव्ही सारख्या कंपन्यांकडे ग्राहकांनी मागणी करूनही मराठी वाहिन्या दाखविण्यात येत नसतील तर संबंधितांचे लायसेन्स रद्द करण्याचे अधिकार 'ट्राय' या केंद्र शासनाच्या नियामक आयोगाला आहेत. तेव्हा शासनाने या बाबीची दखल घेऊन 'ट्राय' कडे आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. या सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर मी विशेष उल्लेख दाखल करीत आहे आणि त्यासाठी आपण मला परवानगी दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.

..... 3पी 2 ..

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.संजय दत्त यांनी 'विशेष उल्लेख' द्वारा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा येथे उपस्थित केला आहे. या राज्यातील मराठी वाहिन्यांना प्राईम बॅडवर, कलर बॅडवर आणि एस बॅडवर अजूनही पहिल्या 20 चॅनेल्सच्या यादीत प्राधान्यक्रम दिलेला नाही. राज्य शासनाचा अधिकार आहे, केबल नेटवर्क जवळपास 86 लाख घरांमध्ये पोहोचते, आणि डिश टीव्हीचे नेटवर्क देखील काही लाखांच्या घरात पोहोचलेले आहे. तेव्हा शासनाने त्वरित पावले उचलून या सगळ्या वाहिन्या, म्हणजे झी टीव्हीने मराठी वाहिनीसाठी एक चांगली सुरुवात केली आहे. त्यानंतर ई टीव्ही चॅनल आला, 'मी मराठी' चॅनल आला आणि आता राजदीप सरदेसाईचा ज्याला आपण मराठीची शान म्हणतो ते आणि श्री.विजय दर्ढा यांनी 'आयबीएम लोकमत' हा नवीन चॅनल आणला. या सर्वांनाच 20 चॅनेल्सच्या यादीत समाविष्ट केले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने कायदेशीर पावले उचलावित या करिता मी सन्माननीय सदस्य श्री.दत्त यांना समर्थन देतो.

अॅड. अनिल परब : सभापती महोदय, हा केंद्रीय कायदा आहे त्यात प्रत्येक राज्याच्या भाषेसाठी ठराविक वाहिन्यांचा नियम आहे. मला वाटते की, तो नियम काही ठराविक चॅनल्सपुरता आहे. जे सगळे नवीन चॅनल्स येतात त्या प्रत्येक चॅनलसाठी तो नियम नाही. परंतु प्रत्येक राज्याचा, प्रत्येक भाषेच्या थेरेस्टिटल अॅक्टप्रमाणे तेवढ्या वाहिन्या दाखविल्याच पाहिजेत असा नियम आहे. मला असे वाटते की, आज तेवढ्या वाहिन्या दाखविल्या जातात परंतु ग्राहकांचे प्रेशर यासाठी वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. सभापती महोदय, प्राईम बॅडचा देखील कायदा आहे. प्राईम बॅडवर किती वाहिन्या जायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे थेरेस्टिटलवर तो विषय देखील आहे.

उपसभापती : ठीक आहे. आता 'विशेष उल्लेख' संपले आहेत. यानंतर शासकीय विधेयके घेण्यात येतील.

आजच्या कामकाज पत्रिकेवरील नियम 260 खालील शिक्षण विषयक प्रस्तावाबाबत

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, आता आपण शासकीय विधेयक चर्चेला घेत आहोत. पण त्यानंतर नियम 260 खाली शिक्षण विषयक प्रस्ताव चर्चेसाठी आहे, तो आपण केव्हा चर्चेला घेणार आहात ? तो आज चर्चेला घेणार आहात की, उद्या-परवा घेणार आहात ? याबाबत आपण आम्हाला माहिती दिली तर बरे होईल.

उपसभापती : मी सध्या कामकाज पत्रिकेवरील क्रमानुसार काम घेतो आहे आणि आता त्या क्रमाने आपल्यापुढे 2008 चे वि.स.वि.क्रमांक 2 आणि सदरहू विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा सन्माननीय सदस्य श्री.रावते यांचा प्रस्ताव आहे. सध्या सन्माननीय सदस्य श्री.रावते हे आपला प्रस्ताव मांडण्यासाठी 'अॅन लेग आहेत. तेव्हा प्रथमतः त्यांचा प्रस्ताव प्रस्तुत होऊ घावा त्यानंतर मग नियम 260 चा प्रस्ताव आज घ्यायचा की नाही हे ठरविता येईल.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, आमची आपल्याला विनंती आहे की, नियम 260 खालील शिक्षण विषयक प्रस्ताव आपण आज न घेता, मंगळवारच्या बैठकीत घ्यावा. आज केवळ विधेयकावर चर्चा घ्यावी.

उपसभापती : ठीक आहे. आता आपण विधेयक आणि विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याच्या प्रस्तावावरील प्रस्ताव चर्चेला घेऊ. तरी आता सन्माननीय सदस्य श्री.रावते यांनी आपले भाषण पुढे सुरू करावे. मात्र माझी त्यांना विनंती राहील की, त्यांनी कृपा करून हे विधेयक आज संमत करून घ्यावे.

(यानंतर सौ. रणदिवे3क्यू 1 ..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3Q-1

APR/KTG/MMP/

पूर्वी श्री.सुंबरे

17:00

पृ.शी.: कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन)

(सुधारणा) विधेयक.

L.A. BILL NO. II OF 2008

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.) AND MOTION FOR REFERRING THE BILL TO JOINT SELECT COMMITTEE.

(विधेयक विचारात घेण्यात यावे असा प्रस्ताव पुन्हा प्रस्तुत झाला व विधेयक

संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव - चर्चा पुढे सुरु.)

श्री.दिवाकर रावते (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयकावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे.

(काही सन्माननीय सदस्य खाली बसून बोलतात.)

सभापती महोदय, मी नवीन कलम - 35 बाबत चर्चा करीत होतो. यात बाजार समित्यांच्या कार्यामध्ये निश्चितपणे प्रशासकीय कार्यक्षमता याची यासाठी हा शब्द आहे. सन्माननीय सदस्य आंब्याचा आग्रह धरीत आहेत, ते आंबे कसे मिळावेत यासाठी हे कलम आहे. कारण तुमचे आंबे वेळेवर पोहोचले पाहिजेत. कारण तो नाशिवंत आहे. जर हे आंबे वेळेवर पोहोचले नाहीत तर मग आमचे सन्माननीय सदस्य श्री.विनोद तावडे यांना कुठेतरी आंबा महोत्सव करावा लागतो.

उपसभापती : मग त्याच्या आंबा महोत्सवाचे काय होईल ?

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, बाजार समितीने याची योग्य दखल न घेतल्यामुळे आंबा विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान वाचविण्यासाठी सन्माननीय सदस्य श्री.विनोद तावडे यांना आंबा महोत्सव भरवावा लागतो. माननीय पणन मंत्री हे स्वतःच बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मध्ये यासंदर्भात पुढाकार घेत असतात आणि आमचे सन्माननीय सदस्य श्री.गुरुनाथ कुलकर्णी तेथे आवर्जून जातात. आता याठिकाणी आमचे सन्माननीय सदस्य कर्नल सुधीर सावंत नाहीत. कारण ते या बाबतीत पुढाकार घेत होते.

श्री.गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.विनोद तावडे, हे कोकणामध्ये पिकलेला आंबा येथे आणून विकतात. पण मी खरा शेतकरी आहे एवढेच तुम्हाला सांगू इच्छितो.

(सन्माननीय सदस्य खाली बसून बोलतात.)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3Q-2

APR/KTG/MMP/

17:00

उपसभापती : सर्व सन्माननीय सदस्यांनी बोलू नये. सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांना त्यांचे भाषण करु द्यावे.

श्री.गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय,मधाशी सन्माननीय सदस्यांनी विचारले होते की, कोकणातील आंबा पिकाच्या अनुषंगाने चर्चा केव्हा घेण्यात येणार आहे ? तसे झाले नाही तर शेवटी धोऱ्डियाच्या कपाळी धोऱ्डे, तसे आमचे करु नका.

(अनेक सन्माननीय सदस्य एकदम बोलतात.)

उपसभापती : माझ्याकडे पेटचांसकट आंबे पाठवा, मी ताबडतोब कोकणातील आंबा पिकाच्या संदर्भात चर्चा घेतो. सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी आपले भाषण पुढे सुरु करावे.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, बाजार समितीच्या कार्यामध्ये निश्चित प्रकारे प्रशासकीय कार्यक्षमता यावी म्हणून सहकार विभागातील निबंधक, सहकारी संस्था या पदा पेक्षा कमी दर्जाचे पद नसलेल्या अशा समिती सचिवाच्या संदर्भात मी बोलत आहे. यापूर्वी बोलताना मी असा उल्लेख केला होता की, ज्या तालुका बाजार समित्या आहेत, तेथे जे सहा.निबंधक आहेत, त्यांना मताचा अधिकार नाही. आता त्या दर्जाचा किंवा त्याच्या वरच्या दर्जाच्या व्यक्तीला सचिवपदी नेमणार आहात. मी एक तरतूद आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, सन 2005 चे वि.स.वि. विधेयक क्र.68 - महाराष्ट्र कृषी पणन विनियमन सुधारणा विधेयक 2005, सदनामध्ये आले होते. मॉडेल अऱ्कट मध्ये ज्या तरतूदी आहेत, त्याचा मी आवर्जून उल्लेख करीत आहे. त्यातील खास तरतुदींमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संदर्भात बोलत आहे. आज कॅग संस्थेच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेने आपल्या बाजारपेठेमध्ये प्रवेश केला आहे आणि आपणही जागतिक बाजारपेठेमध्ये प्रवेश करणार आहोत.

(सभापतीस्थानी - तालिका सभापती श्री.जगदीश गुप्ता)

यानंतर कृ.गायकवाड

श्री. दिवाकर रावते..

हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे याकरिता आम्ही आग्रह धरला होता. त्याप्रमाणे नंतर हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आले. तेथे या विधेयकावर संपूर्णपणे चर्चा झाली. मला आठवते आहे की, त्या वेळी बाजार समितीच्या बाबतीत मी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. हे विधेयक आणण्याचे मूळ कारण काय आहे असे मी त्यांना विचारले होते. त्यावेळी माननीय राज्य मंत्री महोदयांनी स्पष्टीकरण दिले होते. जागतिक बाजार समित्यांच्या संदर्भात केंद्र शासनाने काही करार केलेले आहेत. आपल्या शेतकऱ्याचा माल दुसरीकडे गेला पाहिजे, तेथील माल येथे आला पाहिजे. बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण व्हावे याकरिता केंद्र शासनाने काही बदल केलेले आहेत. अशा प्रकारचे विधेयक आणले नाही तर बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार नाही असे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी मी त्यांना विचारले की, केंद्र शासनाला अशा प्रकारे कायदे करण्याचा कोणता अधिकार आहे ? कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणता अधिकार आहे ?

सभापती महोदय, कायद्याच्या संदर्भातील माहिती मिळविण्याकरिता मी घटनेचे 7 वे शेड्यूल पाहिले. त्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या यादीमध्ये केंद्र शासनाने करावयाच्या कायद्यांची यादी दिलेली आहे. त्या यादीमध्ये पणनच्या संदर्भात केंद्र शासनाने कायदा करावा असा कोठेही उल्लेख नाही. दुसर्या यादीमध्ये राज्य शासनाने करावयाच्या कायद्यांची माहिती दिलेली आहे. राज्य शासनाला पणनच्या संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर मी कॉन्करन्स लिस्ट पाहिली. त्यामध्ये राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी मिळून कोणते कायदे करावयाचे आहेत याची यादी दिलेली आहे. या यादीमध्ये पणनच्या संदर्भात कोणताही उल्लेख नाही.

सभापती महोदय, शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी विक्री करण्याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये तालुका पातळीवर 265 कृषि उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा राज्य शासनाने केलेला आहे. केंद्र शासनाला या कायद्यामध्ये आणखी काही चांगल्या सुधारणा करण्याची इच्छा असेल तर घटनेतील कलम 252 कलमाप्रमाणे, तीन राज्यांनी एक ठराव करून केंद्र शासनाकडे

2...

श्री. दिवाकर रावते..

पाठविल्यानंतर एक वेगळा कायदा तयार करण्यात आला होता. हा आंतरराज्यीय कायदा त्या राज्यांना अपेक्षित होता त्याप्रमाणे करण्यात आला. माझ्या माहितीप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या कृषि मंत्रालयाने ड्राफ्ट तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्याप्रमाणे कायद्यामध्ये बदल करा असे सांगण्यात आले आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून बाजारपेठ निर्माण करण्याकरिता केंद्र शासनाकडून दीड ते दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. केंद्र शासनाकडून हा निधी मिळविण्याकरिता आग्रह करून हे सुधारणा विधेयक क्रमांक 68 आणण्यात आलेले आहे. हा निधी राज्य शासनाला मिळाला काय ? बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करण्याकरिता काय तरतूद करण्यात येणार आहे हे माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये सांगावे. हा निधी मिळविण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कोणते पाऊल उचलण्यात आलेले आहे ?

सभापती महोदय, माझ्याकडे एक नस्ती आहे. निवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याला 3 महिन्याची तातडीने मुदतवाढ द्यावयाची होती. या संदर्भात संबंधित खात्यामध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मग एका विषयावर बोलताना आम्ही सांगितले होते की, या राज्यामध्ये मुख्य सचिवांची नियुक्ती करीत असताना अनेक ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले. याची खंत अनेकांच्या मनामध्ये आहे.

यानंतर श्री. बरवडा..

श्री. दिवाकर रावते

त्याचे अनेक पद्धतीने होणारे प्रशासकीय परिणाम आपण वाचतो, बघतो. तो विषय आता या ठिकाणी नाही. अशा प्रकारे ज्यावेळेला ते पद रिकामे होते त्यावेळी निवृत्त झालेल्या व्यक्तीकडे ते पद तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन द्यावयाचे काय ? त्यावेळी त्या ठिकाणी श्री. शेळके, श्री. काशीकर, श्री. श्रीकांत दातार असे ज्येष्ठ अधिकारी होते. पण त्यांना ते पद न देता श्री. खवले यांना दिले. श्री. खवले हे माझ्या परिचयाचे होते. श्री. खवले हे सक्षम अधिकारी होते. त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न नाही. परंतु श्री. खवले यांना तीन महिन्यांचे एकरंतेशन देण्याचे ठरले. तो विषय संपला. ही गोष्ट 2007 मधील म्हणजे गेली वर्षीची आहे. त्याच्यावर माननीय मंत्री पण, रोजगार हमी योजना, संसदीय कार्य, महिला व बालविकास यांनी 21.2.2007 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना लिहिलेल्या पत्रात "Please grant three months extension" असा शेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेला असून सदर पत्राची प्रत विभागाला अग्रेषित केली. यातील दोन गोष्टी खटकतात. एक तर त्याच अधिकाऱ्याला तीन महिने एकरंतेशन देण्याचा अद्वृहास का हा प्रश्न खटतो आणि दुसरे म्हणजे महाराष्ट्र राज्याची राज्यभाषा मराठी असताना माननीय मंत्रिमहोदय आपल्या नस्तीवर "Please grant three months extension" असा शेरा लिहून आपल्या खालच्या अधिकाऱ्यांकडे असा संदेश पाठवित आहेत की, आपण ती भाषा वापरली नाही तरी चालेल. मी अत्यंत वेदनेने हे सांगत आहे. ज्यावेळेला या सदनामध्ये मराठी भाषा वापरली गेली पाहिजे अशा प्रकारचा ठसाव झाला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला पण ती अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या सदनामध्ये पाच दिवस सतत चर्चा झाली. या संपूर्ण सदनाने त्यावेळी सांगितले तेव्हा माननीय मंत्रिमहोदयांनी आश्वासन दिले. सभापती महोदय, ते आश्वासन गंभीर आहे. पटलावर किंवा चर्चेत काय आश्वासन दिले त्यापेक्षा त्यांनी मला लिहून कळवले. मी ते कधी तरी हक्कभंग आणण्याकरिता लॅमिनेट करून ठेवले आहे. त्यांनी मराठीचा वापर सर्व पातळीवर करूच असे म्हटले आहे. जी.ए.डी. कडून कडक पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल असे त्यामध्ये म्हटले आहे. त्यांनी सही करून मला पत्र पाठवलेले आहे. खाजगी नोट अशी आहे की, आता वाढवू नका, थांबा. मी ते जपून ठेवले आहे. सभापती महोदय, या विषयावर बोलत

श्री. दिवाकर रावते

असताना या नस्तीवर असलेल्या इंग्रजीचा मी मुद्दाम उल्लेख करतो. तो एवढ्याकरिता की, अजूनही आपण या सर्व मंत्रिमहोदयांना पत्र लिहिणार काय की, आपण राज्यकर्ते म्हणून तरी इंग्रजी वापरु नका. पण या नस्तीवर ते आहे. यामध्ये "Please grant three months extension" असा शेरा लिहिला आहे. पुढे असा रिमार्क आहे की, श्री. खवले सध्या अपर निबंधक, सहकारी संस्था या पदावर कार्यरत असून सध्या सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यांच्याकडे कृषी पणन संचालक या पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. कृषी पणन संचालक हे पद गेल्या 9 महिन्यांपासून रिक्त असून प्रयत्न करूनही सदर पद पदोन्नतीने भरता आले नाही. त्यावेळी पदोन्नतीला कोर्टाचा स्टे होता. आता तो स्टे उठला आहे. कृषी पणन संचालक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यासाठी सध्या योग्य अधिकारी उपलब्ध होऊ शकत नाही हे जे वाक्य आहे ते सहकार खात्यामध्ये अत्यंत टॅलेंटेड असलेल्या, हुशार असलेल्या अधिकाऱ्यांचा अवमान करणारे आहे. मी हे रेकॉर्डवर बोलत आहे. एक श्री. खवले सोडले तर बाकीचे नालायक आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. मी मुद्दाम ते रेकॉर्डवर आणत आहे. सचिव नेमण्याची बाब येते त्यावेळेला तुमचे खाते कसे चालते, कसे मत चालते हे आपल्याला माहीत आहे. हे वाक्य अतिशय क्लेशकारक आहे. ज्यावेळी असे वाक्य अधिकाऱ्यांना कळते त्यावेळी आपली या ठिकाणी काय लायकी आहे, आपली काय योग्यता आहे असा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतो. म्हणून मी हे वाक्य पुन्हा वाचतो. कृषी पणन संचालक एकाच व्यक्तीला करावयाचे असेल तर त्याच्याकरिता कशा क्लृप्त्या योजल्या जातात हे यावरुन दिसते. यामध्ये असे म्हटले आहे की, कृषी पणन संचालक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यासाठी सध्या योग्य अधिकारी उपलब्ध होऊ शकत नाही. हे शब्द वापरणे म्हणजे इतर सर्व अधिकाऱ्यांचा अवमान करण्यासारखे आहे. पण ते शब्द या नस्तीमध्ये वापरले आहेत. पुढे मी कारण सांगणार आहे. पुढे असे म्हटले आहे की, सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता श्री. खवले यांच्याकडे सोपविण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. मग तीन महिन्यानंतर लायक अधिकारी आकाशातून पडणार आहे काय ? असलेल्या अधिकाऱ्यातूनच तो येणार आहे की नाही ? पण तीन

श्री. दिवाकर रावते

महिन्याकरिता श्री. खवले यांना द्या कारण तो लायक अधिकारी आहे अशा पद्धतीचे यामध्ये म्हटले आहे. त्यांना का द्यावयाचे याचे कारण दिले आहे आणि तो विषय आता माझ्यासमोर आहे. त्याबाबत आपल्या उत्तरामध्ये माहिती उपलब्ध व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून मी मुद्दाम हा उल्लेख करतो. कारण ही सगळी माहिती घेण्याकरिता आम्हाला दुसरी संधी नसते. माझ्या माहितीप्रमाणे पणनचा विषय पाच सहा वर्षामध्ये एकदोन वेळा आला असेल. एकदा चिकित्सा समितीकडे गेलेले विधेयक ज्यावेळी परत सभागृहामध्ये येते त्यावेळी नियमानुसार, संकेतानुसार त्यावर चर्चा करत नाही.

यानंतर श्री. खंदारे...

श्री.दिवाकर रावते.....

कारण ते सर्वपक्षीय मंजूर असते. श्री.खवले यांना मुदतवाढ का द्यावयाची, त्यांच्याएवजी दुसरे लायक अधिकारी नाहीत काय ? यामध्ये असे म्हटले आहे की, "सध्या पणन विभागामध्ये बरेच प्रकल्प चालू असून ते लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये विशेष कृषि निर्यात हा महत्वाचा प्रकल्प आहे. कृषि प्रक्रिया व पणन सुविधा सक्षम करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून प्रस्तावित केलेल्या निधीचा समावेश आहे." म्हणजे जागतिक बँकेकडून पणन करिता निधी येत आहे. कृषि सुविधा सक्षम करण्यासाठी निधी येत आहे. मग आतापर्यंत किती निधी आला ? त्यापैकी किती खर्च केला ? त्याच्यातून किती सक्षमीकरण झाले ? या एका गोष्टीसाठी श्री.खवले यांना त्या काळात 3 महिने मुदतवाढ दिली होती. यामध्ये असेही म्हटले आहे की, "हे सर्व प्रकल्प तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे या प्रकल्पामध्ये श्री.खवले यांचा सहभाग व अनुभव उत्कृष्ट असल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी." सभापती महोदय, अनेक वेळा सभागृहात मंत्रिमहोदयांकडून ही बाब तांत्रिक आहे, लवकरात लवकर करु, अशाप्रकारची उत्तरे देऊन वर्षानुवर्षे निर्णय होत नाहीत. पण श्री.खवले यांना 3 महिने मुदतवाढ दिल्यानंतर प्रकल्प तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय स्वरूपाचे असल्यामुळे ते निकालात निघतील असा त्याचा अर्थ होतो. यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. ज्यावेळी सरकारला वाटते त्यावेळी एखादा सरकारी अधिकारी लायक ठरला जातो बाकीचे नालायक ठरले जातात असा त्याचा अर्थ आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, श्री.खवले एकट्रॉ ऑफिनरी होते. जागतिक बँकेतून येणा-या पैशातून हे सर्व प्रकल्प तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय स्वरूपाचे असले तरी त्यांनी ते मार्गी लावले आहेत. ही आर्थिक योजनेतील गुंतवणूक आहे. शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या मालावर प्रक्रिया करण्याकरिता येणा-या पैशाचे वाटप करण्याची क्षमता फक्त त्यांच्यामध्ये होती. श्री.खवले यांचा मुदतवाढीचा कालावधी संपल्यावर ते निवृत्त झाले. त्या 3 महिन्यामध्ये 275 कोटींचे प्रकल्प मार्गी लागले अशी माझी माहिती आहे. कोणाला यामध्ये खास रस होता ? 275 कोटींचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी श्री.खवले यांना थांबविले होते. त्या 3 महिन्यात 275 कोटींचे असे कोणते निर्णय घेतले. यानिमित्ताने सभागृहाला माहिती होणे आवश्यक आहे. 3 महिन्यामध्ये सर्व अधिका-यांना नालायक ठरविले

2...

श्री.दिवाकर रावते....

आणि त्यांना ठेवले जाते त्यावेळी कोठे तरी संशयाची माशी शिंकते. त्या कालावधीत 275 कोटीचे प्रकल्प राबविले जातात, त्यातील एखाद दोन कोटींनी आकडा मागेपुढे होईल. उत्तराच्या भाषणात मंत्रिमहोदयांनी यातील खरा आकडा सांगावा, कदाचित 280 कोटी असतील, 360 कोटी असतील. परंतु या 3 महिन्यात 275 कोटीचे प्रकल्प घाईघाईने मार्गी लागले असतील आणि तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय क्षमता वापरण्याकरिता श्री.खवले यांना ठेवले असेल तर त्याची माहिती आम्हाला होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण हे सचिव पद आहे. एका सचिवाच्या कार्यक्षमतेवर इतर सर्वांना वेडयात काढून एकाच माणसाच्या कर्तृत्वाचा येथे ज्यावेळी उल्लेख होतो त्यावेळी सचिव पदासाठी असलेल्या कलम 35 चा संबंध येतो. हे सचिव पद येणार आहे. ते सचिव पद कशासाठी आणणार ? प्रशासकीय कार्यक्षमता यावी यासाठी सचिव पद येणार आहे. प्रशासकीय मंडळ कशासाठी येणार ? बाजार समितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्याकरिता प्रशासकीय समिती व सचिव येणार आहे. मी पुन्हा माझ्या मूळ मुद्याकडे येतो.

नंतर श्री.शिगम

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3U-1

MSS/ SBT/ KTG/

17:20

(श्री. दिवाकर रावते)

या विधेयकामध्ये कलम 35 समाविष्ट करण्यात येत आहे. सहकार विभागातील सहायक निबंधक, सहसकारी संस्था, या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या पदावर नसेल अशा कोणत्याही अधिका-यास कोणत्याही बाजार समितीचा सचिव म्हणून नियुक्त करता येईल, अशा प्रकारची तरतूद या कलमामध्ये करण्यात आलेली आहे. ..

तालिका सभापती : माननीय मंत्री महोदयांना कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. तो सादर झाल्यानंतर सन्माननीय सदस्यांनी आपले भाषण पुढे सुरु करावे.

...2...

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3U-2

MSS/ SBT/ KTG/

17:20

पृ.शी./मु.शी.: कामगाज सल्लागार समितीचा अहवाल सभागृहाला सादर
करणे व संमत करून घेणे

श्री. राजेश टोपे (संसदीय कार्य राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने
कामकाज सल्लागार समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहाला सादर करतो.

विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक गुरुवार, दिनांक 10 एप्रिल, 2008 रोजी
दुपारी 3.30 वाजता विधान भवन, मुंबई येथे झाली. सदरहू बैठकीत समितीने विचार-विनियम करून
मंगळवार, दिनांक 15 एप्रिल, 2008 ते शुक्रवार, दिनांक 25 एप्रिल, 2008 पर्यंतचे सभागृहाचे
कामकाज पुढीलप्रमाणे असावे, असा निर्णय घेतला

एप्रिल, 2008

मंगळवार, दिनांक 15

- 1) शासकीय विधेयके
- 2) सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव

बुधवार, दिनांक 16

- 1) शासकीय विधेयके
- 2) विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव

गुरुवार, दिनांक 17

शासकीय विधेयके

शुक्रवार, दिनांक 18

सुट्टी (महावीर जयंती)

शनिवार, दिनांक 19

बैठक होणार नाही.

रविवार, दिनांक 20

सुट्टी.

सोमवार, दिनांक 21

शासकीय विधेयके

मंगळवार, दिनांक 22

- 1) शासकीय विधेयके

बुधवार, दिनांक 23

2) जागतिक हवामानात होणा-या बदलाचे परिणाम
(ग्लोबल वॉर्मिंग) संबंधीचा प्रस्ताव

- 1) शासकीय विधेयके
- 2) विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव

..3..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3U-3

गुरुवार, दिनांक 24

1) शासकीय विधेयके

2) अंतिम आठवडा प्रस्ताव

शुक्रवार, दिनांक 25

अशासकीय कामकाज (ठराव)

तालिका सभापती : कामकाज सल्लागार समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहाला सादर झाले आहे.

श्री. राजेश टोपे : सभापती महोदय, कामकाज सल्लागार समितीचे प्रतिवृत्त सभागृहास
संमत आहे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो.

प्रस्ताव मतास टाकून संमत झाला.

...4..

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3U-4

MSS/ SBT/ KTG/

17:20

पृ.शी.: कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक

L.A. BILL NO. II OF 2008

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963 AND MOTION FOR REFERRING THE BILL TO JOINT COMMITTEE.)

(चर्चा पुढे सुरु....)

तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी आपले भाषण पुढे सुरु करावे.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सन 2005च्या विधेयकातील 10व्या कलमामध्ये मुख्य अधिनियम 35, पोट नियम (1), विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात यावे, असे म्हटलेले आहे. हे कलम देखील फार महत्वाचे आहे. मग या 2 क्रमांच्या विधेयकामध्ये ही तरतूद का करण्यात आली असा प्रश्न पडतो. तरतूद अशी आहे की,आणखीन असे की, राज्य पणन महामंडळ अर्हता आणि अनुभव यानुसार बाजार समित्यावर सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात यावयाच्या व्यक्तीची यादी तयार करील आणि नावे नोंद केलेल्या व्यक्तींच्या यादीतून एका व्यक्तीची सचिव म्हणून नियुक्त करणे बाजार समितीवर बंधनकारक राहील." याचा अर्थ काय आहे ? साखर कारखान्यांच्या एम.डी.ची यादी तयार केलेली आहे. त्या यादीमधूनच साखर कारखान्यांवर एम.डी. घेता येईल. ही यादी क्वॉलिफाय करण्याच्या संदर्भात साखर आयुक्त निर्णय घेतात. या यादीतील व्यक्ती साखर कारखान्यांवर एम.डी.म्हणून घेता येते. एखादी व्यक्ती आमच्या गावची आहे, नातेवाईक आहे, पाहुणा आहे म्हणून एम.डी.च्या पदावर त्याची नियुक्ती होत नाही. बाजार समितीमध्ये नियोजन असावे या करिता या विधेयकाला सदनाने मान्यता दिली. राज्य पणन महामंडळ अर्हता आणि अनुभव यानुसार बाजार समितीवर सचिव म्हणून नियुक्त होणा-या व्यक्तीची यादी तयार करील आणि नाव नोंदणी केलेल्या यादीतून एका व्यक्तीची सचिव पदावर नियुक्ती करणे हे बाजार समितीवर बंधनकारक राहील.

...नंतर श्री. गिते...

श्री. दिवाकर रावते...

या विधेयकान्वये तुम्हाला सचिवांची यादी तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यासंबंधी आपल्याला निकष बनवावे लागतील. त्यामध्ये शैक्षणिक अर्हता आली, या पदासाठी ज्या काही पात्रता लागतील त्यासंबंधीची माहिती आपल्याला घ्यावी लागेल. सूचीमध्ये बसतील अशा प्रकारचे उमेदवारांची यादी तयार करावी लागेल. अशा प्रकारच्या उमेदवारांची यादी कळवून राज्यातील 265 बाजार समित्यांना कळवून टाकावयाचे आम्ही पाठविलेले उमेदवारच सचिव म्हणून काम करतील. एखाद्या साखर कारखान्यात चांगल्या प्रकारे काम करणारा एम.डी. असेल तर त्याला आपल्या कारखान्यावर नेमण्यासाठी उडया पडतात. हे एम.डी.आम्हाला पाहिजेत अशा प्रकारची मागणी साखर कारखान्यांच्या संचालकांकडून केली जाते. सहकार संस्थांमध्ये नेहमी "ए" क्लास दिला जातो. "ए" क्लासच्या पुढे क्लास नसल्यामुळे त्या संस्थांना हा एकच क्लास दिला जातो. अनेक अधिकारी चांगले काम करणारे आहेत. काही अधिकारी आपल्या कामाची कार्यक्षमता दाखवीत असतात. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून बाय प्रॉडक्टचे प्रकल्प निघता आहेत ते एम.डी.च्या कार्यक्षमतेमुळे निघत आहेत. वीज निर्मिती पासून काही बाय प्रॉडक्ट साखर कारखान्यामधून तयार होत आहेत त्यामागे एम.डी.यांची कार्यक्षमता आहे. तुम्ही तर पूर्वी विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. या सभागृहाने विधेयक मंजूर करून सचिव निर्माण करण्याचा अधिकार दिला आणि या विधेयकात तुम्ही असे म्हटले आहे की, या यादीतूनच एका व्यक्तीची सचिव म्हणून नियुक्ती करणे हे बाजार समितीला बंधनकारक आहे. जर आपण हे पूर्वीच बंधनकारक केले आहे तर तसेच क्लम आताच्या विधेयकात का आणले आहे याचा खुलासा माननीय मंत्री महोदयांनी करावी. या विधेयकात हे क्लम का आणले याचा उलगडा मला झाला आहे. त्याचे कारण देखील मला समजलेले आहे. परंतु हे दोन्ही क्लमे सदनाने मंजूर केल्यानंतर आम्ही काय समजावयाचे? सहकार खात्यामध्ये तुम्हाला अनेकांना पदोन्नती द्यावयाच्या आहेत. सध्या जे सहाय्यक पदावर काम करीत आहेत, त्यांना वरच्या पदावर पदोन्नती द्यावयाची आहे. त्यांच्या जागी दुसरे सहाय्यक आणावयाचे आहेत. सचिव पदावर आपली माणसे नियुक्त करावयाची आहेत. तुमचे जे काही ठरले आहे त्याबद्दल माझी काही तक्रार नाही. परंतु श्री. खवले एकटे लायक आहेत, बाकी लायक नाहीत. मी नालायक हा शब्द वापरत नाही. तीन महिन्यात पदोन्नती द्या, त्याचे कारण आमच्याकडे लायक अधिकारी नाहीत. सहाय्यक निंबंधक किंवा त्यांच्या पेक्षा मोठया दर्जाचा योग्य अधिकारी

2...

श्री.दिवाकर रावते...

नसल्यामुळे या यादीतील उमेदवाराची आम्ही नियुक्ती करीत आहोत असे तुम्ही आम्हाला सांगा. तुम्हाला अधिकार प्राप्त झालेले असल्यामुळे तुम्ही सचिवांची यादी तयार केली असेल. सचिवांच्या नियुक्तीच्या बाबतीमध्ये विधेयकामध्ये दोन कलमे आणून गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. हा गोंधळ का निर्माण करून ठेवला आहे ? ही सर्व प्रोसीजर पूर्ण करताना सचिव हे शासनाचे कर्मचारी आहेत. या सचिवांना बाजार समितीने पगार दिले तरी त्यांची जबाबदारी वाढली. त्या बाजार समितीमध्ये प्रचंड प्रमाणावर जे काही घडेल त्याला तोच जबाबदार राहणार आहे. या सदनात अनेक चर्चा होतात. या सभागृहाच्या माध्यमातून आतापर्यंत करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली आहेत. भ्रष्टाचारामध्ये कोण अडकले ? भ्रष्टाचारात कोण गुंतले आहेत ? यासंदर्भात कारवाई कोणावर झाली ? त्याच्यावर दबाव आणणा-या, त्याला ते करण्यास लावणा-या, त्याला ते करण्यास भाग पाडणा-या राज्यकर्त्यावर कधी घरी जावे लागले नाही. त्या अधिका-याला घरी जावे लागले. आजही सहकार क्षेत्रामध्ये या क्षणाला परिस्थिती अशी आहे की, बाजार समिती निवडून आलेली असली आणि त्यांनी नेमलेला नोकर तो सचिव असतो. तो सचिव काही सरकारला बांधील नाही.....

यानंतर श्री. कानडे....

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3W-1

SSK/ KTG/ SBT/

17:30

श्री. दिवाकर रावते

त्याला केव्हाही काढून टाकायचे. त्याला बाजार समितीने नियुक्ती दिलेली असते. त्याची शैक्षणिक अर्हता काय आहे माहीत नाही, पदासाठी पात्र आहे काय माहीत नाही, संचालकांना वाटेल तो आणि संचालकांच्या मर्जीतील, त्यांच्या बडदास्तीमधील सचिव पाहिजे. सहकार क्षेत्रातील दादागिरी हा वेगळा विषय आहे. सहकार मंत्रांना मी सांगू इच्छितो की, मी सहकार मंत्री म्हणून चार-साडेचार महिनेच होतो. परंतु माझ्या कारकिर्दीत मी 300-400 अधिकारी घरी पाठविले होते. आजही माझ याकडे अनेक प्रकरणे आहेत. शेवटी आपले सहकारी आहेत. लोक निवडून देतात, खासदार होतात आणि आमदार होतात. 100 टक्के आरोप सिध्द झालेले आहेत. परिवहन खात्यातील उदाहरण मी दिले होते. 100 टक्के जबाबदारी फिक्स झाल्यानंतर सरकार बदलेले तोपर्यंत आपल्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून कोर्टातून स्थगिती मिळविली. सरकार बदलले आणि यादीतून नांव देखील बदलले. खासदारकीला उभे राहिले होते आता आमदार आहेत. सांगण्याचा हेतू असा आहे की, खोल चिखलात असला तरी तो राज्यकर्ता आहे आणि पायाला नुसता चिखल लागला की कर्मचारी भ्रष्ट ठरविला जातो ही प्रशासकीय यंत्रणेची नितिमत्ता आहे. सगळ्यांचे अनुभवाचे बोल आहेत. सुळावर राज्यकर्ते चढत नाहीत. मराठवाड्यातील जवळजवळ सर्वच जिल्हयांमध्ये बँक घोटाळे आहेत. हिंगोली मध्यवर्ती बँक वेगळी होत नाही म्हणून तेथे घोटाळा नाही. परभणी बँक विभक्त केली तर हिंगोलीची चालेल परभणीची बद करावी लागेल. एक बँक घोटाळा कोर्टात सिध्द झाला. 10 वर्षे झाली आहेत. 36 कोटीची जबाबदारी फिक्स झाली. रक्कम वसूल करा म्हणून आदेश झाले. त्यांनी एक निवडणूक लढविली. आधार देण्याचे प्राबल्य, मतदार आणले, पक्ष वाचविला त्यांच्याकडून रिकव्हरी होत नाही. याच ठिकाणी अधिकारी असता तर काय केले असते ? सापडला नाही तर कोर्टात जायचे. लपला असेल, सापडत नाही, बेपत्ता आहे म्हणून त्याची प्रॉपर्टी जप्त करायची. सचिव तुमच्या खात्याचा आहे आणि सरकारी अधिकारी आहे. नियमाप्रमाणे त्याला फक्त तेथून पगार मिळणार. बाजार समित्या कशा असतात हे मंत्रीमहोदयांना चांगले माहीत आहे. कितीही घोटाळा झाला तरी जबाबदारी सचिवावर येतो. बाकी सुटणार आणि कर्मचारी बाराच्या भावात जाणार. नियुक्तीच्या सेवाशर्तीप्रमाणे त्याच्यावर कारवाई करता येते. त्याची चौकशी करता येते. त्याला निलंबित करता येते. आता सचिवांना करता येत नाही. शासन हे सचिव नेमणार मग यादीचे काय करणार ? हे सगळे सचिव कशासाठी नेमता ?

नंतर श्री. भोगले

श्री.दिवाकर रावते.....

उद्देश चांगला आहे. म्हणजे अगदी खुळखुळा होणार असे नाही. असा सचिव नेमल्यानंतर तो त्याला जे करावयाचे आहे ते करणार. तुम्हाला काय करायचे ते करा. फार फार तर त्याची बदली होईल. तुम्ही सचिव पदावर सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा अधिकाऱ्याला सचिव म्हणून नेमणार आहात. तेव्हा तो सरकारचा अधिकारी असणार आहे. बाजार समितीचा संचालक किंवा अध्यक्ष यांचे जेवढे वजन असेल तेवढा त्यांच्यावर दबाव असणार आहे. नाही तर घरी जावे लागेल. दुसरा अधिकारी बदलून येईल. म्हणजे एका बाजार समितीची जबाबदारी घेणारा सचिव राहील असे नाही. फार मोठा घोळ झाल्यानंतर त्याची बदली होईल. तिथे नवीन अधिकारी आला, तो म्हणेल माझा या घोळाशी काही संबंध नाही. तो शासनाचा असला तरी या सचिवांची जबाबदारी राहणार या संदर्भात कोणते नियोजन करणार आहात? बाजार समित्यांचे काय बळकटीकरण करणार आहात, काय सक्षमीकरण करणार आहात? मी मागच्या वेळी म्हणालो होतो की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जीवनधारा असलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण नव्हे तर बाजार समित्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. त्यावेळी माननीय पणनमंत्री म्हणाले, असे म्हणून नका. ग्रामीण भागातील बाजार समित्या मॉडर्न होतील. संगणक येतील. हेल्पलाईन सुरु होईल. प्रचंड निधी येतो. शेतकऱ्यांना संपूर्ण जगाची माहिती इंटरनेटवर मिळेल. आज ती मिळते आहे. परंतु इंटरनेटवर मिळणार. परंतु कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उत्पन्न कशासाठी आहे? कृषि उत्पन्न बाजार समितीची एकापेक्षा अधिक जिल्हयासाठी विभागीय बाजार समिती किंवा एकापेक्षा अधिक तालुक्यांसाठी प्रादेशिक बाजार समिती म्हणून घोषित करण्यात यावी, याकरिता हे विधेयक आणले. मग हा सचिव जो नियुक्त होणार आहे त्याची बाजार समिती ही जर आमच्या नवीन झालेल्या मॉडेल ॲक्टप्रमाणे एका जिल्हयांसाठी जाहीर होऊ शकते. या कायद्याप्रमाणे असेच आहे. तो सचिव या चार जिल्हयांच्या बाजार समितीचा सचिव असणार आहे. त्यामध्ये एकापेक्षा अधिक जिल्हयासाठी विभागीय बाजार समिती किंवा एकापेक्षा अधिक तालुक्यांसाठी प्रादेशिक बाजार समिती म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्या बाजार समितीचा हा सचिव होणार आहे.

.2..

श्री.दिवाकर रावते.....

सभापती महोदय, अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी बाजार क्षेत्र असल्याचे मानण्यात येईल. त्या क्षेत्रासाठी असलेल्या बाजार समितीला राज्य शासनाने अधिसूचित केले असेल अशा नावाने ओळखले जाईल आणि ती विभागीय किंवा प्रादेशिक बाजार समिती होईल, तिचा हा सचिव होईल. या नवीन मॉडेल ॲक्टप्रमाणे हे सगळे घडत असताना काय काय घडले? म्हणजे हा सचिव आपण नेमणार आहात त्याची व्याप्ती मॉडेल ॲक्टप्रमाणे वाढेल. कायदा याठिकाणी झालेला आहे. सचिव हे होणार आहेत ते सहाय्यक निबंधक किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे असणार आहेत. त्यांची यादी तयार करणार आहात. ती यादी तयार केली की नाही त्याचा आम्हाला थांगपत्ता लागत नाही. राज्यातील शेतकरी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत आपल्या कृषि उत्पादनाची घाऊक विक्री करु शकतात. अशा बाजार समित्यांमार्फत कृषि उत्पादनाची घाऊक विक्री करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय नसतो म्हणून अधिक पर्यायामुळे अधिक सौदाशक्ती प्राप्त होणे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषि उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी अधिक पर्याय देण्यासाठी तो अधिनियम झाला. आता ही त्या सचिवाची जबाबदारी आहे.

(नंतर श्री.जुनरे....)

श्री. दिवाकर रावते ...

त्याचा एकमेकाशी संबंध आहे. तुम्ही जे नियम करीत आहात त्यामुळे मॉडेल ॲक्टची व्याप्ती वाढल्यानंतर बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राची व्याप्ती वाढणार आहे. यांसदर्भात या विधेयकामध्ये माहिती देण्यात आलेली आहे. मी सुरुवातीला विधेयकाचे कलम 13 सांगितलेले आहे त्यामध्ये निवडणूकीचा संदर्भ आहे. मघाशी या ठिकाणी येऊन माननीय मंत्रीमहोदय म्हणाले की, नेहमी सारखेच हे विधेयक आहे, यामध्ये विशेष असे काही नाही. परंतु सभापती महोदय, या विधेयकामध्ये नेहमी सारखे काही नाही. या विधेयकामध्ये काय मेख मारलेली आहे तेच मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे. साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील जो शेतकरी 250 रुपये भरतो तोच शेअर होल्डर होत असतो परंतु या शेतक-याला शेअर होल्डर बनवायचे की, नाही त्याला मतदानाचा अधिकार द्यावयाचा की, नाही हे संचालक आजही ठरवतात. संचालकच सगळे अधिकार आपल्याकडे घेत असतो. शेतक-याला शेअर होल्डर केले नाही तर तो अपील करू शकत नाही कारण त्याच्याजवळ तेवढी शक्ती नसते. असा प्रकार महाराष्ट्रातील शेतकरी आज सुध्दा अनुभवत आहेत याची आपल्या सर्वांना माहिती आहेच. पुर्णा साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील एका शेतक-याचा मला फोन आला होता तो म्हणाला "साहेब आपण कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विधेयकावर सभागृहात बोलत आहात परंतु माझा ऊस घेतला जात नाही त्यामुळे यासंदर्भात तुम्ही मला मार्गदर्शन करा." अशा प्रकारे आज सुध्दा शेतकरी संचालक आणि राजकारण्यांकडून नाडला जात आहे. एवढया मोठया प्रमाणात संचालक आणि राजकारण्यांचे प्राबल्य वाढलेले आहे. या विधेयकामुळे बाजार समित्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात फेरफार केले जाणार आहेत. या बिलामुळे व्याप्ती वाढली जाणार आहे. तालुक्याची बाजार समिती ही जिल्हयाच्या किंवा विभागाच्या स्थरापर्यंत जाऊ शकते. या ठिकाणी आपण जे कृषि बाजार समित्यांचे विधेयक आणले आहे त्यातून शेतक-यांना काय सवलती मिळणार आहेत ? यामध्ये असे म्हटले आहे की, "थेट पण विशेष वस्तुचा बाजार घोषित करणे, खाजगी बाजार व ग्राहक शेतकरी बाजाराची स्थापना करणे याबाबतची तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणले होते. या अधिनियमामध्ये योग्य त्या सुधारणा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे." सभापती महोदय, "आशा बाजारामध्ये उत्पादक थेट विक्री करू शकेल आणि ग्राहक कृषि उत्पादक थेट शेतक-यांकडून मालाची खरेदी करू शकेल" हे प्रयोजन

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

3Y-2

SGJ/ SBT/ KTG/

17:40

श्री. दिवाकर रावते ...

त्या कायद्यात होते. शेतकरी आपल्या शेतामधील माल आडत्या नाही कोणीही नाही, डायरेक्ट लिलाव करून विकूं शकत होता. अशा प्रकारची प्रोब्हीजन करण्यात आली होती. अशा प्रकारची प्रोब्हीजन करीत असतांना सन्माननीय सदस्य श्री. गणपतराव देशमुख यांचे मला फार सहकार्य मिळाले होते, मार्गदर्शन मिळाले होते. यामध्ये शेतक-याला फक्त बाजार समितीचा सेस भरवयाचा होता. या कायद्यामध्ये महत्वाच्या तरतुदी आहेत व त्या तरतुदी प्रमाणे सचिवाचे काम राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण कृषि उत्पन्न हे उक्त अधिनियमाच्या कलम 13 (1) (अ) अन्वये गठीत करण्यात आलेली बाब मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीकडे येते. या कायद्याशी सचिवाची जबाबदारी निगडीत आहे. राज्यातील इतर कृषि बाजार समित्यांमधील शेतक-यांना मुंबईतील बाजार समितीवर प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या प्रतिनिधीत्वचा अर्थ काय आहे? म्हणून राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतक-यांना त्या प्रमाणात सचिवाचे काय राहणार आहे ?

यानंतर श्री. गायकवाड....

श्री.दिवाकर रावते ...

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवस्थापन, प्रशासकीय सुधारणा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन आणण्यासाठी या अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा सांभाळ करण्याकरता सचिव अमुक दर्जाचा पाहिजे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. निबंधक, सहाय्यक निबंधक आणि त्याहून कमी दर्जाचा नसेल असा सचिव नेमण्यात येईल असे सांगण्यात आलेले आहे. मी अत्यंत खेदाने नमूद करु इच्छितो की, कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे त्या त्या भागातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना उत्पन्न मिळते. मराठवाडा आणि विदर्भातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना तर कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे उत्पन्न तर मिळत असतेच. किंबहुना विदर्भातील बाजार समित्यांचा तो एक श्वास आहे. मराठवाड्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेतून मोठे उत्पन्न मिळत असते याबाबतीत मी काल सभागृहात उल्लेख केला होता. रेकॉर्डवर 4 लाख विंचटल कापूस खरेदी करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले असून त्यातून 1 कोटी 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न आले आणि तेवढाच कापूस खाजगीमध्ये गेला, त्या कापसाची कोठेही नोंद झालेली नाही. अधिकाऱ्यांनी त्याचे पैसे जमा केले होते. हे कोणी केले, कसे केले ? ते माननीय मंत्री महोदयांना माहीत आहे त्याचबरोबर मला देखील माहीत. आहे. परभणीतील ही माणसे असल्यामुळे आपल्याला माहीत आहे. घरातील एखादी गोष्ट माहीत असल्यामुळे ती सांगता येते परंतु बाहेरची गोष्ट माहीत नसल्यामुळे सांगता येत नाही. 1 कोटी 5 लाख रुपये बुडालेले आहेत म्हणजे प्रत्यक्षात किती जमा केले असतील ? राज्यातील बाजार समित्या विकलांग करण्याचे काम शासनाच्या एका निर्णयामुळे झाले होते. कापूस एकाधिकार योजना आज अस्तिवात आहे. परंतु त्या कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. सुरुवातीला या योजनेतून प्रचंड तोटा येत आहे असे सारखे सांगितले जावयाचे. या सदनामध्ये खूप चर्चा करण्यात आली होती. कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेमुळे 3000 कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहेत. परंतु साखर कारखान्यांना जे 58 हजार कोटी रुपये दिले त्याचा शासनाने हवाला द्यावयाचा आहे. त्याचबरोबर 15 हजार कोटी रुपयांचे पैकेज दिले जावयाचे आहे त्याचा हवाला सरकार देणार आहे परंतु कापूस उत्पादक शेतक-याच्या दृष्टीने सुरु असलेल्या कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेत 3000 कोटी

श्री.दिवाकर रावते ...

रुपयांचे जे नुकसान झाले होते त्याचे मात्र मोठया प्रमाणावर भांडवल करण्यात आले आहे.जवळजवळ कापूस एकाधिकार खरेदी योजना मोडीत काढून टाकली होती.. या योजनेतून बाजार समित्यांना उत्पन्न मिळणार असल्यामुळे ही योजना म्हणजे बाजार समित्यांचा श्वास होता.

सभापती महोदय, अशा प्रकारे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला या योजनेतून पैसे मिळत होते. त्या उत्पन्नातून प्रमुख बाजार समित्यांना म्हणजेच पुण्याच्या मंडळाला देखील पैसे मिळत होते. त्यासंबंधीचा क्लॉज या विधेयकामध्ये आहे. गेल्या वर्षी या सदनामध्ये जी आकडेवारी सांगण्यात आली हाती ती मी पुन्हा सांगतो. साधारणपणे दोन हजार किंवटल कापूस खरेदी करण्यात आला होता त्यावर्षी 300 लाख टन कापसाचे उत्पादन झाले होते.यावर्षी फक्त 20 किंवटल कापसाचे उत्पादन झाले आहे. या वर्षी जर 20 किंवटल कापूस जमा झाला असेल तर त्यातून बाजार समितीची फी किती गेली असेल ? ही फी फक्त 200 रुपये होईल. शासनाचा कापसाचा भाव 1600 ते 1900 रुपये किंवटल एवढा असून व्यापा-यांचा भाव 3000 रुपये आहे. मला या निमित्ताने माननीय मंत्री महोदयांना असे विचारावयाचे आहे की, 3000 रुपये किंवटल या भावाने शेतक-यांनी व्यापा-यांना जो कापूस विकला होता त्यातील सेस करिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रेकॉर्डवर किती कापूस आला होता ? यातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीला किती सेस मिळाला होता आणि त्या व्यतिरिक्त किती कापूस व्यापा-यांना विकण्यात आला होता.

सभापती महोदय, मला सांगण्यास अत्यत दुःख होत आहे. या प्रकारामुळे आमच्या भागातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्न बुडत आहे. या सदनामध्ये माननीय मंत्री महोदयांनी मंत्री मंडळाच्या निर्णयाची 2006 च्या नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये एक घोषणा केली होती. ती घोषणा अशी होती की, " पर राज्यात जो कापूस जातो तो जाऊ नये याकरता मोठया प्रमाणावर जिनिग प्रेसिंग चालू करू आणि हा कापूस पर राज्यात जाऊ देणार नाही. कारण हे उत्पन्न आपल्या बाजार समित्यांचे आहे, आपल्या हदीतील हे उत्पन्न आहे ते आपल्याकडे राहिले पाहिजे " म्हणून अशा प्रकारची घोषणा नागपूरच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती.

नंतर श्री.सुंबरे

श्री. रावते

मला सांगावयास खेद वाटतो आणि अत्यंत निराशेने मी सांगतो की, केवळ ती घोषणा झाली, प्रत्यक्षात मात्र काहीही सरकारने केलेले नाही आणि परप्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपला कापूस गेला. कृषी खात्यानेच जाहीर केले होते त्यानुसार जवळपास 300 लाख किंवटल कापसाचे उत्पादन झाले हाते आणि त्यात व्यापाच्यांनी आणि आपल्या योजनेतून, जी काही तथाकथित एकाधिकार खरेदी अस्तित्वात आहे त्यातून खरेदी केला गेला. तो सर्व मिळून जवळपास दीड लाख हजार किंवटल आहे, त्याचा आपल्याला जो सेस मिळाला त्या व्यतिरिक्त 50 टक्के कापूस गुजराथमध्ये गेला. हा आतबट्टचाचा व्यवहार आपल्या सरकारने कसा केला ? जेव्हा कापसाला बाजारभाव जास्त नव्हता तेव्हा सरकारने कापसाला 2100 रुपये भाव देऊन खरेदी केला आणि नंतर कापसाचा भाव 2600 ते 2700 रुपये झाला तेव्हा सरकारने 1600 रुपयाने घेण्याचे ठरविले. मग आपल्याकडे कोणी कापूस देत नाही हे ओघानेच आले. त्यामुळे हे लोढणे आपल्या गळ्यात कशासाठी ठेवून घ्यायचे ? हे लोढणे आपल्या गळ्यात ठेवले तर त्यावरून सत्तारूढ-विरोधी पक्षात मारामार्या होणे नाही, कापूस उत्पादन शेतकऱ्यावर तुटून पडणे नाही, सरकारची त्यावर चर्चा नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, आपल्या मार्केट कमिट्यांचे उत्पन्न बुडाले, खरेदी-विक्री संघाला नुकसान झाले. जो कापूस गुजरातमध्ये गेला त्यामुळे विक्रीकरातून 4 टक्के प्रमाणे जे उत्पन्न आपल्या राज्याला मिळणार होते तेही मिळाले नाही. सभापती महोदय, एक किंवटल कापसामागे 1 रुपया बाजार समितीला मिळतो. दीड लाख किंवटल कापूस अशा प्रकारे गेला म्हणजे त्यातून 15 कोटी की 150 कोटी रुपये आपले गेले त्याचा हिशोब तुम्हीच करा. त्याचा अर्थ असाही आहे की, अशा व्यवहारात 50 पैसे खरेदी-विक्री संघाला मिळतात तेही गेले. थोडक्यात सांगावयाचे तर या संस्था सक्षम होण्यासाठी म्हणून आपण हा जो उत्पन्नाचा स्रोत तयार केला होता त्यातून या संस्थांना यामुळे काहीच मिळू शकले नाही. त्या नुकसानीतच गेल्या. कापसाच्या एका बेलमागे 4 टक्के सेस आपल्या सरकारला मिळत असतो. एका बेलची किंमत 10 हजार रुपये आहे असे गृहीत घरले आणि अशा 50 लाख बेल्स कमी झाल्या तर 4 टक्क्याने जवळपास 20 कोटी रुपयांचे नुकसान आपले झाले आहे. म्हणजेच हा सरकारच्या आणि मार्केट कमिट्यांच्याही उत्पन्नाचा भाग आहे. या शिवाय रुई आहे. आपण जिनिंग-प्रेसिंग घेतले आहे ना ? मार्केटमध्ये 1 पैसा रुईची किंत आहे आणि त्या किंमतीमध्ये 1 पैशानेही फरक झाला तरी कोट्यवधी रुपयांची

..... 4बी 2 ...

श्री. रावते

गोळाबेरीज होते. तर अशा प्रकारे आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मार्केट कमिट्चांचे नुकसान झाले. मग हा जो कापूस बाहेर जातो आहे तर जाऊ द्यात, हे नाहक गळ्यातील लोढणे बाजूला होत आहे तर ते कशासाठी आपल्या गळ्यात घ्यायचे ? असाही प्रयत्न होतो. सभापती महोदय, आणखी एक मुद्दा आहे. या सर्वांमध्ये तुमच्याकडे जे नोकर होते ते जवळपास 700 आहेत आणि त्यांना तुम्ही बसून पगार देत आहात, त्यात किती कोटी रुपये जात आहेत तेही येथे आपण सांगितले पाहिजे. त्यातून सरकार कारण नसताना अशा बिनकामाच्या लोकांच्या पगारापोटी किती पैसे खर्ची घालत आहे हेही समोर येईल. तेव्हा माझा प्रश्न असा आहे की, हा अशा प्रकारे आतबट्ट्याचा व्यवहार सरकार कशासाठी, कोणासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली करीत आहे तेच मला कळत नाही. सभापती महोदय, आणखी एक प्रकरण आहे. मुसिकोल ही कंपनी आहे ती फेडरेशनला 1 रुपयात दिली, ही कशासाठी दिली ? ...

(यानंतर श्री. सरफरे

श्री. दिवाकर रावते...

15 वर्षे बंद पडलेली कंपनी सरकारकडे एक रुपयामध्ये जमा केली. दी महाराष्ट्र ऑर्डिनेशन अँड कमर्शिअल ऑर्गनायझेशन लिमिटेड ही "मोसिकॉल" कंपनी कामगारांना एक रुपयांमध्ये कशासाठी दिली? त्याठिकाणी असलेल्या कामगारांचा वर्षाचा 25 कोटी रुपयांचा पगार देण्यासाठी दिली? आपण पण बंद केले तेव्हा 700 कामगारांचा पगार देत आहोत, आणि एक रुपयामध्ये घेतलेल्या या मोसिकॉलच्या कामगारांचा 25 कोटी रुपयांचा पगार देत आहोत. आम्ही अशापृष्टीने बिन कामाची माणसे संभाळून जागतिक बाजारपेठेमध्ये उतरत आहोत. जागतिक बाजारपेठेमध्ये कापसाची किंमत वाढली, जागतिक बाजारपेठेमध्ये कापसाला तेजी आली. 2700 ते 3000 रुपये भावाने कापूस घेतला जात आहे. हा कापूस परप्रांतामध्ये जात आहे, त्यामध्ये सरकारचे उत्पन्न बुडविले जात आहे. हा कापूस थांबविण्याकरिता या सदनामध्ये शासनाने धोरण जाहीर केले होते, ते धोरण अपयशी ठरले आहे. आपल्या तिजोरीवर भार नको, आपल्या गळ्यामध्ये लोढणे नको, काय होईल ते होऊ दे. अशापृष्टीने बिन कामाची 700 माणसे आपण पोसत आहात. आपण "मोसिकॉल" कंपनीच्या कामगारांचा 25 कोटी रुपयांचा पगार देत आहात, ही सर्व रक्कम पणनच्या माध्यमातून जात आहे. सभापती महोदय, शेतकऱ्याला आपला माल थेट विकता यावा, आणि बाजार समिती सक्षम व्हावी याकरिता तुम्ही हे विधेयक आणले. या बाजार समितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासक नेमणार आहात. अशाप्रकारे आपल्याला प्रशासक नेमता येईल, मडळ नेमता येईल. आणि त्यानंतर सचिव म्हणून सहाय्यक निबंधकापेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी नेमणार आहात. या मॉडेल अँकटप्रमाणे शेतकऱ्याच्या मालाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यानंतर त्याच्या मालाचे संरक्षण होईल. आणि नंतर ती बाजार पेठ जिल्हयाची, चार जिल्हयाची आणि विभागाची होईल. या सर्व तरतुदी आपण शेतकऱ्यासाठी केल्या तर मग बाजारहाट कोण करीत आहे? मी त्याबाबतची माझ्याजवळ असलेली यादी वाचून दाखवितो. भांडवलदारांचे बटीक बनून शेतकऱ्याला गहाण रहावयास लावण्याच्या या सरकारने मॉडेल अँकट आणून त्यामध्ये या सर्व सुधारणा आणल्या आहेत. सभापती महोदय, या विधेयकावर विस्तृतपणे बोलण्याचा मला पूर्ण अधिकार असल्यामुळे आपण मला विनंती करीत आहात. परंतु मला काही गोष्टी सांगण्याची आवश्यकता आहे. त्या याठिकाणी न सांगता शेतकऱ्यांच्या वृत्तीशी बेईमानी करणे मला जमणार नाही. मला शेतकऱ्यांबद्दल आणखी काही करता येत नसेल परंतु आपण त्या शेतकऱ्यांसाठी कब्रस्तान खोदत आहात.

श्री. दिवाकर रावते...

सभापती महोदय, मागील वेळी आपण कृषी महामंडळाच्या जमिनी देऊन टाकण्यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात आणले होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व काळ्याभोर जमिनी देऊन टाकल्या म्हणून मी त्या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. माननीय सदस्य श्री. शिंदे साहेब आपल्याकडे तर जास्त जमिनी होत्या. त्यावेळी विधेयकावर भाषण करतांना मी आपले नाव घेऊन बोललो होतो. त्या जमिनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला करता येत नाहीत म्हणून आपण देऊन टाकल्या. शेतकऱ्यांच्या हिताचे तुम्ही निर्णय घेता. तर मग मी परवा बि-बियाणे महामंडळावरील चर्चेच्यावेळी माझ्या भाषणामध्ये बोललो आहे. आपण आजसुधा सकाळी गिरण्यांच्या जमिनी खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करण्याबाबत सांगितले आहे. त्या दिलेल्या जमिनीवर खाजगी बि-बियाणे निर्माण करणाऱ्या कंपनीकडे संपूर्ण यंत्रणा असतांना त्यांच्याबरोबर आपल्या कृषी बि-बियाणे महामंडळाने जर करार केला असता तर आमच्या शेतकऱ्याला सकस चांगल्या पध्दतीचे बेने मिळाले असते. आणि आज शेतकरी पेरणीपासून उद्धरण्यात आहे....

तालिका सभापती : सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ 6 वाजेपर्यंत होती. माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांना मला विचारावयाचे आहे की, भाषण पूर्ण करण्यास आपणास आणखी किती वेळ लागेल?

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, मला किती वेळ लागेल हे मी सांगू शकत नाही...

श्री. जयप्रकाश दांडेगावकर : सभापती महोदय, मला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास जावयाचे आहे. तसेच, माननीय सहकार मंत्री सभागृहात उपस्थित नाहीत. तेव्हा विधेयकावरील चर्चा उद्या किंवा मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

10-04-2008

(असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही)

4C-1

APR/ SBT/ KTG/

18:00

तालिका सभापती (श्री.जगदीश गुप्ता) : ठीक आहे. मला पुढीलप्रमाणे घोषणा करावयाची आहे.

आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्या जीवनावर रमेश देव प्रॉडक्शन प्रा.लि.यांनी मराठी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. संचालक, सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन व श्री.रमेश देव यांनी मा.सदस्यांसाठी "वासुदेव बळवंत फडके" या चित्रपटाचा "विशेष खेळ" आज गुरुवार, दिनांक 10 एप्रिल 2008 रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे सायंकाळी 7.30 वाजता आयोजित केला आहे. तरी सर्व माननीय सदस्यांनी अवश्य उपस्थित रहावे.

सभागृहाची बैठक आता स्थगित होऊन उद्या शुक्रवार, दिनांक 11-4-2008 रोजी सकाळी 11.00 वाजता पुन्हा भरेल.

(सभागृहाची बैठक सायंकाळी 06 वाजून 01 मिनिटांनी, शुक्रवार, दिनांक 11-4-2008 रोजीच्या सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत